

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

दो विश्व युद्धों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

[१९१६ — ३६]

ई० एच० कार



लक्ष्मी नारायण अग्रवाल

प्रकाशक, बुक्स एंड स्टेशनरी विक्रेता

'हॉस्पिटल रोड, आगरा ।

मूल्य ६।)

सर्वाधिकार सुरक्षित



१९५६



मूल्य छै: रुपये पच्चीस नये पैसे

© 1956 by the author. All rights reserved. No part of this book may be reproduced without the written permission of the author.

प्रकाशक :
लक्ष्मीनारायण अग्रवाल,
आगरा

मुद्रक -
मॉडर्न प्रेस,
आगरा

प्रकाशकीय

यह पुस्तक अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध व रोचक ग्रन्थ *International Relations Between The Two World Wars : E. H. Carr* का हिन्दी रूपान्तर है। यथा संभव रूपान्तर को सरल, बोधगम्य एवं भाषा की दृष्टि से वैज्ञानिक बनाने की चेष्टा की गई है। फिर भी कार्य दुस्तर है।

पुस्तक के मूल लेखक श्री ई० एच० कार ने रूपान्तर के निमित्त आज्ञा प्रदान की, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसका रूपान्तर श्री राजमल जैन ने किया था और अब इस द्वितीय संस्करण का सशोधन तथा परिवर्धन श्री एस० आर० महेन्दरी, लेखरार, राजनीति विभाग, आगरा कॉलेज ने किया है। इस प्रकार यह पुस्तक सभी दृष्टियों से और भी पूर्ण तथा उपादेय बना दी गई है।

विषय-सूची

विषय प्रवेश

- शांति समझौता १
- ✓ योरोपीय समझौता; निक्ट पूर्व और अफ्रीका, अमेरिका और सुदूर पूर्व
प्रथम भाग—प्रवर्तन काल : गुटबेरिया (१९२०-२४)
- १—फ्रांस और उसके साथी २३
गारंटी मार्ग; गुटबन्दी मार्ग, पोलैंड, लघुमैत्री संध
- २—पराजित जर्मनी ४१
युद्ध अपराध और युद्ध अपराधी; निःशस्त्रीकरण और अमेनीकरण, क्षतिपूर्ति
- ३—योरोप के अन्य विक्षोभ केन्द्र ५७
उन्पूवीय राज्य, इटली, सोवियत संघ
द्वितीय भाग : शांतिकरण काल राष्ट्र संध (१९२४-३०)
- ४—शांति की नींव ७५
डेविस योजना, मित्रराष्ट्रों के आपसी वर्ज, जेनेवा उपमंडि, लोकतंत्रों संधि
- ५—राष्ट्र संध उन्नति के चरम शिखर पर ८१
राष्ट्र संघ पूर्ण शक्ति के समय, राष्ट्र संध शांति स्थापक के रूप में, राष्ट्र संध की अन्य गति विधियाँ
- ६—युद्ध विरोधी अभियान १०५
राष्ट्र संघ समझौते; पेरिस समझौता, यंग योजना
तृतीय भाग : संकट काल - शक्ति कूटनीतिका पुन आरंभ (१९३०-३३)
- ✓ ७—अर्थ व्यवस्था भंग १२३
जर्मनी में संकट, सर्वनाश का वर्ष; क्षतिपूर्ति का अन्त, विरव अर्थ सम्मेलन; अन्तिम दौर
- ८—सुदूर पूर्व में सकट १४०
✓ वाशिंगटन सम्मेलन के बाद चीन; जापान द्वारा मंचूरिया विजय, राष्ट्र संघ पर परिणाम

६—नि शस्त्रीकरण सम्मेलन १६१

नि शस्त्रीकरण समस्या, नि वस्त्रीकरण सम्मेलन, चार-राष्ट्र सम्मेलन -

चतुर्थ भाग जर्मनी का पुनर्संगठन संधियों का अन्त (१६३३-३६) ।

१०—नात्सी शक्ति १८१

पोलैंड और सोवियत सघ, ऑस्ट्रिया और इटली, फ्रांस, इटली और लघुमैनी सघ, बालकन मैत्री सघ ।

११—संधियों का परित्याग १६८

जर्मनी द्वारा परित्याग, इटली द्वारा परित्याग, लोकार्नो का अन्त

१२—गैर योरोपीय ससार २१४

मध्य-पूर्व, सुदूर पूर्व, अमेरिका और विश्व राजनीति ब्रिटिश राष्ट्र मंडल ।

१३—पुन युद्ध की लपटों में २३६

स्पेनिश गृह-युद्ध, राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्वात्मक गुटबन्दी, जर्मनी द्वारा आक्रमण का प्रारम्भ, युद्ध का आरम्भ ।

परिशिष्ट १ मुनरो सिद्धान्त २६३

परिशिष्ट २ विल्सन के चौदह सूत्र २६५

परिशिष्ट ३ राष्ट्र सघ के अनुबध पत्र-से उद्धरण २६८

महत्वपूर्ण घटनाओं की कालक्रमानुसार तालिका २७५

शब्दावली—अंग्रेजी हिन्दी पर्याय २७६

शब्दानुक्रमणिका

मानचित्र सूची

वर्सेलीज की संधि ५

पूर्वीय योरोप २६

भूमध्यसागरीय बेसिन ६२

सुदूर पूर्व १४३

मध्य पूर्व २१५

विषय-प्रवेश

(INTRODUCTION)

शांति समझौता

(Peace Settlement)

प्रथम विश्व-युद्ध की अवधि चार वर्ष तथा तीन महीनों से कुछ अधिक हो थी। युद्ध का प्रारम्भ २८ जुलाई, १९१४ को सर्बिया (Serbia) पर ऑस्ट्रिया-हंगरी द्वारा आक्रमण किए जाने से हुआ। युद्ध की समाप्ति ११ नवम्बर, १९१८ को हुई जब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से विराम सन्धि (armistice) की।

मित्र और साथी राष्ट्रों (Allied and Associated Powers) ने १९१९ में जर्मनी से वसॅलोज़ (Versailles) की सन्धि (२८ जून), ऑस्ट्रिया से सेन्ट जर्मेन (St. Germain) की सन्धि (१० सितम्बर), बल्गेरिया से न्यूइली (Neully) की सन्धि (१७ नवम्बर) तथा १९२० में हंगरी से ट्रिएनॉ (Trianon) की सन्धि (४ जून) सम्पन्न की। किन्तु टर्की के साथ अन्तिम शांति सन्धि (treaty of peace) पर २३ जुलाई, १९२३ को जाकर कहीं लुसाने (Lausanne) में हस्ताक्षर हो सके। यह सन्धि ६ अगस्त १९२४ को प्रमल में आई और उसके बाद ही सारे सप्ताह में पुनः विधिवत् शांति स्थापित हो सकी। इसी बीच प्रज्ञान महासागर में हित (interest) रखने वाले राष्ट्रों का एक सम्मेलन १९२१-२२ के बीच काल में वाशिंगटन में हो चुका था। इस सम्मेलन में, इन राष्ट्रों ने कई संधियाँ की थी जिनका उद्देश्य यह था कि सुदूर पूर्व (Far East) में पूर्व स्थिति (status quo) दृढ़तापूर्वक कायम रखी जाए। इन सभी संधियों और इनके कारण की गई अनेक छोटी-मोटी सन्धियों और इकरारनामों (agreements) को शांति समझौता कहा जा सकता है। प्रथम और द्वितीय विश्व-युद्ध के बीच की अवधि में हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की प्रायः प्रत्येक राजनैतिक घटना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस समझौते का ही परिणाम थी; इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपना अध्ययन इसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं पर एक संक्षिप्त दृष्टिपात करते हुए प्रारम्भ करें।

यूरोपीय समझौता of Versailles (The European Settlement)

वर्सेलीज की सन्धि में कुछ ऐसी विशेषताएँ थी जिन्होंने इस सन्धि के परवर्ती (subsequent) इतिहास को बहुत प्रभावित किया।

एक तो यह सन्धि जर्मन प्रचारकों के सुपरिचित शब्दों में “आरोपित शांति” (dictated peace) स्थापित करने वाली सन्धि थी। वह विजैताओं द्वारा विजितों पर लादी गई थी और उसका आधार परस्पर आदान-प्रदान नहीं था। वैसे तो युद्ध समाप्त करने वाली लगभग प्रत्येक सन्धि ही, एक सीमा तक, आरोपित शांति स्थापित करने वाली सन्धि होती है किन्तु वर्सेलीज की सन्धि में आरोप या थोपने का भाव आधुनिक युग की किसी भी पिछली शांति सन्धि की अपेक्षा अधिक स्पष्ट था। वर्सेलीज में जर्मन प्रतिनिधिमण्डल का सन्धि के प्रारूप (draft) पर लिखित आलोचना करने का केवल एक ही अवसर दिया गया था। उसकी कुछ आलोचनाओं पर ध्यान भी दिया गया किन्तु संशोधित (revised) सन्धि उसके हाथों में इस घमकी के साथ सौंप दी गई थी कि यदि उस पर पाँच दिन में ही हस्ताक्षर नहीं किये गए, तो युद्ध पुनः प्रारम्भ कर दिया जाएगा। जर्मन प्रतिनिधिमण्डल का कोई भी सदस्य प्रारूप दिए जाने और सन्धि पर हस्ताक्षर किए जाने के दो औपचारिक (formal) अवसरों को छोड़ और किसी भी समय मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधियों से आमने-सामने नहीं मिला। इन अवसरों पर भी साधारण सामाजिक शिष्टाचार का पालन नहीं किया गया। जर्मनों को और से हस्ताक्षर करने वाले दोनों ही प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर-विधि के समय मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधियों की बराबरी से नहीं बैठाया गया अपितु, इसके विपरीत, पहले में ही उन्हें अपराधियों की भाँति हॉल के भीतर और बाहर लाया-लेजाया गया। इतना अवसर अपमानों के, जिनका औचित्य केवल यही हो सकता है कि युद्ध की तीव्र कटुता अब भी अवशिष्ट थी, जर्मनों में व अन्यत्र व्यापक मनोवैज्ञानिक परिणाम हुए। उन्हीं के कारण “आरोपित शांति” को धारणा में जर्मन लोगों के मन में घर कर लिया और जर्मनों में यह विश्वास सामान्य रूप से फैल गया कि उपरोक्त परिस्थितियों में जर्मनों से कराये गए हस्ताक्षर उस पर नैतिक रूप से बंधनकारी (binding) नहीं हैं। जर्मन लोगों

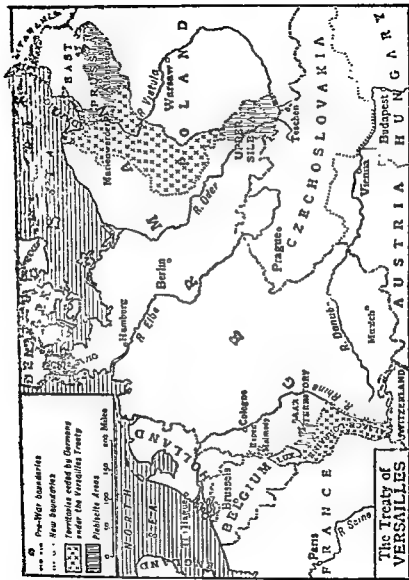
की इस धारणा को अन्य देशों के अधिकांश लोकमत ने भी सहज में ही स्वीकार कर लिया ।

दूसरे, वसैलीज की सन्धि पिछली किसी भी शांति सन्धि से इस बात में भिन्न थी कि उसका विज्ञापित आधार युद्ध के समय प्रचलित किये गए कुछ व्यापक सिद्धान्त थे । इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन के चौदह सूत्र (Fourteen Points) हैं जिन्हें जर्मनी ने विरामसन्धि से पहिले ही सम्झौते के आधार के रूप में स्वीकार कर लिया था । मुख्यतः विल्सन द्वारा इन सिद्धान्तों का दृढ़ समर्थन किए जाने के कारण ही, इस सन्धि की नींव विद्युद्ध आदर्शवाद पर थी । इस सन्धि में यह व्यवस्था की गई थी कि निम्नलिखित सस्यामों की स्थापना की जाय :—राष्ट्र-संघ (League of Nations) जिसका प्रमुख उद्देश्य शांति बनाए रखना हो, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) जो कि श्रमिकों की स्थिति का विनियमन (regulation) करे ; और जर्मनी द्वारा सौंपे जाने वाले उपनिवेशों में सरकारात्मक शासन प्रणाली (mandatory system of government) । सन् १९१९ के बाद की नई विश्व व्यवस्था (new world order) की ये सत्थाएँ एक नियमित और आवश्यक अंग बन गई । जो भी हो, सन्धिकर्त्ताओं द्वारा विनेश राष्ट्रों की तात्कालिक आवश्यकताओं के साथ आदर्शवाद का मेल बैठाने के प्रयत्न के अन्य परिणाम इतने शुभ नहीं रहे । यही कारण था कि मूल चौदह सूत्रों के साथ सन्धि के कुछ भागों की तुलना कर उनके दोष दिखाना आलोचकों के लिए रुठिन नहीं रह गया । यह भी विवादास्पद था कि जो क्षेत्र (territories) जर्मनी से अलग कर पोलैण्ड को सौंपे गए 'निर्विवाद रूप से पोल आबादी' के थे, या जर्मनी से उसके समुद्र पार के सारे प्रदेश छीन कर 'समस्त औपनिवेशिक दावों का अबाधित, उदार व पूर्णतया निष्पक्ष निवटारा' किया गया था । इसके साथ ही जर्मनी और ऑस्ट्रिया का संघ बनाने का निषेध (prohibition), विशेषकर उस स्थिति में, निराधार था जब कि सम्झौते के लिए मित्र-राष्ट्रों ने जनता द्वारा आत्म-निर्णय (self-determination of peoples) के सिद्धान्त को पथ-प्रदर्शन के लिए स्वीकार कर लिया था । सिद्धान्त और व्यवहार में इन और इसी प्रकार की अन्य असंगतियों ने उन लोगों को आलोचना का अवसर

दिया जिनका यह मत था कि वर्सलोज की सन्धि एक कलुषित दस्तावेज (tainted document) थी और मित्र-राष्ट्रो ने विरामसन्धि की शर्तों का ही उल्लंघन किया था।

वर्सलोज की सन्धि के अनुसार जर्मनी पर लगाये गए बन्धन, कुछ ही अपवादों को छोड़कर, या तो भागसी समझौते के द्वारा या समय की गति के साथ-साथ या जर्मनी द्वारा अस्वीकार (repudiation) कर दिये जाने के कारण, अन्ततः रह हो गए।¹ उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण [दण्ड (penalties), क्षतिपूर्ति (reparations), असेनीकृत क्षेत्र (demilitarised zone), निःशस्त्रीकरण (disarmaments)] का विवेचन अगले अध्यायों में किया जायगा। यहाँ योरोपीय क्षेत्रों सम्बन्धी व्यवस्था का केवल सार दे देना ही आवश्यक है।¹ पश्चिम में, जर्मनी ने फ्रांस को आल्सैक (Alsace) और लॉरेन (Lorraine) वापस दे दिये और यूपेन (Eupen) तथा मालमेडी (Malmédy) के दो छोटे-छोटे क्षेत्रसहब बेल्जियम को सौंप दिये तथा लक्जेमबर्ग के साथ पुराने युगी समझौते को समाप्त कर दिया। सार (Saar) का कोयला-खदान क्षेत्र पन्द्रह वर्षों के लिए राष्ट्र-संघ आयोग (commission) के प्रशासन (administration) में सौंप दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि इस अवधि के बाद उसके भाग्य का निपटारा जनमत (plebiscite) द्वारा किया जाये। किन्तु इन खदानों का स्वामित्व फ्रांस को उसकी (फ्रांस की) उन कोयला-खदानों की क्षतिपूर्ति के रूप में हस्तान्तरित (transferred) कर दिया गया जो कि युद्धकाल में तप्त हो गई थी। दक्षिण में, जर्मनी ने एक छोटा सा भू-भाग नवगठित बेकोस्लोवाकिया राज्य को सौंप दिया, इसके साथ ही जर्मनी पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि राष्ट्र-संघ परिषद् (Council of the League) की निर्विरोध स्वीकृति (unanimous consent) के बिना वह ऑस्ट्रिया के साथ संघ नहीं बना सकेगा। उत्तर में, श्लेसविग की ग्रेंड डची (Grand Duchy of Schleswig) के एक भाग में, जिसे

1 "The servitudes imposed on Germany in the Treaty of Versailles were eventually, with few exceptions, abrogated either by agreement, or by lapse of time, or by repudiation on the part of Germany."



१८६४ में डेनमार्क ने प्रशा से छीन लिया था, जनमत लेने का निश्चय किया गया। सन् १९२० की फरवरी और मार्च में वहाँ जनमत लिया गया जिसका परिणाम सन्तोषजनक स्पष्ट निर्णय हुआ। उत्तरी भाग में, ७५ प्रतिशत मत डेनमार्क के पक्ष में पड़े किन्तु दक्षिणी भाग ने इससे भी अधिक बहुमत जर्मनी के पक्ष में दिया।

पूर्व में, जर्मनी ने मेमेल (Memel) बन्दरगाह और उसकी पार्श्व-भूमि (hinterland) प्रमुख मित्र और साथी राष्ट्रों (Principal Allied and Associated Powers) को इसलिये सौंप दिये कि वे मन्त्र में उन्हें लिथुआनिया को हस्तान्तरित कर दें। पोलैण्ड को उसने पोजेन (Posen) प्रान्त और लगभग चालीस मील समुद्री किनारे के प्रदेश सहित पश्चिमी प्रशा के प्रान्त का अधिकांश भाग—तथाकथित गलियारा (corridor) जो कि पूर्वी प्रशा को शेष जर्मनी से अलग करता है—सौंप दिया। डानजिग (Danzig) नामक एक जर्मन नगर जो कि पोलैण्ड (जिस चौदह सूत्रों में "अबाधित और सुरक्षित समुद्री मार्ग की सुविधा" देने का वचन दिया गया था) का ही एक प्राकृतिक बन्दरगाह था, पोलैण्ड के साथ सधि सम्बन्धों वाला एक स्वतंत्र नगर (Free City) बन गया। यह नगर पोलैण्ड के चुगी क्षेत्र (customs area) में सम्मिलित हो गया और उसने अपने वैदेशिक संबंध पोलैण्ड के हाथों में सौंप दिए। इसके अतिरिक्त पश्चिमी प्रशा के मेरीनवर्डर (Marienwerder) और पूर्वी प्रशा के एलेन्स्टीन (Allenstein) जिलों तथा समस्त ऊपरी सिलेशिया (Upper Silesia) में जनमत लेने की व्यवस्था भी की गई थी। जुलाई, १९२० में मेरीनवर्डर और एलेन्स्टीन में जनमत लिया गया जिसका परिणाम अत्यधिक जर्मन बहुमत रहा। किन्तु दोनों ही जिलों के जिन छोटे से गाँवों में पोलैण्ड के पक्ष में बहुमत दिया उन्हें पोलैण्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया। ऊपरी सिलेशिया में जनमत लेना अगले वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस कारण दोनों पक्षों में बहुत दुर्भावना फैली और गंभीर हिंसात्मक उपद्रव भी हुए। अन्य जनमत जिलों (plebiscite-districts) से ऊपरी सिलेशिया इस बात में भिन्न था कि उसमें कोयले और लोहे की प्रचुरता थी तथा विस्तृत और घनी आबादी वाला औद्योगिक क्षेत्र भी उसमें शामिल था। मतदान से कुछ निर्णय नहीं

हो सका। लगभग ६० प्रतिशत मन जर्मनी के पक्ष में पड़े तो करीब ४० प्रतिशत पोलैण्ड के पक्ष में। किंतु कुछ स्पष्ट ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी क्षेत्र में जनमत का परिणाम इतना खितरा हुआ था कि किसी निर्णय पर पहुँच सकना कठिन हो गया। एक तरफ तो ब्रिटिश और इटैलियन आयुक्तों (commissioners) ने और दूसरी तरफ फ्रांसीसी आयुक्त ने परस्पर विरोधी सिफारिशें प्रस्तुत की। मित्र-राष्ट्रों की सर्वोच्च परिषद् (Supreme Council) इन सिफारिशों के सबध में एकमत नहीं हो सकी और उसने न जाने किस दुष्प्रेरणावत्त, यह मामला राष्ट्रसंघ परिषद में भेज दिया। दूसरी बार भी अनिरोध की आशका से परिषद ने फ्रांसीसी आयुक्त तथा ब्रिटिश और इटैलियन आयुक्तों द्वारा प्रस्तावित नीति के लगभग मध्य का मार्ग अपनाया। बूनि ब्रिटिश-इटैलियन नीति मनवान के परिणामों को ही यथासंभव अमली रूप दिलाने का एक सतर्कतापूर्ण प्रयत्न था और फ्रांसीसी नीति स्पष्ट रूप से पोलैण्ड के दावों की पक्षपाती थी, इसलिए परिषद का निर्णय भी पूर्णतया निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। इस निर्णय से जर्मनी में रोष फैल गया और राष्ट्रसंघ के प्रारंभिक वर्षों में ही जर्मन लोकमत को राष्ट्रसंघ के विरुद्ध बनाने में उसने काफी सहायता की। वसैलीज की संधि के क्षेत्रिक उपबंधों (provisions) के परिणामस्वरूप जर्मनी को योरोप में २५,००० वर्ग मील से भी अधिक भूमि और लगभग ७० लाख नागरिकों से हाथ धोना पड़ा।

अन्य योरोपीय शांति-संधियों पर यहाँ और भी संक्षेप में विचार किया जायेगा।

नवम्बर १९१८ में ऑस्ट्रो-हंगेरियन राजतन्त्र के पतन के कारण जर्मन-ऑस्ट्रिया एक पृथक् और विचित्र अनुपात वाला भू-भाग रह गया। उसके ७०,००,००० निवासियों में से २०,००,००० से भी अधिक नागरिक बिस्त्रा में ही बसे हुए थे। कोहेमिया, मोरेविया और ऑस्ट्रियन सिलेशिया उससे अलग हो कर चेकोस्लोवाकिया का केन्द्रभाग बन चुके थे। स्लोवेनिया सहित सर्बिया (Serbia) और क्रोएशिया को मिलाकर यूगोस्लाव राज्य का निर्माण किया गया था। इटली ने भी ट्रिस्ट (Trieste) और उससे लगी हुई पार्श्वभूमि पर अधिकार कर लिया। सेंट जर्मन की संधि ने इन सम्पन्न संधियों (accom-

plished facts) को पंजीयित (register) करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया। आत्मनिर्णय के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने वाले दो उपबन्ध इस संधि में भी थे। उनमें से एक का सबध ऑस्ट्रिया और जर्मनी का संध बनाने सबधी निषेध से था। वास्तव में यह निषेध वसेलीज की संधि में पहिले से ही कर दी गई व्यवस्था को दोहराने जैसा था। दूसरा उपबन्ध शुद्ध जर्मन भाषी दक्षिणी टायरोल (Tyrol) इटली को सौंपे जाने से सम्बन्धित था ताकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ब्रेनर का सीमांत मिल जाए। किन्तु ऑस्ट्रिया की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी (कुछ महीनों तक विएना के लोग वास्तव में भूखी मरते रहे) कि शांति से सम्बन्धित राजनैतिक अपमानों का उसे क्षायद ही अनुभव हुआ हो। मित्र राष्ट्रों ने इस भय से कि जर्मनी के साथ संध बनाने का आन्दोलन व्यापक रूप धारण न कर ले, सन्धि के क्षेत्रेतर (non-territorial) उपबन्धों को लागू करने का कोई गम्भीर प्रयत्न ही नहीं किया, और ऑस्ट्रियन क्षतिपूर्ति आयोग (Austrian Reparation Commission) भी एक सहायता-संगठन (relief organisation) मात्र बन गया।

हंगरी का प्राचीन राज्य भी जिसके १,७०,००,००० निवासियों में आधे से कुछ अधिक हंगरी के निवासी थे, जाति-समूहों में बँट गया। ट्स्विंकी की सन्धि ने चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रूमानिया को क्रमशः स्लोवाकिया, क्रोएशिया और ट्रांसिलवानिया हस्तान्तरित किए जाने की पुष्टि कर दी। मोटेतौर पर ये निराय न्यायोचित थे। किन्तु जर्मनी के पूर्वी सीमांत की अपेक्षा हंगरी के सीमांत इस बात के अधिक स्पष्ट प्रमाण है कि सन्धिकर्ता अपने सिद्धान्तों की मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में यथासम्भव तोड़ने-मरोड़ने और शत्रु राष्ट्र के अहित-साधन के लिए उनका उपयोग करने के लिए कुछ उत्सुक अवश्य थे। इस तोड़ मरोड़ का एकत्रित परिणाम बहुत गहरा पड़ा। हंगरी के प्रचारकों ने इन छोटे मोटे अन्यायों का अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए पूरा उपयोग किया।

हंगरी के समान बल्गेरिया की भी बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी किन्तु उसकी अधिकांश हानि १९१६ के समझौते से नहीं अपितु १९१३ के शांति-समझौते के समय प्रारम्भ हुई थी जब कि द्वितीय बाल्कन युद्ध समाप्त हुआ था।

सन् १६१२ के प्रथम बाल्कन युद्ध के समय टर्की को बाल्कन द्वीपों से निकाल बाहर करने और उसे कांस्टेंटिनोपल (Constantinople) से लगभग ५० मील दूर खदेड़ देने के उद्देश्य से बल्गेरिया ने सर्बिया, यूनान और रूमानिया से सहयोग किया था। किन्तु लुट के विभाजन के प्रश्न पर विजेताओं में फूट पड़ गई। द्वितीय बाल्कन युद्ध के समय बल्गेरिया के तीनों ही पुराने साथियों और टर्की ने एक साथ बल्गेरिया पर आक्रमण किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई सन्धि के अनुसार बल्गेरिया को विवश होकर इन चारों राष्ट्रों को भूमि देनी पड़ी। सन् १६१६ की न्यूइली की सन्धि ने बल्गेरिया की हानि पर अपनी मुहर लगा दी। बल्गेरिया को और अधिक हानि में डालते हुए इस सन्धि ने सर्बिया और यूनान से लगी हुई उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर दिया तथा रूमानिया से लगे हुए उसके अन्यायपूर्ण सीमानों में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जो कि १६१३ में निश्चिन किया गया था। बल्गेरिया की सबसे अधिक शिकायत मेसिडोनिया नहीं मिलने से थी जो कि प्रथम बाल्कन युद्ध में भाग लेने के बदले में उसे दिए जाने का वचन दिया गया था। यहाँ हमारे सामने अब एक ऐसी लैंग्विक समस्या आ खड़ी हुई है जो कि अभी तक विवेचित समस्याओं से भिन्न है। जर्मनी और पोलेण्ड या हंगरी और रूमानिया के बीच न्यायपूर्ण सीमानें निश्चित करना कठिन हो सकता था, किन्तु संबंधित आबादी विसंभूत जाति (race) की है उसके बारे में तो कम से कम कोई संदेह था ही नहीं। मेसिडोनिया में, इस प्रारम्भिक मुद्दे को लेकर ही, बटु विवाद उठ खड़ा हुआ। मेसिडोनिया के लोग स्लाव जाति के थे किन्तु उनमें राष्ट्रीय चेतना (national consciousness) या तो कमजोर थी या उसका अभाव था। उनकी बोली (dialect) एक तरफ सर्बियन में मिल गई थी तो दूसरी तरफ बल्गेरियन में। समय आने पर उन्हें पूरे बल्गेरियन या पूरे सर्बियन माना जा सकता था क्योंकि वे लोग इस बात के प्रति स्वयं उदासीन थे। सन् १६१३ के समझौते, जिसकी पुष्टि १६१६ में हुई, के अनुसार मेसिडोनिया का अधिकांश भाग सर्बिया को मिला और शेष भाग का भी अधिकांश यूनान के हाथ आया। किन्तु मेसिडोनिया के लोग एक ऐसी आदिम जाति के थे जिनमें ब्रूटलसोट (brigandage) को सम्मान की बात माना जाना था। उनमें से कुछ ताहसी लोग बल्गेरिया चले गए और वहाँ उन्होंने मेसिडोनियन क्रांतिकारी संगठन (Me-

cedonian Revolutionary Organisation) की स्थापना की जिसका काम यूगोस्लाव या यूनान-क्षेत्र में समय-समय पर घावे बोलना था। इस सगठन ने सीमांत के दोनों ओर की जनता में आतंक फैला दिया और युद्ध के बाद के दस वर्षों से भी अधिक समय तक बल्गेरिया और उसके पड़ोसी देशों के सबधों को कटु बनाये रखा। इस अवधि में योरोप के अन्य किसी भी भाग की अपेक्षा मेसिडोनिया में ही समभवतः जीवन और संपत्ति कम सुरक्षित थे।

न्यूइली की सन्धि के जिस एक और अन्य उपबन्ध का यहाँ उल्लेख आवश्यक है, वह उस धारा से संबंधित है जिसके अनुसार मित्र-राष्ट्रों ने यह वचन दिया था कि “एजियन समुद्र में बल्गेरिया को आर्थिक बहिर्भाग (economic outlet) सुनिश्चित करा दिये जायेंगे।” बल्गेरिया निवासियों ने इसका अर्थ, पोलेण्ड की भाँति, क्षेत्रिक गलियारा (territorial corridor) समझा। मित्र-राष्ट्रों ने बल्गेरिया को यूनान के एक बंदरगाह में एक कर-मुक्त क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा किंतु बल्गेरिया निवासियों ने इसे शिरोधार्य करने की अपेक्षा अस्वीकार करना ही उचित समझा, आखिर, इस विवाद-ग्रस्त उपबन्ध को अमल में लाने के लिए इसके बाद कुछ भी नहीं किया गया।

अतः मैं, इस बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि नवनिर्मित राज्यों—पोलेण्ड और चेकोस्लोवाकिया—तथा जिन राज्यों के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई थी उन्हें—यूगोस्लाविया, रूमानिया और यूनान—प्रमुख मित्र और साथी राष्ट्रों से सन्धियाँ करनी पड़ी। इन सन्धियों के अधीन इन राज्यों ने अपने क्षेत्र में रहने वाले “मूलजातिक, धार्मिक और भाषिक (racial, religious and linguistic) अल्पसंख्यकों” को यह गारंटी दी कि उन्हें राजनैतिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी तथा उनके लिए विद्यालय खोले जायेंगे और वे न्यायालयों में तथा शासन से काम-काज पढ़ने पर अपनी भाषा का उपयोग कर सकेंगे। आस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और टर्की के साथ हुई शांति सन्धियों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी। किन्तु अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में जर्मनी का कोई कर्तव्य निश्चित नहीं किया गया। बड़ी विचित्र बात है कि वसॅलीज के शांति-स्थापकों ने केवल इसी मामले में जर्मनी को अन्य बड़े राष्ट्रों की बराबरी का स्तर दिया था।

निकट पूर्व और अफ्रीका (The Near East & Africa)

जुलाई, १९२३ में टर्की के साथ की गई लुसाने की संधि (Treaty of Lausanne) ही केवल एक ऐसी शांति संधि है जिसे उसके सभी हस्ताक्षरकर्ता तेरह वर्षों तक बंध और प्रभावशील (valid and applicable) मानते रहे तथा जिसे १९३६ में भी (देखिए, दसवें अध्याय का अन्तिम भाग) स्वेच्छापूर्व समझौते द्वारा केवल एक ही बात के लिए संशोधित किया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से, उसकी यह विशेषता कई कारणों से थी जिनकी वजह से वह अन्य शांति-संधियों से विभिन्न हो सकी। यह संधि उस समय की गई थी जब कि युद्ध समाप्त हुए लगभग पांच वर्षों के बाद थे और युद्ध की कड़वाहट की कम होने के लिए भी अवसर मिल चुका था, वह योपी नहीं गई थी अपितु दोनों ही पक्ष लम्बी चर्चाओं के बाद उस पर सहमत हो सके थे। उस पर हस्ताक्षर भी किसी मित्र-राष्ट्र की राजधानी में नहीं, अपितु तटस्थ देश की भूमि पर किये गए थे। जिन लम्बी और जटिल घटनाओं के कारण यह सतोपजनक संधि हो सकी, उन पर यहाँ एक सरसरी निगाह डालना उचित होगा।

मई १९१९ में जब कि शांति सम्मेलन (Peace Conference) जर्मनी की अधिक महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने के समय बीच-बीच में टर्की के भविष्य पर भी विचार कर रहा था, यूनानी प्रधान मंत्री वेनिजेलास (Venizelas) ने मित्र-राष्ट्रों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि एशिया माइनर स्थित स्मर्ना (Smyrna) पर यूनानी सैनिक टुकड़ियाँ रक्खा कर लें। अपने कट्टर और अत्यन्त घृणित शत्रुओं द्वारा, विरामसंधि के काफी समय बाद, टर्की की भूमि का इस प्रकार प्रतिक्रमण (violation) किये जाने पर टर्की ने बहुत रोष प्रकट किया। इस रोष के फलस्वरूप राष्ट्रीय विद्रोह का एक व्यापक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ जिसका नेतृत्व मुस्तफा कमाल के समय और शक्तिशाली हाथों में आया। लगभग एक वर्ष में ही कमाल के दल के लोग सारे देश में छा गये और मित्र-राष्ट्रों की एक नगर रक्षक सेना (garrison) के बल पर ही कांसटेंटिनोपल में कठपुतली टर्की सरकार कायम रह सकी। खतरे को इस सूचना के बावजूद भी, मित्र-राष्ट्रों ने अगस्त, १९२० को, सेव्रेस (Sevres) में टर्की सरकार से एक शांति संधि कर ली। यह संधि वर्सेलीज

की सन्धि के ढग की ही थी और उसमें अन्य बातों के साथ ही साथ (inter alia) यह व्यवस्था भी की गई थी कि स्मर्ना पाँच वर्षों तक यूनान के कब्जे में रहें तथा उसके बाद जनमत द्वारा उसके भाग्य का निबटारा किया जाय।

जो भी हो, सेव्रेस की संधि (Treaty of Sevres) को ममल में लाने की धुँधली सी आशा को भी यूनान की घटनाओं ने मिटा दिया। अक्टूबर, १९२० में यूनानी शासक अलेक्जेंडर की मृत्यु एक पासतु बन्दर के काटने से हो गई। इस घटना के बाद जो आम चुनाव हुए, उनमें बेनिजेलास के हाथ से सत्ता निकल गई और भूतपूर्व शासक कॉन्स्टेंटिन (Constantine) को, जिसे युद्ध के समय जर्मन-पक्षी (pro-Germany) भावनाओं के कारण यूनान से निष्कापित कर दिया गया था, गद्दी पर पुन बँठाया गया। इस कदम से यूनान के प्रति मित्र-राष्ट्रों की सहानुभूति हट गई—यह सहानुभूति मुख्यतः बेनिजेलास के आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ही थी। अगले वर्ष, पहिले फ्रांस ने और उसके बाद इटली ने कमाल सरकार से युक्त समझौते कर लिए जो कि इस समय तक अंगोरा (Angora) में अपने पैर जमा चुकी थी। ब्रिटिश में लॉर्ड जॉर्ज की यूनान नीति की कड़ी आलोचना हुई। यद्यपि यूनानी सेना स्मर्ना से एशिया माइनर के अन्तर्प्रदेश (interior) में निश्चय बढ़ चुकी थी, तदपि यह स्पष्ट हो गया था कि अब उसे मित्र-राष्ट्रों की क्रियात्मक सहायता नहीं मिल सकती थी। इन परिस्थितियों में उसका पतन (debacle) अवश्यम्भावी था। यूनानियों को धीरे-धीरे पीछे खदेड़ दिया गया और सितम्बर, १९२२ में कुछ भयंकर मुठभेड़ों के बाद, मुस्तफा कमाल ने एशिया की भूमि से अन्तिम यूनानी सेनाओं को भी मार भगाया। विजय से उत्साहित हो, कमाल के लोगो ने अब कांस्टेंटिनोपल (Constantinople) की ओर ध्यान दिया। फ्रांसीसी और इटालियन सरकारों ने उतावलेपन में अपनी टुकड़ियों को हटा लिया। परिस्थिति नाजुक हो गई और कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होने लगा कि ब्रिटिश और टर्की में पुनः अवश्य ही युद्ध छिड़ जायेगा। किन्तु मुस्तफा कमाल ऐन मोके पर रुक गया। विरामसंधि हो गई और तुलाने में होने वाली शांति कांग्रेस के लिए रास्ता तैयार हो गया, जहाँ कि अगले ग्रीष्म में संधि पर हस्ताक्षर कर दिये गए।

सन् १९१८ की विरामसन्धि के समय ऑस्ट्रो-हंगेरियन राजतन्त्र की भाँति ऑटोमन (Ottoman) साम्राज्य भी विघटन के रास्ते लग चुका था, उसके

विशाल अरब अधिराज्य (dominions) ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के कब्जे में थे। सौभाग्य से, कमालवादी आन्दोलन ने आरम्भ से ही ऑटोमन साम्राज्य के प्राचीन इस्लामी आधार को अस्वीकार कर, राष्ट्रीय आत्म-निर्णय (national self-determination) के आधुनिक धर्म निरपेक्ष (secular) सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। टर्की की नई सरकार ने अरब बहुमत वाले क्षेत्रों सम्बन्धी अपने सभी दावों को खुलेआम त्याग दिया, इस कारण शांति स्थापित करने में कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आई। योरोप में, यूनाइटेड किंगडम को भी टर्की की सीमा एड्रियानोपल (Adrianople) से भी आगे बढ़ा दी गई; स्मर्ना में जनमत सम्बन्धी कोई भी चर्चा आगे नहीं बढ़ाई गई। सेब्रिस की संधि की दृष्टि, क्षतिपूर्ति और निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी धाराएं भी ज्यों की त्यों रह गईं। किन्तु कुछ आश्चर्य की ही बात है कि टर्की सरकार ने दो असेमीकृत क्षेत्र—थ्रेस (Thrace) में और जलदमरूमध्य (Straits) क्षेत्र में—अपनी ही भूमि पर स्थापित करना स्वीकार कर लिया। प्रगौरा में, राष्ट्रीय सभा (National Assembly) ने अपनी प्राप्ति से सन्तुष्ट हो, टर्की की गणतन्त्र (Republic) घोषित कर दिया तथा मुस्तफा कमाल को उसका राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद उसने धर्म-निरपेक्षता के अपने कार्यक्रम को जोरो से कार्यान्विष्ट करना प्रारम्भ किया। सन् १९२४ के बसन्त में, उसने इस्लाम धर्म के प्रमुख ऑटोमन खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया जो कि साढ़े चार सौ वर्षों से कांस्टेंटिनोपल में बसा आ रहा था।

प्राचीन ऑटोमन साम्राज्य के अरब प्रान्तों की जो स्थिति हुई उससे सर-सरात्मक वासन प्रणाली का परिचय मिल सकता है।^१ राष्ट्र संध के अनुबन्ध पत्र (covenant) में यह व्यवस्था की गई थी कि पराजित राष्ट्रों द्वारा सौंपे जाने वाले उन क्षेत्रों को, “जिनके निवासी आधुनिक सत्तार की कठिन परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ हो”, “समृद्ध राष्ट्रों” (advanced nations) के संरक्षण में रखा जाए। किन्तु समृद्ध राष्ट्र “यह संरक्षण राष्ट्रसंध की ओर से नियुक्त संरक्षक राष्ट्रों (mandatories) के रूप

१ “The fate of the Arab provinces of the old Ottoman Empire may serve as an introduction to the mandatory system.”

ही करें।” किन्तु यह कह सकना निश्चय ही सदेहास्पद था कि संरक्षक राष्ट्र किस सीमा तक राष्ट्रसंघ की ओर से काम करने वाले कहे जा सकते थे। प्रस्ताव-स्पद क्षेत्रों को जर्मनी और टर्की ने प्रमुख मित्र और साथी राष्ट्रों को सौंपा था तथा मित्र और साथी राष्ट्रों ने ही संरक्षक राष्ट्रों का भी चुनाव किया था। राष्ट्रसंघ ने संरक्षण की शर्तों पर अपनी स्वीकृति दी थी। संरक्षक राष्ट्र अपने संरक्षण-क्षेत्र सम्बन्धी प्रतिवेदन (report) प्रति वर्ष राष्ट्रसंघ को भेजते भी थे किन्तु राष्ट्रसंघ उनको केवल मित्रतापूर्ण आलोचना ही कर सकता था। चूंकि उसने संरक्षण अधिकार नहीं दिये थे, इसलिए वह उन्हें वापस भी नहीं ले सकता था। इसके साथ ही यह भी एक कानूनी पेंच (legal conundrum) की बात थी—जिसका हल नहीं निकाला जा सका था—कि संरक्षित क्षेत्रों की सम्प्रभुता (Sovereignty) किसमें निहित है।

अनुबन्ध-पत्र में तीन प्रकार के संरक्षित राज्यो (जिन्हें साधारणतः ‘क’ (A) ‘ख’ (B) और ‘ग’ (C) संरक्षित राज्य कहा जाता है) की व्यवस्था की गई थी। यह वर्गीकरण सम्बन्धित जनसंख्या के विकास की अवस्था (stage of development) के अनुसार किया गया था।

‘क’ संरक्षित-राज्य में जिसके कि अधीन टर्की के भूतपूर्व प्रांत किये गए थे, संरक्षक राष्ट्र का कर्तव्य इस प्रकार निश्चित किया गया था, “जब तक कि ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएं तब तक उन्हें प्रशासकीय सलाह और सहायता देना (administrative advice and assistance)”..... इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि, “संरक्षक राष्ट्र का चुनाव करते समय इनके लोगों की इच्छाओं का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए।” यह कहना कठिन है कि अंतिम शर्त का पूरी तरह पालन किया गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध के समय ही एक गुप्त समझौता हो जाने के कारण, अरब क्षेत्रों के भाग्य का निर्णय पहले ही हो चुका था। युद्ध के बाद इस समझौते को लागू करने के लिए काफी सोचावानी हुई किन्तु जनता की भावना का सम्मान करने का किसी ने नाम तक भी नहीं लिया। सीरिया का संरक्षण फ्रांस के जिम्मे किया गया, तथा ईराक, फिलिस्तीन और ट्रांसजोर्डन का ब्रिटेन के। फिलिस्तीन का संरक्षण अंग्रेज सरकार द्वारा सन् १९१७ में दिये गए इस वचन पर आधारित था कि वह फिलिस्तीन को “यहूदी लोगों की

मातृभूमि" (a national home for the Jewish people) बना देनी। ऑटोमन साम्राज्य के शेष अरब प्रांतों को स्वतंत्रता मिल गई। लाल सागर के किनारे के अरब देश का समुद्रतटीय भाग—जिसे सभी मुसलमान महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हैं क्योंकि उसमें मक्का और मदीना नामक धार्मिक स्थान हैं—हदजाज (Hedjaz) नामक स्वतंत्र राजतंत्र के रूप में गठित हो गया। शेष अरब देश में, टर्की की सम्प्रभुता हटाना ही नाममात्र की थी; और जहाँ तक इन प्रदेशों की स्थिर (settled) जनसंख्याओं का प्रश्न है, कई सुलतान, शेख और इमाम उन पर स्वतंत्र रूप से राज्य करते थे।

‘ख’ सरक्षित-राज्यों, जो कि अफ्रीका में जर्मनी की पछिछान वस्तियों में स्थापित किये गए थे, की जनता को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक स्वायत्ता (autonomy) के अयोग्य माना गया। किंतु सरक्षक राष्ट्र का केवल यही कर्तव्य नहीं था कि वह दासों तथा शस्त्रों के व्यापार को रोकें। “पुलिस प्रयोजनों या अपने क्षेत्र की रक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए” (यह दोहरे अर्थ वाली भाषा हो है) देशों लोगों की भरती न करे अथवा राष्ट्र-संघ के अन्य सदस्यों का व्यापार और वाणिज्य के समान अधिकार देना भी उसके लिए आवश्यक था। पूर्वी अफ्रीका में, भूतपूर्व जर्मन उपनिवेश टेंगनिका (Tanganyika) पूरा का पूरा इंग्लैंड के संरक्षण में दे दिया गया। किंतु बेल्जियम बांगो (Congo) से लगे हुए इस उपनिवेश के दो पश्चिमी प्रांत बेल्जियम के संरक्षण में रखे गये। इसी प्रकार दक्षिण में कियोंगा (Kionga) नामक बदरगाह सीधा ही पुर्तगाल को सौंप दिया गया। पश्चिमी अफ्रीका में कैमेरून (Cameroons) और टोगोलैंड (Togoland) दोनों ही इंग्लैंड और फ्रांस के संरक्षण में बाँट दिए गए।

‘ग’ वर्ग का सरक्षित-राज्य, जर्मन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका और जर्मन प्रशान्त द्वीपों (German Pacific Islands) के लिए गठित किया गया था और इन्हे कमरा दक्षिण अफ्रीका संघराज्य (Union of South Africa) तथा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान के संरक्षण में रखा गया था। ‘ग’ वर्ग के सरक्षित-राज्यों का “प्रशासन संरक्षण-राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार चलता था।” ‘ख’ और ‘ग’ वर्ग के सरक्षित राष्ट्रों में आवश्यक व्यावहारिक अन्तर यह था कि ‘ग’ वर्ग के सरक्षित राज्यों को अपने क्षेत्र में अन्य राज्यों को व्यापार और वाणिज्य के समान अधिकार देना आवश्यक नहीं था।

अमेरिका और सुदूर पूर्व (America & The Far East)

युद्ध के बाद किये गए समझौते के प्रति अमरीकी जनता का रुख कभी उग्र भावदर्शवाद की ओर रहा तो कभी अत्यन्त सतर्कता (extreme caution) बरतने की ओर। तत्कालीन विदेशी मामलों के प्रति उसका यह रुख एक विशेषता लिए हुए ही था। पहिले तो अपने राष्ट्रपति के जरिए उसने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र-संघ के अनुबन्ध पत्र (Covenant of the League) को भी वसॅलीज की सधि में सम्मिलित किया जाए किन्तु बाद में, अपनी ही महासभा (Congress) के जरिए उसने इस सधि को इसलिए अस्वीकृत कर दिया कि अमेरिका अनुबन्ध के कर्तव्यों को निभा सकने में असमर्थ है। अमरीकी सहयोग को इस प्रकार खींच लेने के अन्ततोगत्या परिणाम अपरिमित और दूरगामी हुए। किन्तु योरोपीय समझौते पर उसका तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिका ने जर्मनी, आस्ट्रिया और हंगरी (वलगेरिया या टर्की से अमेरिका का युद्ध नहीं हुआ था) से पृथक् किन्तु मुख्यतः औपचारिक सधियाँ की। इस प्रकार अमेरिका पर योरोप सम्बन्धी अनिश्चित कर्तव्यों का भार डाले बिना ही शांति पुनः स्थापित हो गई।

सुदूर पूर्व में, अमेरिका गम्भीर उदासीनता की अपनी नीति पर स्थिर नहीं रह सकता था। जिस जापान ने नाम मात्र से कुछ ही अधिक सैनिक गतिविधि की थी, वही जापान युद्ध समाप्त होने के बाद, प्रशांत महासागर क्षेत्र के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में इस समय सामने आया। वसॅलीज की सधि के अनुसार जर्मनी से उसे चीन के शान्तु ग प्रान्त में स्थित कियोचाओ (Kiaochow) नामक “पट्टाकामित क्षेत्र” (leased territory) मिला—यह क्षेत्र हाथ से चले जाने के कारण ही चीन ने सधि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। इसके साथ ही साथ जापान को उत्तरी प्रशांत महासागर स्थित जर्मनी के भूतपूर्व द्वीपों का संरक्षण भी दिया गया था। रूस को यदि छोड़ दिया जाए तो, चीन की सीमा पर केवल जापान ही इस समय एक बड़ा राष्ट्र (Great Power) था। रूसों और जर्मनी बेडों के एक साथ ही नष्ट हो जाने के कारण, जापान न केवल सुदूर पूर्व में ही सबसे अधिक शक्तिशाली समुद्री बेड़े वाला राष्ट्र रह गया था अपितु संसार में भी वह तीसरे नम्बर की समुद्री

शक्ति हो गया था। जापान से चीन को खतरे की भावना और प्रशान महासागर में अपना सामुद्रिक प्रभुत्व (naval supremacy) स्थापित करने के जापान के प्रयत्नों से अमरीकी पर्यवेक्षकों (observers) को बहुत चिन्ता हुई। आखिर, सन् १९२१ के अन्त में, अमरीकी सरकार ने अन्य बड़े राष्ट्रों (ब्रिटिश साम्राज्य, जापान, फ्रान्स और इटली) और प्रशान में क्षेत्रिक हित (territorial interest) रखने वाले अन्य तीन राष्ट्रों (चीन, नीदरलैंड और पुर्नगाल) तथा बेल्जियम (सम्मेलन में बुनाए जाने का बेल्जियम का दावा केवल नावुकनायों या) को "शस्त्रीकरण (Armament) नॉमिन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए होने वाले एक सम्मेलन में नाग लेने के लिए, जिसमें शस्त्रीकरण के साथ ही साथ प्रशान महासागर और गुडर पूर्व के प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा" आमन्त्रित किया। यह सम्मेलन नवम्बर, १९२१ में वॉशिंगटन में हुआ।

वॉशिंगटन सम्मेलन के परिणामस्वरूप तीन संधियाँ हुईं। उनमें से प्रथम चार राष्ट्रों की संधि (Four Power Treaty) कहलाती है जो कि अमेरिका, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रान्स तथा जापान के बीच की गई थी। उसका प्रनुसार इन राष्ट्रों ने यह सम्मोक्षा किया था कि वे प्रशान महासागर स्थित अधीन-प्रदेशों (possessions) सम्बन्धी एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेंगे और यदि इन अधिकारों के सम्बन्ध में उनमें कोई विवाद उठ खड़ा हुआ या अन्य किसी राष्ट्र की आक्रमणकारी कार्रवाई (aggressive action) के कारण यदि उन्हें किसी प्रकार का खतरा हुआ तो वे आपस में परामर्श करेंगे। इस साधारण से दस्तावेज (document) का महत्त्व दो बातों में था। उसके कारण अमेरिका पहली बार (राष्ट्र संधि के अनुबन्ध-पत्र को अस्वीकार कर देने के बाद) सामान्य हित के मामलों पर अन्य बड़े राष्ट्रों से एक नामा तक परामर्श करने के लिए तैयार हो गया। इसके साथ ही इस संधि के कारण इस समय अनावश्यक उस एग्रेसी जापानी गुम्बन्दी को भी समाप्त करने का एक अच्छा बहाना मिल गया जो कि अमेरिका, अधिराज्यों (dominions) और ग्रेट ब्रिटेन के अधिकांश लोगों में बहुत अप्रिय हो चुकी थी। द्वितीय या पांच राष्ट्रों की संधि (Five Power Treaty) में विस्तृत नौसैनिक निशस्त्री-

करण (naval disarmament) की व्यवस्था की गई थी। उसकी प्रमुख विशेषताएं थी—ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिका के बीच नौसैनिक समानता (parity) स्थापित करना तथा जापान के बड़े जहाजों की संख्या ब्रिटेन और अमेरिका की संख्या के ६० प्रतिशत के बराबर निश्चित करना। फ्रांस और इटली के लिए यह संख्या ३५ प्रतिशत ही थी। हलके गश्ती जहाजों (cruisers), विध्वंसकों (destroyers), पनडुब्बियों (sub-marines) या अन्य सहायक यानों (auxiliary craft) की संख्या पर कोई बन्धन नहीं लगाया गया था। संधि पर हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्र इस बात पर भी सहमत हो गए कि प्रशांत महासागर के एक निर्धारित क्षेत्र में वे किलेबन्दियों और समुद्री अड्डों (naval bases) सम्बन्धी पूर्ब स्थिति (status quo) बनाये रखेंगे। तृतीय या नौ राष्ट्रों की संधि (Nine Power Treaty) के अनुसार सम्मेलन में शामिल हुए सभी राष्ट्रों ने यह वचन दिया कि वे चीन की स्वतंत्रता और अखण्डता (independence and integrity) का सम्मान करेंगे तथा, “चीन की वर्तमान स्थिति से लाभ उठाकर उससे ऐसे कोई भी विशेष अधिकार या सुविधाएं प्राप्त नहीं करेंगे जिनसे अन्य मित्र-राज्यों की प्रजा और नागरिकों (subjects and citizens) के अधिकार में किसी प्रकार की कमी हो।” इन संधियों के प्रतिरिक्त, एक और दस्तावेज पर वाशिंगटन में हस्ताक्षर हुए थे। यद्यपि उसे सम्मेलन की कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया था, तथापि यह निश्चित है कि ब्रिटिश और अमरीकी प्रतिनिधिमण्डलों के विशेष आग्रह के बिना यह समझौता नहीं हो सका था। इस समझौते के अनुसार, जो कि केवल जापान और चीन के बीच ही किया गया था, जापान ने चीन को कियोचाओ क्षेत्र लौटा देने का वचन दिया जो कि वॉर्सेलोज की संधि के समय जर्मनी ने उसे सौंपा था।

वाशिंगटन सम्मेलन को सकारण ही एक महत्त्वपूर्ण सफलता माना गया था।^१ उसके फलस्वरूप कम से कम ऊपरी तौर पर प्रशांत महासागर में युद्ध-पूर्व का शक्ति-संतुलन पुनः स्थापित हो गया। हृद एंग्लो-अमरीकी मोर्चों से भयभीत होकर और विश्व लोकमत के नैतिक दबाव के कारण, जापान ने

1. "The Washington Conference was hailed, not without reason, as an outstanding success."

यद्यपि प्रकट रूप से अपनी पराजय स्वीकार नहीं की थी, तथापि अपनी महत्वा-
साक्षात् पर बहुत अधिक अकुश लगाना उसने स्वीकार कर लिया था। चीन
की मुख्य भूमि (mainland) पर युद्ध के समय उसे जो एकमात्र प्राप्ति हुई थी,
उसका भी परित्याग कर देने के लिए उसे राजी कर लिया गया था। अब उसने
ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिका के साथ नौसैनिक समानता का दावा करने का
साहस किया किंतु ब्रिटिश और अमरीकी बेड़े का ७० प्रतिशत टन वेडा रखने
की उसकी मांग कम कर ६० प्रतिशत कर दी गई। इस प्रकार चीन की
प्रसन्नता और प्रभाव महासागर में एग्लो अमरीकी सामुद्रिक प्रभुत्व की जापानी
सनरा दूर किया जा चुका था। किंतु फिर भी वाशिंगटन संधियों से उत्पन्न
स्थिति खनरे से खाली नहीं थी क्योंकि एशिया की मुख्य भूमि पर भागे बचने
की अपनी नीति को जापान ने अनिच्छापूर्वक ही त्यागा था। कभी न कभी,
अपनी शक्ति से परिचित होते-होते, जापान वाशिंगटन सम्झौते से हुई अपनी
प्रतिष्ठा हानि का विरोध करता ही। यह मूल प्रश्न कि सुदूर-पूर्व में एग्लो-
संयुक्त प्रभुत्व रहेगा या जापान की ही तूती बजेगी अभी भी अनिर्णीत (un-
'decided) था। किंतु यह वाशिंगटन सम्मेलन का ही परिणाम था कि यह
प्रश्न ठीक दस वर्षों तक भविष्य के घम में ही पड़ा रहा।



प्रथम भाग

प्रवर्तन-काल (The Period of Enforcement) :

गुटघंदियाँ (The Alliances)

[१६२०—१६२४]

१. फ्रांस और उसके साथी

(France and Her Allies)

सन् १९१६ के बाद के योरोपीय घटनाचक्र का सबसे महत्वपूर्ण एवं स्थायी तथ्य फ्रांस की सुरक्षा-मांग (demand for security) था।^१ सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में फ्रांस यह ठीक ही समझता था कि वह योरोप का सबसे शक्तिशाली सैनिक राष्ट्र है, यह परम्परा नेपोलियन-युद्धों के बाद तक चलती आई थी जबकि योरोप के अन्य राष्ट्रों ने आपस में गठबंधन कर उसे हरा दिया था। सन् १८७० में, फ्रांस व प्रशा (Prussia) के मध्य हुए युद्ध के समय उसकी शक्ति का भ्रम एकाएक दूर हो गया। उस समय मध्य योरोप में एक ऐसे नए राष्ट्र का उदय हो चुका था जिसके लोगो व राष्ट्रीय भावना फ्रांसीसियों के समान ही दृढ़ और ऐक्यपूर्ण थी तथा जिसके प्राकृतिक साधन फ्रांस के साधनों की तुलना में बहुत अधिक थे। अपनी खनिज संपत्ति के कारण जर्मनी को औद्योगिक विकास का अवसर तो मिला ही, किन्तु उसके साथ ही साथ उसमें युद्ध-सामग्री के उत्पादन की वह क्षमता भी आ गई जिसकी समता करने की फ्रांस आशा भी नहीं कर सकता था। फ्रांस की जन संख्या चार करोड़ से भी कम के आँकड़े पर लगभग स्थिर होगई थी। जर्मनी की आबादी हर दशक (decade) में ५० लाख के हिसाब से बढ़ रही थी और १९०५ तक वह छ करोड़ से भी अधिक हो चुकी थी। इसके अनिर्विक्त जर्मन लोगो में सैन्य-संगठन की अपूर्व क्षमता भी थी। फ्रांस की अपेक्षा जर्मनी का सैन्य संगठन न केवल अधिक सुसज्जित और अच्छे सैनिकों से परिपूर्ण था अपितु उसका संचालन भी अधिक अच्छे ढंग से होता था। सन् १९१४ में यदि ब्रिटेन तुरन्त ही हस्तक्षेप नहीं करता तो फ्रांस छ मप्ताहों में ही पुनः पराजित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाता— फ्रांसोसो इस बात को भली-भाँति जानते थे। सन् १९१८ की विजय की प्रसन्नता अल्पकालिक ही सिद्ध हुई ;

१. "The most important and persistent single factor in European affairs in the years following 1919 was the French demand for security"

विजयोल्लास के साथ ही साथ गम्भीर चिन्ता भी शीघ्र ही परिलक्षित होने लगी। सन् १८७० में—सन् १९१४ से तो और भी अधिक—ही फ्रांस को जर्मनी की तुलना में अपनी कमजोरी का भीतिपूर्ण आभास था। इस समय तो उसने १८७१ के विजेता का पासा पलट दिया था। किन्तु जर्मनी १९१८ के विजेता का तख्ता किसी दिन न उलट सके इसके लिए कौन सी युक्ति काम मलाई जा सकती थी ?

इस प्रश्न पर फ्रांस का प्रथम उत्तर स्पष्ट और आग्रहपूर्ण था। उसकी यह माँग थी कि उसे “भौगोलिक गारन्टी” (physical guarantee) दी जावे—राइन नदी और उसके पुल, जिन्हे पार करना पूर्व से फ्रांस पर आक्रमण करने के हेतु आक्रामक (invader) के लिए आवश्यक था, स्थायी रूप में उसके अधिकार में रहे। फरवरी, १९१६ में हुए शांति-सम्मेलन में फ्रांस द्वारा प्रस्तुत एक स्मरणपत्र (memorandum) में कहा गया था, “राइन का बायाँ किनारा और उसके पुल यदि जर्मनी के अधिकार में रहे तो खतरा है”। पश्चिमी और समुद्र पार के प्रजातन्त्रों (overseas democracies) की अपनी सुरक्षा के लिए, वर्तमान परिस्थितियों में यह नितान्त आवश्यक है कि वे स्वयं राइन नदी के पुलों की रक्षा करें।” किन्तु फ्रांस को बिल्कुल निराश होना पड़ा। मित्र राष्ट्रों ने राइन सीमान्त को फ्रांस की सुरक्षा में देना इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इस प्रकार की व्यवस्था करने से राइन के बाएँ किनारे पर रहने वाले ५० लाख से भी अधिक जर्मन निवासियों को जर्मनी से पृथक् करना पड़ता। काफी सिर पटक लेने के बाद फ्रांस को अपनी माँग छोड़ देनी पड़ी और उसकी इस माँग के बदले में :

(१) वर्सेलोज की संधि में इस आशय की धाराएँ जोड़ी गईं कि राइन का बायाँ किनारा पन्द्रह वर्षों तक मित्र राष्ट्रों की सेना के अधिकार में रहेगा और उसका स्थायी रूप से असेनीकरण (demilitarisation) कर दिया जायेगा (अर्थात् राइन के पश्चिम में किले बनाना या सेना रखना निषिद्ध कर दिया गया), तथा ।

(२) वर्सेलोज की संधि के साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिका ने फ्रांस से संधियाँ की जिनके अनुसार फ्रांस को यह वचन दिया गया कि, “यदि

जर्मनी ने अकारण ही फ्रांस पर आक्रमण करने सम्बन्धी कोई गतिविधि की" तो वे तुरन्त ही फ्रांस की सहायता करेंगे ।

किन्तु वसैलोज में हुई संधियों का अमेरिका ने अनुसमर्थन (ratification) ही नहीं किया । फनस्वरूप ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा दिए गये वनन शून्य (void) हो गए । फ्रांस को ऐसा अनुभव हुआ कि उसे धाखा दिया गया है । उसने अपना दावा एक ऐसे यथन के विश्वास पर छोड़ दिया था जो कि निभाया ही नहीं गया । सुरक्षा के प्रश्न को लेकर फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में इसके बाद जो बार्नार्ड बर्ली, उनमें फ्रांस की यह सिनायत बराबर बनी रही ।

इस प्रकार "भौगोलिक" गारन्टी की आशा छोड़ देने के लिए बाध्य कर दिए जाने के बाद फ्रांस अगले चार वर्षों तक जर्मनी की तुलना में अपनी प्राकृतिक हीनता (natural inferiority) दूर करने और जर्मन प्रतिशोध (vengeance) के भय को दूर करने की उपेक्षित में ही लगा रहा । उसने दो पृथक् किन्तु समानान्तर (parallel) मार्ग अपनाए : उनमें से एक था गारन्टी संधियों (treaty guarantees) का माग और दूसरा था गुटबन्धियों (alliances) का ।^१

गारन्टी-मार्ग (The System of Guarantees)

सन् १६२० के प्रारम्भ में, जब यह बात स्पष्ट हो गई कि अकारण आक्रमण (unprovoked aggression) के विरुद्ध ग्रेट-ब्रिटेन और अमेरिका ने फ्रांस को जो गारन्टी दी ह, वह कभी भी पूरी नहीं की जायगी, तब राष्ट्रसंघ के अनुबन्धपत्र में निहित संरक्षण के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का संरक्षण फ्रांस का जर्मनी के विरुद्ध प्राप्त नहीं था । इसलिये फ्रांस ने प्रारम्भ में ही यह निश्चय कर लिया कि यह संरक्षण अपर्याप्त है । यह अवश्य ही सत्य था कि अनुबन्धपत्र के दसवें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रसंघ के सदस्य इस बात के

- 1 "Having thus been compelled to abandon her hope of a "physical" guarantee, France worked feverishly during the next four years to find compensation for her natural inferiority to Germany, and to allay her fear of German vengeance. She followed two separate and parallel methods: a system of treaty guarantees and a system of alliances "

लिए वचनबद्ध थे कि वे “राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य-राष्ट्रों की वर्तमान राज-
नैतिक और क्षेत्रीय अखण्डता (territorial integrity) की बाह्य आक्रमण
से रक्षा करेंगे तथा उन्हें उनके वर्तमान रूप में मानेंगे।” साथ ही अनुच्छेद १६
और १७ में यह व्यवस्था भी की गई थी कि अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते
हुए, यदि कोई राज्य युद्ध का आग्रह लेगा तो उसके विरुद्ध अनुशास्ति (sanctions)
और दंड (penalties) की कार्रवाई की जायगी। किन्तु दमक
अनुच्छेद को ब्रिटेन (जिसका बहुत अधिक बोलबाला था) ने अनिच्छापूर्वक
ही स्वीकार किया था, और फ्रांस के इस प्रस्ताव को कि एक अन्तर्गष्ट्रीय सेना
संगठित की जाए ताकि उसके बल पर अनुशास्ति को प्रभावकारी ढंग से लगाया
जा सके, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका ने कड़ा विरोध कर अस्वीकृत करा दिया।
अनुच्छेद १६ के अनुसार राष्ट्रसंघ के सदस्यों के लिए यह आवश्यक था कि
किसी भी आक्रमणकर्ता से वे अपने वित्तीय और आर्थिक (financial and
economic) सम्बन्ध तोड़ लें। किन्तु सैनिक कार्रवाई (और दूसरी किसी
कार्रवाई से जर्मनी को रोका भी नहीं जा सकता था) के लिए परिपक्व की
सिफारिश (recommendation of the Council) आवश्यक थी।
इस सिफारिश के लिए निर्धारित मत प्राप्त होना जरूरी था। यदि परिपक्व ऐसी
सिफारिश कर भी देती, तो भी कोई भी राज्य अपनी इच्छानुसार उसे स्वीकार
या अस्वीकार कर सकता था। इसके साथ ही अमेरिका की कर्तव्यविमुखता
(defection) के कारण यह बात अत्यधिक सदेहास्पद हो गई कि वित्तीय और
आर्थिक नाकेबंदी (blockade) संभव भी हो सकती या नहीं, और यदि वह
संभव हुई भी, तो उसका कुछ प्रभाव भी हो सकेगा अथवा नहीं।

राष्ट्रसंघ जिस समय वास्तव में अस्तित्व में आया, उस समय ही फासीसियों
का यह सशय बढ गया था कि अनुबचपत्र प्रभावकारी नहीं होगा। दिसम्बर
१९२० में, जेनेवा में जब राष्ट्रसंघ सभा (Assembly) की प्रथम बैठक हुई,
तब अनुच्छेद १० और १६ की ही सबसे पहिले आलोचना हुई। कनाडा
अनुच्छेद १० को बिलकुल की निकलवा देना चाहता था। इसी प्रकार
स्वैडेनेविया के प्रतिनिधिमंडल की यह इच्छा थी कि अनुच्छेद १६ के अधीन
आर्थिक अनुशास्तिमें अपने आप ही लागू होने सबधी उपबन्ध में कुछ अपवाद
भी रखे जाएं। इन दोनों ही प्रस्तावों के कारण लम्बा विचार विनिमय हुआ।

अगले वर्ष (१९२१ में) राष्ट्रसंघ सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें और बातों के साथ ही साथ (inter alia) यह व्यवस्था की गई थी कि भावश्यकता पड़ने पर परिषद् “यह सिफारिश करेगी कि अनुच्छेद १६ के अधीन अधिक अनुशास्त्रियाँ कितनी तारीख से लागू की जाएँ ।” इसका भाव्य यह था कि परिषद् को वार्षिक अनुशास्त्रियों का लागू करना, स्वगित करने, और उनकी तारीख में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दे दी गई । मई १९२३ में इस भाव्य का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद १० के अधीन वक्तव्यों का पालन कराने के लिए कौन से कदम उठाना आवश्यक है इस बात का निश्चय “हर सदस्य (राष्ट्र) के वैधानिक अधिकारियों (constitutional authorities) द्वारा ही किया जाना चाहिए ।” इस प्रस्ताव का मान्य भी यही था कि सैनिक सहायता सम्बन्धी सारे मामले का निबटारा सर्वोच्च सरकारों के विवेक (discretion) के अनुसार ही हो, किन्तु एक छोटे से राज्य के विपरीत मन (adverse vote) के कारण यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका । यद्यपि अनुच्छेद १० और १६ में विधिवत् (formally) कोई संशोधन नहीं किया गए, तथापि इन चर्चाओं से यह स्पष्ट हो चुका था कि सकट काल में इन अनुच्छेदों का वास्तविक प्रवर्तन अनुवचन की वास्तविक मर्यादा काफी पीछे हो रहेगा । अब यह भी स्पष्ट हो चुका था कि लोग सगठन वह तत्काल सैनिक कार्यवाही (prompt military action) भी सम्भव नहीं कर सकेगा जिसका आश्रय लेने से ही फ्रांस को आक्रमण से बचाया जा सकता था ।

ऐसी स्थिति में, यदि फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन से यह आग्रह करता रहे कि जर्मन आक्रमण से उसकी रक्षा के लिए ब्रिटेन अतिरिक्त गारंटी दे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं । जो भी हो, इन प्रयत्नों के परिणाम परस्पर विरोधी (paradoxical) हुए । जनवरी १९२२ में, ब्रिटिश सरकार ने आखिर हिम्मत की और १९१६ की निष्फल संधि (abortive treaty) की बातों के ही लगभग समान शर्तों पर फ्रांस को गारंटी देने के लिए वह तैयार हो गई । किन्तु तत्कालीन फ्रांसीसी प्रधान मंत्री पोंकारे (Poincaré) हठी और मझूरदर्शी था । वह सम्पूर्ण या शून्य (All or nothing) की नीति में विश्वास रखता था । उसने यह माँग रखी कि इस गारंटी के साथ ही साथ एक सैनिक सम्मेलन (military convention) भी किया जाए जिसमें यह बात सुस्पष्ट कर दी

जाए कि ब्रिटिश सेना किस प्रकार की सहायता देगी । उसने यह भी कहा कि यदि इस प्रकार का समझौता नहीं किया गया तो केवल गारटी संधि का फ्रांस को कोई उपयोग नहीं होगा । ब्रिटिश सरकार इस सीमा तक आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी । उसने अपना बड़प्पन निभा लिया था, इसलिए अब उसने फ्रांसीसियों की सुरक्षा-तृष्णा शांत करने का स्पष्ट रूप में आशा शून्य (hopeless) कार्य कुछ समय के लिए एक ओर रख दिया ।

गुटबन्दी-मार्ग (The System of Alliances)

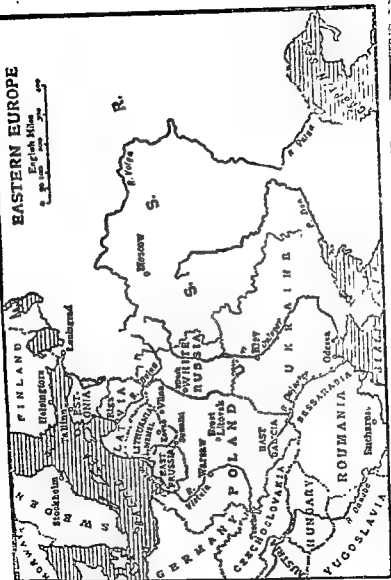
पौकारे के इस मनमानापूर्ण रखवा कारण कुछ अंश में यह भी था कि फ्रांस की सुरक्षा-निर्माण के अपने दूसरे प्रयत्न—गुटबन्दीयों का मार्ग अपनाने—में इसी बीच सफलता मिल चुकी थी । आक्रमण से सुरक्षा की कोरी गारंटियों पर भरोसा करने की अपेक्षा सैनिक गुटबन्दीयों की नीति अपनाना फ्रांसीसी प्रकृति और परम्परा के अनुकूल था । इसी नीति के कारण अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस की धाक सारे योरोप में गम गई थी जब कि फ्रांस ने आस्ट्रिया के छोटे छोटे पड़ोसियों से गुटबन्दी कर उन चारों ओर से घेर लिया था । इस समय भी वह इसी नीति का अनुसरण कर जर्मनी को घेर लाना चाहता था । पश्चिम में, बेल्जियम के साथ सितम्बर १६२० में सैनिक गुटबन्दी कर लन से उसकी स्थिति सुरक्षित हो चुका थी । अन्य दिशाओं में उसे यह कार्य नए सिरे से करना था । रूस अब एक सैनिक राष्ट्र नहीं रह गया था । किन्तु उसके स्थान में जर्मनी के पूर्वी सीमा पर पोलैंड के नए गणतन्त्र का उदय हो चुका था । दक्षिण में, मित्र राष्ट्रों की विजय के परिणामस्वरूप तीन नए या अत्यधिक बर्धित (enlarged) राज्य—चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रूमानिया—अस्तित्व में आ चुके थे । वे राज्य फ्रांस के स्वाभाविक मित्र और आसामी (clients) थे । युद्ध के बाद के तीन वर्षों में फ्रांस ने इन्हें लेकर ही एक प्रभावकारी और सुगठित गुटबन्दी की ।

पोलैंड

युद्ध-समाप्ति के बाद गठित पोलिश गणतन्त्र कोई नया राज्य नहीं था, अपितु प्राचीन राज्य ही पुनः अस्तित्व में आ गया था । दसवीं सदी से लगाकर अठारहवीं शताब्दी तक, पोलैंड विशाल और शक्तिशाली राजतन्त्र था । अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में, उसे रूस, प्रशा और आस्ट्रिया की संयुक्त शत्रुता का सामना करना पड़ा, और तीन विभाजनों (partitions) के बाद, जिनमें

EASTERN EUROPE

English Miles
0 50 100 150 200 250 300 350 400



कि उसके क्षेत्र का अधिकाधिक भाग उसके हाथ से निकलता गया, सन् १७६१ में उसकी स्वतन्त्रता भी जाती रही। सन् १६१८ में रूसी, जर्मनी और ऑस्ट्रियन साम्राज्यों पर एक साथ आपत्ति के बादलों का घिर जाना पोलैंड के लिए सीमाशय की एक ऐसी घड़ी थी जिसने कि उसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित बना दिया। किन्तु प्रारम्भ के कुछ वर्षों तक उसका लिए बड़ी कठिनाई के रहे। जर्मन और ऑस्ट्रियन पोल (Pole) जनता जिसे संयुक्त कर अब एक राज्य का निर्माण किया गया था, सवा सौ वर्षों तक विभिन्न कानूनों और विभिन्न प्रशासनो (administrations) के आधीन रह चुकी थी, उसने विभिन्न सेनाओं में काम किया था और एक दूसरे के विरोधी पक्ष का ओर से युद्ध लड़े थे, उसकी विभिन्न परम्पराएँ एवं विभिन्न निष्ठाएँ बन चुकी थी। दृष्टिकोण की इन विभिन्नताओं को मिटाने के लिए सामान्य देश प्रेम की स्वल्प भावना से ही काम नहीं चल सकता था। इसके अतिरिक्त, विस्तृत योरोपीय मैदान के बीच में स्थित होने के कारण, दक्षिण की छोड़ और किसी भी दिशा में, पोलैंड की स्पष्ट भौगोलिक सीमाएँ नहीं थी। केवल दक्षिण में ही, कारपेथियन पर्वत (Carpathian Mountains) उसे स्लोवाकिया से अलग करना था। जर्मनी के साथ लगे हुए उसके पश्चिमी और उत्तरी सीमाएँ जैसा कि हम पहिले कह रहे हैं, वसैलीज की संधि द्वारा निश्चित किये गए थे। अन्य और सभी दिशाओं में, सीमाओं के प्रश्न को लेकर अपने पड़ोसी देशों से पोलैंड की लीखी झड़प हुआ करती थी।

दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रियन सिलेशिया (Silesia) का छोटा सा जिला, जो एक महत्वपूर्ण कोयला खदान क्षेत्र था और जिसमें चेक (Czech) और पोलिश मिश्रित आबादी थी, पोलैंड और नवगठित चेकोस्लोवाकिया राज्य के बीच झगड़े की जड़ बन गया। सन् १६१६ के प्रारम्भ में ही चेक और पोलिश सेनाओं में इस विवादग्रस्त क्षेत्र के लिए झुठमेड़ हो गई और ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी अधिकारियों की मध्यस्थता (mediation) के कारण ही धमासान युद्ध टल सका। अन्त में, यह निश्चय किया गया कि इस विवाद का निबटारा जनमत द्वारा किया जाए। किन्तु मतदान का समय समीप आते आते, इतनी उत्तेजना फैल गई कि इस योजना को भी त्याग देना पड़ा। परन्तु फ्रांस द्वारा बहुत अधिक दबाव डाले जाने पर, दोनों ही पक्षों ने समझौता कर लिया। इस

समझौते के अनुसार चेकोस्लोवाकिया को रोपेने की खदानें मिली और पोलेट की टेसेन (Teschen) (पोलेट की इस शहर का रेलवे स्टेशन नहीं मिला, वह चेकोस्लावाकिया के अधिकार में ही रहा) नामक प्रमुख नगर। इस समझौते का मूल्य समझौते के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, इसलिए दोनों ही पक्ष मानते रहे कि उन्हें बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी है।^१

ऑस्ट्रियन पोलेट में, एक दूसरी ही समस्या उठ खड़ी हुई। उसे पूर्वी और पश्चिमी गैलेसिया (Galicia) नामक दो प्रांतों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी गैलेसिया में शुद्ध पोलिश भाषाधीन थे। पूर्वी गैलेसिया के जमींदार और अधिकांश बुद्धिवादी (यहूदियों को छोड़कर जिनकी सस्या यहाँ विरोध रूप से अधिक थी) पोल थे। किन्तु वहाँ का किसानवर्ग दक्षिण पश्चिम में रहने वाले उन लोगों का सजातीय था जिन्हें कि लिटिल रूसी (Little Russians), यूक्रेनियन, (Ukrainians) या रुथेनीज (Ruthenes) आदि कहा जाता है। यह समय है कि पूर्वी गैलेसिया का भूमिहीन रुथेनी किसान पोलिश जमींदार की जमींदार होने को अपेक्षा पोल होने के कारण ही अधिक घृणा करता हो। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह घृणा अत्यन्त तीव्र थी। सन् १९१६ के आरम्भिक महीनों में पूर्वी गैलेसिया में सत्ताह्व (ruling) पोल अल्पसंख्यकी और शक्ति बहुसंख्यकी (majority) में एक दुर्दम गृह युद्ध छिड़ गया। पोलिश क्रमुक (reinforcement) योद्धा ही बुलाई गई और अन्त में, रुथेनियों का यह सघर्ष जिसे पोलेट की अत्याचारपूर्ण नीति के विरुद्ध पेरिस मित्र-राष्ट्रों के मामूली विरोध के अतिरिक्त और किसी का भी प्रभावपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं था, मई में समाप्त हो गया। इस सम्पन्न तथ्य (accomplished fact) को बदल सकने में अपने आपको असमर्थ पाकर मित्र राष्ट्रों ने पोलेट के सामने यह प्रस्ताव रखा कि पूर्वी गैलेसिया में पञ्चवीस वर्षों तक सरक्षण-राज्य (mandate) रहे और उसके बाद इस क्षेत्र के भाग्य का निवटारा राष्ट्रसंघ द्वारा किया जाये। पोल जनता ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और पूर्वी गैलेसिया पर अपना अधिकार पूर्ववत् बनाए रखा। आसिर १९२३ में मित्र-राष्ट्रों ने पूर्वी गैलेसिया

१. "It was a compromise which had no virtue except that of being a compromise; and both sides continued to regard themselves as deeply injured parties."

पर पोलैंड की सप्रभुता को यह वचन (जो कभी पूरा नहीं किया गया) दिए जाते पर विधिवत् स्वीकार कर लिया कि पोलैंड पूर्वी गेलेशिया में स्वायत्त शासन (autonomous regime) की स्थापना करेगा ।

पोलैंड के पूर्वी सीमात पर यही समस्या और भी बड़े पैमाने पर सामने आई । अपनी महानता के दिनों में पोल रात्रतत्र केवल पोलिश भाषावादी वाले क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था अपितु वह पूरे लिथुमानिया, श्वेत रूस (White Russia) के अधिकांश भाग और काले सागर (Black Sea) तक पूरे यूज़न में फैला हुआ था । इन क्षेत्रों की अधिकांश भूमि, पोलिश जमींदारों के अधिकार में थी—यह अवस्था १९१७ की रूसी क्रांति के समय तक चलती रही । क्रांति के बाद, इन जमींदारों ने पोलैंड में शरण ली । मगर यह स्वाभाविक ही था कि इन जमींदारों ने पोलैंड की सरकार पर इस बात के लिए बहुत अधिक दबाव डाला कि उनकी भूमि पुनः विजित कर पुनः उनके अधिकार में दी जाए । कुछ उत्साही देशभक्तों ने तो बाल्टिक से काला सागर तक पोलिश साम्राज्य पुनः स्थापित करने के स्वप्न भी देखे । पेरिस मित्र राष्ट्रों का इस भाषण का एक प्रस्ताव कि पोलैंड का पूर्वी सीमात इस प्रकार निश्चित किया जाए कि उनमें केवल वे ही क्षेत्र आएँ जिनमें पोल जनता बहुसंख्यक हो, घोर अपमान समझा गया ।

तो, ऐसी मनोदशा में, पोलिश राज्य का प्रधान (head) और सर्वोच्च सेनापति पिलसुडस्की (Pilsudski) १९२० के बसंत में यूज़न विजय के लिए निकल पड़ा । गृहयुद्ध के कारण अव्यवस्थित सोवियत सेना उसका पूरी तरह सामना न कर सकी, और पोल सेना तेजी से कीव (Kiev) तक पहुँच गई । जो भी हो, जून में सोवियत सेना ने बड़े पैमाने पर प्रतिरोध आक्रमण (counter offensive) किया । उसके परिणामस्वरूप न केवल पोल सेना तितर बितर कर यूज़न के बाहर खदेड़ दी गई अपितु सोवियत टुकड़ियाँ वारसा (Warsaw) से कुछ ही मील की दूरी तक आ पहुँची । यहाँ युद्ध (fortunes of war) ने एक बार फिर सहसा पलट लिया । पोलिश आक्रमणकारियों की भाँति सोवियत आक्रमणकारी भी शिथिल पड़ गए । पोलैंड की सेना एक बार फिर आगे बढ़ी । किन्तु इस बार वह यूज़न को छोड़ पूर्व में श्वेत रूस (White Russia) की ओर कूच कर चली । अन्त में, जब विरामसंधि हुई, तब जो सीमा रेखा निश्चित की गई, वह मित्र राष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित तथाकथित “वर्जन

रेखा" (Curzon line) के पूर्व में लगभग ११० मील की दूरी पर थी। किन्तु सोवियत सरकार इस समय उदारतापूर्वक भूमि देने के लिए तैयार थी क्योंकि उसे शान्ति की आवश्यकता थी। सन् १९२१ में हुई रीगा की संधि (Treaty of Riga) ने उक्त विरामसंवि-रेखा की पुष्टि कर उसे पोलैंड और सोवियत रूस के बीच स्थायी सीमा के रूप में निश्चिन कर दिया। पोलैंड ने यूक्रेन पर अपने दावे का परित्याग कर दिया और उसके बदले में उसे श्वेत रूस का छिन्ना भावादी ब्राला (sparsely populated) किन्तु विस्तृत भू-भाग मिला।

इसके बाद लिथुआनिया (Lithuania) की बारी आई। वहाँ भाड़े की मुख्य एवं मूल जड़ विल्ना (Vilna) नगर और जिला थे। मध्ययुग में विल्ना लिथुआनिया साम्राज्य (जो कि सोलहवीं शताब्दी में एक राजवंशी विवाह के कारण पोलैंड में मिल चुका था) की राजधानी रह चुका था। जब १६१८ में लिथुआनिया के स्वतन्त्र राज्य की पुनः स्थापना की गई, तब लिथुआनिया ने विल्ना को तुरन्त ही अपनी राजधानी घोषित कर दिया। दुर्भाग्य से विल्ना के लोगों में पोलैंड में ही बने रहने के लिए भी उतनी ही अधिक भावुकतापूर्ण भावना थी। वहाँ एक प्रतिष्ठित पोलिश विश्वविद्यालय था और पोलैंड के ज्ञान-विज्ञान का वह एक प्राचीन केन्द्र भी था। मानववंश विज्ञान की दृष्टि (ethnological standpoint) से, न तो लिथुआनिया का और न पोलैंड का ही उस पर दावा समीचीन था। इस नगर की आबादी यहूदों (यहूदियों का वहाँ निवास प्रचुर था), पोलिश और श्वेत रूसी थी, और उसके आसपास के जिला भाग में, श्वेत रूसी तथा लिथुआनी। किन्तु जिस समय अनेक प्रकार की उत्तेजनाएँ फैल रही थी, उस समय सम्बन्धित जनसंख्या की इच्छाओं (यदि वास्तव में उनकी कोई इच्छाएँ रही हों तब) का कोई निर्णायक प्रभाव होने की कोई सम्भावना ही नहीं थी।

जुलाई १९२० में, जिस समय सोवियत सेना, वारसा की ओर बढ़ रही थी, उस समय लिथुआनिया ने सोवियत सरकार के साथ एक सन्धि की थी, जिसके अनुसार सोवियत सरकार ने विल्ना पर लिथुआनिया के दावे को स्वीकार कर लिया था। किन्तु बाद में पोलैंड के आगे बढ़ जाने के कारण लिथुआनिया का सम्बन्ध भरने सोवियत मित्रों से ब्रिक्कुल टूट गया और उसे अकेले ही पोलैंड का सामना करना पड़ा। सुवाल्की (Suwalki) के पास युद्ध शीघ्र ही आरम्भ

हो गया। आशा के विपरीत, उसका परिणाम पोलैंड के हित में अधिक भ्रष्टा नहीं रहा। भ्रष्टाचार में एक विरामसन्धि हो गई जिसके अनुसार विलना नगर और जिला लिथुआनिया के ही अधिकार में रहन दिये गये। तीन दिन के बाद, जेलिगोवस्की (Zeligowski) नामक एक स्वतन्त्र पोलिश सेनापति ने कुछ सैनिक इकट्ठे किये और लिथुआनिया पर एकाएक घावा बोलकर विलना पर अधिकार कर लिया। इस निदास्पद विश्वास भंग (flagrant breach of faith) को पोलैंड सरकार ने सरकारी तौर पर निन्दा की। किन्तु लूट का यह माल उसने बिना किसी हिचक के अपने पास रख लिया। कुछ वर्षों के बाद, पिलसुडस्की ने यह स्वीकार भी किया कि यह राज्यहरण (coup) उसका जानकारी और अनुमोदन (approval) से ही हुआ था। राष्ट्रसंघ द्वारा लम्बी वार्ताएँ चलाए जाने के बाद भी पोल लोग विलना नहीं हटे और १९२३ में, जबकि मेमल (जिस पर वसेलीज की सन्धि के समय से ही मित्र राष्ट्रों का कब्जा था) पर कब्जा करके लिथुआनी न्यायपथ से हट चुके थे, मित्र-राष्ट्रों ने विलना को पोलैंड के ही एक भाग के रूप में विधिवत् मान लिया।

इस प्रकार गठित पोलिश राज्य की तीन करोड़ से भी अधिक जनसंख्या थी—यह संख्या उसे बड़े राष्ट्र की श्रेणी में लगभग सा बिठाती थी। उसके प्राकृतिक साधन प्रचुर थे। उसके दक्षिण पश्चिमी भाग में कोयले और लोहे की तथा पूर्वी गैलेशिया में तेल की प्रचुरता थी। उसके पूर्व में विस्तृत वन थे और लगभग सारे ही देश में अच्छी कृषि योग्य भूमि थी। लेकिन उसकी कुछ स्पष्ट कमजोरियाँ भी थी। उसकी कम से कम २५ प्रतिशत जनसंख्या गैर पोलिश थी जिसमें ४० लाख यहूदी भी शामिल थे, और अधिकांश अल्पसंख्यक या तो वास्तव में या सम्भाव्यतः (potentially) उसके विरोधी थे। इसके अतिरिक्त अपने आरम्भिक दिनों में ही, पोलैंड के सम्बन्ध एक भी पड़ोसी राष्ट्र के साथ अच्छे नहीं थे। जर्मन अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और डान्जिग (Danzig) के प्रश्न को लेकर जर्मनी से हमेशा ही उसका संघर्ष चलना रहता था और इसमें सदेह ही था कि कोई भी जर्मन सरकार पोलिश गलियारे (corridor) के कारण छेड़ जर्मनी से पूर्वी प्रजा का पृथक् हो जाना अनिश्चित काल तक सहन करती रहेगी। सोवियत रूस को भी अपनी उदारता पर किसी दिन पछतावा हो सकता था। चेकोस्लोवाकिया क्षमार्हित रोष में था,

लिथुआनिया यूँ ही गुर्रा रहा था और पूर्वी गैलेसिया में फिर कोई प्राप्त सदी हो सकती थी। वैसे पूर्वी योरोप में पोलैंड सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था किन्तु मुश्किल से वह इस प्रकार की दुनिया का अकेले सामना कर सकता था।

ऐसी परिस्थिति में, जर्मनों के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ गुटबन्दी करने की फ्रांसीसी नीति और पोलैंड की अपनी आवश्यकताओं का पूरा-पूरा मेल बैठ गया। फरवरी १६२१ में हुई गुटबन्दी सम्बन्धी फ्रांसीसी-पोलिश संधि घनिष्ठ राजनैतिक सहयोग का एक साधन थी। उसके साथ ही एक गुप्त सैनिक समझौता भी किया गया था जिसके बाब फ्रांस ने पोलिश सेना को सुसज्जित बनाने के लिए सुगम शर्तों पर काफी युद्ध सामग्री पोलैंड भेजी। सतर्कता की नीति पर चलने वाले कुछ फ्रांसीसियों का यह मत था कि इतना भगड़ानू मित्र लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक करेगा तथा कोई भी फ्रांसीसी सैनिक पोलैंड के लिए अपने प्राण होम देने के लिए तैयार नहीं होगा। कुछ पोलैंडवासियों ने भी अपने फ्रांसीसी मित्रों के सरसकड़ रुझ (patronising attitude) और बारम्बार स्थित फ्रांसीसी सैनिक मिशन की सख्या तथा उस पर होने वाले व्यय की आलोचना की। किन्तु यह गुटबन्दी समान हित के सुदृढ़ आधार पर हुई थी, इस कारण मामूली भ्रमणोप से टूट नहीं सकती थी। अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के हर राजनैतिक प्रश्न पर फ्रांस और पोलैंड ने एक दूसरे का साथ दिया। क्या जेनेवा में, क्या निजी वार्ताओं में, फ्रांसीसी और पोलिश प्रतिनिधिमण्डल एक दूसरे का बराबर साथ देने रहे तथा हर सार्वजनिक चर्चा में उन्होंने साथ-साथ मत दिया एवं एक-एक भाषण दिये।

लघु मंत्रीसंध (The Little Entente)

लघु मंत्रीसंध उन तीन राज्यों की गुटबन्दी का असरकारी नाम था जिन्हें ऑस्ट्रोहंगेरियन राजतन्त्र के क्षाईत हो जाने से सबसे अधिक लाभ पहुँचा। ये राज्य चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और यूगोस्लाविया थे।

चेकोस्लोवाकिया, जैसा कि उसके नाम (उसका यह नाम हाल में गढ़ा गया है) से ही स्पष्ट है, का निर्माण दो पड़ोसी देशों की जनता को संयुक्त कर दिया गया था। चेक और स्लोवाक एक ही स्लाव (Slav) जाति की दो शाखाएँ हैं जो मज़्, दो, म्याग, बरे, परस्पर-प्रति, निरुद्ध, व्येन्सिप, व्येन्सिरी, कै, किन्तु इन दोनों जनताओं का इतिहास एक दूसरे से सर्वथा मिला है। चेक जनता

मध्ययुग में बोहेमिया के एक स्वतन्त्र राजतन्त्र का प्रमुख भाग थी और १६२० के बाद से ऑस्ट्रियन साम्राज्य के जर्मन प्रभाव में आ गई थी। प्राचीन चेक घनी-वर्ग पूरी तरह जर्मन हो चुका था, जबकि अर्वाचीन चेक जनता मितव्ययी, परिश्रमी, सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय और श्रमिकवर्ग की है। इसके विपरीत, १९१८ से एक हजार वर्ष पहिले से ही स्लोवाकिया हंगरी का एक भाग रह चुका था। स्लोवाक अशिक्षित किसानवर्ग के थे और उनकी (स्लोवाक) संस्कृति के प्रतिनिधि विदेशों में, मुख्यतः अमेरिका में रहने वाले, मूर्खमर बुद्धिजीवी लोग थे। इन परिस्थितियों ने, नए चेकोस्लोवाक राज्य को, अपने सैनिक अधिकारी, प्रसन्निक कर्मचारी (civil servants) और शिक्षक, मुख्यतः चेक लोगों में से ही लेने के लिए बाध्य कर दिया। किन्तु स्लोवाक दोनों में इस असमानता का विरोध हुआ; और स्लोवाक जनता का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाली स्लोवाक पार्टी लगातार यह माँग करती रही कि स्लोवाकिया में “राष्ट्रीय स्वायत्त शासन” (“national autonomy”) की स्थापना की जाये।

चेकोस्लोवाकिया की अधिकांश भूमि पर खेती होती थी। नए राज्य ने विस्तृत भूमि-सुधार कर अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाली। इन सुधारों के समय बड़े-बड़े जमींदारों से भूमि छीन ली गई जो कि मुख्यतः जर्मनी या हंगेरियन थे। उनकी यह भूमि छोटे-छोटे किसानों और खेतिहरों में जो कि चेक या स्लोवाक थे, बाँट दी गई। किन्तु चेकोस्लोवाकिया एक अत्यन्त विकसित औद्योगिक (industrial) राज्य भी था और वहाँ श्रद्धा सामग्री प्रचुर मात्रा में तैयार होती थी। उसके भूतपूर्व ऑस्ट्रियन प्रान्तों में लगभग ८० प्रतिशत कोयला और लोहा पैदा होता था तथा युद्ध-पूर्व के ऑस्ट्रियन साम्राज्य के बड़े बड़े उद्योग भी वहाँ थे। उसकी कमजोर भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के मिश्रित स्वरूप ने इन सुविधाओं को कुछ अंशों में अनुपयोगी बना दिया। उसकी एक करोड़ चालीस लाख से अधिक की आबादी में चेक लोग, जो कि शासक वर्ग के थे, की संख्या ६५ लाख थी और स्लोवाकियन की संख्या इनसे २० लाख अधिक थी। शेष आबादी सुसंगठित और परिश्रमी जर्मन अल्पसंख्यकों, जो कि संख्या में ३० लाख थे, और बोहेमिया के किनारे रहते थे, हंगेरियन, रूमेनी और पोलिश अल्पसंख्यकों की थी। सकटकाल के समय स्लोवाक साथ दंगे या नहीं यह सदिग्ध था तथा अल्पसंख्यक ऐसे किसी भी युद्ध के समय विरोधी हो सकते थे जिसमें चेकोस्लो-

वाकिया घसोटा जाये। इसके प्रतिरिक्त चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्रेग (Prague) सोमान के इतने निकट बसी हुई थी कि जर्मनों से युद्ध छिड़ जाने पर जर्मन सैनिक उस पर कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में अधिकार कर सकते थे। इसी तरह यदि हंगरी आक्रमण करता तो स्लोवाकिया के लम्बे और संकरे भू-भाग की प्रतिरक्षा (defence) करना नठिन हो जाता। मध्य योरोप के सभी राज्यों में, चेकोस्लोवाकिया सबसे अधिक बहुजातिपूर्ण (heterogeneous) और सैनिक दृष्टि से, सर्वाधिक सुगमतापूर्वक जेय राज्य था।^१

युद्धकाल के अपने अनुभावों की अपेक्षा शान्ति समझौते पर रुमानिया अधिक गर्व कर सकता था। युद्धकाल में, उसने दो बार पक्ष बदले और युद्ध समाप्त होने पर उसे हंगरी से ट्रांसिलवानिया (Transylvania) का अधिकांश भाग और सोवियत सरकार के विरोध के बावजूद भी, रुस से बेसारेबिया (Bessarabia) मिला। इस कारण उसकी भूमि ती दुगनी हो गई उसकी जनसंख्या भी ७० लाख से १७० लाख हो गई। चेकोस्लोवाकिया की भांति रुमानिया ने भी विस्तृत भूमि सुझार किए और छोटे छोटे किसानों में भूमि का पुनर्वितरण किया। उसके अल्पसंख्यक—हंगेरियन, रुसी और यहूदी—इनने अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को उनसे किसी प्रकार का खतरा हो। किन्तु रुमानिया का शासन भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो चुका था। रुमानियन सेना की क्षमता भी बालकन सेना की तुलना में कम थी। सोवियत यूनियन के बाद योरोप में सबसे अधिक तेल रुमानिया में ही उत्पन्न होता था, और तेल तथा गैँँ ही उसकी संपत्ति के प्रमुख साधन थे।

घरेलू मामलों में, यूगोस्लाविया को भी चेकोस्लोवाकिया जैसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। यह समस्या सजातीय जातियों (cognate races) की एकता के सूत्र में पिरोने की थी। यूगोस्लाव राज्य की जनसंख्या में शामिल तीन जातियों में से, सर्व (Serbs) जाति १८६७ में तुर्की नगर-रक्षक सेनाओं (garrisons) को अंतिम रूप से हटा लिए जाने के बाद से, स्वतंत्रता का

1. "Of all the states of Central Europe, Czechoslovakia was the most heterogeneous and, from the military standpoint, the most vulnerable."

उपभोग करती आ रही थी। सन् १९१८ तक क्रोटस (Croats) हंगरी के ग्रीर स्लोवेन्स (Slovenes) ऑस्ट्रिया के अधीन रहे थे। सर्व लोग, जो कि प्रारम्भ से ही सभ के सबसे प्रमुख अंग थे और जिनमें सहज ही संगठित हो सकने की प्रवृत्ति थी, प्रच्ये योद्धा थे, किन्तु राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से वे क्रोटस और स्लोवेन्स लोगों की तुलना में नहीं ठहरते थे। वे दोनों जातियाँ उन्हें आधे जंगली (semi-barbarians) मानती थी। इन जातियों का सघर्ष नए राज्य की प्रगति में बहुत अधिक हो गया तथा उसके साथ ही साथ स्वयं सब लोगों की राजनैतिक परिपक्वता (political immaturity) ने उस देश में किसी भी प्रकार की संसदीय शासनव्यवस्था (parliamentary system) चल सकना कठिन बना दिया। क्रोट नेता स्वायत्त शासन (autonomy) की माँग करते ही रहे; इस माँग के परिणामस्वरूप उनमें से कई ने वर्षों तक जेल भुगती या देश निकाला सहा। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का दोष दोनों पक्षों के मध्ये है। इन देश की समृद्धि, बलिष्ठ और परिधर्मी कृषकों पर मुख्यतः निर्भर थी यद्यपि उसके खनिज साधन भी प्रचुर थे।

जहाँ तक विदेशी मामलों का सम्बन्ध है, यूगोस्लाविया सधु मंत्रीसभ का एक ऐसा सदस्य था जिसके हित सर्वाधिक विविधतापूर्ण और विस्तृत थे। चेकोस्लोवाकिया प्रधानतः मध्य योरोप का देश था और रूमानिया बाल्कन देशों में से था, किन्तु यूगोस्लाविया दोनों ही में समान रूप से शामिल था। उत्तर में, उसका सीमांत बिएना के एक सौ मील के भीतर था और दक्षिण पूर्व में एजियन (Aegean) के पचास मील के भीतर। हितों की, इस विविधता (multiplicity) के कारण सभ में उसका एक विशिष्ट स्थान बन गया। हंगरी से सामूहिक रक्षा के लिए सधु मंत्रीसभ की स्थापना की गई थी और केवल हंगरी ही एक ऐसा देश था जिसके नाम का स्पष्ट उल्लेख गुट की स्थापना संबंधी सधियों में किया गया था। किन्तु यूगोस्लाविया को हंगरी से सबसे अधिक भय कभी भी नहीं रहा। उसके हिस्से में हंगरी का जो भू-भाग आया था, वह चेकोस्लोवाकिया और रूमानिया के हिस्सों से छोटा था। उसे हंगरी के अनुप्राप्तिवादियों (irredentism) से भी भय कम ही था। इसके विपरीत एड्रियाटिक (Adriatic) में इटली की प्रमुख स्थिति से उसे अत्यन्त ईर्ष्या थी। यूगोस्लाविया यह मानता था कि इटली ने अपने उचित हिस्से से भी अधिक स्लाव (Slav) क्षेत्र

हड़प लिया था और यह एक कुख्यात तथ्य था कि इटली यूगोस्लाव राज्य को ही द्विध्न-भिन्न करने के स्वप्न देख रहा था और शायद, उसके लिए पड़्यत्र भी रच रहा था। यूगोस्लाविया के लोग तीव्र घृणा करते थे। दोनों युद्धों के बीच की अवधि में योरोप में जितने भी आपसी भगड़े (feuds) हुए उनमें यूगोस्लाविया और इटली का आपसी द्वेष सबसे पुराना कारण था।

लघु मंत्रीसभ के हर दो सदस्यों ने १९२० और १९२१ में गुटबंदी की आपस में जो सन्धियाँ की थीं, उनके परिणामस्वरूप लघु मंत्रीसभ अस्तित्व में आया था। उसके काफी समय बाद फ्रांस ने लघु मंत्रीसभ के राज्यों से राजनैतिक संधियाँ की। किन्तु धारम से ही, औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से, यह सैनिक समझौते हो चुके थे जिसमें व्यवस्था थी कि (जैसा कि पोलैंड के साथ हुई सन्धि में) फ्रांसीसी सैनिक मिशनो की नियुक्ति की जाएगी और लघु मंत्रीसभ की सेनाओं के लिए फ्रांस युद्ध-सामग्री देगा। चाहे जेनेवा हो या और कोई स्थान, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और यूगोस्लाविया विदेशी मामलों में फ्रांस के विद्यवातपात्र पिछलान्छू (Satellites) राज्य हो गये। लघु मंत्रीसभ के साथ फ्रांस के सम्बन्धों का आधार पोलैंड के साथ सम्बन्धों से भिन्न था। पोलैंड के साथ उसकी गुटबंदी का आधार जर्मनी को भागे न बढने देने के सम्बन्धों से स्पष्ट एक सामान्य हित था। इसके विपरीत, लघु मंत्रीसभ के देशों के साथ उसका समझौता एक शुद्ध सौदा था जिसके अनुसार वसैलोज की सन्धि को कार्यान्वित करने में फ्रांस की सहायता करना लघु मंत्रीसभ के तीनों राष्ट्रों का कर्तव्य था जबकि इस सन्धि में स्वयं उनका अपना हित नगण्य ही था। फ्रांस ने यह वचन दिया था कि वह लघु मंत्रीसभ के सभी देशों की हफरी से रक्षा करेगा तथा यूगोस्लाविया को इटली से विशेष रूप से बचाएगा। इस सारे प्रयत्न की साफल्यता इसी बात में थी कि फ्रांस की सुरक्षा सीमा में वृद्धि हो गई। अब वह न केवल वसैलोज की संधि का पालन करने के लिए ही निश्चित रूप से वचनबद्ध था अपितु सारे योरोपीय शांति समझौते के पालन के लिए भी। अब उसका सम्बन्ध केवल इसी बात से नहीं रह गया था कि वह जर्मनी को राइन तक ही सीमित रखे और पूर्व में उसे अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं बनाने दे। यह जान सर्वमान्य हो चुकी थी कि लिथुआनिया से पोलैंड को, हंगरी से चेकोस्लोवाकिया को, बल्गेरिया से यूगोस्लाविया तथा रूमानिया की रक्षा करने, एवं अपने भिन्न राष्ट्रों को उनके

अल्पसंख्यकों के प्रति कर्तव्यों के जबरन तोड़ मरोड़ कर निकाले गए धर्मों की असुविधाओं से बचाने में भी फ्रांस का हित था। इन सभी प्रश्नों पर उसके सुदृढ़ प्रभाव (powerful influence) को देखते हुए फ्रांस का आश्रय लेने में ही सार था।^१

सन् १९२०-२४ की अवधि में फ्रांस, जिसके पास विशाल, सुसज्जित और जयी (victorious) सेना थी तथा प्रचुर मात्रा में गोला बारूद का सग्रह था, यूरोप में शक्ति और गौरव की चरम सीमा पर पहुँच गया।^२ वह पूर्व-स्थिति (status quo) बनाए रखन का प्रबल पक्षधर (champion) और सशोधनवाद (revisionism) का कट्टर विरोधी था। उसकी स्थिति की तुलना सन् १८१५ के शांति समझौते के बाद मेटर्निच (Metternich) की स्थिति से की जा सकती है। पोलैंड और लघु मंत्रीसभ के देशों के साथ समझौते कर उसने “ईसाई देश गुटबन्दी” (“Holy Alliance”) का आधुनिक प्रतिरूप ही तैयार कर लिया था।

1. “The importance of this move was that it enlarged France’s conception of her own security. She was now definitely committed to the maintenance not only of the Versailles Treaty, but of the whole European peace settlement. It was no longer her concern merely to keep Germany at bay on the Rhine and prevent her from strengthening her position in the east. It became a recognised French interest to support Poland against Lithuania, Czechoslovakia against Hungary, and even to save her friends from the inconvenience of a too rigorous interpretation of their obligations towards their minorities. In view of the powerful influence which she could exercise in all these questions, France was a patron well worth having.”

2. “During the period 1920-24 France, the possessor of a large, well equipped and victorious army and of enormous stocks of ammunitions, reached the summit of her prestige and power in Europe.”

२. पराजित जर्मनी (Germany in Defeat)

जिन दिनों फ्रांस की तूती बँज रही थी उन्हो दिनों जर्मनी को सबसे अधिक अपमान सहना पड़ रहा था।^१ उसकी परेछु राजनीति इस पुस्तक का विषय नहीं है। किन्तु दोनों ही विश्वयुद्धों के बीच की अवधि में जर्मनी के आन्तरिक घटना घत्र का अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर इतना सीधा प्रभाव पड़ा था कि उसके बारे में दो शब्द यहाँ कहना आवश्यक है। सन् १९१४ से पहिले जर्मनी में संसदीय प्रजातन्त्र (parliamentary democracy) और सैनिक निर्दुशता (military autocracy) दोनों ही के सभ्रणों वाली शासन प्रणाली थी। संभवतः यह प्रणाली जर्मन जनता के राजनैतिक विकास के अधिक अनुकूल थी। युद्ध के बाद, प्रजातन्त्र प्रेम की विश्व-यापी सहर जर्मनी में भी फैल गई, और नवम्बर १९१८ की अज्ञाति के बाद वहाँ जो सरकार बनी उसका स्वरूप गणतन्त्रीय था। सोशल डेमोक्रेटस सत्ताख्ड हुए और इबर्ट (Ebert) नामक एक भूतपूर्व चमकार को राष्ट्रपति बनाया गया।

“वीमर गणतन्त्र” (“Weimar Republic”) (उसका यह नाम इसलिए पड़ा कि वीमर नामक स्थान पर राष्ट्रीय सभा न १९१९ में उसका संविधान स्वीकार किया था) का प्रारम्भ बहुत ही निगडाजनक परिस्थितियों में हुआ। उसे चारों ओर अव्यवस्था, असंगठन और अकिचनता (disorder, disorganisation and destitution) का सामना करना पड़ा। उसकी पहला काम वसैलोज की सन्धि का अनुसमर्थन (ratification) करना था। इस कारण जर्मन जनता के मन में उनका नाम राष्ट्रीय अपमान के साथ जुड़ गया। सन् १८१५ में नेपोलियन का तख्ता उलट देने वाले राष्ट्रो ने यह उचिन समझा था कि यदि वे फ्रांस में पुनर्स्थापित राजतन्त्र (restored monarchy) को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें उसके प्रति सम्मान और

¹ “The years of French supremacy were also the years of Germany's deepest humiliation”

औदार्य दिखाना चाहिये, किन्तु १९१८ के विजेताओं ने इस प्रकार की बुद्धिमानी नहीं दिखाई। यह उनके हित में ही था कि शांतिप्रिय बीमर प्रजातन्त्र को जर्मनी में अपने पैर जमा लेने में वे उसकी सहायता करते। किन्तु उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का हर समभव प्रयत्न करने के बदले, वे उसे हमेशा ही इस प्रकार नीचा दिखाते रहे कि वह जर्मन जनता का प्रेम और उसकी निष्ठा (loyalty) सम्पादित करने की कभी आशा भी नहीं कर सकता था। वर्सेलोज की सन्धि के शैक्षिक उपबन्धों की चर्चा विषय प्रवेश वाले अध्याय में की जा चुकी है। इस अध्याय का विषय सन्धि के वे अन्य उपबन्ध हैं जिन्होंने १९२०-२४ तक जर्मनी के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को सबसे अधिक प्रभावित किया।

युद्ध-अपराध और युद्ध-अपराधी

(War Guilt and War Criminals)

“युद्ध अपराध” और “युद्ध-अपराधियों” सम्बन्धी सन्धि की धाराओं का प्रास की अपेक्षा ग्रेट ब्रिटेन में अधिक उत्साहपूर्वक अनुमोदन किया गया। पिछले युद्धों के विजेता अपने पराजित शत्रु के साथ कितना ही निर्दयतापूर्ण व्यवहार क्यों न करते रहें हो, किन्तु वे यह अनावश्यक समझते थे कि अपने शत्रु की सार्वजनिक रूप से नैतिक निन्दा की जाये। परन्तु ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स दोनों ही देशों में युद्ध प्रचार के समय जर्मनी की नैतिक पथ भ्रष्टता (delinquencies) (विशेषकर बेल्जियम की तटस्थता भंग करने, अपने अधिकार के क्षेत्रों का अनावश्यक रूप से मरियामेट करने, वगैरह) कर नागरिकों की हत्या करने और व्यापारिक जहाजों से वनहूबो द्वारा अबाधित (unrestricted) युद्ध (करने) की निरन्तर इतनी निन्दा की गई थी कि लोकमत जर्मनी के कृत्यों की औपचारिक रूप से निन्दा करना चाहता था। जर्मनी के अपराधों पर जोर दिए जाने के कारण ही शान्ति की शर्तों की कठोरता को उचित ठहराया जा सकता था। ब्रिटिश और अमरीकी दोनों ही क्षेत्र इस प्रकार के औचित्य की आवश्यकता अनुभव भी करते थे। क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अध्याय के आरम्भ में ही लिखे गए एक अनुच्छेद के अनुसार, जर्मनी को, “जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों के आक्रमण के कारण विवशतापूर्वक युद्ध में सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप मित्र और साथी राष्ट्रों की सरकारों तथा जनता को जो भी हानि और क्षति उठानी पड़ी, उसकी (जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की) जिम्मेदारी को स्वीकार करने” के

लिए धाव्य किया गया। इस अनुच्छेद की स्थिति महत्त्व से खाली नहीं थी। इस संधि के अतिरिक्त सम्बन्धी उपबन्धों ने घमरीकी और कुछ ब्रिटिश क्षेत्र में सबसे अधिक भ्रान्त धारणाएँ फैलाई।

प्रथम विश्वयुद्ध की उत्पत्ति पर इतिहासकार सममतः शताब्दियों तक बहस करते रहेगे। इतिहास का निर्णय शायद यह हो सकता है कि युद्धरत सभी राष्ट्रों में (all belligerent Powers) जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों पर ही युद्ध की सबसे अधिक जिम्मेदारी थी। किन्तु ऐतिहासिक सत्य की स्थापना किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि से नहीं की जा सकती—जो संधि विजैताओं द्वारा विजितों पर लादी गई हो उससे तो कदापि नहीं। उसे जना के उन धारणों में मित्र-राष्ट्रों की सरकारों ने यह नहीं सोचा कि जबरदस्ती अपराध स्वीकार कराने से कुछ काम नहीं चल सकता और उसके परिणामस्वरूप जर्मन जनता में तीव्र रोष की भावना फैले बिना नहीं रहेगी। जर्मनी का विश्व समाज यह सिद्ध करने में लग गया कि उनका देश निर्दोष था। इस समाज का यह स्वप्न था कि यदि यह बात सिद्ध कर दी गई तो सन्धि का सारा ढाँचा ही लटखड़ा पड़ेगा। मित्र-राष्ट्रों में भी, युद्ध-अपराध सम्बन्धी धारा की व्यर्थता शीघ्र ही अनुभव कर ली गई। किन्तु उसे कभी भी विधिवत् रद्द नहीं किया गया तथा सन्धि के साथ ही नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया।

युद्ध-अपराधियों सम्बन्धी सन्धि के अनुच्छेद (तत्सम्बन्धी अध्याय को “शस्त्रियों” (penalties) नाम दिया गया है) तत्काल अपना प्रभाव दिखाने वाले थे। उनमें से पहले में मित्र-राष्ट्रों ने “भूतपूर्व जर्मन सम्राट्—होहेनजोल्लर्न के विलियम द्वितीय (Hohenzollern) पर सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता और सन्धियों के विश्व गुप्ततम अपराध किया है।”

भूतपूर्व कैसर पर पाँच सदस्यों वाले—घमरीकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, इटालियन और जापानी—एक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना था। इन सदस्यों का काम “दंड निश्चित करना” था। सन्धि अमल में आने के तुरन्त बाद ही, मित्र-राष्ट्रों ने सरकारी तौर पर हॉर्लैंड (जहाँ कि नवम्बर १९१८ में भूतपूर्व कैसर ने शरण ली) सरकार से यह अनुरोध किया कि वह कैसर को उन्हें सौंप दे। पूर्वपिछानुसार हॉर्लैंड सरकार ने यह उत्तर दिया कि “राजनैतिक शरणार्थी

को वापस सीप देना अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा (usage) के विरुद्ध है। इस प्रकार सन्धि के कुर्यात अनुच्छेदों में से एक कुछ ही महीनों में अतीत की वस्तु बन गया। यह एक सोभाग्यपूर्ण अन्त था। यदि मित्र राष्ट्र भूतपूर्व कैसर पर खुले घाम मुकद्दमा चलाते तो सम्भवतः कैसर की जमनी में खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हो जाती और वह जर्मनी के राष्ट्रीय नेता एव शहीद के रूप में सामने आ जाता।

उपरोक्त अनुच्छेद के बाद के अनुच्छेदों ने अनुसार जर्मनी ने यह वचन दिया कि मित्र राष्ट्रों ने जिन व्यक्तियों पर “युद्ध के नियमों और प्रथाओं के उल्लंघन में इत्थं करने” का आरोप लगाया हो उन जर्मनी स्थित व्यक्तियों को वह मित्र-राष्ट्रों के सैनिक न्यायालयों को मुकद्दमा चलाने के लिए सीप देगा। इसमें सन्देह ही है कि यह व्यवस्था जिसका किन्ना हो युक्तिमगत अर्थ क्यो न लगाया जाए, जर्मनी में जाति किए बिना अमल में लाई जा सकती थी। किन्तु जब इस बात का पता चला कि मित्र-राष्ट्रों द्वारा तैयार की गई सूची में हिन्डेन-बर्ग, लुडेनडाफ के युवराज और युद्ध के समय जर्मनी की ओर से लगे हुए प्रमुख व्यक्ति का नाम सम्मिलित है, तब क्रोधाग्नि इतनी भड़क उठी कि इस माँग को पूरा करना असम्भव हो गया। जर्मनी और मित्र-राष्ट्रों (Allies) की सरकारों के बीच सम्बन्धी कशमकश के बाद, एक समझौता हुआ जिसके अनुसार जर्मन सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि वह कुल अपराधियों में से बारह अपराधियों को (जिनके विरुद्ध निश्चित और निन्दाजनक रूप से युद्ध नियमों को भंग करने का आरोप था) लिपज़िग (Leipzig) स्थित जर्मन सर्वोच्च न्यायालय (German Supreme Court) के सामने उपस्थित करेगी और इस न्यायालय में मित्र-राष्ट्रों की सरकारें अभियोक्ता (prosecutors) रहेगी। मुकद्दमे १९२१ में चले। छः अपराधियों का अपराध सिद्ध हुआ और उन्हें कारावास की सजा दी गई। उसके बाद सन्धि की इन धाराओं के विषय में और कुछ कभी भी नहीं सुना गया। यदि उस समय के गरम वातावरण ने मित्र राष्ट्रों की सरकारों को यही व्यवस्था पारस्परिक आधार पर करने दी होती और यदि ये सरकारें भी जर्मन सरकार द्वारा इसी प्रकार के अपराधों के लिए आरोपित अपने देशवासियों पर भी मुकद्दमा चलाने के लिए तैयार हो जाती तो इस सारी कार्यवाही से एक महत्त्वपूर्ण नई प्रथा का श्रीगणेश होता तथा अन्तर्राष्ट्रीय

कानून को यथाथं में प्रभावकारक बनाने की मानवता की उत्सुकनापूर्ण इच्छा भी पूरी हो जानी ।^१

निःशस्त्रीकरण और असेनीकरण

(Disarmament and Demilitarisation)

अपनी विजय के कारण मित्र-राष्ट्रों के मध्य में यह इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक और आवश्यक थी कि वे अपने शत्रुओं को यथासंभव दीर्घकाल तक के लिए सैनिक दृष्टि से पशु बना दें। विरामसन्धि के समय जर्मनी ने अपना अधिकांश बेड़ा (fleet) और भारी तोपखाना (artillery) समर्पित कर दिया था। सन्धि के द्वारा उसकी सैनिक शक्ति पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उसकी सेना की संख्या सीमित कर १००,००० कर दी गई थी जिसमें स्वेच्छा ही किसी को भरती किया जा सकता था। अनिवार्य भरती (conscription) करने का निषेध किया गया था। उसकी नौसेना में केवल छः युद्धपोत (battle-ships) और इतने ही गश्तीजहाज (cruisers) तथा विध्वंसक (destroyers) रह सकते थे। वह पनडुब्बियाँ (submarines), सैनिक वायुयान और भारी तोपें नहीं रख सकता था तथा किलेबंदी नहीं कर सकता था। वह किस प्रकार की कितनी युद्ध सामग्री अपने पास रख सकेगा और युद्ध-सामग्री तैयार करने वाली कितनी फैक्ट्रियाँ उसके पास रह सकेंगी यह ठीक ठीक निर्दिष्ट कर दिया था। मित्र-राष्ट्रों के सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक आयोग (Allied Naval, Military and Air Commissions) जिनके अधिकारियों की संख्या एक समय लगभग २,००० तक पहुँच गई थी जर्मनी में इन उपबन्धों का पालन करवाने के लिए १९१५ और १९२७ तक उन्हें अन्तिम रूप से हटाया भी नहीं गया। इस कार्यवाही के दृढ़तापूर्ण प्रयोग

1. "Had the passions of the time permuted the Allied Government to make the arrangement reciprocal and had they themselves been willing to bring to trial any of their own nationals accused of similar offences by the German Government the whole procedure might have been a valuable innovation and an earnest of the desire of mankind to make international law an effective reality."

से बचने के लिए जर्मनी ने हर प्रयत्न किया। काफ़ी युद्ध-सामग्री छिपाकर सभ-
वतः नष्ट होने से बचा ली गई तथा ज्यों ही नियंत्रण गिराया गया त्योंही
जर्मनी की सैनिक शक्ति को पुनः बढ़ा लेने की सर्वत्र हो गुप्त तैयारियाँ की जाती
रही। किन्तु इन सभी बातों पर विचार करने के बाद इतना अवश्य कहा जा
सकता है कि १९२४ तक जर्मनी का जिस कठोरतापूर्वक और संपूर्णरूपेण
निःशस्त्रीकरण किया जा चुका था, उतना और किसी भी देश का कभी किया गया
था—इसका उल्लेख लिखित रूप में प्राप्त आधुनिक इतिहास में नहीं मिलता।

यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि वसैलीज की सन्धि के अनुसार, राइन-
भूमि (Rhineland) का न केवल स्थायी रूप से असेनीकरण कर दिया जाता
था, अपितु पंद्रह वर्षों तक उस पर मित्र-राष्ट्रों की सेना का अधिकार भी रहना
था। अधिकृत क्षेत्र का नागरिक प्रशासन जर्मन अधिकारियों के हाथों में रहा
परन्तु मित्र-राष्ट्रों की सेना की 'सुरक्षा निर्वाह (maintenance) और आव-
श्यकताओं को पूर्ण के लिए आवश्यक होने पर" अन्तर मित्र राष्ट्रीय उच्च आयोग
(Inter Allied High Commission) को जिसमें फ्रांस, बेल्जियम,
ब्रिटेन और अमेरिका के प्रतिनिधि रखे गए थे, अध्यादेश (ordinances) जारी
करने की शक्ति (power) प्राप्त थी। ये अध्यादेश कानून व समान ही प्रभावशील
होते थे। अमेरिका द्वारा सन्धि का अनुसमर्थन नहीं किए जाने क बावजूद भी,
अमरीकी सेनाएँ राइनभूमि में १९२३ तक बनी रहो और अमरीकी आयुक्त
(Commissioner) उच्च आयोग की बैठकों में बराबर भाग लेता रहा किन्तु
उसे मत देने का अधिकार नहीं था।

जर्मनी के प्रति फ्रांस और ब्रिटेन के दृष्टिकोणों की विभिन्नता—जो कि १९२०
से ही योगोपीय राजनीति में समाधानहीन घटक (unsettling factor) रही थी
राइनभूमि पर संयुक्त अधिकार (joint occupation) के समय पहिली बार
सामने आ गई। युद्ध समाप्ति के समय जर्मन विरोधी भावनाएँ लंदन में भी उन्नी
ही कटु थी जिनकी कि पेरिस में। वसैलीज की सन्धि की कुछ अत्यन्त दुर्भावनाजनक
(invidious) धाराएँ यदि ब्रिटिश सरकार को प्रेरणा से नहीं ली गई, तो
कम से कम उनका हादिक अनुमोदन तो ब्रिटेन ने किया ही था। किन्तु
ब्रिटेन में यह दुर्भावना तेज़ी से कम होनी गई। फ्रांस को जहाँ
एक ओर पराजित जर्मनी से भी भय था, वहीं दूसरी ओर जर्मन बेड़े के

नष्ट हो जाने से ब्रिटिश साम्राज्य अपने को पूरी तरह सुरक्षित समझने लगा। ब्रिटेन इस बात के लिए फुसुयात है ही कि उसे योरोप महाद्वीप में किसी भी राष्ट्र का शक्तिशाली होना पूरी आँखों नही सुहाता, इस समय यदि ब्रिटेन फ्रांस को जर्मनी को धूल में मिलाने देता तो यह बात उसकी परंपरा के विरुद्ध होती। पराजित शत्रु के प्रति श्रोदार्य दिव्याने और न्याय करने की परंपरागत (time-honoured) ब्रिटिश मान्यताओं और फ्रांसिसियों की सूक्ष्म बंधिक (legal) मनोवृत्ति में जो कि बंधन (bond) में निर्दिष्ट रक्त की अन्तिम बूँद भी निवास लेने के लिए उत्सुक हो, सघर्ष हुआ। राइनभूमि के दक्षिणी भाग पर अधिकार करने वाली फ्रांसीसी सेना ने जहाँ एक ओर शत्रु-भूमि (hostile land) में विजेताओं का रौब दिखाया और अपनी शक्ति का बड़ा चंदाकर परिचय दिया, वही दूसरी ओर ब्रिटिश सेना ने जिसका मुख्यालय (head quarter) कोलोन (Cologne) में था, जर्मन लोगों को भीष्म ही अपना घनिष्ट मित्र बना लिया। ब्रिटिश सिपाही, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से एक अनिश्चित प्रतिधि या तथापि वह जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हो गया। यह बात अक्सर कही जाती थी कि ब्रिटिश सिपाही को अपने भूतपूर्व-मित्रों (ex-allies) की अपेक्षा अपने भूतपूर्व शत्रुओं (ex-enemies) की सगति अधिक अच्छी लगती थी। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो चुका था जिनके कारण जर्मनी सम्झौते कई घटनाओं को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन में मतभेद की छाई बनी।

इस प्रकार की घटनाओं में पहिली घटना फ्रांस की अधिकार सेना में अश्वेत (coloured) सैनिक टुकड़ी (detachment) को सम्मिलित किए जाने से सम्बन्धित थी। फ्रांस रंगभेद नही मानना और यह असंभाव्य (unlikely) है कि जर्मन जनता का और भी अपमान करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों ने अश्वेत सिपाहियों को जानबूझकर राइनभूमि में भेजा हो। जर्मन लोगों ने तो इसका यही अर्थ लगाया था। इसलिए उन्होंने यह सोचकर कि ब्रिटेन और अमेरिका रंगभेद का नीति में जर्मनी में भी अधिक विश्वास रखते हैं, अपनी इस शिकायत को उनके सामने रखने का अवसर हाथ से नही छोड़ा। “अश्वेत प्रणामन” (“black shame”) और अश्वेत सेना के तथाकथित कुकृत्यों (misdeeds) को जर्मन प्रचारकों ने अपने प्रचार का खूब साधन बनाया। इस प्रकार युद्ध के बाद पहिली बार, ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों के फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी का दृढ़ समर्थन किया।

दूसरी घटना फ्रांस द्वारा राइनभूमि में एक तथाकथित “पार्थक्यवादी” (separatist) आन्दोलन को प्रोत्साहन दिए जाने से सम्बन्धित थी। शांति चर्चाओं के समय जर्मनी से राइनभूमि को बलात् पृथक् (forcible separation) करा लेने में असफल हो जाने के बाद कुछ फ्रांसीसी सेनापति और अधिकारी, फ्रांसीसी सरकार के मोन (la loi) अनुमोदनपूर्वक, अब इसी उद्देश्य की पूर्ति स्थानीय जनता की वॉलिन की सत्ता को उलट फेंककर राइनभूमि एक स्वतन्त्र राज्य घोषित कर देने के लिए उभाड़कर करना चाहते थे। यह आन्दोलन लगभग बिल्कुल नकली था। ती वर्षों से भी अधिक समय से राइनभूमि का अधिकांश भाग प्रशा में शामिल बला सा रहा था और बहुत ही कम राइनरासी फ्रांस के संरक्षण में अवास्तविक स्वायत्त शासन चाहते थे। किन्तु फ्रांसीसियों को किराए के कुछ टुकड़े मिल गए या फ्रांसीसी उन्हें बाहर से ले आए। ये लोग फ्रांस से काफी पैसा लेकर यह नाटक करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार तीन वर्षों तक पार्थक्यवादी आन्दोलन का नाटक बनाए रखा गया किन्तु १६२३ के शरद में परिस्थिति बिगड़ गई। पेलेटिनेट (Palatinate) में, जो कि बेवेरिया (Bavaria) का भाग था, न कि प्रशा का, उच्च अयोग के स्थानीय फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने पार्थक्यवादियों को एक स्वतन्त्र सरकार के रूप में मान्यता दे दी और पार्थक्यवादियों ने, जिन्हें फ्रांसीसी सैनिक अधिकारियों ने इसी उद्देश्य के लिए सहायता दी थी, जर्मन अधिकारियों को निकाल बाहर दिया तथा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। जनवरी १६२४ में उच्च अयोग ने बहुमत से (फ्रांस और बेल्जियम ने ब्रिटेन के विरुद्ध मत दिया था) पेलेटिनेट की “स्वायत्त शासी (autonomous) सरकार” को अधिकृत रूप से मान्यता दे दी। ब्रिटिश लोकमत और ब्रिटिश सरकार को यह बात बहुत बुरी लगी। जब फ्रांसीसी सरकार पर काफी दबाव डाला गया, तब उसने राइनभूमि स्थित अपने प्रतिनिधियों को आदेश दिए कि वे पार्थक्यवादियों का समर्थन करना बन्द कर दें। इसका परिणाम विध्वंसकारी हुआ। सात आन्दोलन कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। पेलेटिनेट के प्रमुख नगरों में दंगे हुए, और सेना के हस्तक्षेप से पहिले ही जनता ने बीसेक (a score or more) पार्थक्यवादियों को मौत के घाट उतार दिया। फरवरी १६१४ के बाद राइनभूमि में पार्थक्यवादी आन्दोलन का नामोनिशान भी नहीं रहा।

जर्मनी और मित्र राष्ट्रों तथा फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के सम्बन्धों को इस

अवधि में प्रभावित करने वाली तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना क्षतिपूर्ति का पेचीदा प्रश्न था जिस पर हम अब विचार करेंगे ।

क्षतिपूर्ति (Reparation) 20320

युद्ध-काल में अनेक देशों की प्रजातन्त्रीय विचारधारा इस बात के विरोध में थी कि शांति-संधियों में, पराजित देशों से दण्ड रूप में, 'युद्ध क्षतिपूर्ति' (war indemnity) वसूल की जाय । मित्र-राष्ट्रों की सरकारों ने यह राय स्वीकार कर ली और वसैलोज की संधि में घननी माँग केवल इसी बात तक सीमित रखी कि जर्मनी, 'मित्र और साथी राष्ट्रों की नागरिक जनता की जन-धन की जो भी हानि हुई हो, उसकी क्षतिपूर्ति करे ।' जो भी हो, यह कोई खाम रियायत नहीं थी, क्योंकि यह शोध हो स्पष्ट हो गया कि जर्मनी के वर्तमान साधनों से इस क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं हो सकेगा । जहाँ तक पराजित राष्ट्र द्वारा विनैनामो को भुगतान करने का प्रश्न है, वसैलोज का मन्त्रि और विद्वानों द्वारा सन्धियों ने केवल यही अन्तर था कि इस बार संधि में भुगतान की कोई रकम निर्दिष्ट नहीं की गई थी । यह बात मित्र-राष्ट्र आयोग (Allied Commission), जिसे 'क्षतिपूर्ति आयोग' कहा गया था, पर छोड़ दी गई थी कि वह दिल तैयार करे और यह निर्दिष्ट करे कि इस ढिल की रकम किस प्रकार चुकाई जाये । निर्धारण (assessment) पहली मई १९२१ तक किया जाना था । इस तारीख से पहिले जर्मनी को १,०००,०००,००० पाँड आंशिक भुगतान (on account) के रूप में चुकाने थे । यह अनुमान लगाया गया था कि इसके बाद न भुगतान कम से कम तीस वर्षों में जाकर पूरा हो सकेगा ।

वसैलोज संधि पर हस्ताक्षर होने से पहिले मित्र राष्ट्रों और जर्मन प्रतिनिधि मंडल में हुए पत्र व्यवहार में, मित्र-राष्ट्रों ने यह वचन दिया था कि "पूरे दायित्व (liability) के निबटारे में जर्मनी यदि कोई एकमुश्त रकम (lump sum) देना चाहे, तो मित्र राष्ट्र ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।"—यह एकमुश्त भुगतान क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित निवारण के स्थान में किया जा सकता था । इस प्रकार १९२० की प्रमुखताएँ ये थी—उक्त प्रस्ताव की समाविष्ट शर्तों और माल में भुगतान (deliveries in kind) (विशेषकर कोयले के रूप में)" पर चर्चा, जिसके द्वारा जर्मनी १,०००,०००,०००

पौड का प्रारम्भिक भुगतान करना चाहता था। उसी वर्ष जुलाई में स्पा (Spa) में एक सम्मेलन हुआ जिसमें जर्मनी के प्रधानमंत्री (Chancellor) और विदेशमंत्री ने मित्र-राष्ट्रों के प्रमुख मंत्रियों से पहिली बार वरावरी की हैसियत से चर्चाएँ की। किन्तु इन मंत्रियों में केवल यही समझौता हो सका कि भगले ॥ महीनों में कितना कोयला दिया जाये, और क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर स्पा सम्मेलन में हुआ प्रमुख निर्णय इस समय तक अप्राप्त प्राप्तियों (भामद) (hitherto non-existent receipts) का मित्र राष्ट्रों में आपस में बँटवारे से सम्बन्धित था। इस प्राप्ति का ५२ प्रतिशत फ्रांस को, २२ प्रतिशत ब्रिटिश साम्राज्य को, १० प्रतिशत इटली को, और ६ प्रतिशत बेल्जियम को मिलना था, तथा शेष भाग छोटे छोटे मित्र-राष्ट्रों में आपसी बँटवारे के लिए छोड़ दिया गया। चूँकि बेल्जियम को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी थी, इसलिए उसे १००,०००,००० पौड तक ग्रहण करने का प्राथम्य (priority) दिया गया था।

जर्मनी से “एकमुश्त” कितनी रकम की माशा करना युक्तिसंगत है, इस बारे में जर्मन सरकार और मित्र राष्ट्रों की सरकारों में इतना मतभेद था कि कोई समझौता हो सकना कठिन था। जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रारम्भिक भुगतान तथा निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी कुछ उपबन्धों पर अमल करने में असफल होने के कारण मार्च १९२१ में, मित्र-राष्ट्रों की सेना ने राइन के पूर्व में स्थित ड्यूसेल्डोर्फ (Dusseldorf), ड्यूसबर्ग (Duisberg) और रूह्रोर्ट (Ruhrort) नामक तीन नगरों पर अधिकार कर लिया। संधि का अनुसरण करते हुए क्षतिपूर्ति आयोग ने अप्रैल २७, १९२१ को जर्मनी का कुल दायित्व ६,६००,०००,००० पौड निर्दिष्ट किया। इस समय तक मित्र-राष्ट्रों के विचारशील व्यक्ति यह मान चुके थे कि जर्मनी इतने बड़े बिल की बहुत थोड़ी ही रकम चुका सकता है। मित्र राष्ट्रों की सरकारों में अभी इतना साहस नहीं था कि वे अपने दावों की कुछ रकम खुले भाम छोड़ दें। जर्मनी के कर्ज (debt) को तीन प्रकार के ऋणपत्रों (bonds) के अनुसार तीन भागों में बाँटा गया था। ये ऋणपत्र “क” (“A”) “ख” (“B”) और “ग” (“C”) प्रकार के थे। “ग” ऋणपत्रों की रकम ४,०००,०००,००० पौड थी और ये ऋणपत्र जर्मनी की भुगतान-क्षमता स्थिर हो जाने तक क्षतिपूर्ति आयोग के पास ही रहने थे। इस प्रकार पूरे कर्ज की दो तिहाई रकम की वसूली प्रतिनिश्चित समय के लिए छटाई में डाल दी गई। शेष रकम की भुगतान के लिए मित्र-राष्ट्रों की सरकारों ने एक “भुगतान कार्यक्रम” (“schedule of pay-”

ments") तैयार किया जिसके अनुसार जर्मनी १००,०००,००० पौंड घोर अपनी निर्यात-वस्तुओं के मूल्य का २५ प्रतिशत चुकाये, यह निश्चित किया गया था। यह कार्यक्रम जर्मन सरकार के पास इस मल्टीमेंटम के साथ भेज दिया गया कि १२ मई तक यदि उसे स्वीकार नहीं किया गया, तो मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ रूर (Ruhr) घाटी पर अधिकार कर लेंगी—रूर घाटी जर्मनी के धातु उद्योग (metallurgical industry) का केन्द्र थी तथा जर्मनी के कोयले, कच्चे लोहे, तथा इस्पात का ८० प्रतिशत से भी अधिक वहाँ उत्पन्न होता था। जर्मनी में मंत्रिमंडलीय संकट (Cabinet crisis) उत्पन्न हो गया, अन्त में, ११ मई को यह माँग स्वीकार कर ली गई।

कार्यक्रम के अनुसार अदायगी (due) के ५०,०००,००० पौंड की पहिली किश्त जर्मनी ने अगस्त में चुका दी और तीन वर्षों से भी अधिक समय तक यही उसका अन्तिम नकद भुगतान रहा। किन्तु जर्मनी की घड़ी मुद्रा-संकट (currency crisis) में फँस गया। संकट से पहिले २० मार्क (mark) का सामान्य मूल्य (normal value) एक स्टर्लिंग पौंड था किन्तु १९२० के मध्य तक लगभग २५० मार्कों का मूल्य एक पौंड तक हो चुका था। कुछ समय तक वह इस मार्कडे पर स्थिर रहा। इस स्थिरता के लिए कुछ विदेशी सट्टेबाज (speculators) अधिकांशतः जिम्मेदार थे जोकि जल्दबाजी में यह मान बैठे थे कि मार्क का अपने मूल मूल्य (original value) पर किसी न किसी दिन आना सुनिश्चित है। किन्तु १९२१ के प्रीव्म में, जब यह स्पष्ट हो गया कि भुगतान कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने दायित्वों के भुगतान के लिए जर्मनी को विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी, तब मार्क के मूल्य का गिरना पुन प्रारम्भ हो गया। नवम्बर में तो १००० मार्क का एक पौंड तक मूल्य हो गया और १९२२ के प्रीव्म में उसकी गिरावट (fall) त्वरित और अनिष्टकारक (rapid and catastrophic) हो गई।

इस समय तक विश्व के अर्थ विशेषज्ञ यह मान चुके थे कि क्षतिपूर्ति का नकद भुगतान करने की जर्मनी की हैसियत अब बिल्कुल भी नहीं रही है। मित्र-राष्ट्रों के लिए मार्कों का कोई महत्त्व नहीं था। जर्मन सरकार यदि भुगतान करना चाहती भी तो उसके पास अन्य मुद्राएँ ज़रूरी करने के साधन नहीं थे। ब्रिटिश सरकार इस बान पर जोर दे रही थी कि जर्मनी दो वर्षों के भुगतान-

विलम्बवाला (moratorium) के भीतर सभी नकद-भुगतान कर दे। फ्रांसीसी लोकमत यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि एक नज्दार् अपने न्याय दायित्वों (just obligations) से भी इस प्रकार बचने का प्रयत्न करे और विजयी मित्र राष्ट्रों को युद्ध तथा पुनर्निर्माण (reconstruction) का भारी बोझ स्वयं उठाना पड़े। सन् १९२१ के अल्टीमेटम के कारण फ्रांसीसी सरकार की तृष्णा और भी बढ़ गई थी। यदि रूर पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो जाये, तो न केवल फ्रांस की सुरक्षा बढ़ सकती थी, अपितु जर्मन उद्योग का लाभ भी मित्र-राष्ट्रों के राजकोषों (exchequers) में बलात् जमा कर लिया जा सकता था। यह योजना जो कि “उत्पादक गारण्टियों” (“productive guarantees”) की नीति के रूप में घोषित की गई थी, कुछ फ्रांसीसी राजनीतिज्ञों को अत्यन्त आकर्षक प्रतीत हुई। पौकारे भी उनमें से एक था। दिसम्बर १९२२ में जर्मनी माल-भुगतान के वचनबद्ध कार्यक्रम की कुछ मात्रा पूरी नहीं कर सका। इस पर क्षतिपूर्ति आयोग ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि का मत विरोध में होते हुए भी, यह घोषित कर दिया कि जर्मनी ने “जानबूझकर भुगतान नहीं दिया”। इस कदम की महत्ता सन्धि के उस अनुच्छेद में निहित थी जिसके अनुसार मित्र-राष्ट्रों को यह अधिकार था कि “यदि जर्मनी जानबूझकर भुगतान नहीं करे” तो “संबंधित सरकारें आवश्यक कदम उठा सकती हैं।”

फ्रांसीसियों ने जिस प्रयोग को आजमाने पर अपनी दृष्टि लगा रखी थी, उस प्रयोग के लिए अब रास्ता साफ हो चुका था। जनवरी ११, १९२३ को ब्रिटिश सरकार का सहयोग प्राप्त करने या कम से कम उसका अनुमोदन प्राप्त कर लेने का निष्फल प्रयत्न कर लने के बाद फ्रांस व बेल्जियम की सेनाएँ ने रूर में प्रवेश किया। जर्मन सरकार ने निष्क्रिय प्रतिरोध [(सत्याग्रह) (passive resistance)] की नीति अपनाने की घोषणा कर दी। आक्रमणकारियों के साथ किसी प्रकार का भुगतान सहयोग करने की जर्मन लोगों को मनाही कर दी गई। जिसके साथ ही स्वेच्छा से किए जाने वाले सभी क्षतिपूर्ति भुगतान तथा माल भुगतान बन्द कर दिए गये। फ्रांसीसियों ने भी इसका जबाब प्रत्युत्तर बहिष्कार (counter boycott) स दिया। उन्होंने अधिकृत (occupied) और अनधिकृत (unoccupied) जर्मन क्षेत्र में भेद किया तथा अनधिकृत जर्मन

क्षेत्र में कोई भी वस्तु नहीं जाने दी। अधिकृत क्षेत्र के सहयोग विमुख अधिकारियों और उद्योगपतियों को या तो निजात दिया गया या जेलों में ठूस दिया गया तथा हर उद्योग के उत्पादन से क्षतिपूर्ति की रकम वसूल करने के लिए एक पृथक् संगठन की स्थापना कर दी गई।

ब्रिटिश सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि फ्रांस और बेल्जियम द्वारा एक अनर्थापित कारण को लेकर और गिर-राष्ट्रो की सहमति से बिना पृथक् रूप से की गई यह कार्रवाई सन्धि का उल्लंघन (contravention) है। उसे यह विश्वास भी नहीं था कि इस प्रकार का मार्ग अपनाने से क्षतिपूर्ति की रकम वसूल हो सकेगी। फ्रांस और ब्रिटेन के सम्बन्धों में निश्चित रूप से तनाव पैदा गया। राइनलैंड में स्थापित सबसे कठिन हो गई। सन् १९२३ में उच्च आयोग ने लगभग सभी निर्णय बहुमत से किये किन्तु ब्रिटेन का मत उनके विरोध में रहा। यदि निर्णयों का सम्बन्ध हर पर अधिकार से होना था, तो ब्रिटिश क्षेत्र के अधिकारी उन्हें बमल में लाने से इन्कार कर देने दे।

हर पर अधिकार के कारण जर्मनी का सारा आर्थिक जीवन ही ठप्प हो गया। जहाँ तक फ्रांस का प्रश्न है, हर क कोयल और लोहे से उपकी लागत ही नहीं निकलनी थी। इधर जर्मनी पर इस अधिकार का तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि उसका राजकोष (exchequer) बिलकुल ही खाली हो गया। अधिकार से कुछ समय पूर्व ही, मार्क का मूल्य गिरकर प्रति पाँड ३५,००० हो चुका था। सन् १९२३ में पूरे वर्ष यह हास (decline) जारी रहा, यहाँ तक कि कमी-कमी ता उमवा मूल्य दूसरे दिन ही धारा हो जाता था। जो विश्वासी अपनी "खरी" ("Good") मुद्राओं का इन अनापसन्नाय दरो (fantastic rates) पर विनिमय करता था, वह कुछ ही पैसे प्रतिदिन व्यय कर जर्मनी में डाट बाट से रह सकता था या कुछ ही शिल्लिंगों में सारे जर्मनी की यात्रा कर सकता था। सन् १९२३ के समाप्त होने-होने, एक पाँड के ५०,००० अरब (Milliard = One thousand millions—Tr.) मार्क प्राप्त किये जा सकते थे।

इसमें सन्देह नहीं कि मार्क का मूल हास (original decline) जिन कारणों—युद्ध काल की आर्थिक गड़बड़ी, प्रशासनतन्त्र (state machine) का अव्यवस्थित हो जाना और अन्ततः मित्र-राष्ट्रो के दावे (claims)—से हुआ था, उन पर जर्मन सरकार का कोई प्रभाव नहीं था। किन्तु एक बार

जब यह प्रक्रिया (process) आरम्भ हो गई, तब जर्मन अधिकारियों ने उसे रोकने के सभी प्रयत्न भी शीघ्र ही छोड़ दिये । अत्याधिक और अनिश्चित क्षति पूर्ति कर्ज ने जर्मनों को न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में बिल्कुल ही असमर्थ बना दिया अपितु इस दिशा में कोई भी गंभीर प्रयत्न करने की, उसकी इच्छा को भी पशु कर दिया, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति जितनी ही अच्छी होती, उतना ही अधिक भुगतान उसे करना पड़ता । मार्क की क्षिप्र ह्रास (downward race) प्रवृत्ति को जर्मन अधिकारी प्रसन्नताहीन आत्म-संतुष्टिपूर्वक (with grim complacency) देखते रहे क्योंकि उनका यह विचार था कि यह ह्रास क्षतिपूर्ति वसूल करने की मिन राइट्रो की अन्तिम आशाओं पर भी पानी फेरे दे रहा था । इस प्रक्रिया की अन्तिम अवस्थाओं ने तो मुद्रास्फीति (inflation) के आन्धिक अर्थ—अर्थात् राजकोष की तत्काल आवश्यकताओं को छोड़ और किसी भी बात का विचार किए बिना असीमित सख्या में पत्र-मुद्रा (paper money) छापते चले जाना—का शास्त्रीय (classic) उदाहरण ही प्रस्तुत कर दिया ।

वर्सेलीज की सधि की अपेक्षा मुद्रास्फीति का जर्मनी पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा । हर बचक (mortgage), स्थिर व्याज पर विनियोजित (invested) हर घन, मार्कों में रखा जाने वाला बैंक का हर खाता मूल्यहीन हो गया । सारी बचत एक ही बार में समाप्त हो गई । इस प्रहार का सबसे बुरा प्रभाव बहुसंख्यी मध्यमवर्ग पर पड़ा । घनिक लोग भी यद्यपि बर्बाद हो चुके थे तदपि उनके पास भूमि, भवन और पशु शेष रह गए थे । मुट्ठी भर उद्योगपतियों और सट्टेबाजों ने मुद्रास्फीति से भी अपनी तिजोरियाँ भरीं, किन्तु सदा ही आर्थिक समस्याओं से झूँके रहने वाले श्रमिकवर्ग को किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ी । बलकों और अधिवारियों (clerks and officials) की अपेक्षा श्रमिक के वेतन का बढ़ी हुई कीमतों के साथ समायोजन (adjustment) अधिक शीघ्रता से कर दिया गया था । अपनी बचत से वंचित हो जाने पर मध्यमवर्ग को सर्वहारावर्ग (proletariat) की कोटि में आना पड़ा और दारिद्र्य होने के सभी अपमान भी सहने पड़े । उसे उस श्रमिक वर्ग से घृणा थी जिसके स्तर पर उसे उतर आना पड़ा था । इसके साथ ही यहूदियों से भी उसे नफरत थी क्योंकि वह उन्हें मुद्रास्फीति से मुनाफाखोरी करने वाले (कई मामलों में तो गलती से)

मानता था। इसी हतबल और घबनल (dispossessed and degraded) मध्यमवर्ग से राष्ट्रीय समाजवाद (national socialism) की किसी दिन सबसे अधिक अनुयायी मिलने थे।

जो भी हो, रूर पर अधिकार जिसने कि जर्मनी को बिलकुल मिटा दिया, योरोप के युद्धोत्तर इतिहास में एक नया मोड़ था। सितम्बर १९२३ तक, जर्मन विरोध की कमर टूट गई। इसी समय बर्लिन में एक नए गन्निमटल का निर्माण हुआ था। विदेशों में अभी तक अविश्यात गुस्टव स्ट्रेसमान (Gustav Stresemann) नामक एक राजनीतिज्ञ उसने प्रधानमन्त्री (Chancellor) और विदेशमन्त्री बना। जर्मनों के “निष्क्रिय-प्रतिरोध” (सत्याग्रह) को समाप्त करने का भार स्ट्रेसमान पर ही आया। किन्तु प्रतिरोध वापन ल लेने से ही मित्र-राष्ट्र सरकारों की समस्याएँ हल नहीं हो सकीं। किन्तु बड़े पैमाने पर क्षतिपूर्ति युगतान पुनः प्रारम्भ करने से पहिले, जर्मनों की अर्थव्यवस्था में घामूल-पूल परिवर्तन करना स्पष्ट रूप से आवश्यक था। इस वर्ष के अन्त में अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया कि वह ब्रिटिश, फ्रान्सीसी, बेल्जियम और इटालियन सरकारों की सहायता “विशेषज्ञों” की एक समिति नियुक्त करने में करेगा जो कि केवल व्यापारिक और भराजर्नलिक दृष्टिकोण से, इस बात पर विचार करेगी कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कौन से अर्थोपाय (ways and means) काम में लाए जायें। फ्रांस की भावनाओं को ठेक न पहुँचाने की दृष्टि से, समिति के निर्देश-शर्तों (terms of reference) में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि समिति को इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि जर्मनी क्षतिपूर्ति की रकम किस सीमा तक चुका सकता है। किन्तु यह सभी जानते थे कि असली उद्देश्य क्या था। अभीसी “वेविस” डेविस (Dawes) इस समिति का अध्यक्ष था, इस कारण यह समिति “डेविस समिति” (Dawes Committee) के नाम से विख्यात हुई। समिति ने अपना काम जनवरी १९२४ से पेरिस में प्रारम्भ किया।

जर्मनों के विदेशमन्त्री पद पर स्ट्रेसमान (उसने अभी ही प्रधानमन्त्री पद छोड़ दिया और अपना पूरा समय विदेशी मामलों में लगाया) की नियुक्ति और डेविस समिति का गठन उन तीन घटनाओं में से दो घटनाएँ थी जिन्होंने कि हृदय परिवर्तन (change of spirit) की पूर्व सूचना दी। तीसरी घटना

फ्रांस में घटी। वहाँ की जनता भी यह अनुभव कर चुकी थी कि रूर पर अधिकार एक खर्चीली भूल थी और जर्मनी का दिवाला निकलने का मतलब था “उत्पादक गारन्टियो” की नीति का भी बिलकुल असफल हो जाना। स्वयं फ्रांस में भी अधिक सकट की आशंका थी। इसलिए जर्मनी से क्षतिपूर्ति की पर्याप्त रकम की उसे इस समय सबसे अधिक आवश्यकता थी। अतः स्पष्ट था कि इस रकम को वसूल करने का और कोई तरीका अपनाया जाये। मई १९२४ में फ्रांस में जो चुनाव हुए, उनमें वामपक्षियों (leftists) की विजय हुई। पोंकारे मन्त्रीमंडल गिर गया और उसका स्थान हैरियत (Harriot) के उग्र मन्त्रीमंडल (radical ministry) ने लिया। इस घटना की तारीख—११ मई १९२४—को शक्ति द्वारा शांति स्थापित करने (establishing peace by force) के प्रयत्नों की प्रथम पुख्तार अवधि भी समाप्त हो गई—ऐसा माना जा सकता है। कुछ फ्रांसीसियों ने बाद में इस बात पर दुःख भी प्रकट किया कि किसी भी कीमत पर संधि को लागू करने की पोंकारे की नीति को हमेशा के लिए तिलाजलि दे दी गई। किन्तु १९२४ में यह सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया था कि वह नीति असफल रही थी और यदि उसी का अनुसरण किया गया होता तो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में खुली टक्कर हो गई होती।

३. योरोप के अन्य विद्रोम केन्द्र (Other Storm-Centers in Europe)

योरोपीय रगमच के केन्द्रबिन्दु पर जिस समय फ्रांस और जर्मनी के बीच द्वन्द्व युद्ध चल रहा था, उस समय उसी के पार्श्व में अन्य संघर्ष भी चल रहे थे जिनका इस मुख्य विवाद से या तो संबंध ही नहीं था या तो बहुत कम। इन्हें तीन शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है— डेन्यूबीय राज्य, इटली, और सोवियत राज्य।

डेन्यूबीय राज्य (The Danubian States)

मध्य योरोप, जिसे मध्य डेन्यूब का नदी क्षेत्र (basin) कहना ही अधिक उपयुक्त होगा, में १९१४ से पहिले ५५,०००,००० जनसंख्या वाला एक विविध जातियों से गठित ऑस्ट्रिया-हंगरी नामक राज्य था जिने रुमानिया का छोटा-सा राज्य काले सागर (Black Sea) तक पृथक् करता था। युद्ध के बाद डेन्यूब नदी क्षेत्र में पाँच राज्य हो गये—(जनसंख्या के क्रमानुसार) यूगोस्लाविया, रुमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, और ऑस्ट्रिया। इस प्रांतिकी पुनर्व्यवस्था का परिणाम खुली नाकियों (customs barriers) में वृद्धि और प्राथमिक जीवन का असन्-व्यस्त हो जाना (dislocation) हुआ जिससे डेन्यूबीय देश पूरी तरह बर्बाद भी मुक्ति नहीं पा सके। सन् १९२०-२४ की अवधि में, इस उपल-पुषल के भयकरतम परिणामों से यूगोस्लाविया, रुमानिया और चेकोस्लावकिया को फ्रांस के संरक्षण ने ही बचाया। यह फ्रांसीसी शास्त्रास्त्री और प्राचीनी श्रृंग का ही परिणाम था कि वे इस काल में अपेक्षाकृत गठि-शाला और समृद्धि रह सके। लघु मंत्रिसंघ (Little Entente) बनाने वाले इन राज्यों का अर्थन पहिले अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ डेन्यूबीय नदी क्षेत्र के दो भुतपूर्व शत्रु राष्ट्रों—ऑस्ट्रिया और हंगरी—का हा कुछ वर्णन देना अपेक्षित है।

ऑस्ट्रिया गणतन्त्र का प्रारम्भ से ही इतना कृत्रिम स्वरूप था कि उसका स्थायी अस्तित्व ही संदेहास्पद था। उसमें न तो राष्ट्रीय एकता थी और न ही अस्तित्व में बने रहने की राष्ट्रीय आकांक्षा ही। उनकी आवादी प्राचीन ऑस्ट्र-

यन् साम्राज्य के जर्मन-भाषी लोगों की थी। किन्तु इन जर्मन लोगों की जो कि विएना के बहुभाषा भाषी (polygot) हेप्सबर्ग (Hapsburg) साम्राज्य की राजधानी रहने तक हेप्सबर्गों की निष्ठावान प्रजा रह चुके थे, यह इच्छा कभी भी नहीं थी कि जर्मन-ऑस्ट्रिया एक छोटे-से स्वतन्त्र राज्य के रूप में गठित हो जाये। यह नया गणतन्त्र दो भागों में विभाजित था। एक तो उसकी अति-वर्धित (overgrown) राजधानी जिसमें इस गणतन्त्र की लगभग एक तिहाई जनसंख्या, जो कि प्रमुखतया समाजवादी और धर्मविरोधी रहती थी। उसका दूसरा भाग कट्टर रोमन कैथोलिक ग्राम क्षेत्र था जिसमें कुछ प्रांतीय नगर भी थे किन्तु ये नगर विएना का अनुसरण ही अधिक करते थे। ऑस्ट्रिया की शक्ति केवल इसी बात में थी कि उसके लगभग सभी निवासियों की यह आकांक्षा थी कि ऑस्ट्रिया जर्मनी में मिल जाये। उनकी यह आकांक्षा समय समय पर लिए गए अनधिकृत (unofficial) "जनमतों" (plebiscite) के परिणामों में भी व्यक्त हो जाती थी। किन्तु मित्र-राष्ट्रों के लिए यह बात एक मौन घमकी ही थी। चूंकि मित्र-राष्ट्र (विशेषकर फ्रांस और इटली) इस बात के लिए कुनसकल्प थे कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी को सध नहीं बनाने दिया जाये, अतएव उनके लिए यह आवश्यक था कि वे स्वतन्त्र ऑस्ट्रिया को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रलोभन दें।

इस प्रकार मित्र-राष्ट्रों की नीति के परिणामस्वरूप, न कि उनकी अनुकंपा के कारण, ऑस्ट्रिया मित्र-राष्ट्र सरकारों का निवृत्ति वेतन भोगी (pensioner)^१ हो गया। सर्वप्रथम, एक अन्तर्राष्ट्रीय राहत समिति (International Relief Committee) की स्थापना की गई जिसने सदस्य देशों से सहयोग माँगा गया था; और ऑस्ट्रियन क्षतिपूर्ति आयोग ने सेन्ट जर्मेन संधि द्वारा उसे प्रदत्त "ऑस्ट्रिया की सभी आस्तियों और राजस्व पर प्रथम श्रृण-भार (first charge on all assets and revenues of Austria)" लेना त्याग दिया ताकि इन आस्तियों (security) पर "राहत श्रृणपत्र" ("relief bonds") जारी किए जा सकें। सन् १९१६ और १९२१ के बीच ऑस्ट्रियन सरकार को "राहत श्रृण" (relief credit) के रूप में लगभग २५,०००,००० पाउंड प्राप्त

1. "It was therefore, policy rather than pity which made Austria the pensioner of the Allied Governments."

हुए। तदनन्तर, मित्र-राष्ट्र सरकारें इस सारे मामले को राष्ट्रसंघ में भेजना चाहती थी। ऑस्ट्रिया को कुछ महोनों तक और कर्ज युक्त (to keep afloat) रखने के लिए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और चेकोस्लोवाकिया की सरकारों ने उसे काफी रकम और प्रग्रिम (advance) धन दिया। उसके बाद राष्ट्रसंघ की प्रथम-समिति ने ऑस्ट्रिया के आर्थिक पुनर्निर्माण, उसकी मुद्रा की स्थिरता और एक अन्तर्राष्ट्रीय ऋण जारी करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जिसे अक्टूबर १९२२ में ऑस्ट्रिया की सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। ऋण पूर्वपत्र (protocol) में एक महत्वपूर्ण राजनैतिक शर्त का समावेश था। ऑस्ट्रिया ने सेंट जर्मेन सन्धि के अन्तर्गत अपनी इस बाध्यता (obligation) को न केवल दोहराया कि वह राष्ट्रसंघ-परिषद् की स्वीकृति के बिना "अपनी स्वतन्त्रता का परकीकरण (alienation)" नहीं करेगा अपितु यह बचन भी दिया कि उसकी स्वतन्त्रता का किसी भी प्रकार का सौदा करने वाले किसी भी अन्य राष्ट्र से वह आर्थिक समझौते नहीं करेगा। इन पूर्वपत्र के आधार पर १९२३ के दसत में ऑस्ट्रिया ने इस राष्ट्रों को विनियोजक जनता (investing public) से केवल ३०,०००,००० पौंड ऋण मांगा। ब्रिटिश, फ्रांसीसी, इटालियन, चेकोस्लोवाक और कुछ तटस्थ सरकारों ने कुछ अनुपातों में इस ऋण की गारंटी दी थी और सर्वत्र ही उसमें बहुत अधिक रकम प्राप्त हुई। इस अपूर्व सफलता से न केवल ऑस्ट्रिया की ही समस्या अनेक वर्षों के लिए हल हो गई अपितु उन अन्य यूरोपीय देशों को ऋण दिए जाने के लिए, उसने एक पूर्वोन्मूलन (precedent) को प्रस्तुत कर दिया जिन्होंने कि आगे चलकर राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में ऋण लिये।

ऑस्ट्रिया की अपेक्षा हंगरी मजे में रहा। युद्ध-पूर्व की अपनी लगभग आधी आबादी और आधे से भी अधिक क्षेत्र से वह हाथ धो बैठा था। किन्तु एक प्रकार से यह बात उसकी शक्ति का स्रोत ही थी क्योंकि अब उसके क्षेत्र में अनिच्छावान विद्रोही लोग (disaffected subjects of alien race) नहीं रह गये थे। आर्थिक दृष्टि से हंगरी एक घनी कृषक देश था जिसकी शहरी आबादी अनुपात से अधिक नहीं थी। राजनैतिक दृष्टि से, वहाँ प्रजातन्त्र के कई स्वरूप अपनाये गए थे। किन्तु वास्तविक शक्ति छोटे और बड़े जमींदारों के एक शासक वर्ग के हाथों में थी, जिसने उना और प्रजासैन दोनों ही पर अपना

अधिकार जमा रखा था। किन्तु हंगरी के किसान की स्थिति योरोप के किसी भी आधुनिक राज्य के किसान की अपेक्षा खराब थी, वह लगभग दासता का जीवन व्यतीत कर रहा था। हंगरी के श्रमिक संख्या में कम और असंगठित थे। सन् १६१६ में निष्फल (abortive) रैम्युनिस्ट क्रांति के बाद, जब कि बुडापेस्ट लगभग पाँच महीनों तक बेला कुन (Bela Kun) के अधिकार में रहा, हंगरी में किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी प्रचार का कठोरतापूर्वक दमन किया जाता था।

अपने पर लादी गई सधि की शर्तों का विरोध करने और मौका मिलते ही सनसे विमुख हो जाने के लिए हृदयकल्प रहन में, शांति समझौते के समय से ही जर्मनी के बाद हंगरी का दूसरा स्थान रहा था। यह संकल्प चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और यूगोस्लाविया—जिन्हें कि ट्रिएनॉ की सधि के अनुसार हंगरी का कुछ क्षेत्र प्राप्त हुआ था—के लिए भय का कारण बन गया और इसी कारण जैसाकि हम पहिल बता चुके हैं लघु मंत्रीसभ का निर्माण हुआ। किन्तु लघु मंत्रीसभ ने राज्यों को एक और बात का भय लगा रहना था। नवम्बर १९१८ में अन्तिम हप्सबर्ग राजा, कार्ल चतुर्थ (Karl IV), द्वारा सिंहासन त्याग कर दिए जाने के बाद भी, अपने राजा के प्रति हंगेरियन जनता की परंपरागत निष्ठा नष्ट नहीं हुई थी। हंगरी के नए संविधान का स्वरूप राजतंत्रीय था और राज्य के प्रमुख की राजप्रशासक (Regent) कहा गया था जिसका गर्भितार्थ यह था कि भविष्य में राजतंत्र के पुन स्थापित हो सकने की संभावना थी। इसके विपरीत, यह भी विश्वास किया जाता था कि स्लोवाकिया, ट्रांसिलवानिया और क्रोएशिया के समर्पित क्षेत्रों (ceded territories) की जनता अपने भूत-पूर्व हंगेरियन शासकों से चाहे असंतुष्ट क्यों न रही हो किन्तु हेप्सबर्ग राजवंश के प्रति उसके मन में कुछ निष्ठा अवश्य बाँची है। इसीलिए लघु मंत्रीसभ की सरकारों को यह भय था कि हंगरी में हेप्सबर्ग राजवंश यदि पुन सिंहासना रुढ़ हो गया, तो यह बात उनकी नई प्रजा में अशांति उत्पन्न करने का एक संभाव्य कारण बन जाएगी।

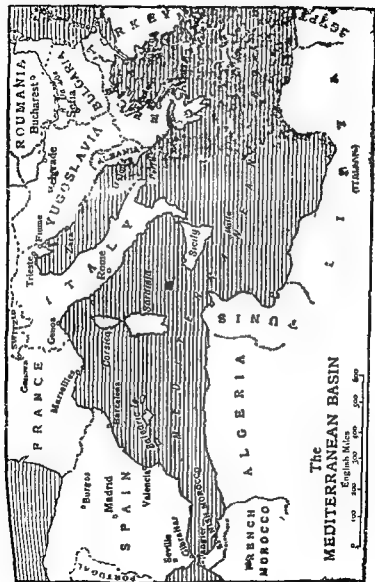
लघु मंत्रीसभ देशों का असंतोषित होना बिल्कुल निराधार भी नहीं था। हंगरी के अपने सिंहासन पर पुन अधिकार करने के लिए भाबुक और बहकाए गए कार्ल ने १९२१ में दो बार प्रयत्न किए। स्विट्जरलैंड स्थित अपने निवास-स्थान से वह हर बार बिना किसी घोषणा के यह सोचकर हंगरी चला जाता

कि सारा हगरी उसका साथ देया। वास्तव में हगरी की सरकार लघु मंत्रीसभ के देशों से युद्ध मोल लेने की स्थिति में नहीं थी। क्योंकि हेन्सबग राजा के पुनः सिंहासनाखंड होने से युद्ध होकर ही रहना। इसलिए हगरी म कार्ल की उपस्थिति से वह बड़ी मुसीबत में पड़ गई। पहिली बार तो उगने कार्ल को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह हगरी छोड़कर चुपचाप चला जाएगा। किन्तु दूसरी बार उसने उसे गिरफ्तार कर मित्र-राष्ट्रों को सौंप दिया। कार्ल की मेदारा (Madeira) भेज दिया गया जहाँकि उसने अपना संप जीवन बिताया। मित्र-राष्ट्रों के दबाव के कारण, हगरी सरकार को बाध्य होकर एक शान्ति बनाना पड़ा जिसके अनुसार हेन्सबग राजवंश के लोग हगरी के सिंहासन से सदा के लिए वंचित कर दिए गये। कार्ल की मनको का बचत यही परिणाम हुआ कि लघु मंत्रीसभ के देशों ने अपनी शक्ति और सगठन का आश्चर्यजनक प्रदर्शन कर दिखाया। छ माह के बाद मेदोरा में ही कार्ल की मृत्यु हो गई और आर्कड्युक आटो (Archduke Otto) नामक एक नौ वर्षीय उत्तराधिकारी वह अपने पीछे छोड़ गया। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि हेन्सबग राजवंश सबधी प्रश्न अनेक वर्षों तक मध्य यूरोप को परेशान नहीं करेगा।

आर्थिक पुनर्गठन के लिए अब रास्ता साफ हो चुका था। आस्ट्रिया की राष्ट्रसभ श्रृंखला की सफलता से यह विचार उत्पन्न हुआ कि इसी प्रकार की सहायता हगरी को भी दी जाये। हगरी की आर्थिक स्थिति यद्यपि आस्ट्रिया के समान भयंकर नहीं थी, तथापि, युद्ध और क्रांति के कारण, अस्तव्यस्त अवस्था हो गई थी। राष्ट्रसभ की सभ्य समिति (The Financial Committee) ने १९२३ में पुनर्निर्माण की एक योजना तैयार की, और आगामी वर्ष के बसंत में मांड देखा की योजना से १२,०००,००० पाँड खर्च प्राप्त कर लेने में हगरी की सफलता भा मिल गई। आस्ट्रियन श्रृंखला और इस श्रृंखला में एक महत्त्वपूर्ण अंगर था। हंगेरियन श्रृंखला की कोई अन्तर्राष्ट्रीय गारंटी नहीं थी बल्कि हगरी सरकार की शान (credit) ही उसकी एकमात्र प्रतिभूति (security) थी।

इटली (Italy)

इंग्ली जन पाँच "प्रमुख मित्र और साथी राष्ट्रों" में से एक था जिन्होंने सन्धि की शर्तें निर्धारित की थी। किन्तु जापान की तरह युद्ध के परिणामों ने उसकी कृष्ण बुझी नहीं, बल्कि बढ गई। युद्ध के बाद की पुरी अवधि में इटली



की गणना जापान और मृतपूर्व दशु देशों की भाँति “असन्तुष्ट” और “कष्ट-दायी” राज्यों (“discontented and troublesome states”) में की जानी चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में यह असन्तोष इतना अशांतिकारक हो गया कि उसके कारणों पर यहाँ कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है।

प्रथमतः, जर्मनी के समान इटली का वर्तमान राजनैतिक स्वरूप १८७० में स्थिर हुआ था। सन् १८४८ में, इटली प्रायद्वीप आठ विभिन्न राज्यों में बँटा हुआ था और इटली को एकता कुछ उत्साही लोगों का स्वप्नमात्र थी। यहाँ तक कि १९२०-२६ में भी, वह अपनी उद्वेग और साहमपूर्ण युवावस्था को पार ही कर रहा था। इसलिए पुराने राष्ट्रों की सम्माननीय और शान्तिमय परम्पराएँ उनमें अभी तक नहीं आ पाई थी। उसे यह स्मरण था कि उसने अपनी एकता लड़कर प्राप्त की है, इसलिए अपनी शक्ति और सौँच का विस्तार करने के लिए वह अब भी युद्ध का आश्रय लेना ही उचित समझता था। यदि यह पूछा जाए कि अन्य बड़े राष्ट्रों की अपेक्षा इटली की निष्ठा राष्ट्रसंघ में क्यों कम थी तो उसका एक उत्तर यह होगा कि यदि राष्ट्रसंघ उत्तरीय शताब्दी में ही अस्तित्व में आ गया होता और यदि उस समय उसके अनुबन्धन पत्र का पालन किया गया होता, तो इटली कभी भी एक राष्ट्र (nation) नहीं हो सकता था।

द्वितीयतः, इटली के असन्तोष के कुछ विशेष कारण भी थे। सन् १९१५ में जब इटली मित्र-राष्ट्रों में शामिल हुआ था, तब ही उसने अपना पुरस्कार ठहरा लिया था। गुप्त क़ूब से की गई लंदन सन्धि (Treaty of London) के अनुसार यह समझौता किया गया था कि शान्ति समझौते के समय इटली को आस्ट्रिया से दक्षिण टायरोल (South Tyrol), जिसकी आबादी जर्मन थी, और ट्रिस्ट (Trieste), तथा उसकी पार्श्वभूमि एवं डलमेसियन किनारा जिनके (ट्रिस्ट नगर को छोड़कर) निवासी मुख्यतः स्लाव थे, मिलेंगे। यह सौदा (bargain) आत्म-निर्णय के उस सिद्धान्त की अमान्य करने का एक निदास्पद प्रयास था जिसे अमरीकी राष्ट्रपति विलसन ने प्रतिपादित किया था और अन्य मित्र-राष्ट्रों ने १९१८ में शान्ति समझौते के आधार के रूप में स्वीकार कर लिया था। विलसन ने इस गुप्त लंदन-सन्धि को मानने से इकार कर दिया। विलसन के सिद्धान्तों और अपने हस्ताक्षरों के प्रति निष्ठा के प्रश्न को लेकर फ्रान्स और

ग्रेट ब्रिटेन में मतभेद हो गया। इस प्रश्न को लेकर शान्ति सम्मेलन में खूब झड़प (altercation) भी हुई। विलसन ने दक्षिणी टायरोल सम्बन्धी अपनी जिद छोड़ दी, क्योंकि उससे सम्बन्धित सौदा एक शत्रु की बलि चढ़ाते हुए किया गया था। किन्तु जब नवगठित यूगोस्लाव राज्य प्रनिहन्दी दावेदार (claimant) के रूप में सामने आया, तब विलसन उस से मस नहीं हुये। इटली ने फ़िूम (Fiume) को भी अपने दावे में शामिल कर अपने पैरो पर कुल्हाड़ी मारली क्योंकि लंदन-संधि के द्वारा उसे फ़िूम भी दिए जाने का वचन नहीं दिया गया था। सितम्बर १९१६ में इटली के इस दावे को जब पेरिस में अस्वीकार कर दिया गया, तब एक गैर-सरकारी इटालियन सेना ने कवि द'अनुन्जियो (D'Annunzio) के नेतृत्व में किन्तु इटालियन सरकार की मौन उपेक्षा (tacit connivance) से उत्साहित हो, फ़िूम पर अधिकार कर लिया। सन् १९२० के प्रारम्भ में, मित्र-राष्ट्रों ने संपूर्ण सीमान्त विवाद से अपने हाथ खींच लिये और यूगोस्लाविया तथा इटली को आपस में निपट लने के लिए छोड़ दिया। वार्ताएं कई वर्षों तक चलती रही और उनमें कई दौर घाये। यूगोस्लाविया का समर्थन कर फ्रान्स ने इटली से तीव्र शत्रुता मोल ले ली। आखिर १९२४ में जाकर वही अन्तिम समझौता हो सका। इटली ने जारा (Zara) बन्दरगाह को छोड़कर सम्पूर्ण डलमेशियन किनारा यूगोस्लाविया को दे दिया किन्तु और बाकी स्थानों में, उमें लंदन-संधि से भी अधिक अनुकूल शर्तें मिली जिनमें फ़िूम नगर पर अधिकार भी शामिल था।

इसी बीच, इटली और यूगोस्लाविया, जिनके सम्बन्ध इस समय तक अत्यन्त कटु हो चुके थे, को अलबानिया के प्रश्न के रूप में भगड़े की एक और जड़ मिल गई। सन् १९१३ में, अलबानिया (Albania) को एक स्वतन्त्र राज्य मान लिया गया था। किन्तु युद्धकाल में उसकी स्थिति बिल्कुल अ-यथस्थित हो गई। लंदन सन्धि के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि इटली को वेलोना (Valona) बन्दरगाह मिलेगा तथा इटली ही अलबानिया के विदेश-सम्बन्धों का भार भी सम्भालेगा। युद्ध समाप्ति के बाद, लगभग सम्पूर्ण देश पर इटालियन सेना का अधिकार था। इटालियन सेना अपना अधिकार कायम नहीं रख सकी क्योंकि स्वयं अलबानिया निवासियों ने और यूगोस्लाविया वालों ने, जोकि एड्रियाटिक के पूर्वी किनारे पर इटालियन सेना को अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क मानते थे, इसका विरोध किया। सन् १९२० में, इटालियन सेना हटा ली गई

और अलबानिया को एक स्वतन्त्र राज्य की हैसियत से राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया।

फिर भी, एक नाजुक प्रश्न का निवारण बाकी रह गया था। इटली ने यह दावा किया कि लंदन-सन्धि के अन्तर्गत अपने अधिकारों का परिष्कार (abandonment) करने के बदले में, मित्र-राष्ट्र अलबानिया के मामलों में इटली की "विशेष स्थिति" ("special status") को मान्य करें। नवम्बर १९२१ में पेरिस राजदूत सम्मेलन (Ambassadors' Conference), जिसने कि मित्र-राष्ट्र सरकारों के प्रमुख अंग के रूप में सर्वोच्च परिषद् का स्थान ले लिया था, ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर यह घोषणा की कि यदि अलबानिया की स्वतन्त्रता की किसी प्रकार का खतरा उपस्थित हुआ तो ब्रिटेन, फ्रान्स और जापान की सरकारें राष्ट्रसंघ परिषद् में अपने प्रतिनिधियों की यह हिदायत देंगी कि वे इस आशय का एक प्रस्ताव परिषद् में पेश करें कि अलबानिया की स्वतन्त्रता की रक्षा करने का काम इटली को सौंपा जाये। व्यवहार रूप में इस प्रस्ताव का कोई भी तात्कालिक उपयोग नहीं हो सकता था। और यदि सब पूछा जाए तो इस तरह का प्रस्ताव कुछ बेनुकी बात (absurdity) थी क्योंकि अलबानिया की स्वतन्त्रता को यदि किसी राष्ट्र से खतरा था भी, तो केवल इटली से ही। किन्तु इटली ने इसका यह अर्थ लगाया कि अलबानिया के मामलों में हस्तक्षेप कर सकने का उसका अधिकार मान लिया गया है और यह अधिकार उसके सिवाय अन्य किसी भी राष्ट्र को नहीं है। इटली का यह दावा यूगोस्लाविया के लिए सतत आशंका और चिड़ का कारण बन गया।

लंदन सन्धि के एक तीसरे अनुच्छेद ने इटली के असन्तोष को और भी बढ़ा दिया तथा उसमें इस भावना को घर करने दिया कि मित्र-राष्ट्र उसके साथ व्यापारिक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस अनुच्छेद में यह उपबन्धित किया गया था कि यदि जर्मनी को हानि में डालते हुए थ्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स अपनी अपना औपनिवेशिक क्षेत्र बढ़ावें तो इटली की "न्याय्य क्षतिपूर्ति" ("equitable compensation") की जाएगी जो कि इटली के वर्तमान अफ्रीकी उप-के सीमाओं और उनसे लगे हुए थ्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स के उपनिवेशों का उपयुक्त समायोजन कर देने के रूप में होगी। यह वचन इतना

था कि उसके कई अर्थ निवाले जा सकते थे। सन् १९२४ में जाकर कही इटली और ग्रेट ब्रिटेन में समझौता हो सका। इस वचन को पूरा करने के लिए ब्रिटिश उपनिवेश केनिया का जुबालैंड (Jubaland) क्षेत्र इटली के सोमालि-लैंड (Somaliland) क्षेत्र में मिला दिया गया। इटली और फ्रान्स में समझौता हो सकना और भी कठिन सिद्ध हुआ। सन् १९१६ में उत्तरी अफ्रीका में सीमान्त-परिवर्तन किए जाने के वाद भी, इस अनुच्छेद के अन्तर्गत इटली के लम्बे-चौड़े दावों को पूरा नहीं किया जा सका। इटली को यह शिकायत १९३५ तक बनी रही और उसके कारण फ्रान्स तथा इटली के सम्बन्ध और भी कटुता-पूर्ण हो गये।

अक्टूबर १९२२ में, जब कि इटली और यूगोस्लाविया का सीमान्त निश्चित भी नहीं हो पाया था, इटली की शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। वहाँ की प्रजातन्त्र सरकार को, जो कि आन्तरिक व्यवस्था बनाए रखने में निर्बल होने के कारण अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी थी, फासिस्ट पार्टी ने उलट दिया और इटली में २० से अधिक वर्षों के लिए बेनिटो मुसोलिनी (Benito Mussolini) नामक फासिस्ट नेता की व्यक्तिगत तानाशाही स्थापित हो गई। इस घटना के दो प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिप्रभाव (repercussions) हुये। एक तो योरोप के अन्य कई राज्यों में भी शीघ्र ही प्रजातन्त्र के स्थान में ताना-शाही की स्थापना की गई। इस प्रकार के राज्यों में स्पेन सर्वप्रथम था। दूसरे, मुसोलिनी के सत्तारूढ़ होने से, इटली की विदेश नीति और भी घातमण्डात्मक होगी—इसका आभास मिल गया। मुद्रोत्तर प्रजातन्त्र काल में, इटली की नीति में अशांतिपूर्ण असंतोष स्पष्ट परिलक्षित होता था। मुसोलिनी के हाथों में सत्ता आने पर, यह असंतोष अधिक महत्वाकांक्षी, अधिक अहंकारी तथा अन्य राष्ट्र की विवशनाओं और कठिनाइयों से लाम उठाकर इटली का हितसाधन करने के लिए अधिक दृढसंकल्प हो गया।

मुसोलिनी ने योरोप को शीघ्र ही अपनी शक्ति का परिचय दे दिया। अल-बानिया और यूनान का सीमांत निश्चित करने में व्यस्त आयोग के इटालियन प्रतिनिधि और उसके तीन सहायकों को अगस्त १९२३ में यूनानी डाकुओं ने गोली से उड़ा दिया। इस पर इटली के बेड़े ने तुरन्त ही कोर्फु (Corfu) पर बम वर्षा कर दी, कई नागरिकों के प्राण ले लिये और द्वीप पर अधिकार कर

क्षतिपूर्ति की माँग की—इस माँग का पेरिस राजदूत सम्मेलन ने भी समर्थन किया था। वेनिजेलोस के पतन के बाद से, यूरोप में मित्रहीन यूनान ने एकदम भयभीत होकर राष्ट्रसंघ और राजदूत सम्मेलन दोनों ही से अपील की। प्राधिकार (authority) के इस विभाजन से लाभ उठाकर मुसोलिनी ने यह घोषणा कर दी कि वह राष्ट्रसंघ के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) को नहीं मानेगा। अन्त में, निजी वार्ताओं के परिणामस्वरूप, एक समझौता हुआ जिसके अनुसार यूनान ने यह स्वीकार कर लिया कि इटली के दावे की वैधता (validity) का निर्णय होने तक वह हेग (Hague) स्थित अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice) में ५०,०००,००० लायर (lire) जमा रलेगा। किन्तु ऐन मौके पर, इटली ने इस समाधान को भी प्रस्वीकार कर दिया। अन्त में राजदूत सम्मेलन के दबाव के कारण, यूनान की क्षतिपूर्ति की रकम सीधी ही इटली को दे देनी पड़ी।

सोवियत संघ

(The Soviet Union)

सन् १९१८ के बाद के वर्षों में, सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ (Union of Soviet Socialist Republics)—पहिले रूस के नाम से नात इस देश का यह नाम सरकारी तौर पर १९२३ में रखा गया था—की गणना यूरोपीय राजनीति में विद्रोहकारी शक्तियों (disturbing forces) में की जानी चाहिये यद्यपि इसके कारण एकदम भिन्न हैं। रूस के उस गृहयुद्ध (civil war) का अन्त १९२० से पहिले नहीं हो सका था जिसमें कि सोवियत विरोधी ताकतों को ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और (कुछ समय तक) अमेरिका की सरकारों से सन्निध्य सहायता मिली थी। सोवियत सरकार और मित्र-राष्ट्रों के सम्बन्ध उसके बाद भी कई वर्षों तक आपसी अविश्वास और शत्रुतापूर्ण ही बने रहे। यह शत्रुता स्वाभाविक और अवश्यम्भावी थी। धर्मसुधार के बाद से, यूरोप के राज्य स्वयं अपने को और अन्य राज्यों को असह्य और स्वतन्त्र राष्ट्र मानते थे। दूसरे राज्य की जनता में असंतोष फैलाकर किसी राज्य की सुरक्षा सतरे में डालना युद्ध-काल में इष्टकर (expedient) हो सकता था, किन्तु सामान्य सम्बन्धों के समय ऐसा करना एकदम गलत बात थी। सोवियत सिद्धान्त ने इन मूलभूत धारणाओं को साहसपूर्वक एक ओर रख दिया। उसने इस बात से

भी इन्कार किया कि सोवियत संघ एक राष्ट्रीय इकाई (national unit) है। राज्य को वह राजनैतिक संगठन का एक अस्थायी रूप मानता था जिसका मेल कम्युनिस्ट आदर्श की प्राप्ति के साथ नहीं बैठता था। उसके अनुसार हर सच्चे कम्युनिस्ट का यह कर्तव्य था कि वह सारे विश्व में उस क्रांति का प्रचार करे जो कि रूस में सफल हो चुकी थी और, चूँकि सोवियत संघ के प्रारम्भिक दिनों के नेताओं का यह विश्वास था कि शेष संसार में भी पूँजीवाद की समाप्ति हुए बिना रूस की अतिकारी सरकार टिक नहीं सकेगी, इसलिए उनके प्रचार-कोषित उत्साह (missionary zeal) में स्वार्थ की भी कुछ बू भाती थी।

जो भी हो, जब तक पूँजीवादी राज्य अस्तित्व में बने रहें, तब तक व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक तो था ही कि सोवियत संघ और इन देशों में किसी न किसी प्रकार के सम्बन्ध स्थापित हो। एक ओर जहाँ अन्तर्राष्ट्रिक कम्युनिस्ट संस्था (Communist International) [संक्षिप्त नाम "कॉमिन्टर्न" (Comintern)] जिसका मुख्यालय (head quarters) मास्को में था, अपनी स्थानीय शाखाओं की सहायता से अन्य देशों की पूँजीवादी सरकारों को उलट देने का प्रयत्न कर रही थी, वहीं दूसरी ओर सोवियत सरकार, जिसके सचालनकर्त्ता ही कॉमिन्टर्न का भी सलासन करते थे, उन्हीं देशों की सरकारों से सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा कर रही थी। इस दोहरी नीति के कारण इस संपूर्ण अवधि में सोवियत सरकार को विदेशी राष्ट्रों के साथ अपने व्यवहार में बड़ी उत्तमता का सामना करना पड़ा।

प्रारम्भ में, सोवियत संघ अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों से ही कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर सका। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को महत्व नहीं देने सबधी सोवियत सरकार की नेकनीयती (sincerity) का पता इसी बात से लग सकता था कि वह उन नवनिर्मित राज्यों को मान्यता देने के लिए तैयार थी जो रूसी साम्राज्य से भलग हो गये थे। सन् १९२० में उसने फ़िनलैंड (जो रूसी साम्राज्य के अंतर्गत अर्ध-स्वतंत्र ग्रेंड डची रह चुका था) और इस्टोनिया (Estonia), लेटविया (Latvia) तथा लिथुआनिया (Lithuania) (जिसकी भूमि रूस का अखंड भाग रह चुकी थी) से शांति सन्धियाँ कीं। इन सन्धियों के बाद ही अगले वर्ष पोलैंड (देखिए पृष्ठ २५) के साथ सन्धि हुई। किन्तु तीनो कॉन्फ़ेडरेशन

(Caucasian) राज्य—जॉर्जिया (Georgia), अज़रबैजान (Azerbaijan) और आर्मेनिया (Armenia)—घाटे में रहे। चायद जॉर्जिया को छोड़कर इनमें से कोई भी स्वतंत्रता के लक्ष्यों से युक्त नहीं था। मित्र-राष्ट्रों की सेना, जिसके संरक्षण में ये राज्य युद्ध के अन्तिम वर्ष अस्तित्व में आये थे, हटा लेने से उनके भाग्य का सितारा ही अस्त हो गया। उनकी भूमि सोवियत संघ तथा टर्की को वापस मिल गई। सन् १९२१ के प्रारम्भ में, सोवियत संघ ने टर्की, फारस और अफगानिस्तान से मित्रता की संधियाँ की; और कुछ समय तक तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच उन्नीसवीं शताब्दी में एशिया में हुई प्रतिद्वन्द्वता पुनः प्रारम्भ होने की चाली है।

बड़े राष्ट्र सोवियत सरकार से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने से इस समय भी बचना चाहते थे। किन्तु सोवियत संघ (जिसने कि जारकालीन रूस (Tsarist Russia) का कर्ज चुकाने से इन्कार कर दिया था) से व्यापार की समावनाओं की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती थी। सन् १९२१ में ग्रेट ब्रिटेन ने सोवियत सरकार के साथ एक व्यापारिक समझौता किया तथा एक "व्यापारिक मिशन एडल" ("trade mission") मास्को भेजा। इटली ने ग्रेट ब्रिटेन का अनुकरण किया, और अगले वर्ष सोवियत संघ को इतनी मान्यता मिल चुकी थी कि उसे भी राष्ट्र कुटुम्ब का एक सदस्य मान लिया गया था तथा जेनोवा (Genoa) में अप्रैल १९२२ में हुए सभी यूरोपीय देशों के एक आधिकारिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए उसे आमन्त्रित किया गया। इस सम्मेलन में जर्मनी को भी शामिल किया गया था। लॉयड जॉर्ज (Lloyd George) का यह आशा था कि इस सम्मेलन का उपयोग सोवियत संघ और अन्य राष्ट्रों में समझौता करने में किया जा सकेगा। किन्तु फ्रांसीसी और बेल्जियन प्रतिनिधिमण्डलों के दुराग्रह के कारण इस माया पर भी पानी फिर गया। उनकी यह माँग थी कि सोवियत सरकार से किसी भी प्रकार की वार्ता इस शर्त पर चलाई जानी चाहिए कि सोवियत सरकार रूस के शुद्ध-पूर्व कर्ज को चुकाना स्वीकार करे। फलित, इस सम्मेलन का परिणाम कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसके संयोजकों ने न तो आशा की थी और न इच्छा ही थी। सम्मेलन के एक सप्ताह बाद, सोवियत और जर्मन प्रतिनिधिमण्डल जेनोवा (Genoa) से कुछ ही मीलो की दूरी पर स्थित रेपेलो (Rapallo) नामक एक समुद्रतटीय आश्रय स्थान (seaside resort) पर

गुप्त रूप से मिले और उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता की सन्धि करली। सन्धि की शर्तों का इतना महत्त्व नहीं था जितना कि सन्धि होने का। उसके द्वारा सोवियत संघ को एक बड़ राष्ट्र से पहिली बार कूटनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई। इसके साथ ही जर्मनी ने भी वर्सेलोज की सन्धि द्वारा अपने चारो ओर डाले गये घेरे को तोड़ने का प्रथम खुला प्रयास किया। इस सन्धि पर मित्र राष्ट्र देशो ने जो नाराजी प्रकट की थी वह समझ में आ सकती थी। किन्तु यह संधि तो जर्मनी और सोवियत संघ को महत्त्वहीन देश मानने सवधी मित्र राष्ट्र देशो की अपनी नीति का ही सीधा परिणाम थी। स्वाभाविक ही था कि दोनों बहिष्कृत राष्ट्र आपस में गठबन्धन कर लें। रेपेलो सन्धि के कारण इन दोनों देशों के सम्बन्ध इस वर्षों से भी अधिक समय तक मित्रतापूर्ण बने रहे।¹

सोवियत संघ सम्बन्धी ग्रेट ब्रिटन की नीति इस समय दुर्भाग्य से दलगत राजनीति की चोपड़ का मोहरा हा गई। जनोब्रा सम्मेलन के कुछ समय बाद ही, लॉयड जॉन का पतन हुआ जिसका एक कारण यह बताया गया था कि “बोल्शेविकों को रिझाने” (“coquetting the Bolsheviks”) की उसकी नीति के कारण ही उसका पतन हुआ। लॉयड जॉर्ज की सरकार के बाद अनुदार सरकार (Conservative Government) बनी जिसने यह आवश्यक समझा कि इस मामले में और भी बड़ी नीति अपनाई जाये। अनुदार दल की इस नीति की प्रतिक्रियास्वरूप मजदूरवर्गीय सरकार (Labour Government)

- 1 “The terms of the treaty were unimportant. But its signature was a significant event. It secured for the Soviet Union its first official recognition by a Great Power, and it was the first overt attempt by Germany to break the ring which the Versailles Powers had drawn round her. The indignation with which this treaty was greeted by the Allied Powers was understandable. But it was the direct consequence of their own policy of treating Germany and the Soviet Union as inferior countries. The two outcasts naturally joined hands, and the Rapallo Treaty established friendly relations between them for more than ten years.”

ने, जो कि फरवरी १९२४ में सत्ताह्वित हुई, तुरन्त ही सोवियत सरकार को मान्यता दे दो। पूरे ग्रीष्म काल में, लन्दन में बातचीत चलती रही और अगस्त में ब्रिटिश तथा सोवियत प्रतिनिधियों में एक समझौता हो गया जिसके अनुसार एक दूसरे के बकाया दावों (outstanding claims) को रद्द कर देने, तथा सोवियत सरकार को एक गारंटी देने की व्यवस्था की गई।

इसी बीच, सोवियत संघ के प्रति मजदूरदलीय सरकार की नीति की आलोचना को अनुदारदल ने अपने कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग बना लिया। सन् १९२१ के व्यापारिक समझौते की एक धारा के अनुसार सोवियत सरकार ने यह वचन दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी प्रकार का क्रांतिकारी प्रचार नहीं किया जाएगा। न तो अनुदारदलीय और न मजदूरदलीय सरकार ने ही सोवियत सरकार का यह तर्क स्वीकार किया था कि सोवियत सरकार और कॉमिन्टर्न दो अलग-अलग चीजें हैं तथा कॉमिन्टर्न की प्रतिनिधि को इस वचन का भंग नहीं माना जा सकता। सन् १९२४ के ग्रीष्मकाल में अनुदारदल के लोग ब्रिटिश साम्राज्य में कॉमिन्टर्न द्वारा किए जा रहे प्रचार की ओर मजदूरदलीय सरकार का ध्यान बारबार आकर्षित कर उसकी स्थिति खराब करते रहे। अक्टूबर १९२४ में, ग्राम चुनावों के समय एक अनुदार समाचार पत्र ने, कॉमिन्टर्न के अध्यक्ष जिनोविय (Zinoviev) द्वारा सम्भवतः लिखा गया एक पत्र^१ प्रकाशित किया जिसमें ब्रिटिश कम्युनिस्टों को यह बताया गया था कि वे ग्रेट ब्रिटेन में किस प्रकार कम्युनिस्ट प्रचार-कार्य करें। सोवियत सरकार ने पत्र की प्रामाणिकता (authenticity) का दृढ़ विरोध किया। किन्तु यह सामान्यतः विश्वास किया जाता था कि इस पत्र के प्रकाशन के कारण ही अनुदार दल की अधिक बहुमत प्राप्त हुआ। इस घटना और अनुदारदलीय सरकार के पुनः सत्ताह्वित हो जाने के कारण, ग्रीष्मकाल में हुए समझौते का अनुसमर्थन किए जाने की आशाओं पर पानी फिर गया। सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन के सम्बन्धों में एक बार पुनः तनाव आ गया, यद्यपि वे टूटे नहीं।

जो भी हो, यह तनाव सन् १९२४ के अन्त में सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से भिन्न नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा कूटनीतिक मान्यता दिये जाने के

1 What Purported to be a letter from Zinoviev.

बाद, सोवियत संघ को इटली, फ्रांस और जापान तथा योरोप के अधिकांश राज्यों ने मान्यता दे दी थी। किन्तु इस समय अमेरिका ही एक ऐसा राष्ट्र रह गया था जो सोवियत सरकार से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहता था। इधर सोवियत संघ में, जनवरी १९२४ में लेनिन की मृत्यु के बाद से, विश्वक्रांति को पार्टी कार्यक्रम में गौण स्थान देने की प्रवृत्ति स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। “जिनोविएव पत्र” (“Zinoviev letter”) प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सोवियत संघ में हर कोई इस पत्र की प्रामाणिकता को मस्वीकार करना चाहता था। पत्र प्रामाणिक हो या न हो, किन्तु उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि सोवियत नेताओं की अब तक की घोषित नीति (hitherto declared policy) के विरुद्ध हो। ट्रॉट्स्की (Trotsky) और स्टालिन में १९२४ से नेतृत्व के लिए जो संघर्ष प्रारम्भ हुआ, उसका भी विषय यही था। ट्रॉट्स्की इस परम्परागत सिद्धान्त का समर्थन करता था कि पूँजीवादी दुनिया के रहते हुए, सोवियत सरकार अनिश्चित काल तक टिका नहीं रह सकती। इसलिए क्रांति का विस्तार (spread) ही सोवियत गतिविधि का प्रथम उद्देश्य होना चाहिये। किन्तु स्टालिन नई नीति का समर्थक था जो कि “एक ही राज्य में समाजवाद की नींव पक्की करने” (“building up socialism in a single state”) की नीति के नाम से विख्यात हुई। सन् १९२७ में ट्रॉट्स्की को कम्युनिस्ट पार्टी से निवास देने का अर्थ सप्सार में यह घोषणा कर देना था कि नई नीति की विजय हुई है और विश्वक्रांति की आकांक्षाओं, यद्यपि विधिवत् उनका परिहारा नहीं कर दिया गया था, को सोवियत सरकार और पूँजीवादी राज्यों में सामान्य सम्बन्ध स्थापित होने में अविव्य में बाधक नहीं होने दिया जायगा। इस प्रकार सोवियत संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मूलभूत आधार को आखिर स्वीकार कर लिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय राज्य समाज (international community of states) में उसका पूरी तरह पुनः सम्मिलित होना केवल समय का ही प्रश्न रह गया।

द्वितीय भाग

शांतिकरण-काल (The Period of Pacification)

राष्ट्रसंघ (The League of Nations)

(१९२४—१९३०)

४. शांति की नींव

(The Foundations of Peace)

विश्वयुद्धों के बीच क योरोपीय इतिहास व द्वितीय काल—शांतिकरण-काल (period of pacification)—का आरम्भ उन दो समस्याओं के समाधान से हुआ जिन्होंने कि प्रथम काल में सर्वस अधिक बलशे लडे किये थे । ये समस्याएँ क्षतिपूर्ति और फ्रांस को मरुधा से सम्बन्धित थी । सन् १९२४ और १९२५ में इन समस्याओं के जो समाधान—डेविस योजना (Dawes plan) और लोकार्नो (Locarno) संधि—निकाल गये वे अपूर्व, और, जैसा कि हमें विदिम ही है, अल्पकालिक थे । किन्तु आधी दशक (decade) तक उन्हें ही अंतिम माना जाना रहा; और ये वर्ष, अनिश्चितताओं और अपूरणताओं के होने हुए भी, युद्धोत्तर योरोप के स्वर्णम वर्ष (golden years) थे ।

डेविस योजना (The Dawes Plan)

मई ११, १९२४ का फ्रांस में आम चुनाव हुए जिनके परिणामस्वरूप हरियत (Harriot) फ्रांस का प्रधान मंत्री बना । इन चुनावों से कुछ ही समय पूर्व डेविस समिति ने अपना प्रतिवेदन क्षतिपूर्ति आयोग को प्रस्तुत किया था । जर्मनी में, इस समय तक, वहाँ का विदेश मंत्री स्ट्रेसमान राजनीतिक जगत का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति हो चुका था । ग्रेट ब्रिटेन में, रमजे मकडॉनल्ड की मजदूरदलीय सरकार सत्तारुढ थी । अब ये तीनों राजनीतिज्ञ डेविस प्रतिवेदन के आधार पर क्षतिपूर्ति समस्या का हल निकालने में जुट गये ।

डेविस समिति के सामने मुख्य समस्या जर्मन मुद्रा को पुनः स्थिर करने की थी, क्योंकि उसके बिना विदेशों का मुगलान कर सकना जर्मनी के लिए असंभव था । सन् १९२३ की समाप्ति तक, जर्मनी मार्क (सिक्के) का वास्तव में कोई मूल्य ही नहीं रह गया था । जर्मन सरकार ने अस्थायी रूप से एक नई मुद्रा का प्रचलन किया था जो कि रेन्टेनमार्क (Rentenmark) कहलाती थी (यथा जिसकी दर पुराने सिक्के की दर के ही नमान प्रति पौंड २० थी) किन्तु जब तक इस मुद्रा के पीछे स्वर्ण या विदेशी आस्तिगो (foreign assets) की कोई

ठोस कोष (solid reserve) न हो, तब तक रेन्टेनमार्क की स्थिति भी सकट-पूर्ण ही थी। डेविस समिति ने उक्त दर पर ही—रीशमार्क (Reichsmark) नामक एक नई मुद्रा जारी करने की सिफारिश की थी जिसका नियंत्रण एक प्रचलन बैंक (Bank of Issue)—यह बैंक जर्मन सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होनी थी—द्वारा किया जाना था।

यह मानकर कि मुद्रा स्थिर हो जायगी, समिति ने यह नत प्रकट किया था कि क्षतिपूर्ति के प्राथमिक भुगतानों के रूप में, जर्मनी मित्र-राष्ट्रों को ५०,०००,००० पौंड से प्रारम्भ होने वाली वार्षिकियाँ (annuities) चुका सकेगा जोकि पाँचवें वर्ष के बाद से १२५,०००,००० पौंड व प्रामाणिक अधिकतम (standard maximum) तक पहुँच जाएँगी। इन भुगतानों की प्रतिभूति (security) तीन प्रकार की रखी गई थी : सरकारी रेलों के ऋणपत्र (bonds), जर्मन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के ऋणपत्र तथा मद्यसार (alcohol), शक्कर और तम्बाखू पर करों तथा चुगों से राजस्व आय (revenue receipts) (कहो) ये भुगतान विनिमय (exchange) को पुनः अभ्यवस्थित न कर दें, इसलिए यह सुझाव रखा गया था कि जर्मनी द्वारा ये भुगतान मार्कों में किए जायें तथा विदेशी मुद्राओं में इन रकमों का विनिमय कराने का उत्तरदायित्व मित्र-राष्ट्रों की सरकारों का रहे। लेनदारों (creditors) के हित में यह प्रबंध उचित रूप से चलता रहे, इसके लिए क्षतिपूर्ति प्रायोग को यह अधिकार दिया गया था कि वह प्रचलन-बैंक के बोर्ड, रेलों और “नियंत्रित राजस्व” (“controlled revenue”) [अर्थात् विशेषांकित कर आय (earmarked tax receipts)] के प्रबन्धक मंडल में मित्र-राष्ट्रीय आयुक्त (Allied Commissioners) नियुक्त कर सकेगा। इसके साथ ही संपूर्ण योजना का भार एक “क्षतिपूर्ति भुगतान अभिकर्ता (Agent)” को सौंपे जाने का भी सुभाव था। अन्ततः, इस योजना की सकलता के लिए दो बातों का पूरा होना आवश्यक था। एक तो ^{Ruhr} रूर पर अधिकार की समाप्ति और जर्मनी का अपने संपूर्ण क्षेत्र में पुनः प्राधिक नियतन्त्रण। दूसरे, जर्मनी को विदेशों से ४०,०००,००० पौंड ऋण मिले ताकि उसके दो प्रयोजन—मुद्रा संचय (currency reserve) की व्यवस्था करना तथा उस प्रथम वार्षिकी के भुगतान में उसकी सहायता करना जो कि योजना के लाभसामने आने से पहले ही देय (due) हो जायेगी—पूरे हो सकें।

नेकडॉनल्ड और हेगियत में प्रारम्भिक चर्चाओं के बाद, "डेविस योजना" लंदन में जुलाई और अगस्त में हुए एक सम्मेलन में प्रस्तुत की गई। इस सम्मेलन में स्ट्रेसमान भी शामिल हुये थे। समझौते के इस नए वातावरण में, यह योजना बिना अधिक कठिनाई के स्वीकार कर ली गई यद्यपि कई जटिल बारी-कियों पर समझौता होना आवश्यक था। रूर से शिंसा नेते हुए, जर्मनी ने यह वचन लेने का प्रयत्न किया, और उसमें उन्हें सफलता भी मिली कि जानबूझकर बड़ी रकम इकट्ठा करने के अतिरिक्त और किसी भी समय उस पर शान्ति नहीं लगाई जाएगी। अक्टूबर में, जर्मन ऋण जारी किया गया और फ्रांस को छोड़कर जहाँ कि स्वयं बेको ने यह ऋण दिया था) सर्वत्र ही उसमें अपेक्षा से अधिक रकम प्राप्त हुई। ऋण की माँगों से भी अधिक रकम अमेरिका से मिली और एक चौपाई से भी अधिक ग्रेट ब्रिटेन से। शेष रकम फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड, और स्वीडन से प्राप्त हुई। यद्यपि डेविस ऋण राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में जारी नहीं किया था, तदपि इसमें संदेह की गुंजायश कम ही है कि प्रॉस्टिया और हंगरी को राष्ट्रसंघ द्वारा दिलाए गए ऋण के पूर्वोदाहरण ने इस ऋण की सफलता में बहुत योग दिया। नवम्बर के मध्य में, फ्रांस और बेल्जियम की अन्तिम सेनाएं रूर से हटा ली गई।

डेविस योजना में कई अच्छाइयाँ थी। उसमें माँगों को केवल उतनी ही रकम तक सीमित रखा गया था जितनी कि जर्मनी, परिस्थिति अनुकूल होने पर, चुका सकता था, यद्यपि फ्रांस की आशाओं को पूरी करने की आवश्यकता के कारण विशेषज्ञ लोग सम्भवतः आवश्यकता से अधिक आशावादी बन गए थे। इस योजना ने भुगतान और विनिमय के प्रश्न में अंतर किया तथा विनिमय का उत्तरदायित्व लेनदारों पर ही छोड़ दिया। डेविस योजना ने कुछ निश्चिन् राजस्व (प्रायः) की प्रतिभूति लेनदारों को दी—न कि जर्मनी के साधनों पर व्यापक ऋणमार डाला। सबसे अच्छी बात तो उसके द्वारा यह हुई कि उसने क्षतिपूर्ति के प्रश्न को राजनैतिक विवाद क्षेत्र से हटा लिया और उसका समाधान किसी साधारण व्यापारिक कर्ज की भाँति ही गुंजायश। उसने क्षतिपूर्ति प्रायोग के हाथों से यह सारा मामला ले लिया क्योंकि उसका कार्य असतोषजनक था तथा यह सुनिश्चित बना दिया कि उसका निबटारा निष्पक्ष, अ-राजनैतिक दृष्टिकोण से किया जाएगा। यह बात विशेषकर इसलिए समझनी चाहिए कि "क्षतिपूर्ति भुगतान अभिकर्ता" एक अमरीकी नागरिक को बनाया जाना था।

इन सभी बातों में डेविस योजना ने उसके पूर्व उठाए गये किन्हीं भी कदमों से इतनी अधिक प्रगति की थी कि उसका उत्साहपूर्ण स्वागत आसानी से सम्भवा जा सकता है। किन्तु उसमें गंभीर दोष भी थे। उसके द्वारा वार्षिक भुगतान तो निश्चिन किए गये थे किन्तु वे कब तक किए जाएंगे या जर्मनी को कुल कितना कर्ज चुकाना है यह निश्चित नहीं किया गया था। क्योंकि कोई भी फ्रांसीसी सरकार इस समय यह स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकती थी कि ६,६००,०००,००० पीड के संपूर्ण क्षतिपूर्ति दावे का कोई भाग उसने विधिवत् छोड़ दिया है। अतएव जर्मनी इस समय भी ऐसी निस्सहाय स्थिति में था कि यदि उसको आर्थिक स्थिति में कोई मुबार होता तो उसके दायित्व में भी वृद्धि हो जाती। इस प्रकार वह अपनी बचत जमा करने की इच्छा से भी बचत कर दिया गया क्योंकि वह बचत मित्र-राष्ट्रों के राजकोषों में ही चली जाती। इससे भी अधिक दुरी बात तो यह हुई कि डेविस योजना ने क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए जर्मनी को आवश्यक धनराशि ऋणस्वरूप देने का बातक पूर्वोदाहरण (precedent) प्रस्तुत कर दिया। डेविस ऋण की सफलता के बाद जर्मनी ने खूब ऋण लिया। भगल पांच वर्षों में जर्मनी की हर प्रमुख नगरपालिका (municipality) और लगभग हर प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठान (business concern) ने या तो काफी ऋण लिये या अमेरिका में और कभी-कभी ब्रिटेन में भी उधारी-खाता खोला। लक्ष्मी का यह आगमन आग्य सुन जाने के समान मालूम पड़ने लगा। उसके कारण समृद्धि की ऐसी लहर सी आ गई कि अपने साधनों पर अनुचित भार डाल बिना जर्मनी ढाँवस वार्षिकियाँ चुकाने में समर्थ हो सका तथा प्रचुर विदेशी मुद्रा अपने हाथ में रख उसने अपनी विनिमय समस्या को भी हल कर लिया। इन वर्षों में डेविस योजना एक जबरदस्त सफलता प्रतीत होने लगी। उस समय बहुत थोड़े ही लोग यह अनुभव कर सकते थे कि जर्मनी अमेरिका से धन लेकर अपना कर्ज चुका रहा है और उसकी हेसियत (solvency) इस बात पर निर्भर करती है कि जर्मन ऋणों का वॉल स्ट्रीट (wall street) में सदैव ही स्वागत होता रहे।

मित्र-राष्ट्रों के आपसी कर्ज (Inter-Allied Debts)

यहाँ एक और प्रकार के दावों, यद्यपि वे उत्पत्ति में भिन्न थे, की चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त अवसर है जो कि क्षतिपूर्ति समस्या के साथ अविभिन्नता-

पूर्वक जूड़ गए थे तथा इन में जाकर जिनकी क्षतिपूर्ति के समान ही दशा हुई । युद्धकाल में, ग्रेट ब्रिटेन ने अपने कुछ योरोपीय मित्र-देशों को काफी रकम ऋण में दी थी जिनमें रूस भी शामिल था । किन्तु इस ऋण की प्राप्ति से भी अधिक रकम उसने अमेरिका जिससे कुछ मित्र राष्ट्रों ने सीधे भी ऋण लिए थे, से उधार ली थी । कर्जदारी के इस चक्र के क्षतिपूर्ति समस्या के समान शीघ्र ही असमाधेय और जटिल बन जान की आशंका होने लगी । जहाँ तक मित्र-राष्ट्रों के युद्धकालीन आपसो कर्जों का प्रश्न है, केवल अमेरिका ही साहूकार (creditor) था, योरोपीय मित्र राष्ट्रों केवल कर्जदार ही थे (फ्रांस भी थोड़ी सी रकम का साहूकार था) और ग्रेट ब्रिटेन की बीच की स्थिति थी, वह आंशिक रूप से कर्जदार और आंशिक रूप से साहूकार (creditor) था ।

सन् १९२२ में जब अमरीकी सरकार अपना पैसा वापस चुकाने के लिए अधिक जोर देने लगी, तब फ्रांस ने यह घोषित किया कि वह अपना युद्धकालीन कर्ज केवल तब ही चुका सकता है जबकि जर्मनी क्षतिपूर्ति का भुगतान करे । क्योंकि यह तो एक असहनीय बात थी कि यदि पराजित जर्मनी उसका (फ्रांस का) पैसा नहीं चुका सके, तो विजयी फ्रांस अपने मित्र-राष्ट्रों का भुगतान करे । नाम और जमा (debit and credit) दोनों में ही बराबर होने के कारण ग्रेट ब्रिटेन यह स्वीकार कर लेता कि सभी युद्धकालीन कर्ज विलकुल रद्द कर दिए जायें । अगस्त १९२२ में, अपने योरोपीय साथी राष्ट्रों को, उसने एक पत्र लिखा (जा कि साधारण "बैलफोर-पत्र" (Balfour-note) के नाम से प्रसिद्ध है) जिसमें उसने उन्हीं यह सूचित किया कि ब्रिटेन अपने कर्जदारों से कर्ज की केवल उतनी ही रकम वापस चाहता है जितनी कि उसे अमेरिका कि अपना कर्ज चुका देने के लिए आवश्यक है । कर्ज वसूली की सारी बुराबत (odium) अमेरिका के सिर लाद देने से इस अत्यन्त आलाचीपूर्ण प्रयत्न का अमेरिका में लगभग सर्वत्र ही विरोध हुआ और इस कारण ऋण रद्द कर देने के प्रस्ताव के प्रति अमेरिका की भावनाएँ और भी कठोर हो गई ।¹

1 "This over-clear attempt to place the whole odium of debt collection on the United States was widely resented in that country, and further hardened American opinion against cancellation "

अमेरिका के रुख को देखते हुए, ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि उसे अपना कर्ज चुकाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। दिसम्बर १९२२ में एक सम्मोक्षा हुआ जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि ब्रिटेन अमेरिका का कर्ज उसके ध्वाज सहित लगभग ३३,०००,००० पाउंड की ६२ वार्षिक किस्तों में चुकाएगा। सन् १९२६ तक ग्रेट ब्रिटेन को अपने योरोपीय मित्र-राष्ट्रों से एक भी पैसा नहीं मिला। तब डेविस सम्मोक्षा के बाद, ब्रिटिश-अमरीकी सम्मोक्षा के ही ढग के सम्मोक्षा उस कर्ज को वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए हुए जो कि फ्रांस, इटली, रूमानिया, यूगोस्लाविया, यूनान और पुर्तगाल को ग्रेट ब्रिटेन एवं अमेरिका को देना था। इन लेनदेनों (transaction) का विस्तृत विवरण यहाँ नहीं दिया जा सकता। किन्तु यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जहाँ अमेरिका ने ब्रिटेन के मूल कर्ज (पाँच प्रतिशत मान्य दर व्याज ओढ़ते हुए) में ३० प्रतिशत से भी कम की कमी की, वही ब्रिटेन ने इटली के कर्ज में ८० प्रतिशत से अधिक और अन्य मित्र-राष्ट्रों के कर्ज में ६० प्रतिशत से भी अधिक की कमी की। इसके अतिरिक्त, ग्रेट ब्रिटेन को मित्र-राष्ट्रों के भापसी कर्ज और क्षतिपूर्ति से जो रकम मिली, वह मिलकर भी ब्रिटेन के कर्ज की उस रकम के बराबर कभी भी नहीं हुई जो कि उसे अमेरिका को चुकानी पड़ी। वास्तव में, इस प्रकार कर्ज की सारी रकम, चाहे वह कही भी चुकाई गई हो, अमरीकी राजकोष में ही समा गई।

इन कर्ज-सम्मोक्षा में निधियों (funds) के विस्तृत विनियम की जो व्यवस्था की गई थी, वह डेविस योजना के अन्तर्गत विनियम-व्यवस्था की भाँति, इसलिए संभव हो सकी कि अमेरिका ने कर्जदार-देशों को ऋण और उधारी दी। ऑस्ट्रिया और हंगरी में सफलतापूर्वक प्रारम्भ की गई नीति को राष्ट्र-संघ ने जारी रखा। सन् १९२४ और १९२५ के बीच, राष्ट्र-संघ के तत्वावधान में यूनान, बल्गेरिया, इस्टोनिया (Estonia) और स्वतन्त्र नगर दानज़िग (Free City of Danzig) ने ऋण लिये और उनकी रकम मुख्यतः अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन से प्राप्त हुई। अटलांटिक के इस पार से जर्मनी और अन्य योरोपीय देशों को काफी रकम उधार मिलने से न केवल क्षतिपूर्ति और युद्ध कालीन कर्जों के भुगतान सबंधी सारी भारी भरकम गाड़ी ही चलती रही अपितु उसके कारण योरोप में समृद्धि और कल्याण (well being) का एक सामान्य

वातावरण ही निर्मित हो गया और यह समृद्धि योरोप के प्रमुख राज्यों के सबंधों में सुधार—जो इस अवधि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी—होने के लिए अत्यन्त आवश्यक थी ।

जेनेवा उपसंधि (Geneva Protocol)

जर्मन क्षतिपूर्ति समस्या के समाधान के लिये डेविड योजना स्वीकार करने सबंधी समझौता अगस्त १९२४ में लन्दन में बर चुकने के बाद, मेकडॉनल्ड तथा हेरियट अगले माह राष्ट्रसंघ-सभा के जेनेवा अधिवेशन में सम्मिलित हुये । उसमें उन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण समस्या—फ्रांस की सुरक्षा-मांग—का समाधान निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयत्न किया ।

सन् १९२२ में गारन्टी समझौता (guarantee pact) (देखिये पृष्ठ २१) सबंधी एक ब्रिटिश प्रस्ताव फ्रांस द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद से फ्रांसीसी सुरक्षा के लिए विभिन्न दिशाओं में प्रयत्न किए जाने लगे थे । सन् १९२१ में राष्ट्रसंघ ने नि शस्त्रीकरण के कष्टकर प्रश्न को हल करने के प्रयत्न (जिनका बर्लिन आगे किसी अध्याय में किया जाएगा) करना प्रारम्भ कर दिया था । और १९२२ में फ्रांसीसी सरकार ने प्रथम बार यह युक्ति, जिस पर वह अत्यधिक प्रयत्न रही, पेश की कि फ्रांस केवल उसी स्थिति में अपना नि शस्त्रीकरण कर सकता है जब उसे और अधिक सुरक्षा प्रदान की जाये । सन् १९१६ में जब फ्रांस द्वारा सुरक्षा की मांग पहिली बार की गई थी, तब से अब तक फ्रांसीसी सुरक्षा की कल्पना में वृद्धि हो गई थी । पूर्वी मध्य योरोप में फ्रांस के अब ऐसे आसानी से जिनकी सुरक्षा अब स्वयं उसकी सुरक्षा का अंग हो चुकी थी । अब आवश्यकता इस बात की थी कि फ्रांस और उसके साथियों को अतिरिक्त सुरक्षा की व्यापक गारन्टी दी जाये । इस प्रकार की गारन्टी की मांग करने का उत्तम अवसर नि शस्त्रीकरण सबंधी जेनेवा चर्चाओं के समय ही था । यदि इस की गारन्टी प्राप्त हो जाती, तो फ्रांस को अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण सफलता मिल जाती । यदि वह प्राप्त नहीं होती, तो फ्रांस और उसके साथी नि शस्त्रीकरण सबंधी कोई कर्तव्य स्वीकार ही नहीं करते ।

जेनेवा में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने, समवतः अपने कदम के सम्पूर्ण परिणामों का अनुभव किए, बिना ही फ्रांस की उक्त धारणा को चुपचाप स्वीकार कर

लिया। अस्थायी मिश्र आयोग (Temporary Mixed Commission) जिसे निःशस्त्रीकरण प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था, ने सन् १९२३ में राष्ट्रसंघ की सभा के सामने “परस्पर सहायता संधि” (“Treaty of Mutual Assistance”) का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप-संधि में भावी निःशस्त्रीकरण सबंधी कुछ व्यवस्था की गई थी और वर्तमान सुरक्षा के लिए सुपरिभाषित भारन्टियां निश्चित की थी। किसी भी युद्ध के प्रारम्भ होने के चार दिनों के भीतर राष्ट्रसंघ-परिषद् को यह निर्णय ज्ञाना था कि आक्रमणकारी (aggressor) पक्ष कौन सा है। और उसके बाद राष्ट्रसंघ के सदस्य स्वतः ही इस बात के लिए कतव्यबद्ध हो जाने थे कि वे आक्रमणकारी के विरुद्ध सैनिक सहायता दें। इसलिए इस व्यवस्था का उद्देश्य न केवल अनुबन्ध-पत्र के अनुच्छेद १६ की मिट्टी खराब होने से बचना था, जैसा कि राष्ट्र-सभा के १९२१ के प्रस्तावों के समय उसकी हुई थी (देखिए पृष्ठ २२), अपितु सैनिक अनुशास्तियों को थाप ही थाप लागू होने योग्य और अनिवार्य बनाकर उस अनुच्छेद को हट बनाना भी था।

सन् १९२१ की राष्ट्रसंघ-सभा, जिसमें किसी भी बड़े राष्ट्र के जिम्मेदार मंत्रियों ने भाग नहीं लिया था, इस प्रारूप को संबंधित सरकारों के विचारार्थ भेजने के प्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकी। फलतः, उसके अधिकांश साधियों और पूर्वी योरोप के छोटे छोटे राज्यों ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया किन्तु ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश अधिराज्यो, स्विट्ज़ेरेलैंड, वियन राज्यों और हॉलैंड—ये उन देशों में से थे जो अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपेक्षा अपने बचनों में वृद्धि करने से बचना चाहते थे—ने उसे निश्चित रूप से अस्वीकृत कर दिया। किन्तु अगले वर्ष जब मेकडॉनल्ड और हेरियत एक साथ सभा में उपस्थित हुए, तब वातावरण में इतना सर्वतोमुखी सुधार हो चुका था कि उक्त दोनों विरोधी दृष्टिकोणों में समझौता संभव दिखाई देने लगा। सन् १९२४ में सभा ने “जेनेवा उपसंधि” (Geneva Protocol) नामक प्रसिद्ध समझौते का प्रारूप बनाया और संबंधित सरकारों से उसे स्वीकार कर लेने की निर्विरोध सिफारिश की। इस समझौते का पूरा नाम था, “अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांति-पूर्ण समाधान के लिये उपसंधि” (“Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes”).

उपसधि की प्रमुख नवीनता यह थी कि उसके द्वारा राष्ट्रसंघ के अनुबध्पत्र में सुधार करने और पचनिर्णय (arbitration) का आश्रय लेना अनिवार्य बना कर अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया था।^१ अनुबध्पत्र में की गई व्यवस्था के अनुसार युद्ध का आश्रय दो स्थितियों में लिया जा सकता था—एक तो, उस समय जबकि परिपद जिसमें कि मतदान संबंधित पक्षों को शामिल किये बिना हो, किसी विवाद पर निर्विरोध निर्णय न दे सके और दूसरे, उस समय जबकि विवाद विषय को संबंधित पक्षों का घरेलू मामला करार दे दिया जाए। उपसधि के द्वारा इन दोनों ही खामियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया था। उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि सभी प्रकार के कानूनी विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय में भेजे जाएँ और उसका निर्णय बधनकारी (binding) हो। अन्य विवादों के संबंध में, अनुबध्पत्र में निश्चित किया गया तरीका ही अपनाते ही व्यवस्था की गई थी। किन्तु परिपद यदि किसी एकमत निर्णय (unanimous conclusion) पर नहीं पहुँच सके, तो विवादी पक्षों को युद्ध का आश्रय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी गई थी जैसा कि अनुबध्पत्र में विहित किया गया था। यह उपबध्पत्र किया गया था कि ऐसी स्थिति में परिपद संबंधित विवाद को पक्षों की एक समिति के पास भेजे और इस समिति का निर्णय बधनकारी हो। जहाँ तक दूसरी खामी का संबंध है, उपसधि में यह व्यवस्था की गई थी कि (इसका प्रस्ताव जापानी प्रतिनिधिमंडल ने रखा था) घरेलू क्षेत्राधिकार (domestic jurisdiction) सम्बन्धी विवादों—के सम्बन्ध में अनुच्छेद ११ में निहित समझौते की कार्रवाई की जाय—यद्यपि घरेलू क्षेत्राधिकार के मामलों पर अनुबध्पत्र के अनुच्छेद १५ के अनुसार परिपद नियमानुसार कोई निर्णय नहीं दे सकती थी—तथा उक्त अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रसंघ के सामने मामला पेश करने वाले राष्ट्र को ऐसे विवाद में भागमणकर्त्ता नहीं माना जाये। अतः, सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण में सतुलन बनाए रखने के लिए, उपसधि में यह सुझाव रखा गया था कि १५ जून १९२५ को निःशस्त्री-

1 "The principal novelty of the Protocol was its attempt to improve on the Covenant and to provide additional security through compulsory resort to arbitration"

करण सम्मेलन हो बशर्ते कि इस तारीख तक काफी राज्य उपसधि का अनु-समर्थन कर दें ।

अनुबन्धपत्र के अनुच्छेद १६ के अधीन परिपद की शक्तियों में वृद्धि करने या सैनिक अनुशास्त्रियों (military sanctions) को अनिवार्य बनाने के लिए जेनेवा उपसधि में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । इस कारण पारस्परिक सहायता-सधि प्रारूप (Draft Treaty of Mutual Assistance) की अपेक्षा उससे प्राप्त की मांग कम ही पूरी होती थी । सन् १९२४ की फ्रांसीसी सरकार ने उसे (जेनेवा उपसधि) पर्याप्त मानकर स्वीकार कर लिया था—यह बात ही इस बात का पुष्ट प्रमाण थी कि पौकारे के पतन के बाद से फ्रांसीसी नीति समझौते की ओर उन्मुख हो चली थी । जो भी हो, इस उपसधि से प्राप्त और उसके साधियों का एक महत्वपूर्ण हित-साधन तो होता था—१९१६ के शांति समझौते और, विशेषतः, उसकी सैनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना । शांति उपसन्धि को सशोधित करने की मांग “विवाद” (dispute) नहीं कही जा सकती थी और न इस पर प्रारूप में दी हुई व्यवस्था लागू की जा सकती थी । प्रारूप निर्माण समिति ने भी इस विषय पर कहीं कोई शक न रह जाय, अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे पर विशेष बल दिया था । दूसरे शब्दों में, प्रारूप में दिया हुआ यह बल तत्पश्चात् अनुबन्धपत्र की अन्य कई खामियों में से एक कह कर पुकारा गया—और यह थी इसकी १९१६ के समझौते और सुरक्षा में साम्य स्थापित करने की प्रवृत्ति एवं उस समझौते के सशोधन के लिये पर्याप्त सगठन (adequate machinery) करने की भूल । पर १९२४ में यह समालोचना विलुप्त हो चुकी थी । जर्मनी अब तक भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था । भूतपूर्व एल्य महत्वपूर्ण शत्रु राज्य भी आक्रमण करने की अपेक्षा स्वयं आक्रमित होने से भयातुर थे; अतएव उन्होंने प्रारूप पर सहर्ष हस्ताक्षर कर दिये ।

राष्ट्रसंघ-सभा समाप्त होने तक उपसन्धि के प्रति सामान्य उत्साह बना रहा । उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई । आपत्ति सबसे पहिले इस आशय की धाराओं के सम्बन्ध में उठ खड़ी हुई कि अनुबन्धपत्र के अनुच्छेद ११ के अधीन धरेलू सैन्यशक्ति के मामले सबधी विवाद राष्ट्रसंघ के सामने प्रस्तुत किये जा सकते हैं । इस प्रस्ताव को पेश करने में जापान की नीयत (motive) सर्वविदित थी । अपने क्षेत्रों में जापानी आप्रवासियों (immigrants) को

प्रवेश नहीं करने देने (देखिए अध्याय ८) सबकी अमरीकी नीति का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने हाल ही में अनुकरण किया था, इसलिए जापान इन बंदिगों के विरुद्ध जेनेवा में अपना विरोध प्रदर्शित करने का अधिकार प्राप्त करना चाहता था। अनुच्छेद ११ इतना व्यापक प्रतीत होता था कि स्वयं उससे ही यह अधिकार प्रदत्त मासूम पड़ना था। किन्तु ब्रिटिश अधिराज्य यह शर्त मानने के लिए सर्वाधिक अनिच्छुक थे कि आप्रवासन (immigration) के प्रश्नों से संबंधित उनके कानूनों पर किसी भी स्थिति में राष्ट्रसंघ में चर्चा हो या उन्हें चुनौती दी जाये, और यह बात सोच ही स्पष्ट हो गई कि यदि और किसी कारण से नहीं तो केवल इसी आधार पर वे उपसंधि का अनुसमर्थन करने से इंकार कर देंगे।

उपसंधि के अन्य उपबन्धों के अध्ययन ने, न केवल अधिराज्यों में, अपितु ग्रेट ब्रिटेन में भी विचारोत्तेजना पैदा की। अनिवार्य पक्ष निर्णय एक ऐसी नई बात थी जिसे ब्रिटिश लोकमत ने सहज ही स्वीकार नहीं किया। यद्यपि उत्तर-कालीन ब्रिटिश सरकारें अनुबन्धन के प्रति अपनी अटल निष्ठा की घोषणा करती रही, तदपि ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी भाग में अनुशास्तियों को कभी भी हार्थिक समर्थन नहीं मिला। यह अवश्य सत्य था कि उपसंधि ने अनुच्छेद १६ में कोई सुसोधन नहीं किया था। किन्तु इस तर्क से बचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि जितने ही अधिक विवादों में परिपक्व भावमणकारी का निर्णय करेगी उनमें हों अधिक विवादों में उसे अनुशास्तियाँ भी लगानी पड़ेंगी।

इन परिस्थितियों में, अधिराज्यों के विरोध और उसके साथ ही अनुबन्धन के प्रचीन ग्रेट ब्रिटेन के कर्तव्यों में किसी भी प्रकार की वृद्धि करने में कामन सभा (House of Commons) की सुपरिचित अनिच्छा के कारण उपसंधि का स्वीकार किया जाना शायद समभव ही नहीं होता, चाहे उस पर हस्ताक्षर करने वाली सरकार सत्ताह्व ही क्यों न रहती। किन्तु नवम्बर में, “जिनोवि पत्र” चुनाव के बाद, मेकडॉनलड की मजदूरदलीय सरकार के स्थान में बाल्डविन की अनुदारदलीय सरकार सत्ताह्व हुई। इस घटना ने उपसंधि के भाग्य का फैसला ही कर दिया। मार्च १९२५ में, नए विदेश मंत्री ऑस्टिन चेम्बरलेन (Austen Chamberlain) ने राष्ट्रसंघ की परिपक्व के

सामने यह विधिवत घोषणा कर दी कि ग्रेट ब्रिटेन ने उपसधि को स्वीकार नहीं करने का निश्चय किया है।

लोकार्नो संधि (Treaty of Locarno) -

जेनेवा उपसधि समाप्त हो गई। इस प्रकार फ्रांस का सुरक्षा-प्रयत्न एक बार फिर व्यर्थ चला गया, और फ्रांस इस बार भी यही सोचता था कि यह सब कुछ ग्रेट ब्रिटेन के दोष के कारण हुआ। अब केवल यही रास्ता रह गया था कि फ्रांस के राइनभूमि सीमान्त (Rhineland frontier) को ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्पष्ट गारन्टी सबधी मूल योजना का पुनः आश्रय लिया जाये। किन्तु यह गारन्टी अब एक नए रूप में दी जानी थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसका समाधान एक ऐसे प्रस्ताव से प्राप्त हुआ जिसे दो वर्षों पूर्व सबसे पहले जर्मन सरकार ने रखा था।

सन् १९२२ के अन्त में, जर्मन सरकार ने फ्रांसीसी सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि वे परस्पर यह वचन, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम को भी सम्मिलित किया जाएगा, दें कि एक पीढ़ी तक वे एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे। यह प्रस्ताव अमरीकी सरकार से जरिए किया गया था, जिससे कि इस समझौते के "न्यासी" (trustee) के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया गया था। रूर अधिकार के समय यह योजना फ्रान्स (क्योंकि फ्रांस द्वारा ही जर्मनी पर आक्रमण किए जाने को अधिक आशंका थी, न कि जर्मनी द्वारा फ्रांस पर) की अपेक्षा जर्मनी के ही हित में अधिक थी, इसलिए पोंकारे ने उसे रद्दी की टोकरी में पटक दिया। किन्तु फिर भी, जर्मन सरकार आगामी दो वर्षों में इसके लिए लगातार प्रयत्न करती रही परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। उसके बाद जेनेवा उपसधि के अस्वीकृत हो जाने और इस भावना ने कि अब जर्मनी के साथ राजनैतिक और आर्थिक समझौता किया जाना आवश्यक है, इस योजना में नया आकर्षण उत्पन्न कर दिया। योरोप से सम्बन्धित राजनैतिक प्रश्न में अमरीकी सहयोग को तो अब नल्पना ही नहीं की जा सकती थी। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन, जिसे जर्मनी और फ्रांस के बीच एक मध्यस्थ (mediator) के रूप में, रूर-अधिकार (Ruhr Occupation) के समय उसके स्वतंत्र रक्ष के कारण स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया था, इस समय आगे आने एवं कमी की पूर्ति करने को तैयार था। वह अकेला ही (क्योंकि अधिराज्य

इस मामले में उसका साथ नही देने) फ्रांसोसो-जर्मन सीमात पर जर्मन आक्रमण के विरुद्ध गारन्टी (इसी बात की तो फ्रांस हमेशा माँग करता आया था) देने के लिए तैयार था। समुलन बराबर बनाए रखने की दृष्टि से वह इस बात के लिए भी तैयार था कि फ्रांसोसो आक्रमण के विरुद्ध उपरोक्त सीमान्त सबंधी गारन्टी भी वह दे सकेगा।

तो, मुविख्यात लोकार्ना संधि का आधार उपरोक्त प्रकार का था। सन् १९२५ के पूरे ग्रीष्मकाल में, कूटनीतिक मार्गों द्वारा वार्ताएँ चलती रही और इस योजना का विवरण धीरे धीरे निश्चित होने लगा। जर्मनी और बेल्जियम के सीमात का भी वही आधार रखा गया और उसके लिए भी वे ही गारंटियाँ दी गईं जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच के सीमात के लिए दी गई थी। यह गारंटी न केवल सीमातो पर लागू होती थी, बल्कि उस अखेनीकृत क्षेत्र पर भी, जिसमें सेना रखने या किले बनाने की जर्मनी को मनाही कर दी गई थी। इटली प्रतिरिक्त गारन्टीदाता (guarantor) के रूप में सामने आया। यह ठहराव किया गया था (stipulated) कि सत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, जर्मनी राष्ट्रसंघ में सम्मिलित हो जाए और उसे परिषद् में स्थायी स्थान (permanent seat) मिले।

इसमें दो मुख्य कठिनाइयाँ थी। उनमें से पहिली चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड से लगे जर्मनी के सीमात को लेकर उठ खड़ी हुई। जर्मनी यह बात पुनः स्वीकार करने के लिए तो तैयार था कि वर्सेलीज संधि द्वारा निश्चित किया गया परिधनी सीमात उसे स्वीकार है किन्तु अन्य वर्सेलीज सीमातो के लिए वह ऐसा करने को राजी नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि वह अपने पूर्वी सीमान्त को अन्तिम नहीं मानता यद्यपि उसने इस बात से भी इन्कार किया कि वह प्रयोग कर उसे बदलने का उसका कोई विचार नहीं है। केवल इस बात में जर्मनी का रुख ग्रेट ब्रिटेन के रुख से मिलता था जोकि जर्मनी के पश्चिमी सीमात को छोड़ अन्य किसी भी सीमात की गारन्टी देने के लिए तैयार नहीं था। इस कठिनाई का यथासम्भव समाधान जर्मनी और पोलैंड तथा जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में पबनिरुण्य संधियाँ (arbitration treaties) तथा फ्रांस और इन दोनों देशों में गारन्टी संधियाँ, करके निकाला गया।

दूसरी कठिनाई सोवियत संघ से जर्मनी की मित्रता के कारण उत्पन्न हुई

जो कि रेपोलो संधि (देखिए पृष्ठ १७) के समय से ही चली आ रही थी। जर्मनी को यह भय था कि अनुबंधपत्र के अनुच्छेद १६ के अधीन पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संध के विरुद्ध किसी भी दिन सैनिक कार्यवाही कर सकते हैं तथा इस प्रकार की कार्यवाही में शामिल होने के लिए उसे भी आमन्त्रित किया जा सकता है। यह भय एक पत्र द्वारा दूर किया गया जिसमें अन्य लोकानों राष्ट्री ने जर्मनी को यह सूचित किया था कि, उनकी व्याख्या (interpretation) के अनुसार, राष्ट्रसंध के किसी भी सदस्य के लिए अनुबंधपत्र के समर्थन में केवल "उसी सीमा तक" सहयोग करना आवश्यक है जिस सीमा तक ऐसा सहयोग "उसकी सैनिक स्थिति से समत हो और उसकी भौगोलिक स्थिति का भी उसमें ध्यान रखा गया हो," उसका यह अर्थ निकाला गया कि निःशस्त्र हो जाने पर जर्मनी से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह सोवियत संध के विरुद्ध सैनिक अनुशास्तियों में कोई भाग ले।

अक्टूबर में, इन सभी राज्यों के मन्त्री स्ट्रिज़रलैंड में झील के किनारे बसे लोकानों नामक नगर में एकत्रित हुए जहाँ १६ अक्टूबर को उन्होंने निम्न-लिखित करारों के प्रारूप बनाए और उन पर अपने हस्ताक्षर किए —

- (१) फ्रांस-जर्मनी तथा बेल्जियम जर्मनी के सीमातो की गारन्टी सबधी संधि ("लोकानों संधि" जो कि उसका उचित नाम है)।
- (२) एक ओर जर्मनी और दूसरी ओर फ्रांस, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड में पचनिर्णय संधियाँ।
- (३) एक ओर फ्रांस में तथा दूसरी ओर चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड में पारस्परिक गारन्टी संधियाँ।

इन सभी संधियों पर लंदन में १ दिसम्बर, १९२५ को विधिवत् हस्ताक्षर हुये।

इस प्रकार की गई संधियों में कुछ महत्वपूर्ण आशय छिपा हुआ था जिसे कोई भी हस्ताक्षरकर्त्ता प्रकट रूप से स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता था, किन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे वह स्पष्ट होता गया। सबसे पहिल तो, यह मौन रूप से स्वीकार कर लिया गया था कि जर्मनी द्वारा अपना पश्चिमी सीमात स्वेच्छा से स्वीकार कर लिए जाने के कारण, उसमें पहिले की अपेक्षा या उसके अन्य वर्तमान सीमातो की अपेक्षा अधिक पवित्रता आ गई थी।

और उसका यह गमिताथ था कि वसॅलीज-संधि द्वारा लादे गए दायित्व यदि कानूनी दृष्टि से नहीं तो नैतिक दृष्टि से उतने बघनकारी नहीं थे जितने कि स्वेच्छा से स्वीकार किए गए दायित्व। दूसरे, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा कुछ ही सीमांतों पर गारंटी देने के लिए तैयार होने और अन्य सीमांतों की गारंटी देने से इन्कार करने का व्यावहारिक परिणाम, सुरक्षा की दृष्टि से, प्रथम और द्वितीय वर्ग में सीमांतों को अक्षीबद्ध कर देना ही हुआ। यद्यपि ग्रेट ब्रिटेन ने जोर देकर यह कहा कि अनुबध्पत्र के अधीन अपने सभी कर्त्तव्यों को वह निभाएगा, तदपि लोकार्नों संधि से यह धारणा बन गई कि पूर्वी योरोप के सीमांतों की रक्षा के लिए ग्रेट ब्रिटेन सैनिक कार्रवाई नहीं करना चाहता था। अन्ततोगत्वा, लोकार्नों संधि से वसॅलीज-संधि और अनुबध्पत्र दोनों ही को हानि पहुँची। उससे इस विचार को प्रोत्साहन मिला कि स्वेच्छिक स्वरूप के अन्य करारों द्वारा पुष्टि हुए बिना वसॅलीज संधि बघनकारी नहीं है तथा ऐसे सीमानों की प्रतिरक्षा के लिए सैनिक कार्रवाई करने की सरकारों से अपेक्षा नहीं की जा सकती जिनमें उनका सीधा हित न हो। दस वर्षों बाद, लगभग सभी सरकारें इन्ही धारणाओं के अनुसार कार्य करती हुई प्रतीत हुई।¹

सन् १९२५ में जब सभी ओर सद्भावना और आशावादिता फैली हुई थी, इन आशयों की अपेक्षा की जा सकती थी। इसमें अधिक प्रत्युक्ति करना कठिन होगा कि लोकार्नों संधि ने योरोप के शांतिकरण में योगदान किया है। युद्ध के बाद पहिली बार, उसने फ्रांस और जर्मनी की आवश्यकताओं के बीच व्यापक और निष्पक्ष सन्तुलन स्थापित किया। जो कार्य डेविस योजना ने प्रारम्भ किया था, वही कार्य इस संधि ने जर्मनी को बड़े राष्ट्रों में पुनः स्थान बित्ताकर पूरा किया।



- 1 "In the long run, the Locarno Treaty was destructive both of the Versailles Treaty and of the Covenant. It encouraged both the view that the Versailles Treaty, unless confirmed by other engagements of a voluntary character, lacked binding force, and the view that governments could not be expected to take military action in defence of frontiers in which they themselves were not directly interested. Ten years later, nearly all governments appeared to be acting on these assumptions."

यद्यपि जर्मनी को यह स्थान पूर्ण समानता (क्योंकि निःशस्त्रीकरण और असेनाकरण सबधो बर्दिशों अब भी लगी हुई थी) के आधार पर तो नहीं, किन्तु पूर्ण और सम्मानित सदस्य के रूप में मिला था । अपनी सफलता पर क्षमायोग्य गौरव के साथ ऑस्टिन चेम्बरलेन ने इस सधि को, “युद्ध और शांति के वर्षों के बीच वास्तविक विभाजन रेखा” बतलाया था ।^१

^१ “The real dividing line between the years of war and the years of peace ”

५. राष्ट्रसंघ उन्नति के चरम शिखर पर

(The League At Its Zenith)

सन् १९२४ ने १९३० तक की अवधि में राष्ट्रसंघ को सर्वाधिक प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्त रहे।^१ सन् १९२४ से पहिले, जेनेवा में राष्ट्रसंघ के सदस्यों का प्रतिनिधित्व सामान्यतः ऐसे प्रतिनिधि करते थे, वे किन्ने ही विख्यात क्यों न हो, जो कि अपने देश की विदेशी नीति के लिए उत्तरदायी मन्त्री नहीं होते थे। किन्तु मेकडॉनल्ड और हेरियत जब सन् १९२४ में सभा (Assembly) की कार्रवाई में भाग लेने के लिए स्वयं जेनेवा आए, तब उन्होंने एक दूरगामी महत्त्व का पूर्वोद्धारण उपस्थित किया। उसके बाद से ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और (उसकी सदस्यता-अवधि में) जर्मनी व विदेश-मन्त्री सभा के प्रत्येक अधिवेशन की कुछ कार्रवाई में सामान्यतः तथा परिषद् (Council) के लगभग हर अधिवेशन में भाग लेते रहे। योरोप के कई अन्य राष्ट्रों के विदेश-मन्त्रियों ने भी इस उद्धारण का शीघ्र ही अनुकरण किया। इस कारण सितम्बर तक यह माना जाने लगा कि जेनेवा योरोप के राजनीतिज्ञों का सम्मिलन-स्थान है। एक वर्ष (१९२६) तो सभा में योरोप के सभी विदेश-मन्त्री सम्मिलित हुये थे। गैर-योरोपीय देशों का प्रतिनिधित्व विश्वतापूर्वक ही योरोपीय राजधानियों में स्थित उनके राजदूत अथवा जेनेवा स्थित उनके व्यावसायिक (professional) प्रतिनिधि अधिकांश अवसरों पर करते थे।

राष्ट्रसंघ पूर्ण शक्ति के समय (The League At Full Strength)

लोकार्तों संधियों पर हस्ताक्षर के समय राष्ट्रसंघ-सभा का एक विशेष अधिवेशन मार्च १९२६ में, जबकि उसी समय परिषद् का नियमित अधिवेशन होता था, बुलाया गया था ताकि जर्मनी को राष्ट्रसंघ और परिषद् का स्थायी सदस्य विधिवत् बनाया जा सके। राष्ट्रसंघ के इतिहास में इस अवसर का एक

1 "The years 1924 to 1930 were the period of the League's greatest prestige and authority"

नया मोड़ माना गया था। इस अवधि तक, राष्ट्रसंघ के तटस्थ (neutral) सदस्यों तथा भूतपूर्व अल्प शत्रु-राज्यों, जिन्हें कि शांति के आरम्भिक वर्षों में राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया था, का प्रभाव इतना अधिक नहीं बढ़ पाया था कि इस आरोप का खंडन हो सके कि राष्ट्रसंघ विजेता राष्ट्रों का ही एक संगठन है जिसके निर्माण का प्रथम उद्देश्य १९१९ के समझौते के निबन्धनों (terms) का समर्थन करना है। राष्ट्रसंघ में जर्मनी को शामिल किया जाना तथा परिपद में उसे स्थायी स्थान दिया जाना इस आरोप का खंडन कर देते तथा उसमें नया जीवन लाकर उसे निष्पक्ष आधार पर प्रतिष्ठित कर देते।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक गंभीर न्यायिक भूल के कारण, एक बाधन ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। मूल अनुबन्धपत्र के अनुसार, परिपद के सदस्य इस प्रकार होने थे :—पोंचो विजेता बड़े राष्ट्र—ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, अमेरिका और जापान—स्थायी सदस्यों के रूप में और सभा द्वारा निर्वाचित अन्य चार अस्थायी सदस्य। परिपद के स्थायी सदस्यों में वृद्धि परिपद के निर्विरोध निर्णय से की जा सकती थी किन्तु सभा के बहुमत द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक था। अमेरिका की कर्तव्यविमुक्तता के कारण स्थायी सदस्यों की संख्या चार ही रह गई। सन् १९२२ में, छोटे राष्ट्रों (Lesser Powers) द्वारा जोर दिए जाने के कारण, अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा कर छः कर दी गई। मार्च १९२६ में, जिस समय स्थायी सदस्यता के लिए जर्मनी के आवेदनपत्र पर विचार करने के लिए परिपद का अधिवेशन हुआ तब स्थिति उपरोक्त प्रकार की थी।

परिपद के स्थायी सदस्यों की संख्या में आगे जाकर वृद्धि करने सम्बन्धी अनुबन्धपत्र का उपबन्ध स्पष्ट ही इसी उद्देश्य से रखा गया था कि परिपद से अनुपस्थित बड़े राष्ट्रों—जर्मनी और रूस—को उसका लाभ मिल सके। लोकान्तो-सधि-सर्वांगों के समय, एक और राष्ट्र को स्थायी सदस्य बनाने की संभावना पर बिलकुल भी विचार नहीं किया गया था किन्तु जब यह ज्ञात हुआ कि जर्मनी का आवेदन-पत्र विचाराधीन (pending) है; तो पोलैंड, स्पेन, और ब्राजिल सभी ने परिपद की स्थायी सदस्यता के लिए अपने-अपने दावे प्रस्तुत किए। विशेषकर, पोलैंड की मांग सत्याम आधार (plausible foundation) से खाली नहीं थी। यद्यपि पोलैंड बड़े राष्ट्रों के प्रभाव वृत्त में नहीं था, तदपि योरोपीय राजनीति में उसका प्रमुख स्थान था। जनसंख्या या संपत्ति में वह

इटली से बहुत अधिक हीन नहीं था। लोकार्नों संधियों से यह स्पष्ट हो चुका था कि मोका आने पर फ्रांस पोलैंड के हितों की अपेक्षा अपने हितों को प्राथमिकता दे सकता था। इधर पोलैंड यह अनुभव करता था कि यदि उसे स्थायी सदस्यता मिल जाए, तो उसे हार्गन में डालते हुए यदि फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी से कोई समझौता करना चाहें तो वह उसका प्रतिकार कर सकेगा। इसके विपरीत जर्मनी यह तर्क कर सकता था कि लोकार्नों सौदे के अन्तर्गत केवल उसे ही स्थायी सदस्यता दिलाने का आश्वासन दिया गया था और यदि इस समय ऐसे किसी राष्ट्र को यह सदस्यता दिलाकर उस स्थान का ही मूल्य घटाया जाना है जिसका सभी महत्वपूर्ण मामलों पर दिया गया मत उसके मत की ही अपेक्षा बना दिया, तो लोकार्नों सौदे पर उसी भावनापूर्वक झटल नहीं रहा गया है जिस भावना में कि वह किया गया था।

इसमें संदेह नहीं कि ग्रेट ब्रिटेन का लोकमत और जेनेवा स्थित प्रतिनिधियों में से अधिकांश यह मानते थे कि जर्मनी के दावे का आधार ठोस है और वे इस बात के विरुद्ध थे कि परिषद् का स्वामी सदस्य और किसी को बनाया जाये। दुर्भाग्यवश, ऑस्टिन चैम्बरलेन ने यह वचन दे दिया था कि वह स्पेन के दावे का समर्थन करेगा, और इसमें उत्साहित हो, फ्रांस के नए विदेश मंत्री-ग्रिगोइर न पोलैंड का पक्ष लिया। स्पेन और ब्राजिल (पोलैंड नहीं था) दोनों ही परिषद् के अस्थायी सदस्य थे और जर्मनी को स्थायी सदस्य बनाने के लिए उनका भी मत प्राप्त होना आवश्यक था। उन्होंने अपना मत तब तक देने से इन्कार कर दिया जब तक स्वयं उनका दावा स्वीकार न कर लिया जाये। पूरी तरह घाबली मच गई। परिषद् कोई निर्णय नहीं कर सकी और सभा कुछ किए बिना ही विसर्जित (dispersed) हो गई। इस प्रकार लोकार्नों संधि के बावजूद भी, जर्मनी राष्ट्रसंघ में प्रवेश नहीं पा सका।

सन् १९२६ के ग्रीष्मकाल में परिषद् की एक समिति ने इस स्थिति को सुलझाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। अतः यह समाधान निकाला गया कि अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर छह से नौ कर दी जाय और सभा का दो तिहाई मत प्राप्त होने पर अस्थायी सदस्यों में से तीन को उनकी त्रिवर्षीय (triennial) अवधि समाप्त होने पर पुनः निर्वाचन योग्य करार दिया जाये। इस प्रकार छोटे और बड़े राज्यों के बीच की स्थिति वाले राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के

लिए परिपद में अर्ध स्थायी (semi-permanent) सदस्यों की एक नई श्रेणी ही कायम की गई। पोलैंड और जर्मनी दोनों ने ही इस समझौते को स्वीकार कर लिया। पोलैंड ने उसे इस आश्वासन पर स्वीकार किया कि उसे नई अर्ध-स्थायी सदस्यता दी जायेगी। स्पेन और ब्राजिल ने उसे अस्वीकार कर दिया किन्तु अपने मतों का उपयोग कर जर्मनी को सदस्य बनने से रोकने की बदनामी से बचने के लिए वे राष्ट्रसंघ से ही हट गये। सितम्बर १९२६ की राष्ट्रसंघ-सभा के समय उत्साहक वातावरण में, जर्मनी ने राष्ट्रसंघ में सम्मिलित होकर परिपद की स्थायी सदस्यता प्राप्त की। फिर भी, जर्मन लोगों के दिमाग में यह खेदपूर्ण भावना बनी ही रही कि जर्मनी जेनेवा में अपने साथ न्याय की भाशा नहीं कर सकता। वैसे उस समय, स्ट्रेसमान का प्रभाव उन्हें सतोष दिलाने के लिए काफी था। किन्तु जर्मनी में एक ऐसी राष्ट्रसंघ विरोधी पार्टी को प्रोत्साहन दिया गया था जो कि इस समय तक शक्तिशाली हो चुकी थी। यह बात महत्वपूर्ण है कि अप्रैल १९२६ में जबकि स्थायी सदस्यता सम्बन्धी विवाद अपनी चरम सीमा पर था, जर्मनी ने सोवियत संघ से एक नई संधि की जिसमें दोनों ही पक्षों ने रेपोलो संधि के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराया और एक दूसरे को यह वचन दिया कि उनमें से किसी पर भी आक्रमण हुआ तो वे तटस्थ रहेंगे।

जर्मनी के सदस्य बन जाने से राष्ट्रसंघ की सदस्य संख्या अधिकतम की सीमा तक पहुँच गई और उसकी सदस्यता पर यहाँ संक्षेप में विचार किया जा सकता है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के तीन सबसे बड़े देश—अमेरिका, अर्जेंटीना, और ब्राजिल उससे अनुपस्थित थे। मध्य और दक्षिण अमेरिका के छोटे छोटे राज्यों के समूह से उसे आर्थिक लाभ बहुत ही कम होता था (क्योंकि उन पर राष्ट्रसंघ का चढ़ा हमेशा ही बकाया रह जाता था) और नैतिक समर्थन तो उनसे मिलता ही नहीं था। सुदूर पूर्व में, जापान, चीन और स्याम तथा भारत तथा मध्य पूर्व में फारस उसके सदस्य थे। किन्तु टर्की उससे अलग ही रहा। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका कुछ सक्रिय प्रतिनिधि राष्ट्रसंघ-सभा में सामान्यतः भेजता रहता था। लिबेरिया (Liberia) और प्रवींसीनिया उसके सदस्य तो थे किन्तु उनकी पात्रता कुछ सदेहास्पद थी। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पाँचवे प्रायद्वीप का प्रतिनिधित्व करते थे। किन्तु योरोप ही राष्ट्रसंघ का मुख्याधार था, और सन् १९२८ में स्पेन के पुनः राष्ट्रसंघ का सदस्य बन जाने के बाद, सोवियत

संघ को छोड़कर योरोप के और सभी राज्य उसके सदस्य थे। इस समय सोवियत संघ ही एक ऐसा बड़ा राष्ट्र था जो कि अब भी खुले आम उसका विरोध करता था।

राष्ट्रसंघ के प्रति सोवियत संघ का रुख उन पूँजीवादी राज्यों के प्रति उसके रुख की ही प्रतिछाया ही थी जो कि राष्ट्रसंघ के सदस्य थे।^१ सन् १९२४ के बाद से, सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन के संबंध बिगड़ते गये। सन् १९२६ में, जब सोवियत संघ ने ब्रिटेन की आम हड़ताल का समर्थन किया, तब तो क्रोध की लहर फैल गई। अगले वर्ष, ब्रिटिश सरकार ने मनमानी करते हुए अरकोस (Arcos) के अहाते में छपा मारा, जोकि सोवियत संघ की सरकारी व्यापारिक सत्ता थी। वहाँ उसे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सोवियत पक्षपात को सिद्ध करने वाले दस्तावेज मिले। इस पर ब्रिटेन ने १९२१ के व्यापारिक सम्झौते को रद्द कर दिया तथा सोवियत सरकार से अपने दौलत संबंध (diplomatic relations) तोड़ लिये। जो भी हो, इस अवधि में सोवियत संघ के संबंध जिस प्रकार के रहे, उनमें यह विवाद एक प्रवाद ही था। फ्रांस और इटली के साथ उसके संबंधों में धीरे-धीरे सुधार हो गया। जर्मनी के राष्ट्रसंघ में शामिल हो जाने से जर्मनी के साथ उसके संबंध बहुत अधिक नहीं बिगड़े थे। यद्यपि सोवियत प्रवक्ता राष्ट्रसंघ की मंजूर उठाते रहे, तदपि सन् १९२७ में सोवियत सरकार ने अमेरिका का उदाहरण अपने सामने रखते हुए, राष्ट्रसंघ की आर्थिक, मानवतावादी (humanitarian) और निःशस्त्रीकरण गतिविधियों में सहयोग देना प्रारंभ किया। उस वर्ष पहिली बार, सोवियत प्रतिनिधि एक सामान्य आर्थिक सम्मेलन (देखिए पृष्ठ ८४) और निःशस्त्रीकरण सम्मेलन तैयारी आयोग (Preparatory Commission for the Disarmament Conference) (देखिए मोर्बा अध्याय) की बैठकों में भाग लेने के लिए जेनेवा आये।

राष्ट्रसंघ शांतिस्थापक (The League As Peace-maker) के रूप में राष्ट्रसंघ का प्रमुख कार्य—आगे भी उसका यही कार्य रहना था—विवादों

१ "The attitude of the Soviet Government to the League of Nations was a reflection of its attitude to the capitalist states which composed the League"

का शांतिपूर्ण समाधान निकालकर युद्ध को रोकना था किन्तु उसकी सर्वोच्च उन्नति के समय भी सभी राष्ट्र उसके क्षेत्राधिकार में नहीं पाये थे। सन् १९२६ में जब निकारागुआ की (Nicaraguan) सरकार ने मेक्सिको, जहाँ की सरकार पर यह आरोप था कि वह निकारागुआ के राजनैतिक शत्रुओं की सहायता कर रही है, के विरुद्ध राष्ट्रसंघ से अपील की, तब अमेरिका ने 'अमरीकी और विदेशी जन-धन की रक्षा के लिए' एक जहाजो बेड़ा शीघ्र ही भेज दिया, और राष्ट्रसंघ ने यह सूचना स्वीकार कर ली कि मध्य अमेरिका में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में राष्ट्रसंघ को कोई रुचि नहीं दिखाना चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन और मिस्र (जिसे १९२२ में ही स्वतंत्र राज्य मान लिया गया था) ने विशिष्ट सबंधों के कारण मिस्र राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका तथा इस कारण ग्रेट ब्रिटेन और मिस्र के मतभेदों को अन्तर्राष्ट्रीय विवाद नहीं माना जा सका। चीन में विदेशियों को विशेष अधिकार दिए जाने सबंधी संधियों पर चीन और बड़े राष्ट्रों के विवादों को राष्ट्रसंघ के सामने प्रस्तुत किए जाने योग्य नहीं समझा गया। किन्तु इन अपवादों के होते हुए भी, राष्ट्रसंघ का कार्यक्षेत्र दूरगामी था, और इस अवधि में विश्व के कई भागों से विवाद उसके सामने प्रस्तुत किए गये। उदाहरण के तौर पर, तीन ऐसे विवादों का यहाँ वर्णन दिया जाएगा जिनमें युद्ध की संभावना थी।

पहला विवाद टर्की के साथ शांति-संधि के कारण उठ खड़ा हुआ। इस संधि में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि ब्रिटिश और तुर्की सरकारों में समझौता न हो सके तो टर्की तथा संरक्षित राज्य ईराक के बीच के सीमांत का निर्धारण राष्ट्रसंघ परिषद् द्वारा किया जाये। सन् १९२४ के शरद में, परिषद् ने, जिसमें कि इस उद्देश्य के लिए, टर्की को भी शामिल किया गया था (यद्यपि अभी वह राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना था), सीमान्त रेखा (frontier line) की सिफारिश करने के लिए एक तटस्थ सीमा आयोग नियुक्त किया। विवादग्रस्त क्षेत्र मोसुल (Mosul) का विस्त्रायत (vilayet) या जिला था और उसकी मिश्रित आबादी खुर्द, तुर्क और अरब थी तथा विरासत संधि के बाद से वह ब्रिटेन के अधिकार में हो था। जिस समय सीमा आयोग अपने कार्य में व्यस्त था, उस समय टर्की के खुर्दों (Kurds) ने जो कि एक परिश्रमी पहाड़ी जाति के हैं, तुर्की सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन परम्परानुकूल तुर्की क्रूरता से कर

दिया गया। प्रत्येक खुद मोसूल क्षेत्र में भाग गए और वर्तमान प्रस्थायी सीमाना पर गंभीर मुठभेड़ हुई। स्थिति इतनी भयंकर प्रतीत होने लगी थी कि राष्ट्रसंघ परिषद् ने १९२५ के प्रारम्भ में ही, एक दूसरा आयोजन इन उत्पातों संबंधी प्रतिवेशन देने के लिए मेजा। आयोजन का प्रतिवेदन (report) तुर्की प्रशासन-रीति के अत्यधिक प्रतिकूल था और उससे परिषद् को एक ऐसा सीमाना निश्चित करने में सहायता मिल सकती थी जिसमें संरक्षित क्षेत्र में मोसूल के विलायत का लगभग सारा ही क्षेत्र सम्मिलित हो जाना। कार्रवाई की प्रतिम स्थिति के समय, टर्की ने परिषद् से अपने प्रतिनिधि को वापस बुला लिया और वह अपने इस पुराने आश्वासन पर आ गया कि वह परिषद् के निर्णय को प्रतिम मानेगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय ने, उनके पास यह मामला भेजे जाने पर, यह मत प्रकट किया कि सुनाने सचि के अनुसार, परिषद् के निर्णय को बधनकारी बनाने के लिए सबभिन पक्षों के मन आवश्यक नहीं हैं। कुछ द्विचर्चावाहट के बाद, टर्की ने दुर्योग का भी लाभ उठाया और नए सीमाना को स्वीकार कर लिया, जिसकी पुष्टि जून १९२६ में ग्रेट ब्रिटेन, टर्की और ईराक में हुई एक सचि के द्वारा हो गई।

दूसरा विशाद बालकन देशों से संबंधित था। युद्ध के बाद कई वर्षों तक, यूनान और बल्गेरिया के सीमाना पर, छोटे-छोटे हमले और उत्पात होते रहते थे, जो कि मुख्यतः मेतियोनियन बुंदरों का काम होता था। अक्टूबर १९२५ में, इनमें से एक घटना के परिणामस्वरूप एक यूनानी सीमाना-चीकी (frontier post) के एक सेनापति और उसके एक सैनिक की मृत्यु हो गई। प्रतिशोधस्वरूप, एक यूनानी सेना ने बल्गेरिया के क्षेत्र में कूच कर दिया। बल्गेरिया की सरकार ने अनुबन्धन के अनुच्छेद ११ के अन्वये राष्ट्रसंघ से अरील की। इस पर परिषद् ने तुरन्त ही पेरिस में अपना अधिवेशन किया और यूनानी सरकार से अनुरोध किया था वह अपनी सेना हटा ले। इसके साथ ही अपने ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इटालियन सरकारों से भी यह अनुरोध किया कि वे अपने अधिकारियों को घटनास्थल पर यह देखने के लिए भेजें कि वहाँ क्या-क्या घटनाएँ हो रही हैं? इन कदमों ने यूनानी सरकार पर रोधक (deterrent) प्रभाव डाला। यूनानी सेना बल्गेरिया की भूमि से हट गई और

यूनान को राष्ट्रसंघ आयोग द्वारा निश्चित किए गए पैमाने पर बलगेरिया को उसकी भूमि के अतिक्रमण के लिए क्षतिपूर्ति की रकम चुकानी पड़ी। यूनान ने यह निर्णय मान लिया। किन्तु दो वर्ष पूर्व किए गए न्याय में, जबकि बिल्कुल इसी प्रकार की परिस्थितियों में यूनान को इटली के आक्रमण का सामना करना पड़ा था (देखिए पृष्ठ ५५), और इस न्याय में किए गए भेद की कुछ कटु मालोचना की गई।

तीसरे विवाद की जड़ पूर्वोक्त घटनाओं में ही थी। लिथुआनी सरकार ने, जिसने कि मित्र-राष्ट्र सरकार का यह निर्णय मानने में इन्कार कर दिया था जिसके अनुसार विलना पोलैंड के ही अधिकार में ही रहने दिया गया था, (देखिए पृष्ठ २८) पोलैंड की सरकार से अपने सबंध तोड़ लिये और दोनों देशों के बीच “युद्धस्थिति” (“state of war”) की घोषणा कर दी। इस घोषणा के समय से ही सीमांत सड़क, रेल या नदी द्वारा यातायात के लिए बंद रहा था किन्तु यह अस्वाभाविक स्थिति दोनों ओर से यदा-कदा होने वाली सीमांत घटनाओं और उत्तेजनापूर्ण वक्तव्यों से और भी बिगड़ गई। सन् १९२७ के शरद में, लिथुआनिया के जिदी तानाशाह वोल्डेमेरास (Voldemaras) ने विलना से कुछ लिथुआनियों को निकाल देने के अवसर का लाभ, अनुबध्पत्र के अनुच्छेद ११ के अधीन सारा मामला राष्ट्रसंघ में भेजने से, उठाया। दिसम्बर १० को परिषद् की एक बहुस्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें लिथुआनिया और पोलैंड (केवल इसी समय ही पिलसुदस्की जेनेवा आया था) के तानाशाह भी एक दूसरे के सामने उपस्थित हुए। इस उपस्थिति से जो सम्मत (agreed) प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह घोषणा था कि “राष्ट्रसंघ के दो सदस्यों के बीच युद्धस्थिति अनुबन्धपत्र के शब्दों और भावना से असंगत (incompatible with the spirit and letter) है।” फलस्वरूप लिथुआनिया ने पोलैंड के साथ युद्धस्थिति समाप्त कर दी। प्रस्ताव का शेष भाग अधिक आशाजनक नहीं था। विलना सम्बन्धी “मतभेद” पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। यह सिफारिश कि अन्य प्रश्नों के लिए दोनों सरकारें “स्वयं ही सीधी बातें चलाये” प्रमल में नहीं लाई गई और न ही कूटनीतिक या व्यापारिक सम्बन्ध पुनः स्थापित किए गये। जो भी हो, लंबे समय से चले आ रहे लिथुआनिया पोलैंड के इस विवाद के जेनेवा में प्रकाश में आ जाने से, यदि दोनों देशों में पुनः मित्रता

स्थापित नहीं हो सकी, तो तनाव तो कम से कम स्थायी रूप से कम हो ही गया। और राष्ट्रसंघ के लिए तो यह एक महत्त्वपूर्ण सफलता थी।

राष्ट्रसंघ द्वारा इन तीन विवादों का जो समाधान निकाला गया उस पर कुछ सामान्य चर्चा करने की इच्छा होती है। मोसूल और पोलैंड लियुप्रानिया दोनों ही विवाद बहुत असमान (unequal) शक्त के राज्यों के विवाद थे। दोनों ही मामले ऐसे थे कि उनमें अधिक शक्तिशाली राज्य के पास न केवल विवादग्रस्त क्षेत्र ही था, अपितु किसी तरह, उस पर विधिवत् अधिकार भी उसी का था। इन दोनों ही मामलों में, राष्ट्रसंघ ने कमजोर राज्य को आरामाभिमान (amour-propre) छोड़ बिना ही असमर्थनीय स्थिति (untenable position) से हट जाने में सहायता पहुँचाई। यूनान-बल्गेरिया विवाद कमजोर और बराबरी के ऐसे राज्यों में था, जिनके परिपक्व में प्रभावशाली समर्थक नहीं थे। इस स्थिति ने राष्ट्रसंघ की कार्यवाही को विशेष रूप से सभव बनाया। इससे परिपक्व के लिए निष्पक्ष निर्णय लेना और उसे दोनों ही पक्षों से स्वीकृत करा लेना सरल हो गया। इसके बाद युद्ध का खतरा उपस्थित करने वाले अन्य किसी विवाद के समय परिस्थितियों का ऐसा सीमाव्यपूर्ण सामंजस्य कभी नहीं पाया; अतः युद्ध रोकने में राष्ट्रसंघ की सफलता का यह घटना चरमबिन्दु ही रही।

राष्ट्रसंघ की इन सभी सफलताओं के बारे में सबसे प्रमुख बात यह थी कि ये सफलताएँ समझौते का मार्ग अपनाते हुए प्राप्त की गई थी। अन्तिम दो मामलों में, अनुबन्धपत्र के चौथे और आरहवें अनुच्छेद की प्रक्रिया अपनाई गई थी। चौथे अनुच्छेद में उपबन्धित किए अनुसार, दोनों ही पक्ष परिपक्व में आमने-सामने बैठे और उन्हें परिपक्व के सदस्यों को प्राप्त सभी अधिकार प्राप्त थे जिनमें मन देने का अधिकार भी शामिल था। निर्विरोध नियम (unanimity rule) के अनुसार इसका अर्थ यह था कि स्वयं पक्षों की ही स्वीकृति के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता था। मोसूल विवाद की प्रारम्भिक अवस्था में, बिल्कूल यही प्रक्रिया अपनाई गई थी यद्यपि टर्की राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था; और यद्यपि इस मामले की अन्तिम अवस्था में लोकानों सधि की शर्तों के आधार पर स्थायी न्यायालय द्वारा बिना कुछ अप्रत्याशित (unexpected) निर्णय ने इस प्रक्रिया को चलट दिया था, निर्णय

को कार्यान्वित (enforce) करने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठा। इन सभी मामलों में यह स्पष्ट हो चुका था कि परिषद् केवल अनुरोध रीति (method of persuasion) ही काम में ला सकती थी। अपनी सर्वाधिक प्रतिष्ठा और शक्ति की इस अवधि में, राष्ट्रसंघ का एकमात्र साधन उसका नैतिक अधिकार था, क्योंकि अनुच्छेद ११ के आधीन उसे अन्य कोई शक्तियाँ दी ही नहीं गई थी। अनुच्छेद १५ और १६ में उपबन्धित की गई निणय (judgment) और दण्डशक्ति (penalty) की प्रक्रिया का आश्रय लेने का सन् १९३२ से पहिले कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया।

राष्ट्रसंघ की अन्य गतिविधियाँ (Other Activities of the League)

यद्यपि शांति बनाए रखना ही राष्ट्रसंघ का सबसे महत्वपूर्ण और स्पष्ट कार्य था, तदपि उसकी नैतिक गतिविधियों (routine activities) जिनमें से अनेक अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का मान्य अंग बन गई, की कुछ चर्चा किए बिना १९१९ से बाद के अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों का कोई भी इतिहास अपूर्ण हो रहेगा।

राष्ट्रसंघ की कुछ गतिविधियाँ राजनैतिक थी। सरक्षण-आयोग (Mandates Commission) जिसमें कि स्थायित्व उपनिवेश सरकार विशेषज्ञ (experts in colonial government) शामिल थे, की बैठकें वर्ष में दो बार जेनेवा में होती थी। इन बैठकों में आयोग सरक्षक राष्ट्रों से प्राप्त उनके प्रशासन-क्षेत्रों सबंधी वार्षिक प्रतिवेदनो पर विचार करता था, तथा अपनी आलोचना और सिफारिशों के साथ उन्हें परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत करता था। परिषद् उन पर विचार करती थी और आवश्यकता होने पर उनके सबंध में अपनी सिफारिश करती थी। इस प्रयोजन के लिए सरक्षक राष्ट्र (चाहे वह परिषद् का नियमित सदस्य हो अथवा न हो) को परिषद् में बुलाया जाता था। अल्पसंख्यकों सबंधी संधियों (देखिए पृष्ठ ८) को पूरी करने के लिए एक दूसरे ही प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अल्पसंख्यकों की ओर से प्रार्थनापत्र (petitions) तथा जिस सरकार के विरुद्ध शिकायत की गई हो उसका उत्तर परिषद् के तीन सदस्यों की एक समिति को प्रस्तुत किए जाते थे। समिति संबंधित सरकार से इन मामलों की चर्चा करती थी (न कि अल्पसंख्यकों से जिन्हें कि सुनवाई का अधिकार नहीं था) और सामान्यतः उसका निबंटारा,

या तो सम्बन्धित सरकार को दोषमुक्तकर (exonerating) या उससे यह वचन प्राप्त करके कि शिकायत दूर कर दी जायगी, करती थी। यदि समिति सतोषजनक आश्वासन प्राप्त नहीं कर पाती तो मामला परिपद में भेज दिया जाता था जिसमें कि प्रतिवादी (defendant) सरकार को भी, नियमानुसार प्रतिनिधित्व दिया जाता था। इस प्रकार सरकार और अल्पसंख्यक दोनों ही से सम्बन्धित प्रक्रियाएं अनुवन्धपत्र के अनुच्छेद ११ के सिद्धान्त पर आधारित थीं अर्थात् निर्णय अनुरोध रीति के आधार पर और सम्बन्धित सरकार की स्वीकृति से किये जाते थे।

राष्ट्रसंघ की समय समय पर अन्य राजनैतिक कार्य भी करने पड़ते थे। सार (Saar) क्षेत्र पर उसने अपने शासी आयोग (Governing Commission) के जरिये सन् १९२० से १९३५ तक सफलतापूर्वक प्रशासन किया और १९३५ में वहाँ जनमत लिया। अन्य कोई भी क्षेत्र राष्ट्रसंघ के सीधे प्रशासन में नहीं रखा गया। किन्तु राष्ट्रसंघ ने स्वतन्त्र नगर डानजिग के सविधान की गारन्टी दी थी और वहाँ उसका एक उच्च आयुक्त (High Commissioner) रहता था, जिसका काम इस स्वतन्त्र नगर और पोलैंड के विवादों में पक्षनिष्ठ करना था। उच्च आयुक्त के निर्णयों के विरुद्ध परिपद में अपील करने का अधिकार दोनों ही पक्षों को था। सन् १९२४ से पहिले, जबकि जर्मनी और पोलैंड के बीच समझौते ने स्थिति बदल दी (देखिए अध्याय १० का "पोलैंड और सोवियत संघ" भाग), पोलैंड और डानजिग के बीच जितने विवाद परिपद के समक्ष आते थे, उतनी और कोई समस्या नहीं आती थी। इन विवादों को निबटाने में राष्ट्रसंघ-संगठन ने अत्यधिक कार्यकुशलता प्राप्त कर ली थी।

आर्थिक क्षेत्र में, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये राष्ट्रसंघ ने एक नया और विशाल संगठन तैयार कर लिया था। विभिन्न देशों के विशेषज्ञों की वित्त और अर्थ (financial and economic) समितियों की बैठकें प्रति वर्ष जेनेवा में होती थीं और राष्ट्रसंघ सचिवालय (secretariat) के वित्तीय और आर्थिक भागों के कार्य का संचालन करती थी। वित्तीय समिति विभिन्न राष्ट्रसंघ ऋणों को जारी करने और उनकी देखरेख के लिये उत्तरदायी थी। सन् १९२० में ब्रुसेल्स में एक सामान्य वित्तीय सम्मेलन हुआ था जिसका उद्देश्य युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माण पर विचार करना था। इसी प्रकार आयात नियंत्रण कर

(tariffs) और अन्य व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये जेनेवा में सन् १९२७ में एक ग्रंथ-सम्मेलन भी हुआ था।

राष्ट्रसंघ का सामाजिक और मानवतावादी कार्य किसी सीमा तक उसकी विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में सम्मिलित (co-ordination) था जोकि युद्ध से पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका था और कुछ अंशों तक नए सिरे से भी प्रारम्भ हुआ था। इन सभी गतिविधियों में सबसे पुरानी गतिविधि दासता के विरुद्ध अभियान थी। सन् १९२५ में जेनेवा में एक दासता सम्मेलन (Slavery Convention) हुआ था। सन् १९३२ में राष्ट्रसंघ ने एक स्थायी दासता-आयोग (Permanent Slavery Commission) स्थापित करने का निश्चय किया। राष्ट्रसंघ के अन्य संगठनों के जिम्मे भयंकर प्रोषधियों का व्यापार, स्त्री-व्यापार (traffic in women), शिशु संरक्षण, शरणार्थियों को राहत और उन्हें बसाना, तथा स्वास्थ्य एवं बीमारियों को, उनके अन्तर्राष्ट्रीय पहलू की दृष्टि में रक्षित हुए, उनका निबटारा करना था।

अंत में, दो ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी थे, जो यद्यपि राष्ट्रसंघ के प्राय-व्यय (budget) में शामिल थे तदपि प्रशासनिक तौर पर उनसे स्वतन्त्र थे। ये थे—अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ (International Labour Organisation) संघ और अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice)।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ, जिसका कार्यालय जेनेवा में था, का निर्माण शांति संधियों के परिणामस्वरूप इस उद्देश्य से हुआ था कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा श्रमिकों की स्थिति में सुधार किया जा सके। उसका विधान राष्ट्रसंघ के विधान जैसा बनाया गया था। उसके वार्षिक सम्मेलन (Annual Conference), प्रबन्धकारिणी (Governing Body) और कार्यालय (Office) क्रमशः राष्ट्रसंघ की सभा, परिषद् और सचिवालय के समान थे। इन अर्थों में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ में राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य तथा अमेरिका, जापान और ब्राज़िल शामिल थे। उसके वार्षिक सम्मेलन में हर राष्ट्र के चार प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे जिनमें से दो सरकार द्वारा एक श्रमिकों के संगठनों द्वारा और एक श्रमिकों के संगठनों द्वारा नियुक्त किये जाते थे। श्रमिकों की स्थिति के विभिन्न पहलुओं में सम्बन्धित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किये गये थे किन्तु उनमें से सभी का अनुसमर्थन नहीं किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय की स्थापना राष्ट्रसंघ द्वारा अनुबन्धन के अनुच्छेद १४ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के ऐसे किसी भी विवाद को निबटाने के उद्देश्य से की गई थी जोकि “सम्बन्धित पक्ष उसके सम्मुख प्रस्तुत करें” तथा परिषद् या सभा द्वारा उनके पास भेजे गये प्रश्नों पर “परामर्शपूर्ण राय” (advisory opinions) देने के लिये की गई थी। उसके पंद्रह न्यायाधीशों की एक क्रमसूची (panel) थी जिसकी नियुक्ति हर नौवें वर्ष परिषद् और सभा द्वारा की जाती थी। यह न्यायालय हेग में सगता था। न्यायालय के विधान (statute) में एक तथा-कथित “ऐच्छिक धारा” (“Optional Clause”) भी थी जिस पर हस्ताक्षर करने वालों के लिये यह आवश्यक था कि वे उनके और राष्ट्रसंघ के अन्य सदस्यों के बीच वैदिक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के विवाद को उनके सामने निर्णय के लिये प्रस्तुत करें। लगभग पचास राज्यों ने, जिनमें बड़े राष्ट्र भी शामिल थे, इस धारा पर हस्ताक्षर किये थे यद्यपि उनमें से कुछ ने कुछ ही बातों के लिये उस पर हस्ताक्षर किये थे। अमरीकी सरकार ने दो बार स्थायी न्यायालय जिनमें कि हमेशा ही अमरीकी न्यायाधीश रहना था, की प्रति हठ रहने का प्रयत्न किया किन्तु हर बार उसका यह प्रस्ताव गिर गया। सन् १९२२ और १९३६ के बीच, इस न्यायालय ने पचास से भी अधिक मामलों में अपने निर्णय और राय दी।

६. युद्ध-विरोधी अभियान (The Campaign Against War)

लोकानों सधियों के कारण सुरक्षा-खोज (quest for security) समाप्त नहीं हो सकी थी। प्रास लोकानों पर इस सीमा तक विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि वह (प्रास) अपनी योरोपीय गुटबन्धियाँ समाप्त कर दे या अपना निःशस्त्रीकरण कर दे। उसके कार्यक्रम में सुरक्षा को प्रथम स्थान प्राप्त था। उसके साधियों को इस सुरक्षा की आवश्यकता थी क्योंकि लोकानों सधि ने उसके लिए कुछ भी ध्वरथा नहीं की गई थी, और इस आवश्यकता का प्रास ने निःशस्त्रीकरण के बढ़ते हुए दबाव के विरुद्ध ढाल के रूप में उपयोग किया था। जेनेवा में १९२२ में प्रथम बार फ्रांसीसी मंत्रिमंडल ने जिस चाल से काम लिया था वही चाल अब फ्रांसीसी नीति का एक अंग बन चुकी थी। जब कभी भी ब्रिटिश (या १९२६ के बाद, जर्मन) प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रसंघ या उसके अङ्गों को निःशस्त्रीकरण की महत्ता का पुनर्स्मरण कराता था, तब फ्रांसीसी, पोलिश और लघु मंत्रीसंघ के प्रतिनिधिमंडल यह राग ओरो से सजापते कि निःशस्त्रीकरण से पहिले सुरक्षा आवश्यक है। राष्ट्रसंघ के सदस्य दो खेमों में प्रायः बँट जाते; कुछ का विचार यह होता कि निःशस्त्रीकरण से सुरक्षा बढ जाएगी, और कुछ यह सोचते कि सुरक्षा के पश्चात् ही निःशस्त्रीकरण होना चाहिए। किन्तु कोई भी इस सिद्धान्त में सशय नहीं करता कि निःशस्त्रीकरण और सुरक्षा में क्लिष्ट अन्वयो-याश्रय संबंध (close interdependence) है। यह सिद्धान्त, जो कि परस्पर सहायता-सधि (Treaty of Mutual Assistance) और जेनेवा उपसधि का गभिताधार (implied basis) था, लोकानों-उत्तर काल (post-Locarno period) में राष्ट्रसंघ की कार्यवाही को प्रभावित करता रहा।

सन् १९२६ में गठित किए गए निःशस्त्रीकरण सम्मेलन-तैयारी आयोग (Preparatory Commission for the Disarmament Conference) के बाद से प्रारम्भ हुई निःशस्त्रीकरण वार्ताओं का विवेचन किसी

अगले अध्याय में लिया जाएगा। किंतु इसके साथ ही साथ सुरक्षा-समस्या को सुलझाने के लिए किए गए राष्ट्रसंघ के प्रयत्नों का विवेचन यहाँ करना आवश्यक है। क्योंकि विवादों के समाधान और युद्ध को रोकने के लिए एक नया तरीका अपना देने के लिए किए गए ये सैद्धान्तिक प्रयत्न लोकानों के नाद के आशावाद-काल (period of optimism) की विशेषता थे और पिछले अध्याय में वर्णित राष्ट्रसंघ की व्यावहारिक गतिविधियों ने श्रृंखला में।

राष्ट्र-संघ समझौते (Conventions)

सन् १९२६ से १९२६ तक की अवधि में युद्ध के विरुद्ध सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने संबंधी प्रस्तावों की भरमार रही, सभा के हर अधिवेशन में कोई न कोई नया प्रस्ताव आता।

सन् १९२६ में, फिनलैंड के प्रतिनिधि ने एक योजना प्रस्तुत की कि जिन राज्यों पर आज्ञाकारी की संभावना हो, उन्हें राष्ट्रसंघ के अन्य सदस्यों से अनुकूल शर्तों (favourable terms) पर आर्थिक सहायता किस प्रकार प्राप्त हो सकती है—स्पष्ट ही है कि यह योजना राष्ट्रसंघ ऋणों की सफलता से प्रोत्साहित हो तैयार की गई थी। इस प्रकार की सहायता का वास्तविक अर्थ यह था कि अनु-वधपत्र के सोलहवें अनुच्छेद में विहित किए अनुसार आज्ञाकारी राज्य को आर्थिक सुविधाएँ नहीं दी जाएँ। अन्ततोगत्वा, यह प्रस्ताव “आर्थिक सहायता समझौता” (“Convention on Financial Assistance”) के रूप में सामने आया जो कि १९३० में सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। किंतु चूंकि उसका अमल में आना इस शर्त पर आधारित था (निःशस्त्रीकरण और सुरक्षा के अनिवार्य श्रवण के सिद्धान्तानुसार) कि उससे पहिले एक निःशस्त्रीकरण समझौता किया जाए, यह समझौता एक योजना मात्र ही रह गया।

सन् १९२७ में, जब राष्ट्रसंघ सभा का अधिवेशन हुआ, तब निःशस्त्रीकरण सम्मेलन तैयारी आयोग की अपने मार्ग की चट्टानों का ज्ञान हो चुका था तथा ग्रीष्मकाल में जेनेवा में हुए एक सीमित नौसैनिक सम्मेलन (limited naval conference) की नीका डूब चुकी थी। इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने राष्ट्रसंघ सभा को सुरक्षा-समस्या में फिर ला फँसाया। सन् १९२४ के बाद पहिली बार, यह बाना फूँसी सुनाई देने लगी कि जेनेवा उपसंधि को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। नीदरलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रसंघ-सभा

से अनुरोध किया कि, "अनुबंधपत्र में अभिव्यक्त नि शस्त्रोकरण, सुरक्षा और पंचनिर्णय के सिद्धान्तों का पुनः अध्ययन किया जाए।" तदनुसार सभा ने तैयारी-आयोग से अनुरोध किया कि वह पंचनिर्णय और सुरक्षा के प्रश्न पर विचार के लिए एक समिति नियुक्त कर दे, "जिसका कर्तव्य इस बात पर विचार करना हो कि वे कौन से उपाय हो सकते हैं जिनका आश्रय लेकर सभी राज्यों को सुरक्षा की ऐसी गारंटियाँ मिल जाएँ कि वे अंतर्राष्ट्रीय नि शस्त्रोकरण संधि में अपने शस्त्रों की यथासंभव न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकने में समर्थ हो सकें।"

सन् १९२७ और १९२८ के राष्ट्रसंघ-सभा के अधिवेशनों के अंतराल (interval) में, पंचनिर्णय और सुरक्षा समिति ने अदम्य उत्साह से अपना कार्य किया। राष्ट्रसंघ-सभा के अधिवेशन के समय, नॉर्वे के प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखे गए एक सुझाव से उसे प्रेरणा मिली। सन् १९२४ के अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पंचनिर्णय के पथ पर राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य समान रूप से भागे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अब यह सुझाव रखा गया था कि जेनेवा उपसंधि के समान राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार करने के लिए समझौता तैयार न कर यदि कुछ ऐसी "आदर्श संधियाँ" ("Model Treaties") तैयार की जा सकें जो कि दो-दो राज्यों या कुछ राज्यों के समूहों द्वारा स्वीकार करली जावें, तो इस दिशा में प्रगति की जा सकती है। इस प्रकार अत्यधिक समुन्नत राज्य अपने सभी विवादों के पंचनिर्णय के लिए आपस में समझौते कर सकते थे। अल्प समुन्नत राज्य वैधिक विवादों को पंचनिर्णय द्वारा तय कराने के लिए सहमत हो सकते थे। जो राज्य अनिवार्य पंच निर्णय को स्वीकार करने के लिए अभी बिलकुल तैयार नहीं थे, वे समझौते का माग भ्रपनाना या युद्ध का खतरा कम करने के अन्य तरीकों को भ्रपनाना संभवतः स्वीकार कर सकते थे। इस समिति ने सन् १९२४ की सभा में विचारार्थ कम से कम दस ऐसी "आदर्श संधियाँ", तैयार की जो कि आशय-सकोच की विभिन्न मात्राओं से परिपूर्ण थे।

सामग्री की इस प्रचुरता को देख, सभा ने एक ऐसा मार्ग भ्रपनाया जिसमें "आदर्श संधि" (model treaty) और "सामान्य समझौते" की प्रच्छाद्यों का संभवतः समावेश किया गया था। उसने तीन सर्वाधिक आशाप्रद प्रारूप लिए और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सामान्य

अधिनियम (General Act for the Pacific Settlement of International Disputes) के प्रथम तीन अध्यायों का रूप दे दिया। प्रथम अध्याय में यह व्यवस्था की गई थी कि अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाले हर दो राज्य एक स्थायी समझौता आयोग (Permanent Conciliation Commission) की स्थापना करें जिसका कर्तव्य, उनके विवादों के मित्रतापूर्ण, न कि बघनकारी, समाधान की सिफारिश करना हो। दूसरे अध्याय में यह विदित किया गया था कि सभी वैधिक विवाद अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएँ और उसका निर्णय बघनकारी हो। तीसरे अध्याय में भी इसी प्रकार यह निश्चित किया गया था कि अवैध (Illegal) विवाद एक पक्ष-समिति (committee of arbitrators) के सामने प्रस्तुत किए जाएँगे जिसके अध्यक्ष का चुनाव, यदि समझौता न हो सके तो, अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय द्वारा किया जाएगा। चौथे अध्याय में यह उपबधित किया गया था कि राष्ट्रसंघ के सदस्य एक या एक से अधिक अध्यायों को स्वीकार कर सकते हैं और यदि वे चाहें तो, विशिष्ट प्रकार के विवादों को इस अधिनियम के अधीन निबटाए जाने से मुक्त रख सकते हैं।

यह व्यवस्था सभी लोगों की अच्छी लगने योग्य प्रतीत हुई। किन्तु अधिनियम को अधिक सफलता नहीं मिली। यह अनुभव किया गया कि पहला अध्याय का अधिक महत्त्व नहीं है। समझौता आयोगों की व्यवस्था अमेरिका और अन्य देशों के बीच युद्ध से पूर्व हुई संधियों में तथा जर्मनी और उसके पड़ोसी राष्ट्रों में हुई संधियों में की जा चुकी थी। किन्तु उनका कभी कोई उपयोग नहीं किया गया था। अध्याय दो का समावेश स्थायी न्यायालय के विधान की ऐच्छक धारा को स्वीकार कर लेने में हो ही चुका था। अध्याय तीन में जेनेवा उपसंधि के एक प्रमुख रोड़े को पुनः झा खड़ा किया था किन्तु हम बार केवल यही आश्चर्यजनक था कि इस अध्याय ने राष्ट्रसंघ परिषद् की विलकुल हो तक में रत्न दिया था। यहाँ तक कि उसे पक्ष समिति नियुक्त करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था (जेनेवा उपसंधि तक में उसे यह अधिकार दिया गया था)। सन् १९२८ की राष्ट्रसंघ-सभा द्वारा इस सामान्य-अधिनियम का अनुमोदन किए जाने के दो वर्षों के भीतर केवल बेल्जियम, नार्वे, डेनमार्क और फिनलैंड ने ही इस अधिनियम को आयुक्त स्वीकार किया था जबकि हॉलैंड और स्वीडन ने उसके प्रथम दो अध्यायों को ही स्वीकार किया था।

पेरिस समझौता (Pact of Paris)

इसो बीच, एक दूसरे ही क्षेत्त्र से इस दिशा में नया प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। सन् १९२८ में, राष्ट्रसंघ-सभा के अधिवेशन से कुछ दिनों पूर्व ही, पेरिस में एक प्रभावकारी और महत्त्वपूर्ण विधि सपन्न हुई— यह विधि युद्ध को त्याग देने सबंधी समझौते पर हस्ताक्षर से संबंधित थी जिसे कि साधारणतः पेरिस समझौता या ब्रायएड कीलग समझौता (Briand-Kellogg Pact) कहा जाता है। यह कुछ अन्यायपूर्ण बात ही है कि इस घटना का जनता द्वारा जितना स्वागत किया गया, उसका लेखमात्र भी राष्ट्रसंघ का नहीं किया गया। क्योंकि १९२७ की राष्ट्रसंघ की सभा जिसने कि युद्ध को रोकने के प्रश्न पर इतना विचार किया था, के अधिवेशन में पोलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने यह पवित्र घोषणा करने का प्रस्ताव रखा था कि “अकारण आक्रमण के सभी युद्ध निषिद्ध हैं और सर्वद्व निषिद्ध रहने”^१ और इस घोषणा को निर्विरोध स्वीकार लिया गया था। जो भी हो, ऐतिहासिक दृष्टि से, पेरिस समझौते का इतिहास ही भिन्न था। अप्रैल १९२७ में, कुछ प्रभावशाली अमरीकियों की एक संस्था से प्रेरणा पाकर, ब्रायएड ने अमरीकी सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि फ्रांस और अमेरिका यह समझौता करें कि युद्ध दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय नीति का साधन नहीं रहेगा। चूंकि फ्रांस और अमेरिका के बीच ऐसे किसी राष्ट्रीय हित की कल्पना करना कठिन था जो कि उनमें युद्ध करा सके, अतएव इस प्रकार के समझौते का व्यावहारिक महत्त्व कम ही था। किन्तु इससे फ्रांस को योरोप में अमेरिका के विशिष्ट मित्र और सहकारी (associate) के रूप में कुछ प्रतिष्ठा तो मिल ही सकती थी, और संभवत इसी कारणवश अमरीकी विदेश मंत्री (Secretary of State) कीलग ने, काफी विलंब के बाद, प्रस्ताव का उत्तर एक प्रत्युत्तर-प्रस्ताव (counter proposal) रखकर दिया जिसमें यह सुझाया गया था कि यह समझौता व्यापक रूप में लागू होना चाहिए। आगे चलकर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अगस्त २७, १९२८ को छः माने हुए बड़े राष्ट्रों (अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान) तीन अन्य “लोकार्थो राष्ट्रों” (बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया) ब्रिटिश अधिराज्य और भारत के प्रतिनिधि पेरिस में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए

1. “All wars of aggression are, and shall always be, prohibited”

एकजिन हुए। शेष सत्तार के हर स्वतन्त्र राज्य से इस सम्झौते में शामिल होने का प्रयत्न किया गया था।

“आपसी सम्बन्धों में राष्ट्रीय नीति के साधन” (“as an instrument of national policy”) के रूप में युद्ध को त्यागने सम्बन्धी वचन का जो अर्थ हस्ताक्षरकर्ताओं ने समझाया था, वह हस्ताक्षर में पहिले उनमें हुए पत्र व्यवहार से स्पष्ट है। सम्झौते के मूल लेखक तो पहिले ही यह घोषित कर चुके थे कि आत्मरक्षा के लिए युद्ध पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु यह घोषणा शान्तिवादी सत्याग्रह सिद्धांत (pacifist doctrine of non-resistance) को अस्वीकार करता नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसके मामले में, आत्मरक्षा के अधिकार में, “विश्व के कुछ ऐसे भागों” की रक्षा करने का अधिकार भी शामिल है, “जिनका कल्याण और अखंडता हमारी शान्ति और सुरक्षा के लिए विशेष तथा महत्वपूर्ण हित रखता है।” अमेरिका के लिए, आत्मरक्षा में ऐसी कोई भी कार्यवाही शामिल थी जो कि मुनरो सिद्धांत का उल्लंघन (infringement of the Monroe Doctrine) रोकने के लिए आवश्यक हो। इन शर्तों ने (जिनके उन्हें औपचारिक निर्वन्ध (formal reservations) नहीं माना गया था) इस सम्झौते के सामान्य स्वरूप की सहायता ही की। कई लोगों को उभे कानूनी अनुरोधों (contractual obligation) की प्रतीति सिद्धांतों को घोषणा ही प्राथमिक मानने थे। हर राज्य अपने कृत्यों का एकमात्र निर्णायक था। सम्झौते के निर्वन्ध या प्रवर्तन के लिए न तो कितनी साठन की आवश्यकता ही थी गई थी और न ऐसा विचार ही था।

यद्यपि पेरिस-समझौता अपूर्ण था, तदर्थ वह एक पर्याप्त सीमा चिह्न (land-mark) था। इतिहास में वह पहिला ही राजनैतिक सम्झौता था जिसका क्षेत्र लगभग सभी देश थे।^१ मर्केन्टाइना, ब्राजिल, कोलम्बिया और सेल्वेडोर (Salvador) जिन्हें कि मुनरो सिद्धांत की पुनर्घोषणा में क्षति हुई थी, सबसे दूर ही रहे। किन्तु कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को छोड़, शेष अन्य

१ “Imperfect though it was, the Pact of Paris was a considerable land mark. It was the first political agreement in history of almost universal scope.”

सभी राज्य, शीघ्र ही उसमें शामिल हो गये। आरम्भ में कुछ हिचकिचाहट के बाद, सोवियत संघ का उत्साह इतना बढ़ा-चढ़ा था कि सामान्य अनुसमर्थन के पहिले ही उसने पेरिस-सम्मेलन को परस्पर लागू करने के लिए अपने पड़ोसी देशों से विशेष सम्मेलन सम्पन्न किये। कम से कम पसंठ—यह सख्या राष्ट्रसंघ की सदस्य सख्या से सात अधिक थी—राज्यों ने इस सम्मेलन को स्वीकार कर लिया। यह सचमुच ही सम्भव मालूम पड़ता है कि कुछ राज्य तो मुंह बचाने की इच्छा से इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, न कि उसकी उपयोगिता में किसी विश्वास के कारण। जापान और इटली ने शीघ्र ही उसका निंदास्पद उत्तर दे दिया। जापान ने उसे पुलिस कार्रवाई बताया था तो इटली ने उसमें भी भारी बड़ उसे आत्म-रक्षात्मक युद्ध कहा। किन्तु इससे इस सत्य का महत्त्व नहीं घट जाता कि तत्कालीन राष्ट्र मिलकर युद्ध पर यह प्रतिबन्ध लगाने के लिए उद्यत थे कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के सुलझाने के लिए युद्ध एक सामान्य और वैध (legitimate) मार्ग नहीं है। सम्मेलन के अमरीकी प्रेरणादाताओं द्वारा व्यवहृत “युद्ध की अवैधता (outlawry of war)” शब्द (term) का आशय ही यह था कि यह एक ऐसा सर्वमान्य, अलिखित कानून है जिसके विरुद्ध किया गया युद्ध, अपराध घोषित किया जाना था। इस कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने के लिए या यह घोषित करने के लिए भी कि कानून का उल्लंघन किया गया है, कोई अधिकार नहीं था। किन्तु विश्व के राजनैतिक विचार-जगत में इस सिद्धांत ने अपनी जड़ जमा ली।

पेरिस सम्मेलन का इतना उत्साहपूर्ण स्वागत स्वभावतः राष्ट्रसंघ के लिए चुनौती प्रतीत होने लगा। राष्ट्रीय नीति के एक साधन के रूप में युद्ध का आश्रय लेने पर अनुबन्धपत्र में सम्पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध नहीं था। राष्ट्रसंघ का सदस्य किन परिस्थितियों में न्याय्य रूप से युद्ध का आश्रय ले सकता था इसकी प्रति संक्षिप्त व्यवहार्य सीमाएं अनुबन्धपत्र के लेखकों ने बांध दी थी। बूँकि राष्ट्रसंघ के लगभग हर सदस्य ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया था वह कभी भी युद्ध (आत्म-रक्षा को छोड़) का आश्रय नहीं लेगा, अतः सामान्य बुद्धि का यह तर्काजा प्रतीत होता था कि इस नए उत्तरदायित्व का समावेश अनुबन्ध-पत्र में कर उसे दृढ़ बनाया जाए इसीलिये सन् १९२६ की सभा में, ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने इसी परिणाम की प्राप्ति के लिए जिस समय अनुबन्धपत्र में

कई सन्धियों का प्रस्ताव रखा तो किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। ग्रेट ब्रिटेन में हाल ही में सत्तारूढ़ हुई मजदूर दलीय सरकार अपनी पूर्वगामी (predecessor) सरकार की नकारात्मक नीति (negative policy) को उलट देना चाहती थी।

जो भी हो, यह प्रक्रिया जितनी सहज दिखती थी, उससे कम सहज ही साबित हुई। पेरिस-समझौता एक नैतिक घोषणा थी जिसका आधार युद्ध-नाश (sinfulness of war) की सामान्य भावना थी। अनुवन्धपत्र एक राजनैतिक संधि था जिसके प्रमुख उपबन्धों का आधार वे बातें थी जिन्हें १६१६ के राजनीतिज्ञ व्यवहार्य और इष्टकर (expedient) मानते थे। पेरिस-समझौते के द्वारा सभी प्रकार के युद्धों की निन्दा की गई थी। किन्तु उनमें से किसी के लिए भी दंड की उसमें व्यवस्था नहीं थी। अनुवन्धपत्र में कुछ युद्धों का आश्रय लेने की अनुमति थी और कुछ युद्धों का उसमें निषेध था। किन्तु निषिद्ध युद्धों के लिए दंड की व्यवस्था भी उसमें थी। आशय में इतने विभिन्न लेखों (instruments) को एकीकृत करना और इस एकीकरण को प्राकर्षक बनाना अनिमानवीय कार्य ही था।^१ यदि समझौते की धारणा को अनुवन्धपत्र में जोड़ो का लो शामिल कर दिया जाना तो ऐसा दस्तावेज तैयार हो जाता जिसके एक भाग में युद्ध का पूर्णतया निषेध होता और दूसरे भाग में किन्हीं स्थितियों में युद्ध का आश्रय लेने की अनुमति होती—यह निदास्पद विरोधाभास ही होता। अगर प्राकृतिक एकीकरण (organic fusion) की दिशा में और आगे बढ़ा जाना तो, हमारे सामने एक संशोधित अनुवन्धपत्र आता जिसमें कि सभी

-
- १ "The Pact of Paris was a moral declaration, based on a general sense of the sinfulness of war. The Covenant was a political treaty, based in its essential provisions on what the statesmen of १९१९ deemed practicable and expedient. The Pact condemned all wars, but punished none. The Covenant allowed some wars and prohibited others, but prohibited wars it punished. To fuse together instruments so different in spirit and to make a neat job of the fusion, was a superhuman task."

युद्धों का निषेध होता किन्तु कुछ ही युद्धों के आश्रय पर दण्ड की उसमें व्यवस्था होती—इस प्रकार अनमने भाव से हमें यह स्वीकार करना पड़ता कि अनुबंध-पत्र के कुछ भागों का उल्लंघन अपनी हानि किए बिना ही किया जा सकता था।

ये दोनों ही मार्ग कार्यरतपूर्ण और राष्ट्रसंघ को शोभा नहीं देने वाले प्रतीत हुए। अतएव यही मार्ग चयन रह गया था कि अनुच्छेद १६ की अनुशास्तियाँ न केवल वर्तमान अनुबंधपत्र द्वारा निषिद्ध युद्धों पर लगाई जाएँ अपितु पेरिस-सम्मेलन द्वारा निषिद्ध सभी युद्धों पर भी। इस प्रकार युद्ध को सर्वथा निषिद्ध कर इससे न केवल अनुबंधपत्र का आधार दृढ़ हो जाता अपितु पेरिस-सम्मेलन में भी एक नई शक्ति आजाती क्योंकि राष्ट्रसंघ के सदस्यों द्वारा उसका उल्लंघन दण्डनीय हो जाता। तो, ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने १९२६ में इसी प्रकार का प्रस्ताव रखा था और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने उसका हार्दिक समर्थन किया था क्योंकि फ्रांस को उसमें अपनी सुरक्षा के शुभ चिह्न दिखाई देते थे। इस प्रस्ताव के विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति यह थी जो कि जेनेवा उपसंधि के लिए घातक (fatal) सिद्ध हुई थी अपितु, यदि अनुच्छेद १६ का विस्तार किया गया, तो अनुशास्तियाँ लागू करने से जिन राष्ट्रों का सम्बन्ध सबसे अधिक आएगा, उनका कर्तव्यों में स्वतः ही वृद्धि हो जायेगी। किन्तु इस समय ब्रिटिश सरकार, जिसने कि १९२५ में मुख्य रूप से आपत्ति उठाई थी, इस भय से भयभीत नहीं हुई थी। इस कारण यह प्रतीत होता था कि प्रस्तावित सशोधन भासानी से स्वीकृत हो जाएँगे।

यदि १९२६ में इन सशोधनों पर मत लिए जाते तो यह वास्तव में सम्भव है कि उन्हें सभी का अनुमोदन मिल जाता यद्यपि इस कारण से बाद में उनकी जेनेवा उपसंधि जैसी दुर्गति होने से शायद ही बच सकती थी किन्तु १९३० की सभा तक उन पर विचार-विमर्श स्थगित कर दिया गया, और इस समय तक संशय की लहर भी फैल चुकी थी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल तीव्र-कमान साथ लेकर आए। किन्तु स्केन्डेनेवियन देशों और जापान ने इसका तीव्र विरोध किया। सशोधन इस समय भी काफी बहुमत से स्वीकृत हो सकते थे किंतु इसमें बहुत अधिक संदेह था कि बहुमत द्वारा स्वीकृत सशोधनों का अनुसमर्थन भी किया जाएगा। इसलिए यह दूरदर्शितापूर्ण निश्चय किया गया कि इस प्रश्न को अपनी सभा तक के लिए स्थगित कर दिया जाय। सितम्बर १९३१

तक ग्रेट ब्रिटेन आर्थिक संकट के चंगुल में फँस चुका था और वहाँ की सरकार भी बदल चुकी थी। आशावाद-काल का अन्त हो गया, और प्रस्तावित संशोधनों का निबटारा बातचीत द्वारा ही कर दिया गया।

ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में पेरिस सम्मेलन को अनुबन्धपत्र में शामिल करवाने के लिए किया गया साहसपूर्ण प्रयत्न, राष्ट्रसंघ के ज़रिए बर्धित सुरक्षा-खोज की अन्तिम महत्वपूर्ण कहानी थी जो (सुरक्षा-खोज) १९२२ में प्रारम्भ हुई थी तथा, जेनेवा उपसंधि की असफलता के बाद, १९२७ में पुनः प्रारम्भ की गई थी। सन् १९३० की सभा के बाद बादल शीघ्र ही घिरते चले आए। सन् १९३१ के शीष्म में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों द्वारा सामान्य अधिनियम का अनुसमर्पण किया जाना तथा १९३१ की सभा में युद्ध-निरोधक उपायों में सुधार-सम्मेलन (Convention to improve the Means of Preventing War) (जो कि पब्लिक और सुरक्षा समिति की एक "प्रावर्श संधि" के रूप में प्रारम्भ हुआ था) पर हस्ताक्षर यदा-कदा चमकने वाली विद्युत् के समान घटनाएँ थीं जो कि पहिले जैसा उत्साह पैदा नहीं करती थी। सन् १९३० की राष्ट्रसंघ-सभा का अधिवेशन ही एक ऐसा अन्तिम अधिवेशन था जिसमें यह अनुभव किया जा सकता था (कई लोग तो लोकानों के समय से ही ऐसा अनुभव करने लगे थे) कि ससार प्रतिवर्ष सुरक्षित होता जा रहा है। राष्ट्रसंघ धीरे धीरे एक ऐसा संगठन बना लगा जो युद्ध को रोकने में समर्थ सिद्ध होगा।

✓ युग योजना (The Young Plan)

अन्तर्युद्ध इतिहास काल, (inter-war history) जिसे हमने "शांति-करण अवधि", कहा है, की शांति और आशावाद, जैसा कि हम पहिले देख चुके हैं, मुख्यतः फ्रांस और जर्मनी के सम्बन्धों में सहसा सुधार—जो कि डेविस योजना और लोकानों संधि के कारण हुआ था—के परिणाम थे। लोकानों राजनीतिज्ञों का त्रिगुण (trio)—स्ट्रेसमान, ब्रायण्ड और प्रॉस्टिन चेम्बरलेन—अपने अपने देशों के विदेशी मामलों का संचालन १९२६ के शीष्म काल तक करता रहा। इन तीनों व्यक्तियों में जो आपसी विश्वास और मित्रता उत्पन्न हो सकी, वह इन वर्षों में योरोप में स्थिरता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारण

थी। और इसका श्रेय राष्ट्रसंघ को मिलना चाहिए क्योंकि परिषद् और समा की नियमित बैठकों में ही इन व्यक्तिगत सबंधों का बनना संभव हो सका था। फ्रांस और जर्मनी की पुरानी शत्रुता टल गई और निःशस्त्रीकरण संबंधी चर्चा के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर उसका आभास जेनेवा में मुश्किल से हो मिलता था।

यद्यपि फ्रांस-जर्मनी समस्या अस्थायी रूप से दृष्टि से ओझल हो चुकी थी, तदपि वह कभी भी मुलाई नहीं जा सकी थी। सन् १९२६ की राष्ट्रसंघ सभा के अधिवेशन के दौरान में, जबकि जर्मनी को राष्ट्रसंघ में सम्मिलित किया गया था, ब्रिग्स और स्ट्रेसमान ने जेनेवा के निकट थॉयरी (Thoiry) नामक ग्राम में लम्बे समय तक निजी चर्चाएँ कीं। उनके बाद प्रकाशित की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया था कि दोनों ही मंत्रियों ने दोनों देशों सबंधी सामान्य हित के सभी मामलों पर विचार-विनिमय किया तथा “सामान्य समाधान (general solution) सम्बन्धी उनके दृष्टिकोण एक हो सके हैं” और अपनी-अपनी सरकारों के सामने यह दृष्टिकोण वे अनुमोदन के लिए रखेंगे। दृष्टिकोणों में किस प्रकार की अस्थायी एकता भागई थी यह सरकारी तौर पर प्रकट नहीं किया गया था। किन्तु यह स्पष्ट था कि स्ट्रेसमान ने राइनभूमि को तुरन्त खाली कर देने और सार (Saar) जर्मनी को लौटा देने का अनुरोध किया था और उनके बरले में, उसने क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में “सुविधाएँ” देने का प्रस्ताव रखा था, तथा ब्रिग्स व्यक्तिगत रूप से इस प्रस्ताव पर समझौता कर लेने के लिए तैयार था। किन्तु फ्रांसीसी सरकार वर्सेलोज की संधि द्वारा राइनभूमि पर मित्र-राष्ट्रों के अधिकार और सार पर राष्ट्रसंघ के नियन्त्रण सम्बन्धी समय-सीमाओं (time-limits) में इतनी क्रांतिकारी कमी करने में लिए तैयार नहीं थी। इसके साथ ही स्ट्रेसमान का क्षतिपूर्ति (reparation) के रूप में नकद भुगतान सम्बन्धी प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से अव्यवहार्य था। थॉयरी वार्ताओं का कोई परिणाम नहीं निकला। किन्तु इस असफलता के कारण फ्रांस और जर्मनी की मित्रता को कोई तत्काल-आघात नहीं पहुँचा। दिसम्बर में यह समझौता होगया कि जर्मनी में मित्र-राष्ट्रों का सैनिक नियन्त्रण (military control) समाप्त कर दिया जाये, और ३१ जनवरी १९२७ को अन्तर् मित्र राष्ट्रीय आयोग (Inter-Allied Commission) हटा लिया गया।

पॉररी चर्चाओं के दो प्रमुख विषय—राइनमूमि और क्षतिपूर्ति—मगले दो वर्षों में फ्रांस और जर्मनी के सम्बन्धों को सबसे अधिक प्रभावित करते रहे। वसैलीय की संधि ने अधिकृत राइनमूमि को तीन भागों में विभाजित कर दिया था जो सन्धि समल में आने के बाद क्रमशः पाँच, दस और पन्द्रह वर्षों के बाद खाली किए जाने थे। प्रथम भाग को, १९२५ के अन्त में कई महीनों के बिलम्ब के पश्चात् खाली किया जा चुका था। दूसरे और तीसरे भाग १९३० और १९३५ से पहिले खाली नहीं किए जाने वाले थे। किंतु चूंकि अब सम्बन्धों में सुधार हो चुका था, पूरी राइनमूमि को मित्र-राष्ट्रों के अधिकार से तुरन्त मुक्त कराना जर्मनी का प्रमुख उद्देश्य होगया, और इसी कार्यक्रम में एक यह उपविषय (subsidiary point) भी था कि फ्रांसीसी सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि वह १९३५ में जनमत लेने की प्रतीक्षा किए बिना ही सार (Saar) जर्मनी को वापस सौंप दे। एक नया क्षतिपूर्ति समझौता कर स्वीकृत मान्यता से सुविधाएँ अब भी प्राप्त कर लेने की आशा करता था। डेविस योजना स्पष्ट ही अस्वास्थ्य थी। इसमें दोनों ही पक्षों का हित था कि जर्मनी के दायित्वों, जिसका योग अभी भी अनिश्चित था, का अन्तिम निर्धारण हो जाता। और चूंकि इस समय भुगतान नियमित रूप से और सरलतापूर्वक किए जा रहे थे, जर्मनी भी यह आशा करता था कि डेविस योजना के कारण उसके राजकोष पर किया गया कष्टकर नियन्त्रण अब हटा लिया जाएगा।

हवा का हल जर्मनी के पक्ष में था। ब्रिटिश ब्रिटेन का लोकमत इस बात के लिए मातुर था कि राइनमूमि पर अधिकार समाप्त कर दिया जाये, और फ्रांस ने भी यह बात स्वीकार की जा चुकी थी कि राइनमूमि पर अधिकार घाटे का सौदा (wasting asset) रहा था और उसे जो कुछ भी मिले वह ले-बेकर जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सन् १९२८ में राष्ट्रसंघ-सभा के अधिवेशन में जर्मनी और पाँच प्रमुख क्षतिपूर्तिप्रहीण राष्ट्रों (reparation powers) के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हो गए कि “राइनमूमि को शीघ्र ही खाली करने” के लिए वार्ताएँ प्रारम्भ की जाये और “क्षतिपूर्ति समस्या के संपूर्ण और निश्चित समाधान” के लिए अर्ध-विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाये, जिसकी अध्यक्षता की जाये, वे यह आशा करते हैं, कि “यहाँ” हो, “प्रती”, पर एक साथ विचार किया जाएगा। किंतु फ्रांसीसी सरकार ने प्रारम्भ से ही

यह स्पष्ट कर दिया कि क्षतिपूर्ति-भुगतान हो चुकने के बाद ही राइनमूमि खाली करने का प्रश्न उठ सकता है। इसलिए क्षतिपूर्ति-भुगतान पर ही सबसे पहिले ध्यान दिया गया।

फरवरी १९२६ में “अर्थ-विशेषज्ञों की समिति” की बैठक पेरिस में हुई। उसमें जेनेवा सम्मेलने में शामिल हर देश के दो विशेषज्ञ और दो अमरीकी विशेषज्ञ (जिनकी नियुक्ति को अमरीकी सरकार ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं मानी थी) सम्मिलित थे। वरिष्ठ (senior) अमरीकी विशेषज्ञ ओवेन यंग (Owen Young) को अध्यक्ष चुना गया, और यह समिति उसी के नाम पर “यंग समिति” के रूप में विख्यात हुई। उसका अथसाध्य विचार-विमर्श (ardous deliberations) चार माह तक चलता रहा। जून ७, १९२६ को उसने “यंग योजना” स्वीकार की और उसे सम्बन्धित सरकारों के सामने प्रस्तुत की।

यंग समिति द्वारा “क्षतिपूर्ति समस्या का जो पूर्ण और निश्चित समाधान” निकाला गया था, वह इस प्रकार था—क्षतिपूर्ति का भुगतान सैंतीस वार्षिक भुगतानों (annual payments) में किया जाये जिनका औसत १००,०००,००० पाँड हो (जब कि डेविस समिति ने १२५,०००,००० की अधिकतम वार्षिकी निश्चित की थी) तथा उसके बाद बाईस और वार्षिक भुगतान इतनी अल्पराशि के किए जाएं जितनी कि मित्र राष्ट्रों को अमेरिका का युद्ध कर्ज (war debt) —जो कि १९८८ तक उन्हें चुकाते रहना था—चुकाने के लिए पर्याप्त हो। डेविस योजना द्वारा जर्मनी पर जो विदेशी नियंत्रण लगाया गया था वह हटा लिया गया। चुकाई गई रकमों को हस्तान्तरित कराने की जिम्मेदारी अब लेनदारों की न रहकर जर्मन सरकार की होगी। विनिमय कठिनाइयों से बचने के लिए भी एक तरीका निकाला गया था। हर वार्षिकी (annuity) का लगभग एक-तिहाई भाग (३३,०००,००० पाँड) “बिना शर्त” (“unconditional”) दायित्व माना जाना था। शेष के लिए यह शर्त रखी गई थी कि विनिमय कठिनाइयाँ उत्पन्न होने पर जर्मनी अधिक से अधिक दो वर्षों तक विनिमय को स्थगित कर सकता है। अन्त में, इस योजना में यह सिफारिश की गई थी कि एक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान बैंक (Bank of International Settlements) की स्थापना की जाए जिसका काम क्षतिपूर्ति भुगतान को प्राप्त करना और उनका

वितरण करना, बिना शर्त वार्षिकियों की प्रतिभूति पर अंतर्राष्ट्रीय ऋण जारी करना तथा सामान्य रूप से, एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक के कृत्य (functions) करना हो।

अब विशेषज्ञों के प्रतिवेदन को सम्बन्धित सरकारों से स्वीकृत कराना और राइनलूमि खाली करने सम्बन्धी विस्तृत बातों को निश्चित करना शेष बचा था। इन प्रयोजनों के लिए हेग में अगस्त १९२६ में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें ब्रिटेन के प्रमुख प्रतिनिधि मजदूरदलीय नए धर्ममंत्री (Chancellor of the Exchequer) फिलिप स्नोडेन (Phillip Snowden) और मजदूरदलीय नए विदेशमन्त्री आर्थर हेंडरसन (Arthur Henderson) थे।

यग योजना बड़ी और अप्रत्याशित कठिनाइयों के बिना स्वीकृत नहीं कराई जा सकी। ये कठिनाइयाँ जर्मनी ने नहीं, अपितु ग्रैंट ब्रिटेन ने डाली। पिछले कुछ वर्षों से, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में फ्रांस की नीति का अनुसरण करने की ओर ब्रिटेन की प्रवृत्ति (जिसके लिए कुछ क्षेत्रों में आस्टिन चेम्बरलेन की आलोचना भी की गई थी) स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। यग समिति के ब्रिटिश विशेषज्ञ इस परंपरा से अनुचित रूप से प्रभावित हुए प्रतीत हुए। इस योजना को फ्रांस की इच्छानुकूल बनाने के लिए, वे ब्रिटेन को हानि में डालते हुए, इस बात पर सहमत हो गए कि १९२० क स्पा (Spa) समझौते द्वारा फ्रांस को बट्टे गए क्षतिपूर्ति-भुगतान प्रतिशत में काफी वृद्धि कर दी जाये। बिना शर्त वार्षिकियों (unconditional annuities) में से तीन-चौथाई से भी अधिक फ्रांस को मिलनी थीं; शर्त (conditional) वार्षिकियों का विनिमय नहीं होने पर ग्रैंट ब्रिटेन के इस त्याग की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था तो की गई थी किन्तु वह जटिल और असंतोषजनक थी। स्नोडेन ने फ्रांस को इन विशेष सुविधाओं के प्रति कृपा नहीं दिखाई बल्कि यह मांग की कि स्पा सम्मेलन में निश्चित किया गया प्रतिशत कायम रखा जाये। उसने ग्रैंट ब्रिटेन के मामले के प्रति इतना टेढ़ा और जोरदार हल अपनाया कि वह कुछ फ्रांसोसी राजनीतिज्ञों की आँख का नाँटा (beile noire) बना रहा तथा ग्रैंट ब्रिटेन में वह सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति बन गया। उसने अपनी भाँगे बहुत कुछ पूरी करा ली, और सम्मेलन यग योजना में संशोधन स्वीकार करके ही समाप्त हुआ।

इसी बीच, सम्मेलन के राजनैतिक भायोग में स्ट्रेसमान, ब्रायएड और हेन्डरसन द्वारा राइनभूमि खाली कराने सम्बन्धी चर्चाएँ चलाई जा रही थीं। ग्रेट ब्रिटेन में मजदूरदलीय सरकार होने के कारण राइनभूमि पर अधिकार समाप्त करने की सामान्य इच्छा और भी बढ़ गई थी; और हेन्डरसन के इस सार्वजनिक वक्तव्य ने कि राइनभूमि से ब्रिटिश सैनिकों को किसी भी स्थिति में हटा लिया जाएगा, इस प्रश्न को वास्तव में हल ही कर डाला। फ्रांसीसी सरकार का यह प्रयत्न कि राइनभूमि खाली करने से पहिले एक समिति नियुक्त की जाये जो इस बात की "जाँच" करले कि राइनभूमि के सैनिकरण (militarisation) सबधी स्थायी प्रतिबन्धों का पालन किया गया है अथवा नहीं, निष्फल गया। सम्मेलन में यह समझौता हो गया कि जून ३०, १९३० (निर्धारित तारीख से लगभग पाँच वर्ष पूर्व ही) तक मित्र-राष्ट्रों की सभी सैनिक टुकड़ियाँ राइनभूमि से हटा ली जायें। यह तारीख इस मान्यता पर निश्चित की गई थी कि उस समय तक यह योजना अमल में आ चुकेगी।

अब और कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जर्मनी की राज्य बैंक (Reichsbank) के अध्यक्ष (Governor) हजल्मार शाख्ट (Hjalmar Schacht) ने, जो कि यह समिति में वरिष्ठ जर्मन विशेषज्ञ रह चुका था, सप्ताह को यह चेतावनी दी कि उसकी अपेक्षाएँ (requirements) जर्मनी की भुगतान-क्षमता (capacity) से परे माँवित होंगी। किन्तु इस भविष्यवाणी पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। कुछ शेष मुद्दों का निवटारा करने के लिए तथा हंगरी और बल्गेरिया को क्षतिपूर्ति की थोड़ी-बहुत रकम चुकाना शेष थी, उसके बारे में उपरोक्त प्रकार समझौता करने के लिए जनवरी १९३० में हेग में दूसरा सम्मेलन हुआ। मई १७ को यह योजना अमल में आई। छः सप्ताह बाद, अंतिम मित्र-राष्ट्र सैनिक टुकड़ी ने जर्मन भूमि छोड़ दी।

राइनभूमि का खाली किया जाना और क्षतिपूर्ति प्रश्न का "अंतिम" समाधान जो कि अत्यन्त शीघ्र ही मिट्टी में मिल जाने वाला था, शांतिकरण काल की अन्तिम महत्वपूर्ण घटनाएँ थी। अगले काल पर विचार करने से पहिले, कुछ ऐसे सीमा-चिह्न (land-marks) पर विचार करना शेष रह गया है जिन्होंने कि अवधि-अंतरण की सूचना दी। उन राजनीतिज्ञों के त्रिगुट जो कि १९२५-२६ की अवधि की अनेक सफलताओं के लिए जिम्मेदार था, में से ऑस्टिन चेम्बरलेन

सबसे पहिले प्रस्तावित हो गये क्योंकि उन्होंने मई १९२६ में अनुदारदलीय सरकार (Conservative Government) के साथ त्यागपत्र दे दिया । प्रथम हेग सम्मेलन की समाप्ति के पाँच सप्ताहों बाद, तथा उसका कुछ भी परिणाम निकलने से पहिले, ब्रिस्लर में, स्ट्रेसमान की मृत्यु हो गई । लगभग उसी समय, न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में तहलका (panic) मच गया । यदि यह अनुभव कर लिया गया होता कि क्षतिपूर्ति और मित्र-राष्ट्रों द्वारा कर्ज के मुगताम का सारा प्रश्न ही अमरीकी विनियोजक (investor) और सट्टेबाज की इस इच्छा पर संपूर्ण रूपेण निर्भर करता है कि अटलांटिक पार बॉलर भेजे जाएँ, तो योरोप में उसका प्रभाव और भी तात्कालिक होता । कुछ महीनों और दुनिया झूल-झुलैया में पड़ी रही । जनवरी से अप्रैल १९३० में, लन्दन में एक सफल नौसैनिक सम्मेलन हो चुका था (देखिए नौवाँ अध्याय) । उसी वर्ष की प्रीम्स में, जबकि अन्तिम फासीसो सैनिक टुकड़ी राइनभूमि खाली करने की तैयारी कर रही थी, ब्रायण्ड ने यह घोषणा की कि योरोपीय संयुक्तराज्य (United States of Europe) की स्थापना करने का उपयुक्त अवसर आ चुका है । इस विषय पर एक स्मरण पत्र भी उधने घुमाया जिसे राष्ट्रसंघ सभा ने एक समिति के विचारार्थ भेज दिया ।

किन्तु यह अम अधिक दिनों तक नहीं टिका । राष्ट्रसंघ-सभा के १९३० के अधिवेशन के समय, जर्मनी की लोकसभा (Reichstag) के चुनावों के परिणाम घोषित किए गये । इन चुनावों में राष्ट्रीय समाजवादियों या नात्सियों, (National Socialists or Nazis) जो कि अभी तक अमहत्वपूर्ण पार्टी थी और जिसका नेतृत्व एडॉल्फ हिटलर नामक आकर्षक भाषणकर्ता के हाथों में था, को एक सी स्थान (seats) मिलने पर लगभग सभी को आश्चर्य हुआ । निःशस्त्रीकरण सम्मेलन-तैयारी आयोग ने दिसम्बर में एक शन्धि का प्रारूप उपस्थित किया जिसकी लगभग हर धारा बहुत अधिक और कटु असहमति (disagreement) का विषय थी । सन् १९३१ तक, तूफान सारे योरोप में बुरी तरह फैल गया था ; और अन्तराष्ट्रीय मामलों सम्बन्धी शब्दकोश में "संकट" (crisis) एक सुपरिचित शब्द हो गया था ।

तृतीय भाग

संकट काल (The Period of Crisis)

शक्ति-कूटनीति का पुनः आरम्भ

(The Return of Power Politics)

(१९३०—१९३३)

७. अर्थव्यवस्था-भंग (The Economic Breakdown)

जो आर्थिक संकट १९३१ में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था, उसके कारणों पर अर्थशास्त्रियों में अब भी मतभेद है। इस अध्याय में केवल उसके लक्षणों और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि में उसके परिणामों पर ही विचार किया जाएगा। सन् १९२९ के शरद में अमेरिका द्वारा योरोप को ऋण देना बिलकुल बन्द कर देना इस संकट की प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी। इसके बाद शीघ्र ही सारे विश्व में क्रय-शक्ति (purchasing power) का ह्रास होता गया जिसका परिणाम कीमतों में व्यापक और घबसकारी गिरावट हुआ। योरोप के कर्जदार देशों (debtor countries) को इससे दोहरी चोट लगी। एक तो, अपने कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अमेरिका में डॉलर ख़ास मिलना बंद हो गया और दूसरे, जिन वस्तुओं की बिक्री कर वे अपने कर्ज चुकाने की आशा कर सकते थे उनकी कीमतें भी अब मदी (slump) से पहले के मूल्य की अपेक्षा बहुत ही कम रह गई थी। अब केवल एक ही मार्ग बचा था। सन् १९३० के अधिकांश अतिपूति और कर्ज मुक्तान स्वर्ण हस्तांतरण (transfers of gold) द्वारा किए गए थे। इन हस्तांतरणों ने परिस्थिति को और भी बिगाड़ने में दो प्रकार से सहायता की। एक तो अमेरिका को अत्यधिक मात्रा में सोना भेजे जाने से सोने का कृत्रिम प्रभाव उत्पन्न हो गया जिसने [क्योंकि स्वर्ण ही मूल्य-मान (measure of value) है] वस्तुओं की कीमतों में और भी गिरावट ला दी। दूसरे, जिन देशों को स्वर्ण-कोष (gold reserves) का क्षय सहना पड़ता था, उन्हें स्वर्ण का निर्यात निषिद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सन् १९३१ में अधिकांश योरोपीय राज्यों ने यह कदम उठाया था। इसके अतिरिक्त, अपने उद्योगों और कृषि को ठप्प नहीं होने देने और अनुकूल व्यापार-संतुलन (favourable balance of trade) बनाए रखने के जी-तोड़ प्रयत्न (desperate effort) में इन देशों को आयात-निर्यात कर, आयात-निर्बन्धन और परिमाण-निर्धारण (import restrictions and quotas), निर्यात-सहायता (export subsidies) और विनिमय निर्बन्धन (exchange restrictions) —

कभी कभी तो इनको देख ऐसा मानस पड़ता था कि विदेश-व्यापार पर राज्य का पूरा पूरा नियन्त्रण हो गया है—के रूप में हर इष्ट उपाय (expedient) का आश्रय लेना पड़ा था। सामान्य दायिज्य का क्रम लगभग बिल्कुल टूट गया था। बेकारी के प्रांकड़े हर देश में दिन दूने रात चौगुने बढ़ गए। आधा योरोप दिवालिया (bankrupt) हो चुका था—और शेष आधे भाग को भी दिवालिया हो जाने का भय था।

जर्मनी में सकट (The Crisis in Germany)

जर्मनी में सकट विशेष रूप से तीव्र था। इसके अनेक कारण थे। उस पर सब राज्यों से अधिक कर्ज था और पिछले पाँच वर्षों में उसने ही सबसे अधिक ऋण लिया था। डेविस योजना—जिसने कि अनिश्चित दायित्वों (undefined liabilities) की आशंका जर्मनी के मन से ऐसे समय दूर नहीं की जिस समय वह अपना कर्ज चुका सकता था—से उसे इस बात की प्रेरणा कम ही मिली थी कि वह मितव्ययिता और सतर्कतापूर्ण वित्तीय नीति पर चले। और सकट की अवधि प्रारम्भ होने के कुछ ही समय पूर्व खुलकर उधार लेने का अवसर जब उसके सामने आया तो वह अपना प्रलोभन रोक नहीं सका। यह अनुमान लगाया गया था कि डेविस योजना के पाँच वर्षों में जर्मनी ने क्षतिपूर्ति के आशिक चुकान के रूप में केवल १००,०००,००० पौंड ही चुकाए थे और लगभग ६००,०००,००० पौंड विदेशों से ऋण और साख्त (credits) के रूप में प्राप्त किए थे। इस प्रकार अतिरिक्त (surplus) धनराशि को उसने, उसकी नगरपालिकाओं और निजी उद्योग (private enterprise) ने नवनिर्माण और पुनर्निर्माण की बड़ी बड़ी योजनाओं पर व्यय किया था। आय-व्यय को सतुलित करने का कोई गंभीर प्रयत्न ही नहीं किया गया था क्योंकि घाटे की पूर्ति अल्पकालीन ऋण (short-term borrowing) लेकर सरलतापूर्वक की जा सकती थी। इस प्रकार जर्मनी की अर्थ व्यवस्था, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, उधार लिए गए धन के बल पर ही सदा चलती रही।

इस प्रकार अर्थ संकट को जर्मनी में विशेष रूप से अनुकूल स्थिति (vulnerable condition) मिल गई। विदेशी ऋणों की सहायता के बिना ही उसे प्रथम बार १००,०००,००० पौंड प्रति वर्ष के क्षतिपूर्ति कर्ज, विदेशों में सरकारी और गैर सरकारी अन्य दायित्व जिनका ऋणभार उक्त रकम से बहुत कम नहीं होता था, तथा ६०,०००,००० पौंड बजट में घाटे का, सामना

करना पड़ा। जर्मनी के पास अपने ही देश में पूँजी के ऐसे साधन भी नहीं थे जिनका कि वह आश्रय ले सक। सन् १९२३ की मुद्रास्फीति (inflation) के कारण उसकी बचत और सचय कोष (reserves) समाप्त हो चुका था तथा उनकी पुन. पूति भी नहीं हो पाई थी। जर्मन उद्योग सरकार की सहायता पर सकने की स्थिति में नहीं था। वह भी विदेशों से पर्याप्त साख (credit) पाने की आशा खो चुका था। और इसके साथ ही साथ व्यापक मदी तथा आयात-निर्यात कर एवं परिमाण निर्धारण बाधाओं (tariff and quota barriers) के बढ जाने के कारण वह अच्छे विदेशी बाजारों से भी वंचित हो चुका था। जर्मन निर्यात, जिनका मूल्य १९२६ में ६३०,०००,००० पाँड तक पहुँच गया था, सन् ३२ में गिरकर वही २८०,०००,००० पाँड ही रह गया था। इसी प्रकार इस अवधि में जर्मन आयात में और भी तेजी से कमी—६७०,०००,००० से २३०,०००,००० पाँड—हो गई। सन् १९२६ में वहाँ उसके पजीयिन बैंकारों की संख्या २,०००,००० थी, वहाँ यही संख्या मार्च १९३२ में ६,०००,००० से भी अधिक की शिरोसंख्या (peak figure) तक पहुँच गई।

एक ऐसे देश में जहाँ राजनैतिक सतुलत सदा ही बिनाअनक स्थिति में रहा हो, इस प्रकार की आर्थिक उथल पुथल के भयंकर परिणाम होना अवश्य भावी था। मार्च १९३० में जर्मनी में जो सरकारें बनी, उसमें—बीमर गणतन्त्र के इतिहास में पहिली बार—एक भी सोशल डेमोक्रेट नहीं था। मध्यमार्गी दल (Centre) का सदस्य ब्रूनिंग (Bruning) प्रधानमंत्री बना और स्ट्रेसमान के उत्तराधिकारी कर्टियस (Curtius) के पास विदेश विभाग पूर्ववत् ही बना रहा। अगले माह, आयात निर्यात कर में बहुमुखी वृद्धि की गई और कृषकों को राजकीय सहायता (agrarian subsidies) प्रदान की गई। जर्मनी ही पहिला देश था जिसने आर्थिक मदी से ज़ाए के लिए इन सदेहास्पद (dubious) उपायों का आश्रय लिया। सितम्बर १९३० के आम चुनावों के परिणामस्वरूप, जर्मनी की लोकसभा (Reichstag) में राष्ट्रीय समाजवादी या नात्सी (Nazi)—जिनकी नीति यहूदियों, सोशल डेमोक्रेटों तथा वर्सेलीज सचि की तीव्र भर्त्सना करने की थी—सदस्यों की संख्या १२ से १०७ हो गई। मन्त्रिमंडल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किन्तु प्रजातन्त्र अब वस्तुतः अक्षय हो चुका था, और जर्मनी का शासन कई महीनों तक राष्ट्रपति

की आज्ञप्तियों (decrees)—जो वीमर (Weimar) सविधान के शब्दों के अनुरूप ही था न कि उसकी भावना के—अनुसार ही चलता रहा ।

सन् १९३१ के प्रारम्भ में ही, जर्मनी की राजनैतिक स्थिरता को एक नया घक्का लगा । योरोपीय-संघ (European Union) बनाने सम्बन्धी ब्रायएंड योजना पर विचार करने के लिये १९३० की राष्ट्रसंघ सभा द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी प्रथम कार्रवाई बैठक जनवरी १९३१ में की । यह मूल योजना मुख्यतः राजनैतिक थी । किन्तु उस समय की प्रथम आवश्यकता आर्थिक सहयोग ही थी । अतएव समिति ने योरोपीय देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं (trade barriers) को दूर करने की योजनाओं पर विचार करना प्रारम्भ किया । इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला । किन्तु इन वार्ताओं से एक अप्रत्याशित क्षेत्र में विचारविमर्श प्रारम्भ होगया । कठिण और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री (Chancellor) (जो कि समिति की कार्रवाई में भाग लेने के लिए जेनेवा आया था) के मन में यह विचार आया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच घनिष्टतापूर्ण आर्थिक संघ निर्माण (close economic union) से न केवल व्यापार-बाधाएँ ही कम होगी, अपितु दोनों देशों की राजनैतिक संघ बनाने की महत्वाकांक्षाएँ भी पूर्ण हो सकेंगी जिसका संधियों द्वारा निवेद्य कर दिया गया था । वार्ताएँ बिल्कुल गुप्त रूप से चलाई गईं, और २१ मार्च को विस्मित विश्व को यह ज्ञात हुआ कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने चुगी संघ (customs union) बनाने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कर दिये हैं । इस संघ में सम्मिलित होने के लिये, अन्य पड़ोसी देशों को भी आमंत्रित किया जाना था।

प्रादेशिक आर्थिक समझौतों के सिद्धान्त का समर्थन योरोपीय संघ के समर्थकों द्वारा १९३० की राष्ट्रसंघ सभा में पहिले ही किया जा चुका था । किन्तु इस सिद्धान्त का इस प्रकार अमल में लाया जाना फ्रांसीसी सरकार और लघुमंत्री संघ के देशों को फूटी आँखों नहीं सुहाया । यह क़स्बात था ही कि एक बड़े और एक छोटे राष्ट्र के बीच चुगी संघ का अवश्यभावी परिणाम बड़े राष्ट्र द्वारा छोटे राष्ट्र पर राजनैतिक प्रभुत्व जमाना ही था । यदि यह योजना सफल हो जाती, तो ऑस्ट्रिया की स्वतन्त्रता अतीत की एक कहानी ही बन जाती । इसके अतिरिक्त, चेकोस्लोवाकिया जिसके प्रमुख बाजार जर्मनी और ऑस्ट्रिया ही थे,

मुश्किल से ही इस संधि के बाहर रह सकता था। डेन्यूब क्षेत्र के अन्य राज्य भी इसमें शामिल हो सकते थे। इस प्रकार डेन्यूब नदी क्षेत्र पर जर्मनी का आधिक्य और अंत में राजनैतिक नियन्त्रण हो जाता। फ्रांस और उसके साथियों ने किसी भी कीमत पर इस संधि का विरोध करने का निश्चय किया। संधि पर आपत्ति के लिए वैधिक आधार (legal ground) न केवल ऑस्ट्रिया की स्वतन्त्रता के परकीकरण (alienation) सम्बन्धी संधि निषेध (treaty veto) में मिल सकता था, अपितु १९२२ के श्रृंखला पूर्वपत्र (protocol) में भी प्राप्ति के जिसमें ऑस्ट्रिया ने यह वचन दिया था कि वह अपनी स्वतन्त्रता को संकट में डालने वाला कोई भी आधिक्य समझौता नहीं करेगा।

ब्रिटिश सरकार का रुख हिचकिचाहटपूर्ण (hesitant) था। मोटे तौर पर, डेन्यूबीय नदी क्षेत्र में व्यापारिक चुगी बाजारों के हट जाने से ग्रेट ब्रिटेन को तो हर प्रकार से लाभ ही था। न तो इस योजना से ही और न उसमें अन्य राष्ट्रों को शामिल किए जाने से ही ब्रिटिश हितों पर कोई हानिकर प्रभाव पड़ता था। किंतु यह संभव प्रतीत होता था कि इस योजना से मध्य योरोप में युद्ध नहीं तो गंभीर राजनैतिक उपद्रव तो अवश्य ही होंगे। फिर, संधि-कसंघ की अपेक्षा भी तो नहीं की जा सकती। भई में, राष्ट्रसंघ-परिषद ने यह निर्विरोध निर्णय किया कि यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय में भेजा जाये कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच प्रस्तावित चुगी संधि शांति-संधियों और १९२२ के पूर्वपत्र की शर्तों के विरुद्ध है अथवा नहीं।

प्रालिखित इस प्रश्न का निबटारा वैधिक निर्णय (legal decision) द्वारा नहीं हुआ। विधि प्रश्न (point of law) सदेहपूर्ण था और फ्रांस इस बात की जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं था कि संधि के पक्ष में निर्णय हो जाये। इसलिए ऑस्ट्रिया की ही यह योजना त्याग देने के लिए तैयार कर लेने के प्रयत्न उसने जोर-शोर से करने प्रारम्भ किये। इन प्रयत्नों में फ्रांस को ऑस्ट्रिया ■ गंभीर अर्थसंकट से भी सहायता मिली जिसका वर्णन आगे इसी अध्याय में किया जाएगा। ग्रीष्म में फ्रांसीसी और ऑस्ट्रियन सरकारों के बीच ठीक-ठीक क्या वार्ताएं चली, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। किंतु ३ सितम्बर को ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री ने योरोपीय संधि (European Union) समिति के सामने घोषणा की कि ऑस्ट्रिया ने यह योजना त्याग दी है। समिति के

जर्मन प्रतिनिधि ने भी इस घोषणा के प्रति अपनी सहमति प्रकट की थी। दो दिनों के बाद, स्थायी न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। सात के विरुद्ध आठ मतों के बहुमत से, उसने यह निर्णय दिया था कि जु गी सघ सचियो और पूर्वपत्र के विरुद्ध होगा। इस तथ्य ने, कि बहुमत में फ्रांसीसी, इटालियन, बेल्जिय और रूमनियन न्यायाधीश शामिल थे तथा अल्पमत में ब्रिटिश, जर्मन और अमरीकी न्यायाधीश, इस निर्णय को एक राजनैतिक रंग दे दिया और इस कारण एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण (tribunal) के रूप में इस न्यायालय की प्रतिष्ठा को घटका लगा।

जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जु गी सघ बनाने के निषेध का तात्कालिक परिणाम योरोप के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा। इस योजना को अस्वीकार कर देने से मध्य योरोप में राजनैतिक अनिश्चितता तथा आर्थिक अव्यवस्था में एक ऐसे लंबे युग का प्रारम्भ हुआ जिससे बचने का कोई उपाय नहीं था। जर्मनी में, उसने बीमर गणतन्त्र का अन्त निकट ला दिया। सन् १९२० और १९३३ के बीच हर जर्मन सरकार की प्रतिष्ठा अन्ततः उसकी विदेश नीति की सफलता अथवा असफलता पर निर्भर करती थी। जब जु गी सघ योजना असफल हो गई तब स्ट्रेसमान की नीति और सिद्धांतों के अन्तिम प्रतिनिधि कर्टियस ने अपमानित हो अवकाश ग्रहण कर लिया, और उसके बाद वॉर्सेलोस की सन्धि के अपमानों के विरुद्ध नास्तियों ने पूरे जोर शोर से प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया।

सर्वनाश का वर्ष (The Year of Disaster)

सन् १९३० में भी, यह विश्वास किया जा सकता था कि यह सकट यद्यपि कष्टकर है तथापि विश्व के आर्थिक जीवन का एक अस्थायी दौर है, और आर्थिक जीवन में झूलझूल परिवर्तन किए बिना ही उस पर विजय पा ली जायगी। किन्तु १९३०-३१ के शीतकाल ने तो आशावाद की कमर ही तोड़ दी। विचारशील व्यक्तियों का भी यह मत हो गया कि सम्पत्ता का पतन निकट है। सन् १९३१ में तो इस विपत्तिग्रस्त विश्व पर चिंताजनक घटनाओं का कुछ ऐसा घटाटोप छाया कि इस वर्ष का इतिहास सर्वनाश की एक लगभग अन्तहीन सूची (uninterrupted catalogue of disaster) ही है।

1. In 1931 critical events rained so thickly on a distracted world that the history of the year is an almost uninterrupted catalogue of disaster.

सन् १९३१ के बसत तक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की भारी भरकम गाड़ी धीरे धीरे चरमर करती चली नारही थी। किन्तु यह ठीक-ठीक नहीं जाना जा सकता था कि यह गाड़ी कहाँ जाकर चूर चूर हो जाएगी। यह स्थान बियना निकला। वृत्त उस समय हुआ जब कि चुंगी-संघ योजना विवाद पूरे जोर शोर से चल रहा था, यद्यपि इन दोनों घटनाओं का सम्बन्ध जोड़ने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। मई में सबसे बड़ी गैर सरकारी ऑस्ट्रियन बैंक, क्रेडिट-आन्स्टाल्ट (Kredit-Anstalt) दिवालिया हो गई। वही व्यापक रूप में घबराहट (panic) फैल जाए, इसलिए ऑस्ट्रियन सरकार ने एक प्राज्ञपति (decree) जारी की जिसमें उसने यह गारन्टी दी कि क्रेडिट आन्स्टाल्ट के विदेशी दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑस्ट्रिया राज्य बैंक (Austrian State Bank) को ६,०००,००० पाँड, विपत्ति को रोकने के लिए, दिए किन्तु वह वही नहीं। चुंगी-संघ योजना के कारण बैंक ऑफ फ्रांस ने सहायता देने से इन्कार कर दिया।

किन्तु इस समय तक क्रेडिट आन्स्टाल्ट के पतन को विश्वव्यापी दिवालियापन और विश्वासहानि की केवल शुरुआत माना जाने लगा था। आनक सीमात के पार जर्मनी में भी फैल गया। विदेशी साहूकारों ने शोध ही अपने अल्प-कालीन श्रृंखला का तकाजा करना प्रारम्भ कर दिया। तीन सप्ताह के भीतर ही, जर्मन राज्य बैंक (Reichs Bank) से ५०,०००,००० पाँड का सोना निकाल लिया गया। चेकोस्लोवाकिया को छोड़कर, मध्य और दक्षिण-पूर्व योरोप के छोटे छोटे राज्य अपने विदेशी कर्जों के बकायादार (defaulters) हो गए। इन कर्जों में वे कर्ज भी शामिल थे जो कि हंगरी, ग्रीस और बल्गेरिया ने राष्ट्रसंघ की सहायता से प्राप्त किए थे।

दक्षिणी गोलार्ध (Southern Hemisphere) में ऑस्ट्रेलिया और भर्जन्टाइना की कृषि वस्तुओं के मूल्य की विनाशकारी गिरावट के कारण १९२६ के अन्त में स्वर्ण भुगतान (gold payments) स्थगित कर देने पड़े थे। कॉफी (coffee) बाजार में गिरावट के कारण दिवालिया हो जाने पर, ब्राजिल ने भी अगले वर्ष ऐसा ही किया। ये विपत्तियाँ ग्रेट ब्रिटेन के लिए भीषण प्रहार थीं। क्योंकि इन तीनों देशों में उसके बहुत अधिक आर्थिक हित थे। पिछले कुछ

महीनो में बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना लगातार बाहर मुख्यतः फ्रांस—जो कि इस समय योरोप का सबसे अधिक धनी देश था—जारहा था। सन् १९३१ के ग्रीष्म में तो इसमें और भी वृद्धि हो गई। यह अनुमान लगाया गया था कि जून तक ससार का ६० प्रतिशत सोना (सोवियत रूस के पास के सोने को छोड़कर) या तो अमेरिका पहुँच गया था या फ्रांस। अब स्वर्ण के रूप में भुगतान शीघ्र ही स्थगित हो जाना आवश्यक था।

ऐसा प्रतीत होता था कि सभी बकायादार हो जाएँगे किन्तु इतने ही में अमरीकी राष्ट्रपति हूवर (Hoover) ने २० जून को विश्व के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अमरीकी सरकार विदेशी सरकारों से अपना पैसा वसूल करना एक वर्ष के लिए इस शर्त पर स्थगित कर सकती है कि सभी अन्तर-सरकारी (inter governmental) कर्जों, जिनमें क्षतिपूर्ति कर्ज भी शामिल होंगे, की वसूली इसी प्रकार स्थगित की जायगी। आर्थिक सकट के लिए मित्र राष्ट्रों के युद्धकालीन कर्ज (Allied war debts) जिस सीमा तक जिम्मेदार थे, उसकी यह अप्रत्यक्ष स्वीकृति बड़े साहस और राजनीतिकुशलता (statesmanship) का काम थी। किन्तु यह स्वीकृति बहुत देरी से की गई थी। इस प्रस्ताव का एक स्पष्ट उद्देश्य जर्मनी और, सामान्य रूप से योरोप की क्षम-शक्ति तथा साथ अमरीकी ऋणपत्रधारी (bond holder) तथा निर्यातकर्त्ता (exporter) के लाभ के लिए पुन बढा लेना था। किन्तु इन बातों से हूवर को देय श्रेय में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। मित्र-राष्ट्र सरकारें भी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की वास्तविकताओं का सामना करने में उसनी ही सुस्त रही थी तथा अपना वास्तविक हित जिस में है इसे समझ भी नहीं सकी थी।

हूवर के प्रस्ताव से चारों ओर उत्साह फैल गया। उसका नैतिक प्रभाव इतना अधिक हुआ कि कुछ दिनों तक ऐसा प्रतीत होने लगा कि विश्वास पूरी तरह लौट आया। किन्तु फ्रांस ने एक बार फिर शोकाग्र होकर कहा कि किसी भी राष्ट्र को अपेक्षा फ्रांस को जितना युद्ध-कर्ज चुकाना था उससे भी अधिक क्षतिपूर्ति की रकम उसे लेनी थी। ग्रेट ब्रिटेन या कम से कम अमेरिका की अपेक्षा तो अवश्य ही, फ्रांस यह अधिक चाहना था कि क्षतिपूर्ति भुगतान जारी रहे। उसे इस बात से भी बहुत कम मतलब था कि जर्मनी की वित्तीय और वाणिज्यिक स्थिति पुन. सुधर जाये। योरोप में केवल फ्रांस ने ही हूवर-

प्रस्तावित भुगतान-विलंबकाल पर आपत्ति उठाई। अन्त में जब वह इस बात के लिए तैयार हुआ, तब उसने यह शर्त रखी कि यह योजना द्वारा निर्धारित बिना शर्त वार्षिकियाँ जर्मनी अन्तर्राष्ट्रीय-भुगतान बैंक (International Bank of Settlements) को यथावत् चुकाये किन्तु वे तुरन्त ही जर्मनी की परकारी रेलवे कंपनी को दे दी जाएँगी तथा सम्पूर्ण विलंबित वार्षिकियों पर ब्याज लगाया जाये। केवल यही शर्त मनवाने में पंद्रह दिनों तक घिसघिस चलनी रही तथा हूवर के प्रस्ताव से उस समय जो विश्वास उत्पन्न हुआ था, उसके लिए यह देरी घातक सिद्ध हुई। संकट का वातावरण पहिले से अधिक गहरा होता चला गया। सभी संबधित राष्ट्रों द्वारा हूवर-प्रस्तावित भुगतान विलंबकाल स्वीकार कर लिए जाने के एक सप्ताह बाद, १३ जुलाई को जर्मनी की सबसे बड़ी बैंको में से एक ने भुगतान करना बन्द कर दिया।

हूवर के उक्त प्रस्ताव से सरकारों के आसपी कर्जों की तात्कालिक व्यवस्था ता होगई थी। किन्तु यह बाधा दूर हो जाने पर भी गैरसरकारी कर्जों का निपटारा शेष रह गया था तथा उन्होंने एक असमायेय (insoluble) समस्या खड़ी कर दी थी। जर्मनी इस समय ऐसी स्थिति में था कि यदि मार्क का विदेशों में और अधिक हस्तांतरण किया जाता, तो १९२३ की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की पुनरावृत्ति ही हो जाती। उसके विदेशी साहूकारों के सामने इस बात के प्रति-रिक्त और कोई चारा ही नहीं था कि सभी जर्मनी कर्जों का विलंब से चुकाए जाने के प्रस्ताव पर वे सहमत हो जायें। इससे लंदन के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बड़ी प्रहसन हुई क्योंकि उनकी बड़ी-बड़ी रकमें जर्मनी में अल्पकालान कर्जों के रूप में फँसी हुई थी।

ग्रेट ब्रिटेन स्वयं ही इस समय अर्थ संकट के गर्त में फँसा हुआ था। तेजी (boom period) के प्रारंभ में अप्रैल १९२५ में, ब्रिटिश सरकार ने पौंड को युद्ध-पूर्व की उसकी दर पर स्वर्ण आधार (gold basis) पर पुनः ला दिया किन्तु बाद में अनुभव से यह पता चला कि ब्रिटिश सरकार का यह कदम विचार-हीन साहसपूर्ण था। कुछ समय बाद, फ्रांस, इटली और अन्य अनेक योरोपीय देशों ने भी पुनः स्वर्ण-मान का आग्रह लिया किन्तु अपनी मुद्राओं के मूल स्वर्ण-मूल्य में उन्होंने इस बार काफी कमी कर दी थी। इस प्रकार फ्रैंक (Francs) नामक फ्रांसीसी सिक्के जिनका युद्ध-पूर्व मूल्य प्रति पौंड २५ था, अब प्रति पौंड

१२५ होगये थे। इसमें सदेह की गुजाइश कम ही है कि फ्रांस और अन्य देशों ने बहुत ही कम दर पर अपनी मुद्राओं को स्थिर किया था जो कि अनुचित था किन्तु सम्भवतः किसी योजनापूर्वक नहीं किया गया था। इस सारी कार्यवाही का उद्देश्य अधिकतर योरोपीय देशों में मजदूरी और अन्य उत्पादन-व्यय ग्रेट ब्रिटेन से काफी कम रखना तथा ब्रिटेन को हानि में डालते हुए इन देशों के निर्यात-व्यापार को बढ़ाना था। इसके अतिरिक्त, ग्रेट ब्रिटेन को छोड़ योरोप के हर महत्वपूर्ण देश ने बहुत अधिक आयात-निर्यात कर लगाने की नीति का अनुसरण कर आयात को कुचलने का प्रयत्न किया। सन् १९२७ में हुए अर्थ-सम्मेलन में (देखिए पृष्ठ ६६) आयात-निर्यात कर कम करने और अन्य व्यापारिक बाधाएँ दूर करने सम्बन्धी जो सिफारिशें की गई थी, उनकी उपेक्षा की गई, और १९२९ में ब्रिटिश सरकार द्वारा रखे गए “अस्थायी आयात-निर्यात-कर समझौता” (“tariff truce”) अर्थात् वर्तमान आयात-निर्यात कर में वृद्धि नहीं करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव, को बहुत ही कम समर्थन प्राप्त हुआ।

जब तक समृद्धि बनी रही और विश्व व्यापार बढ़ता रहा, तब तक ग्रेट ब्रिटेन कर्ज में पड़े बिना ही अपना काम चलाता रहा। किन्तु १९२५-२९ की तेजी में उसने अन्य किसी भी महत्वपूर्ण देश की अपेक्षा कम ही कमाया। उसका विपरीत व्यापार-सन्तुलन वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता ही गया। सन् १९३० में सर्वाधिक निर्यातकर्त्ता राष्ट्र (exporting power) के रूप में जर्मनी प्रथम बार उससे आगे (लगभग ३०,०००,००० पाँड से) निकल गया। अमेरिका, जो कि इस सूची में तीसरे स्थान पर था, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश अधिदेशों (कनाडा के अतिरिक्त) और स्कैन्डेनेविया को छोड़कर अन्य सभी बाजारों में ग्रेट ब्रिटेन से आगे थे। अब सकट का उपस्थित हुआ तब प्रतिद्वन्द्विता-शक्ति में यह कमी (decline in competitive power) ग्रेट ब्रिटेन की स्थिरता के लिए घातक सिद्ध हुई। विश्व व्यापार में मंदी के कारण तो उस देश को (ग्रेट ब्रिटेन को) विशेष रूप से घबका पहुँचा जिसकी अधिकांश आय का साधन दूसरे लोगों के व्यापार का परिवहन-कार्य कर देना और पूँजी लगाना (transporting and financing) था। भुगतानों का बकाया धीरे-धीरे विपरीत रूप धारण करने लगा। करो से आय में कमी हो जाने के कारण विश्वास और भी-उठ

गया। इस कमी के कारण, जुलाई १९३१ तक, आय-व्यय में १००,०००,००० पौंड का पाटा हो गया। विदेशी साहूकार (debtors) इस स्थिति से भय खाने लगे। जुलाई के अन्त में एक सप्ताह के भीतर ही २१,०००,००० पौंड का सोना ग्रेट ब्रिटेन के बाहर चला गया। बैंक ऑफ फाम से काफी उधार मिल जाने पर ही पौंड से विश्वास उठने-उठने बना—यह प्रक्रिया पूरे पगस्त भर जारी रही। अगस्त २४ को मजदूरदलीय सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और उसका स्थान एक राष्ट्रीय सरकार (National Government) ने लिया जिसने ७०,०००,००० पौंड का आय-व्यय-घाटा सर्च (budget deficit by economies in expenditure) में कमी कर तथा छुटिरिक्त कर लगाकर पूरा करने के लिए एक पूरक आय व्ययक (supplementary budget) प्रस्तुत किया। किन्तु बेन कटौती के प्रश्न को लेकर बड़े (fleet) में थोड़ा असन्तोष फैल जाने से अविश्वास पुनः दिग गया। सितम्बर २१ को सरकार ने सोने का निर्यात ही निषिद्ध कर दिया। सुपरिचित शब्दों में कहे तो, पौंड “स्वर्ण से मुक्त हो गया” और कुछ ही दिनों के भीतर, स्वर्ण और स्वर्ण-मुद्राओं के रूप में उसका मूल्य लगभग २५ प्रतिशत गिर गया।

एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा के रूप में पौंड की स्थिति इतनी मुट्ठ धी कि उसका परस्पर विरोधी और अप्रत्याशित परिणाम (paradoxical and unexpected result) होना आवश्यक था। पौंड के मूल्य में कमी के कारण ग्रेट ब्रिटेन में मूल्य तो नहीं बढ़े (राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य में कमी का यह स्वामादिक और सामान्य परिणाम होता है) किन्तु विश्व के मूल्यों में गिरावट आ गई। इसलिए जहाँ एक ओर ग्रेट ब्रिटेन में उसका परिणाम बिल्कुल लाभ-दायी था और ह्रासमान निर्यात व्यापार (flagging export trade) को पुनः बढ़ा लेने तथा धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से स्थिति सुधार लेने की प्रेरणा मिली थी, वहाँ दूसरी ओर विदेशों से उनका प्रथम प्रभाव पहिले से ही गिरी हुई और अलाभदायी (unremunerative) कीमतों में और भी गिरावट हुआ था। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर १९३१ के आम चुनाव, जिनमें राष्ट्रीय सरकार को प्रत्यक्ष बहुमत मिला, ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपनी परम्परागत प्रवाहित व्यापार नीति (traditional free-trade policy) त्यागने, अनेक कुवि-उत्पादनों का परिमाण (quota) निर्धारित करने तथा तैयार माल पर जड़सुत्री

आयात-निर्यात कर (tariff) लगाने की नीति प्रारम्भ करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सन् १९३२ में, ओटावा सम्मेलन (Ottawa Conference) में ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश अधिदेशों ने अधिमानात्मक आयात-निर्यात-कर (preferential tariffs) और आयात-परिणाम (import quota) सम्बन्धी कई समझौते किए जिनके लाभ से विदेशी राज्यों को वंचित रखा गया। ब्रिटिश व्यापार के पुनरुत्कर्ष (revival) के लिए ये कदम सम्भवतः अत्यन्त आवश्यक थे।

ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वर्ण-मान का परित्याग कर दिया जाना, जिसका अनुकरण शीघ्र ही स्वेडिनेवियन देशों, न्यूजीलैंड और (कुछ समय बाद) दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया गया, सकट की चरमसीमा (culminating point) था। सन् १९३१-३२ के दौतकाल को १९१८ के बाद सम्भवतः सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काल (darkest period) माना जा सकता है। उसके राजनैतिक तथा आर्थिक पहलू थे। सितम्बर १९ को, जापान ने एक ऐसा सैनिक अभियान प्रारम्भ किया जिसने कि उसे एक वर्ष से भी कम समय में, चीन के उपजाऊ प्रांत, मन्चूरिया का स्वामी बना दिया। फरवरी २, १९३२ को जेनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। तत्कालीन घटनाचक्र से परिचित बहुत ही कम लोग उसकी सफलता के आसारों को अत्यन्त निराशापूर्ण के अतिरिक्त ग्रन्थथा मान सकते थे। मन्चूरिया में जापान की कारंवाही और निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का विवेचन अगले दो अध्यायों में किया जाएगा। इस अध्ययन के शेष भाग में १९३३ के मध्य तक आर्थिक सकट का और अधिक विस्तार से वर्णन किया जायगा।

✓ क्षतिपूर्ति का अन्त (The End of Reparation)

यूरोप के देश इस समय तक तीन वर्गों में बँट गए थे एक तो वे जो स्वर्ण का मुक्त निर्यात (free export) करते थे तथा स्वर्ण-मान पर मुहब्बत थे—फ्रांस, इटली, पोलेण्ड, बेल्जियम, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड (इन्हे कभी-कभी "स्वर्ण-ग्रुप" ("gold bloc") भी कहा जाता था) दूसरे वे जिन्होंने स्वर्ण मान का विधिवत परित्याग कर दिया था—ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और इस्तोनिया (जिन्हें कभी-कभी "स्ट्रुलिङ्ग ग्रुप" कहा जाता था) तथा स्पेन

पुर्नगल और युतान । तीसरे वर्ग में वे देश आते थे जिन्होंने स्वर्ण मान का वर्तमान में परिचय कर सोने का निर्यात भी निषिद्ध कर दिया था किन्तु जो विदेश-विनिमय सम्बन्धी सभी लेन-देनों पर नियन्त्रण कर अपनी मुद्राओं को कृत्रिम स्वर्ण तुल्यता (artificial gold parity) पर बनाए हुये थे ।

अन्तिम और सबसे अधिक सख्या वाले उक्त वर्ग का जर्मनी एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण था । लंबे समय से चले आए क्षतिपूर्ति विवाद सम्बन्धी अन्तिम कदम ने लेनदार सरकारों में भाड़े की एक नई जड़ पैदा कर दी । राज्य बैंक के जरिए, जर्मन सरकार के हाथों ने अब जर्मनी के विदेश-मुद्रा-विनिमय (foreign exchange) का वास्तव में एकाधिकार ही प्राप्त गया था । फ्रांस का यह कथन था कि अन्य सभी विदेशी भुगतान से पहिले यम योजना की बिना-शर्त (unconditional) वार्षिकियों का हस्तान्तरण करने के लिए जर्मन सरकार बचनबद्ध है । इस पर ग्रेट ब्रिटेन का उत्तर इस प्रकार था :—प्रथमतः, फ्रांस की यह दलील तर्क की दृष्टि से बेनुको है क्योंकि आवश्यक आयातों का भुगतान करना जर्मनी ■ लिए सबसे पहिले जरूरी है । द्वितीयतः, जर्मनी की साक्ष को पुनः स्थापित करने के लिए यह अधिक जरूरी है कि जर्मनी अपने व्यापारिक कर्जों (फ्रांस की प्रेषणा ब्रिटेन को ही इन कर्जों से अधिक मनलब था) को क्षतिपूर्ति से पहिले चुका दे । प्राथम्य के इस कठिन प्रश्न पर शायद ही कभी समझौता हो पाता किन्तु हूवर-प्रस्तावित भुगतान विलंबकाल समाप्त होने से पहिले, जनवरी १९३२ में ब्रूनिंग ने इस समस्या को यह घोषणा कर हल किया कि जर्मनी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर सकता है और न ही भविष्य में किसी भी स्थिति में वह ये भुगतान करेगा । यह क्लृप्त अपनाते का एक कारण जर्मनी को आन्तरिक राजनीति था । वर्सेल्लेज संधि के विरुद्ध राष्ट्रीय समाजवादियों का आन्दोलन जोर पकड़ रहा था और कोई भी सरकार क्षतिपूर्ति प्रश्न पर इसमें कम “देशभक्तिपूर्ण” क्लृप्त नहीं अपना सकती थी ।

ऐसी स्थिति में, आवश्यकता इस बात की थी कि पहली जुलाई १९३२ को हूवर-प्रस्तावित भुगतान विलंबकाल समाप्त होने से पहिले किसी प्रकार का समझौता कर लिया जाये । फ्रांसीसी सरकार ने यद्यपि अप्रकट रूप से अवश्य-मावी को स्वीकार कर लिया था, तदपि वह अभी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि क्षतिपूर्ति की रकम ढूँढ गई । जून तक जुलाने में एक

सम्मेलन हुआ जिसमें यह समझौता किया गया कि यदि जर्मनी ५ प्रतिशत विमोच्य ऋणपत्रों (redeemable bonds) के रूप में १५०,०००,००० पौंड एक ही बार में चुका दे, तो उसके बदले में सभी क्षतिपूर्ति दावे रद्द किये जा सकते हैं। सरकारों ने एक पृथक् समझौता कर आपसी मुद्द बर्जों को भी रद्द कर दिया किन्तु यह शर्त रखी कि अमेरिका को उन्हें जो बर्ज चुकाना है उसका सतोषजनक समाधान हो जाने पर ही इस समझौते का अनुसमर्थन किया जाये। किन्तु अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि चुकाने समझौते का अनुसमर्थन किया जाना या नहीं किया जाना (वास्तव में, वह कभी किया ही नहीं गया) कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रखता था। इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई जर्मनी से क्षतिपूर्ति की रकम वसूल करने के लिए पुनः प्रयत्न करेगा। इतिहास का एक सदा अध्याय अब सदा के लिए बन्द हो चुका था।

जो भी हो हूवर-प्रस्तावित भुगतान विलंबकाल (Hoover moratorium) समाप्त होने पर, मित्र राष्ट्रों के अमरीकी बर्जों का प्रश्न व्यावहारिक रूप में सामने आ गया। सीमाग्न्य से, अगली किरतें १५ दिसम्बर से पहिले देय नहीं थी। किन्तु दुर्भाग्य से इसी अवधि के बीच में पड़ने वाले नवम्बर में, अमरीकी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था। यद्यपि अमेरिका में भा आर्थिक सबट की चर्चा इससे पूर्व सुनाई देती थी किन्तु सकट की पूरी भयकरता का अनुभव वहाँ योरोप की अपेक्षा देरी से हुआ। सन् १९३२ के शरद से पहिल यह सकट वहाँ अपनी चरम सीमा को मुश्किल से ही पहुँच पाया था। चुनाव अत्यन्त निराशापूर्ण वातावरण में हुआ। अधिकांश मतदाता यह कठिनाई से विश्वास कर पाते थे कि जो कुछ राष्ट्रपति हूवर ने किया था वह राही था। जो भी हो, यह स्पष्ट था कि हूवर-घोषित भुगतान विलंबकाल से अमेरिका को लाभ नहीं हुआ था। और अब, जिस समय कि अमरीकी राजकोष में ८००,०००,००० पौंड का घाटा था, योरोप के कर्जों को रद्द करने की बात करने के लिए उपयुक्त अवसर नहीं था। चुनाव का कुछ भी परिणाम हुआ होता (वास्तव में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की भारी जीत हुई) इस समय यदि मित्र-राष्ट्र सरकारें अपने कर्जों पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध करतीं तो उन्हें कोरा जवाब (blank refusal) ही मिलता। इन परिस्थितियों में, ग्रेट ब्रिटेन ने, कुछ हिचकिचाहट के बाद, दिसम्बर की किस्त चुका दी। फ्रांसीसी सरकार भी किस्त चुकाना चाहती थी किन्तु फ्रांसीसी प्रतिनिधि

सभा (Chamber of Deputies) ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस कारण अन्य प्रमुख कर्जदार राज्यों के साथ ही साथ फ्रांस भी बकायादार हो गया।

कर्जदार राज्यों में केवल ग्रेट ब्रिटेन ही एक ऐसा राज्य था जिसने दिसम्बर ३२ में विस्त की पूरी रकम चुका दी। यह भुगतान ही अन्तिम पूरा भुगतान था। इसके बाद जून और दिसम्बर १९३३ में उसने २,०००,००० पाउंड का भुगतान प्रत्येक बार किया जो कि देय रकम का बहुत ही कम भाग था किन्तु अमरीकी सरकार ने उसे ही बकायादार नहीं रह जाने के लिए पर्याप्त मान लिया। दूसरी विस्त देय होने से पहले, नए अमरीकी कानून ने इस कहानी की पुनरावृत्ति रोक दी। इसके बाद और कुछ कभी भी नहीं चुकाया गया। वास्तव में, १९३२ का साल क्षतिपूर्ति और मित्र-राष्ट्रों के आपसी कर्जों के नाटक का अन्तिम दृश्य था जिसने कि सत्तार को बस से भी अधिक बर्षों से परेशान कर रखा था। बुसाने सम्मेलन ने उन दोनों को ही असम्मानपूर्वक खपता दिया।

विश्व अर्थ-सम्मेलन

(World Economic Conference)

बुसाने में यह निश्चय किया गया था कि आगामी वर्ष एक बृहद् अर्थ-सम्मेलन किया जाये—जो कि १९२७ के जेनेवा सम्मेलन के बाद प्रथम बार किया जाना था। अमरीकी सरकार ने उसमें इस शर्त पर भाग लेना स्वीकार कर लिया कि उसमें मित्र राष्ट्रों के आपसी कर्जों पर विचार नहीं किया जाएगा। सम्मेलन होने से पहले, अमेरिका में बहुत सी घटनाएँ घट गईं। सन् १९३२-३३ के शीतकाल में, अमेरिका में अर्थ-संकट अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। उस समय यह अनुमान लगाया गया था (क्योंकि सरकारी तौर पर कोई हिसाब नहीं रखा जाता था) कि अमेरिका में १५,०००,००० व्यक्ति बेकार हैं। मार्च १९३३ में, जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, तब अमेरिका की सारी अर्थ-व्यवस्था ही दहड़हानेवाली थी। अगले माह, अमेरिका ने स्वर्ण मान का परिचयाग कर दिया और डॉलर का मूल्य सोघ ही लगभग ३० प्रतिशत घट गया।

इस घटना की वासी छाया में जून १९३३ में लंदन में विश्व अर्थ-सम्मेलन हुआ। लिखित इतिहास में यह राज्यों का सबसे बड़ा सम्मेलन था। उसमें चौंसठ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मानव-समाज की सामूहिक बुद्धि-

मत्ता में प्रत्यापि वर्तमान निष्ठा (still persistent faith) का वह अद्भुत परिचायक था। किंतु अर्थ-समस्या और निःशस्त्रीकरण-समस्या में एक विचित्र समानता शीघ्र ही परिलक्षित हुई। जिस प्रकार फ्रांस और उसके साथी वर्षों तक इस बात पर जोर देते रहे कि निःशस्त्रीकरण से पहले सुरक्षा आवश्यक है, उसी प्रकार विश्व अर्थ सम्मेलन में भी फ्रान्स ऐसे देशों के नेता के रूप में सामने आया जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयात-निर्यात कर कम करने या परिमाण निर्धारण का बंधन हटा देने सम्बन्धी किसी भी प्रकार का समझौता करने से पहले मुद्रा का स्थिरीकरण (stabilisation) आवश्यक है। पहले तो आसार बिल्कुल ही निराशाजनक प्रतीत नहीं हुए। ब्रिटिश सरकार ने आयात-निर्यात कर में कमी करने के लिए जोर देते हुए भी, स्थिरीकरण की आवश्यकता का समर्थन किया तथा इसके लिए चर्चा चलाने की इच्छा भी प्रकट की। अमरीकी विदेशमन्त्री तथा अमरीकी प्रतिनिधिमंडल के नेता कॉर्डेल हल (Cordell Hall) ने भी यही किया। किन्तु अमरीकी राजकोष जिस नम्यमुद्रा (flexible currency) का अनुभव नया नया ही हुआ था, उसके दोषों की अपेक्षा लाभों से ही अधिक परिचित था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक वक्तव्य जारी किया जो अमरीकी प्रतिनिधिमंडल के समझौतात्मक (conciliatory) रुख को अस्वीकार करने के समान ही था। अर्थ-स्थिरीकरण-समर्थकों (stabilisers) की आलोचनाओं के विरुद्ध राजकोष-दृष्टिकोण (Treasury view) का समर्थन करने के लिए एक विशेषज्ञ वाणिज्यतज्ञ स दीर्घ ही भेजा गया। यह अशोभनीय घटना सम्मेलन के लिए प्राणघातक प्रहार (death blow) ही थी। सम्मेलन धीरे-धीरे जुलाई के अन्त तक चलता रहा और अन्त में गेहूँ की खरीद बिक्री (marketing) और चाँदी के मूल्य के संबंध में गौण समझौते किए गए तथा उसके बाद वह अनिश्चित काल तक (sine die) के लिए स्थगित हो गया। सम्मेलन का महत्त्वपूर्ण कार्य निःसंशय रूप से यह जतला देना था कि सभी देशों के लिए एक ही नीति अपनाकर विश्व अर्थ-संकट पर विजय नहीं पाई जा सकती।

अन्तिम दौर (The Last Phase)

विश्व अर्थ-सम्मेलन इसलिए असफल हो गया कि उसके सभी प्रतिनिधियों, अगले कदम के बारे में उनका कुछ भी मत रहे हो, का अन्तिम उद्देश्य अतीत

आयात निर्यात कर की नीची दरों और स्थायी मुद्राओं के युग—को प्रब फिर वापस ले आना था । किन्तु अब ऐसा हो सकना असम्भव था । सम्मेलन की असफलता ने राजनीतिज्ञों को नई दिशा में सोचने के लिए विवश किया । यह स्पष्ट था की आर्थिक राष्ट्रीयतावाद और राज्य द्वारा व्यापार-विनियमन (economic nationalism and state regulation of trade) के तथ्यों ने जड़ जमा ली थी और उनके भावी विश्व व्यवस्था के आधारभूत तथ्यों ने होते हुए भी एक ऐसे सुधार का प्रारम्भ हुआ जो कि प्रारम्भ में तो शायद ही अनुभव किया गया हो किन्तु वह जोर सबल पकड़ रहा था । ग्रेट ब्रिटेन में इस सुधार का प्रारम्भ सन् १९३२ से हुआ जबकि युद्ध के समय ५ प्रतिशत पर जनता से लिए गए अधिकांश ऋण को ३३ प्रतिशत लोक ऋण (public debt) के रूप में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया गया था । अमेरिका में, मार्च १९३३ से वस्तुओं के भावों में तेजी आना और विदेश-व्यापार में सुधार होना प्रारम्भ हुआ तथा डॉलर के मूल्य में कमी एवं राष्ट्रपति रूजवेल्ट के “नया कार्यक्रम” (New Deal) के कारण उसे बहुत प्रोत्साहन मिला । अन्यत्र भी यह सुधार धीरे-धीरे होने लगा । पहिले वह उन देशों तक ही सीमित था जिन्होंने स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया था किन्तु इन देशों—जो कि स्टर्लिङ्ग गुट के थे—अमेरिका और जापान के हाथों में विश्व का भाग्य से भी अधिक व्यापार था (केवल ग्रेट ब्रिटेन के ही हाथों में एक-चौथाई व्यापार था) तथा ये ही तत्कालीन रुझान के निर्णायक थे । सीधे सीधे (direct bargaining) के आधार पर दो दो राज्यों में (pairs of state) द्विपक्षी व्यापारिक समझौतों (bilateral commercial agreements) ने अब अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की बड़ी-बड़ी योजनाओं का स्थान ले लिया । अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर पूँजी लगाना अब भी वास्तव में बन्द ही था । पर राज्य स्वयं ही अपने को सकट से बचाने लगा । अर्थ-आर्थिक उपायों (economic panaceas) का चलन उठ गया तथा राष्ट्रसच के आर्थिक और वित्तीय संगठन अपना समय नित्य कार्यों तथा खोज कार्यों (routine and research) में बिताने लगे ।

द्विपक्षी समझौतों की नई नीति का अनुसरण करने में ग्रेट ब्रिटेन न नेतृत्व किया । विश्व अर्थ-सम्मेलन के बाद के वर्ष में, आपसी तौर पर आयात निर्यात कर में कमी करने और खरीद का बचन देन सबको समझौते प्रजेन्टायना, स्वेन्डनेवियन और वाल्कन देशों तथा सोवियत रूस और पोलैंड से किए गए । फ्रांस, जर्मनी

और हालैंड के साथ किए गए समझौते प्रतिरक्षात्मक उपाय (defensive measures) थे ताकि ये देश ब्रिटिश माल के प्रति यदि भेद-भाव की नीति बरतें भी तो उस का सामना किया जा सके किन्तु उनसे व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई। सन् १९३४ में, अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने देश की कांग्रेस (Congress) से अन्य राज्यों से व्यापारिक समझौते करने—जिनमें अमरीकी आयात निर्यात कर में कमी करना भी शामिल किया जा सकता था—की शक्तियाँ प्राप्त कर ली। इस प्रकार के समझौते कई अमरीकी देशों, जिनमें कनाडा भी शामिल था और कुछ योरोपीय राज्यों से किए गए। स्वर्ण मान पर टिके रहने वाले देश प्रापेक्षाकृत देरी से समृद्धिशाली हुए। सन् १९३४ और १९३५ में, इटली, पोलेंड और बेल्जियम स्वर्ण गुट (gold bloc) से अलग हो गए, प्रथम दो ने तो विनिमय-नियन्त्रण (exchange control) प्रारम्भ कर दिया और अन्तिम ने सरकारी तौर पर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन (devaluation) कर दिया जब फ्रांस, स्विटजरलैंड और हालैंड ने भी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया, तब ता सितंबर १९३६ में स्वर्ण मान का अस्तित्व ही अन्तिम रूप से समाप्त हो गया।

यद्यपि इस बात का तो दावा नहीं किया जा सकता कि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पूरी तरह पुनः स्थापित हो चुकी थी, तदपि १९३३ की सामाजिक इतिहास (contemporary history) के उस स्पष्ट काल का समाप्ति सूचक वर्ष कहा जा सकता है जो कि विश्व अर्थ सकट काल कहलाता है। तीन वर्षों से दुनिया अपनी आर्थिक कठिनाइयों पर गभीर विचार कर रही थी और उसे कोई हल नहीं मिल पा रहा था। सन् १९३३ में जहाँ एक ओर आर्थिक बाढ़ल फटना ही प्रारम्भ हुए थे वहीं दूसरी ओर राजनैतिक क्षितिज पर कालिमा छाती जा रही थी। राजनैतिक विन्ताओं—जापान और जर्मनी का राष्ट्र-संघ से हट जाना तथा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का आसन्न (imminent) अन्त का विश्व घटनाचक्र में पुनः प्राधान्य हो गया। यद्यपि इनके कारण भी अधिकांशतः आर्थिक थे तदपि उन्होंने सकट के शुद्ध आर्थिक पहलू को मनुष्य के विचार जगत में गौण स्थान दिला दिया।

८. सुदूर पूर्व (पूर्वी एशिया*) में संकट (Crisis in the Far East)

सुदूर पूर्व में जापान की स्थिति की तुलना योरोप में जर्मनी और इटली की स्थिति से की जा सकती थी। उसके आन्तरिक शासन इतने पर्याप्त नहीं था कि हमने उसकी तेजी से बढ़ती हुई आवादी का काम चल सके। उसे ऐसा लगना था कि उसे निम्न कोटि से ऊँचा उठा हुआ (upstart) माना जाना है और उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति में अन्य बड़े राष्ट्र द्वेषपूर्ण बाधा डालने हैं। वाशिंगटन सम्मेलन में, एंग्लो-सैक्सन (Anglo-Saxon) राष्ट्रों ने उस पर सशुक्त दबाव डालकर उसे चीन में अपनी युद्धकालीन लाभों (war-time gains) को त्याग देने तथा चीन की अखंडता का सिद्धान्त मानने के लिए विवश किया था। सन् १९२३ में जापान में एक ऐसा भूकंप आया कि उसे सैनिक विजय का कोई भी विचार तत्काल त्याग देने के लिए और भी विवश होता रहा किन्तु १९२४ के अमेरिकी आप्रवासन अधिनियम (American Immigration Act) जिसके द्वारा जापानियों को अमेरिका में बसने की वस्तुनः मनाही कर दी गई थी, को और अपमान समझा गया। अमेरिका की इस नीति का अनेक ब्रिटिश अधिराज्यों ने भी अनुकरण किया था। सन् १९२५ में, ब्रिटिश सरकार का यह निश्चय कि वह सिंगापुर में प्रथम श्रेणी का एक सैनिक प्रबन्ध बनाने की एक दीर्घकालीन योजना कार्यान्वित करेगी, जापान की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक और रोड़े के समान प्रतीत हुआ। इस प्रकार देखल

- इस अध्याय के अनुपाद के समय समाचार-पत्रों में भारत सरकार की यह घोषणा प्रचारित हुई है कि अब सुदूर पूर्व (Far East) और मध्य पूर्व (Middle East) को क्रमशः पूर्वी एशिया एवं पश्चिमी एशिया कहा जायगा। किन्तु एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से इस पुस्तक में (Far East) और (Middle East) को क्रमशः 'सुदूर पूर्व' तथा 'मध्य पूर्व' ही कहा गया है।

—अनु०

एशिया की मुख्यभूमि पर ही जापान अपना विस्तार बर सकता था तथा केवल समान शक्ति संपन्न (equals) राष्ट्र के रूप में अर्पित विजेताप्रा के रूप में भी सामने आ सकते थे। इस घटना की चर्चा के पहिले, यह आवश्यक है कि इन वर्षों में विद्वानों के साथ चीन के सबबों के विषय में मुख्य मुख्य बातें जान ली जायें।

वॉशिंगटन सम्मेलन के बाद चीन (China After the Washington Conference)

सन १९११ की चीनी क्रांति के बाद चीन आपसी कलह का शिकार हो गया। सन् १९१६ में केन्टन (Canton) प्रांत पेंकिंग (Peking) सरकार—क्षेत्र देश पर जिसका शासन करीब-करीब नाम-मात्र का ही था—के हाथ से बिल्कुल ही निष्कल चुका था। वॉशिंगटन सम्मेलन के कुछ ही महीनों के भीतर १९२२ में, समस्त उत्तरी और मध्य चीन, जोकि प्रतिद्वंद्वी तुचु (Tuchuns) या प्रान्तीय राज्यपालों (provincial governors) के शासन में बँटा हुआ था, में गृहयुद्ध भड़क उठा। चीन के अन्तिम उत्तरी छोर पर चांग त्सो-लिन (Chang Tsolin) के कर्मठ नेतृत्व में मचूरिया वस्तुतः स्वतन्त्र होगया। मध्य चीन में वू-पै-फु (Wu-Pei-fu) सभी तु-वानों में सर्वाधिक शक्तिशाली था किन्तु देशों को एकबद्ध करने में वह कभी भी सफल नहीं हो सका। दक्षिण चीन में, केन्टन कोमिन्तांग (Kuomintang) या राष्ट्रवादी पार्टी (nationalist party) का मुख्यालय था। इस पार्टी का नेतृत्व ऐसे तरुण चीनी बुद्धिवादियों के हाथों में था जिनकी शिक्षा दीक्षा पश्चिमी योरोप या अमेरिका या चीन के ही अमरीकी कॉलेजों (colleges) में हुई थी और उनमें प्रजातन्त्र तथा आत्म-निष्ठा के सिद्धांत कूट-कूटकर भरे हुए थे। कोमिन्तांग के अध्यक्ष, सन-यातसेन (Sun Yat-sen) चीन के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनमें एक दूरदृष्टा तथा भविष्यदृष्टा के गुणों के साथ ही साथ चतुर राजनीतिज्ञ के गुणों का भी सम्मिलन था। सन-यातसेन १९२३ में, केन्टन सरकार के प्रधान (Head) बने और उन्होंने बोरोदिन (Borodin) नामक एक रूसी को अपने प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। बोरोदिन ने सोवियत अन्तर्राष्ट्रीयतावाद (internationalism) और चीनी राष्ट्रवाद में शीघ्र ही एक कामचलाऊ मेल स्थापित किया।

चीन के आपसी कलहों का चीनी राजनीति की दूसरी प्रमुख समस्या— विदेशी प्रभुत्व का विरोध (resistance to foreign resistance)— से निकट संबध था। उन्नीसवीं शताब्दी में बड़े राष्ट्रों ने चीन पर तथान्वित "असमान संधियों" ("unequal treaties") बाद दी थी जिनके अनुसार चीन ने उसके क्षेत्र में रहने और व्यापार करने वाले इन राष्ट्रों



सुदूर पूर्व

के नागरिकों को कई विशेष सुविधायें दी थी। इन विशेष सुविधायों में से, दो बहुत महत्व की थी। पहिली के अनुसार चीन आयात और निर्यात चुगी कर के रूप में अधिक से अधिक ५ प्रतिशत ले सकता था। दूसरे के अनुसार बड़े राष्ट्रों की चीन में क्षेत्रातीत अधिकार (Extra-territorial Jurisdiction) प्राप्त थे। उनके राष्ट्रवासियों

(nationals) पर न तो चीनी कानून लागू होते थे और न ही चीनी न्यायालयों में उन पर मुकद्दमा चलाया जा सकता था। वे अप्रत्यक्ष रूप से लगाए गए करों के अतिरिक्त और कोई कर चीन को नहीं देते थे। ऐसे सभी मामले जिनमें कोई विदेशी आरोपी अथवा प्रतिवादी (accused or defendant) होता था, संबंधित विदेशों के ही राष्ट्र के न्यायाधीशों द्वारा उसके राष्ट्र के कानूनों के अनुसार निबटाए जाते थे। इसके अतिरिक्त, चीन ने यह स्वीकार भी किया था कि वह सभी प्रमुख बन्दरगाहों में, विदेशियों के निवास के लिए पृथक् क्षेत्र देगा। कई बन्दरगाहों में इस प्रकार के क्षेत्र "सुविधा क्षेत्रों" ("concessions") और "बस्तियों" ("settlements") के रूप में विकसित हो चुके थे और उनकी नगरपालिकाएँ भी विदेशियों के ही हाथों में थीं। अन्य स्थानों पर बड़े-बड़े "पट्टाकामित" ("leased territories") थे। ये पट्टे इतने विस्तृत थे कि संबंधित विदेशी राष्ट्र को कुछ वर्षों के लिए इस प्रकार के क्षेत्र पर वस्तुतः सार्वभौमत्व ही प्राप्त हो जाता था।

प्रथम विश्वयुद्ध से पहिले जिनचित चीनियों की तरफ़ पोढ़ी इन सुविधाओं का उग्र विरोध करती थी। युद्ध समाप्त होने पर, जब जर्मनी और रूस चीन में इन विशेष अधिकारों से वंचित होगए, तब तो अन्य "असमान संधियों" को रद्द कराने का आन्दोलन व्यापक रूप धारण करने लगा। वाशिंगटन-सम्मेलन द्वारा इस आन्दोलन का मुकाबिला यह आशा दिखाकर करने का प्रयत्न किया गया था कि इन विशेष सुविधाओं में दीर्घ ही कमी की जाएगी। विशेषतः बड़े राष्ट्रों ने यह वचन दिया था कि ५ प्रतिशत के वर्तमान आयात-निर्यात कर पर तुरन्त ही २५ प्रतिशत अधिकर (surtax) लगाने और आगे चलकर आयात-निर्यात कर को १२५ प्रतिशत कर देन का अधिकार देने के लिए वे एक विशेष सम्मेलन का आयोजन करेंगे; और कुछ अस्पष्ट शब्दों में, उन्होंने यह वचन भी दिया था कि चीन में विदेशियों के क्षेत्रातीत अधिकारों और न्याय-प्रशासन (administration of justice) की जाँच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी : किन्तु वाशिंगटन सम्मेलन समाप्त होने के बाद, इन वचनों को कार्य रूप में परिणत करने की किसी को चिन्ता भी नहीं हुई। शृङ्खला के कारण विलम्ब के लिए काफी बहाना मिल गया। शृङ्खला के कारण अल्पसंख्यक प्रांतों स्थिति में इस बात की संभावना नभ ही प्रतीत होती थी कि

लि-किन (li-kin=duties levied on goods in transit in the interior, देश में माल लाने-लेजाने पर शुल्क) समाप्त कर दिया जायेगा—आयात निर्यात कर में वृद्धि के लिए यह भी एक शर्त थी।

विलव ने, उसके लिए किने ही हठ कारण क्यों न खोज निकाले गए हो कोमिन्तांग को लाभ उठाने का एक अवसर दिया जो कि इस समय चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की प्रबल समर्थक के रूप में सामने आई। मार्च १९२५ में सनपात-सेन की मृत्यु हो गई। किन्तु उनको मृत्यु ने चीनी राष्ट्रीयतावाद के पोषक सत्त के रूप में उनका स्थान निश्चित बना दिया। उनका नाम विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध राष्ट्रीय विद्रोह का प्रतीक बन गया। सोवियत प्रभाव में, विदेश-विरोधी इस भावना ने कटु और अप्रतिपक्षीय (implacable) बैर का रूप धारण कर लिया। बोरोडिन ने इस बैर का प्रमुख सहाय ग्रेट ब्रिटेन को—जो कि “सममान सम्बन्धों” के लिए उत्तरदायी तथा बोरोडिन के देश का प्रमुख शत्रु था—को बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। उसके लिए ऐसा कर सकना इसलिए भी सरल हो सका कि चीन में ब्रिटिश हितों का विस्तार काफी था। यदि मई १९२५ में शम्पाई की एक अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती में एक दुर्घटना नहीं घटी होती, तो बोरोडिन का प्रभाव समस्त उनना अधिक नहीं होता। उक्त मास में चीनी-विद्यार्थियों ने जिस समय कपड़ा मिलों में, जो जापानियों के स्वामित्व में थी, अभिको की स्थिति के सम्बन्ध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, उस समय ब्रिटिश अधिकारियों को कमान में नगरपालिका पुलिस ने उन पर गोली चलाई। पुलिस की इतनी कठोर कार्रवाई के लिए सम्भवत कोई औचित्य नहीं था। उसके बाद इस मामले के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों ने जो रुख अपनाया, उसने प्राग में भी डालने का काम किया। इन घटना के कुछ ही सप्ताहों के बाद के टन के ब्रिटिश “सुविधा सौत्र” (concession) में एक और तथा इससे भी भयकर गोलावारी हुई। सारे चीन में क्रोध की लहर फैल गई, और ब्रिटिश माल का बहिष्कार प्रारम्भ होगया।

इसी बीच, कोमिन्तांग के प्रभाव के विस्तार, जिसे बोरोडिन का योग्य समर्थन प्राप्त था, का उत्तर के तु-शुनों की शक्ति पर विग्रहकारी (disintegrating) प्रभाव पड़ रहा था। आयात निर्यात कर पर पुनर्विचार के लिए गठित विशेष

सम्मेलन ने भी आखिर १९२५ के सत्र में पेरिंग में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। किन्तु १९२६ के प्रारम्भ में ही, उसे अपना कार्य छोड़ देने के लिए विवश होना पड़ा क्योंकि उस समय चीन में ऐसी कोई मान्य सरकार ही नहीं थी जिस से कि वह वार्ता चला सके। पेरिंग में यद्यपि इस समय भी विदेशी उपद्रुतावास (legations) थे, तदपि वह चीन की राजधानी नहीं रह गया था। अब दक्षिण गुरुत्वाकर्षणकेन्द्र बन चुका था। अक्टूबर १९२६ में केन्टन की राष्ट्रवादी सरकार ने बड़े राष्ट्रों द्वारा प्राधिकृत (authorisation) किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना ही, अपने अधीनस्थ बदरगाहों में २३ प्रतिशत अधि कर लगाना प्रारम्भ कर दिया।

अब ब्रिटिश सरकार को भी यह सदबुद्धि आई कि बढ़ते हुए राष्ट्रीयतावाद—जो कि चीन की वास्तविक शक्ति थी—से समझौता कर लेना चाहिए। दिसम्बर १९२६ में उसने दो कदम उठाए जिनका काफी प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवादी सरकार के विदेश-मन्त्री से भेंट के लिए एक ब्रिटिश मन्त्री हकाऊ (Hankow) गया—चीन की सरकार को मान्यता देने की विषय में ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। पेरिंग स्थित ब्रिटिश उपद्रुतावास ने एक स्मरणपत्र जारी किया और जोर दिया कि चीनी राष्ट्रीय आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को सहानुभूति है। स्मरणपत्र में यह घोषित किया गया था कि चीन पर विदेशी सरकारें शासन स्थापने का विचार अब पुराना पड़ गया है तथा ब्रिटेन सधि पर पुनर्विचार सम्बन्धी वार्ता चलाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इस स्मरणपत्र के द्वारा ब्रिटेन ने प्रथम कदम के रूप में यह प्रस्ताव रखा था कि सारे चीन में २३ प्रतिशत अधि कर लगाने का अधिकार बड़े राष्ट्र तुरन्त ही दे दें।

इससे पहिले कि इस घोषित नीति का कुछ परिणाम निकले, तूफान आगया। जनवरी १, १९२७ को राष्ट्रवादी सरकार ने अपनी राजधानी कन्टन से हकाऊ में बदली जो कि राष्ट्र की राजधानी के लिए अधिक केन्द्रीय स्थान में था। कुछ ही दिनों बाद, हकाऊ स्थित ब्रिटिश सुविधाक्षेत्र को उत्तेजित चीनी जनता ने नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। इसलिए ब्रिटिश सेना को एक टुकड़ों शीघ्र ही शघाई भेजी गई ताकि वहाँ की अन्तर्राष्ट्रीय बस्तो को इसी प्रकार के आक्रमण से बचाया जा सके। फरवरी में, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी सरकार से एक समझौता किया जिसके अनुसार कुछ शर्तों पर हकाऊ स्थित ब्रिटिश सुविधाक्षेत्र का चीन को

हस्तांतरण बंध घोषित किया गया। समझौते की यह नीति जो कि ब्रिटिश जान-माल की सुरक्षा के दृढ़ निश्चय के कारण अपनाई गई थी, परिणाम सामने आने पर शीघ्र ही उचित सिद्ध हुई। सन् १९२७ दो महत्वपूर्ण बातों में एक नया मोड़ था।

एक तो, इस वर्ष में बोरोडिन (Borodin) के प्रभाव का सहसा और नाटकीय अन्त हो गया। मास्को के क्रांतिकारी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद और कोमिन्ताग के स्वदेशीय राष्ट्रीयतावाद में मेल सदा ही कृत्रिम रहा था। चीन की विदेशियों के नियंत्रण से मुक्त करने का सामान्य उद्देश्य पूरा होने तक, उनमें खूब निभी। किन्तु १९२७ के प्रारम्भ में जब राष्ट्रवादी सरकार ने हुकाऊ में अपने पैर जमा लिए और जब वह सारे चीन की केन्द्रीय सरकार होने का दावा करने लगी, तब कोमिन्ताग में दो दल हो गये। उसका वामपंथी दल (left wing) यह चाहता था कि बोरोडिन के सहयोगपूर्वक पार्टों की क्रांतिकारी परंपराएँ जारी रखी जायें। दक्षिण पंथी दल (right wing) जिस पर ग्रेट ब्रिटेन के नए दल का प्रभाव था, बड़े राष्ट्रीय द्वारा सम्मान और मान्यता पाने की आकांक्षा रखता था। इस दल को इस समय जनरल च्यांगकाई शेक के रूप में एक समर्थ नेता मिल गया जिसे न तो कम्युनिज्म से सहानुभूति थी और न ही वह रूसी सलाहकारों की सहायता लेना चाहता था। च्यांगकाई-शेक ने नानकिंग में एक प्रतिद्वन्द्वी कोमिन्ताग सरकार स्थापित की और हुकाऊ सरकार से यह माँग की कि बोरोडिन तथा अन्य कम्युनिस्टों को निकाल दिया जाए। जुलाई में यह माँग पूरी कर दी गई। बोरोडिन और उसके रूसी सहायक वापस मास्को भेज दिए गये और कई चीनी कम्युनिस्टों को जेल में ठूस दिया गया। राजधानी भी हुकाऊ से नानकिंग स्थानांतरित कर दी गई तथा इस घटना के बाद से नानकिंग ही चीन की राजधानी बना रहा।

दूसरे, सन् १९२७ में चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। दो वर्षों तक विदेशियों में ग्रेट ब्रिटेन ही चीन का कोपमाज्जन अधिकान्तः बना रहा था। वाशिंगटन सम्मेलन में अंगीकार की गई आत्म-नियन्त्रण की नीति का सत्यता से अनुसरण करते हुए जापान पृष्ठभूमि में ही रहा था और ब्रिटिश माल के बहिष्कार से उसने व्यापारिक लाभ उठाया था। किन्तु चीन में एक्यपूर्ण राष्ट्रवादी सरकार की पुनः स्थापना के आसार ने स्थिति उलट दी तथा चीन सम्बन्धी ब्रिटिश और जापानी नीति के मूलभूत अन्तर की सामने ला

दिया। चीन में ग्रेट ब्रिटेन का केवल व्यापारिक स्वार्थ था और उसकी यह हार्दिक इच्छा थी कि चीन एक शांतिपूर्ण तथा संगठित राष्ट्र हो जाए ताकि उसका व्यापार बढ़े। अपने पड़ोसी के मामलों में, जापान की रुचि राजनैतिक थी। वह यह चाहता था कि चीन कमजोर, फूटपरस्त और जापान के प्रभुत्व से टक्कर सेने या उसकी महत्वाकांक्षाओं को रोकने में असमर्थ हो बना रहे। विशेषकर, जापान को यह फूटी आंखों नहीं सुहाता था कि उत्तरी चीन केन्द्रीय सरकार के प्रभाव-शाली नियंत्रण में आ जाये।

इसीलिए, मई १९२७ में जब राष्ट्रवादी सेनाओं ने उत्तर की ओर कूच किया और पेकिंग के दक्षिण में लगभग ५०० मील येलो नदी (Yellow River) तक पहुँच गई तब जापानी सरकार सचेत हो गई। शान्त्युग प्रान्त में उसने कुछ सैनिक टुकड़ियाँ उतार दी और सामरिक महत्व के कुछ स्थलों पर अधिकार कर लिया ताकि राष्ट्रवादियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस कारवाई ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़े राष्ट्रों के दबाव के कारण जापान ने वाशिंगटन में यद्यपि यह घोषणा की थी कि शान्त्युग पर अधिकार करने की इच्छा उसने त्याग दी है, तदपि यह इच्छा अभी भी बनी हुई थी। सारे चीन में इस घटना को बहुत अधिक प्रतिक्रिया हुई। दो वर्षों पूर्व ग्रेट ब्रिटेन के प्रति प्रदर्शित की गई शान्ति प्रवृत्ति जापान के प्रति प्रदर्शित की जाने लगी। चीनी देशभक्तों ने अब जापानी माल का बहिष्कार प्रारम्भ किया। जापान द्वारा विरोध किए जाने पर भी, पेकिंग तक के समस्त चीन ने राष्ट्रवादी सरकार की सत्ता मान ली। किन्तु मंचूरिया के बारे में जापान इस से मस नहीं हुआ और अप्रैल १९२८ में जब चांग-त्सो लिन (Chang Tso-lin) ने नानकिंग से समझौता करने के आसार प्रकट किये, तब एक रहस्यपूर्ण बम के फूटने से उसकी मृत्यु हो गई। इस बम के बारे में कई लोगो का यह विश्वास था कि यह जापान का ही षड्यन्त्र था।

इस प्रकार १९२८ के मध्य तक, चीन में स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी और १९३१ की नाटकीय घटनाओं के लिए रास्ता तैयार हो चुका था। गृह-युद्ध बीच-बीच में चलता रहा। मध्य चीन के कुछ प्रान्तों में, कम्युनिज्म अब भी फैलता जा रहा था। दूरस्थ (outlying) प्रांतों में सरकार का नियंत्रण या तो था ही नहीं या था भी तो कमजोर था। मंचूरिया में, जापान के प्रभाव के कारण नानकिंग में कोई सहयोग नहीं हो पाता था किन्तु कम से कम नाम के लिए तो

चीन एक बार फिर एक केन्द्रीय सरकार के अधीन एक हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान पुनः चीन का प्रमुख सिरदर्द बन गया। चीन को जापान का हमेशा ही भय बना रहता था, इस कारण अन्य विदेशी हितों के प्रति उसके रुख में नरमी बनी रही। सन् १९१६ के बाद से चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध इतने सघर्षपूर्ण कभी भी नहीं रहे जितने कि १९२७ और १९३१ के बीच में थे।

जापान की मञ्चूरिया-विजय

(Japan Conquers Manchuria)

किन परिस्थितियों से प्रेरित होकर जापान से बिना किसी हिष्क के अपने प्रथम आक्रमण की तारीख निश्चित की, यह अनुमान लगा सकता कठिन है। जापान में सैनिक और अर्सेनिक (military and civil) अधिकारियों में बहुत समय से प्रतिद्वन्द्विता थी। दोनों ही जापान की बड़े राष्ट्रों की पंक्ति में ला बैठाने के लिये समान रूप से उत्सुक थे। किन्तु अर्सेनिक-राजनैतिक नेताओं (civilian political leaders) का यह विश्वास था कि यह काम ब्रिटिश और अमरीकी लोकमत को अपने पक्ष में करके भली भाँति किया जा सकता है। इसके विपरीत सैनिक अधिकारी (जिनकी स्थिति इसलिए भी सुदृढ़ थी कि वह अर्सेनिक सरकार के प्रति उत्तरदायी न होकर सम्राट के प्रति ही सीधे उत्तरदायी थे) सैनिक विजयों की नीति का अनुसरण कर जापान को महान् राष्ट्र बनाना चाहते थे। अर्सेनिक पार्टी की वाशिंगटन सम्मेलन में विजय हो चुकी थी और लगभग दस वर्षों तक वह इतनी प्रभावशाली रही कि उसने सेना को कोई कार्रवाई नहीं करने दी। किन्तु १९२७ के बाद से, जापानी हितों के प्रति चीन के उत्तेजनात्मक रुख (provocative attitude) ने जापान का धैर्य तोड़ दिया। सन् १९२६ और १९३१ के बीच के आधिक सकट जबकि जापान के विदेशी व्यापार का मूल्य लगभग आधा रह गया था, के कारण जापान में गम्भीर आन्तरिक विद्रोह की आशंका होने लगी। सन् १९३१ के प्रीव्स में, चीनी लुटेरों द्वारा मञ्चूरिया में एक जापानी अधिकारी की हत्या का उपयोग जनविद्रोह उमाड़ने में किया गया। सितम्बर में, सेना ने मामला अपने हाथों में ले लिया। इसके लिए जो अवसर जुना गया था वह संयोग से अथवा पूर्वयोजना-नुकूल ऐसा पवसर था जबकि थोट ब्रिटेन आर्थिक और राजनैतिक सकट के गर्त में फँसा हुआ था।

रूस और जापान के बीच युद्ध 'समाप्त' करने वाली सधि के अनुसार दक्षिण मचूरिया रेलवे, जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे से पोर्ट आर्थर (Port Arthur) तक दक्षिण की ओर जाती है, की रक्षा के लिए मचूरिया में लगभग १५,००० सैनिक रखने का अधिकार जापान को मिल गया था। ये रक्षक-सैनिक रेलवे क्षेत्र में ही रहते थे और उनका मुख्यालय मुकडेन (Mukden) में था। सितम्बर १८१६, १६३१ की रात को, एक जापानी गश्ती दल (patrol) को मुकडेन के समीप चीनी सैनिकों की एक ऐसी टुकड़ी का वास्तव में या कथित रूप से पता चला, जो कि मुख्य रेलवे लाइन को उड़ा देने का प्रयत्न कर रही थी। तुरन्त ही जापानी रक्षक बुलाए गए और एक छोटी सी मुठभेड़ हो गई जिसके परिणाम-स्वरूप मुकडेन स्थित २०,००० चीनी सैनिकों को या तो निःशस्त्र कर दिया गया या उन्हें तितर-बितर कर दिया गया। चार दिनों के भीतर ही, मुकडेन के उत्तर में २०० मील के घेरे में स्थित सभी चीनी नगरों पर, जिनमें से कुछ तो रेलवे क्षेत्र से बहुत दूर बसे हुए थे, जापान का अधिकार हो गया। चीनी प्रांतीय सरकार, जिसका प्रधान चांग-त्सो लिन का एक पुत्र था, मुकडेन से बाहर खदेड़ दी गई और चिनचो (Chinchow) में नाममात्र के लिए अपना शासत्त्व बनाए रही। नवम्बर के मध्य तक, उत्तरी मचूरिया का विस्तृत और थोड़ा भावादी वाला क्षेत्र जापान के हाथों में आ गया। उसके बाद जापानी सेनाएँ दक्षिण की ओर बढ़ी—इस समय वे युद्ध में बमबर्षक वायुयानों का प्रयोग करती थी। दिसम्बर २८ को चिनचो भी जीत लिया गया और जनवरी ४, १९३२ को, जापानी बड़ी दीवार (Great Wall) स्थित शानहैक्वान (Shanhaikwan) जो कि मचूरिया और मुख्य चीन के बीच का सीमांत स्टेशन है, पहुँच गए। इस प्रकार मचूरिया को जापान ने पूरी तरह विजित कर लिया।

जापान ने अपनी विजय योजना की राष्ट्रसंघ परिषद्, जिसका इस समय लगभग अविराम अधिवेशन हो रहा था, की परेशानी का विचार किए बिना ही कार्यान्वित किया था। आक्रमण होने ही, चीनी सरकार ने अनुबध्न के ग्यारहवें अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रसंघ से अपील की। इस अनुच्छेद के अधीन केवल निर्विरोध प्राप्त होने पर ही निर्णय लिए जा सकते थे। और राष्ट्रसंघ को इसी के अन्तर्गत सभी पिछले सफलताएँ मिली थी। जापानी प्रतिनिधि ने अपनी सरकार की ओर से यह अस्वीकार किया कि जापान चीन क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेने का कोई विचार रखता है और उसने सैनिक कारवाई का औचित्य यह

बताया कि चीनी लुटेरों से जापानी जान माल की रक्षा करने के लिए इस कार्रवाई का आश्रय लेना आवश्यक था। यूनान-बल्गेरिया विवाद में जिस रीति से सफलता मिली थी, (देखिए पृष्ठ ६७) उसी का पुनः अनुसरण करते हुए, राष्ट्रसंघ ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसका उद्देश्य जापान को पोछे हटने के लिए तैयार करना था। प्रस्ताव में जापानी प्रतिनिधि द्वारा दिया गया यह आश्वासन उद्धृत किया गया था कि, जापानी सरकार 'यथासंभव शीघ्र ही अपने सैनिकों को रेल्वे क्षेत्र में केवल उसी अनुपात में वापस हटा लेगी जितने कि जापानियों के जान माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।' प्रस्ताव में यह आशा प्रकट की गई थी कि "पुनः सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए यह और इसा प्रकार के अन्य कदम शीघ्र ही उठाए जाएंगे। सितम्बर ३०, १९३१ को यह प्रस्ताव निर्विरोध रूप से स्वीकार कर लिया गया, और उसके बाद उसका किन्तु निराशा अवस्था में परिपक्व का अधिवेशन एक पक्षधारे के लिए स्थगित हो गया।

पेरिस समझौते (Pact of Paris) के अनुसार, युद्ध का आश्रय लेना निषिद्ध था तथा वांछितगुण में की गई नौ राष्ट्र की संधि (देखिए पृष्ठ १८) के हस्ताक्षरकर्ता चीन की स्वतंत्रता और प्रसङ्गता का सम्मान करने के लिए वचनबद्ध थे। यही कारण था कि जापान हटनापूर्वक इस बात पर जोर देता रहा कि मंचूरिया में उसकी कार्रवाई को युद्ध न मानकर "पुलिस कार्रवाई" ("Police operations") माना जाए तथा चीनी क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाने का उसका कोई विचार नहीं था जैसे-जैसे समय बीतता गया बीसे-बीसे यह बहाना बनाए रखना भी अधिकाधिक कठिन होना गया। जब अक्टूबर १३ को परिपक्व का पुनः अधिवेशन हुआ, तब यह स्पष्ट हो चुका था कि जापान न केवल राष्ट्रसंघ का अनुबध्न ही, अपितु पेरिस समझौते और नौ राष्ट्रों की संधि का भी उल्लंघन करना चाहता था। इस कारण अमेरिका भी तुरन्त ही रगमच पर आगया। अमरीकी नेताओं ने शीघ्र ही यह अनुभव कर लिया कि जापान की इस कार्रवाई ने प्रशान्तसामर में शक्ति संघर्ष (struggle for power) के एक नए अध्याय का प्रारम्भ किया है। अमरीकी सरकार ने परिपक्व के प्रयत्नों की न केवल अप्रसन्न सराहना की, अपितु पेरिस और टोकियो स्थित अपने दूतनीतिक प्रतिनिधियों (diplomatic representations) के जरिए उनका समर्थन भी किया। इसके साथ ही परिपक्व के अध्यक्ष ब्रियान्ड (Briand) को उसने यह

सूचित भी किया कि परिषद् की कार्रवाई में भाग लेने के लिए यदि अमेरिका को कोई निमन्त्रण दिया गया तो वाशिंगटन में उसका स्वागत ही होगा।

चापमूसी और आश्चर्य भरे इस प्रस्ताव के बहकावे में आकर, परिषद् ने पहली गलती की। जब त्रायएण्ड ने परिषद् के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अमेरिका से परिषद् में एक प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया जाए तब जापान के प्रतिनिधि ने तुरन्त ही यह आपत्ति उठाई कि यह प्रस्ताव भवैधानिक है। अनुबंधपत्र के सत्रहवें अनुच्छेद में केवल एक ही स्थिति ऐसी रखी गई थी जिसमें राष्ट्रसंघ के गैर-सदस्यों से भी परिषद् में प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया जा सकता था। अभी ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। लम्बे वाद-विवाद के बाद यह आपत्ति अमान्य कर दी गई। मामले को किसी तरह बनाने की दृष्टि से परिषद् के अन्य सदस्यों ने भी यह निश्चित किया कि अमेरिका को आमन्त्रित किया जाना केवल नियमिक मामला (matter of procedure) है जिस पर बहुमत द्वारा निर्णय किया जा सकता है। अक्टूबर १६ को, एक अमरीकी प्रतिनिधि परिषद् में वासिल हुआ उसने यह घोषणा की कि वह परिषद् की शर्चाओं में केवल उसी सीमा तक भाग लेगा जिस सीमा तक उनका संबंध पेरिस समझौते से होगा। वातावरण में उत्साह बहुत अधिक था। आशावादी लोग यह कहते सुने जाते थे कि यदि राष्ट्रसंघ ने जापान को खो दिया है तो अमेरिका को पा लिया है। किन्तु घटनाओं ने शीघ्र ही यह स्पष्ट कर दिया कि इस आशा-वादिता का आधार ठीक नहीं था। अमरीकी सरकार अपने देश के राष्ट्रसंघ विरोधी जनमत से भय खाती थी। इस कारण अमेरिका का प्रतिनिधि परिषद् की कार्रवाई में कोई सक्रिय भाग नहीं ले सका। अगले माह जब परिषद् की बैठक पुनः प्रारम्भ हुई तब अमरीकी सहयोग परिषद् के सदस्यों से निजी और अशासकीय वार्ताएँ चलाने तक ही सीमित रहा।

इसी बीच अमेरिका के परिषद् में भाग लेने सम्बन्धी विवाद की खाई जापान और परिषद् के अन्य सदस्यों के बीच गहरी पड़ गई थी। दोनों पक्षों का एक कड़ा हो गया। सेना हटाने के लिए जापान ने पहिली शर्त यह रखी कि उसे चीन से सीधी ही वार्ताएँ चलाने दिया जाए तथा परिषद् को उसने यह बताने से भी इन्कार किया कि वार्ता के लिए उसकी शर्तें क्या होंगी। परिषद् के अन्य सदस्य इस बात पर जोर देते रहे कि वार्ताएँ चलाने से पहिले, जापान अपनी सेनाएँ

रेल्वे क्षेत्र में हटा ले। अक्टूबर २४ को इस आशय के एक प्रस्ताव पर मत लिए गए कि “परिषद् को अगली बैठक की तारीख अर्थात्, १६ नवंबर से पहिले जापान अपनी सेना पूरी तरह हटा ले।” किन्तु जापानी प्रतिनिधि के एकमात्र विपरीत मत (adverse vote) के कारण यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका। समझौते का मार्ग निश्चय ही समाप्त हो चुका था और अब ग्यारहवें अनुच्छेद के अनुसार कोई कार्रवाई शेष नहीं बची थी।

किन्तु राष्ट्रसंघ के उत्कर्ष के दिनों में ग्यारहवें अनुच्छेद को इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी और पन्द्रहवें अनुच्छेद में निर्धारित कार्रवाई, जिसके अनुसार सम्बन्धित पक्षों के मत के विरुद्ध भी निर्णय दिया जा सकता था, का आशय लेने की इतनी प्रगाढ़ अभिच्छा थी कि उक्त निष्कर्ष (समझौते का मार्ग समाप्त हो चुका है) पर तुरन्त ही नहीं पहुँचा जा सकता था। नवम्बर १६ से दिसंबर १० तक के पेरिस के अपने लम्बे अधिवेशन में, परिषद् ग्यारहवें अनुच्छेद के अनुसार इस समस्या को सुलझाने में खूभी रही। पूर्ण गतिरोध उपस्थित हो गया। किन्तु प्रकट रूप से असफलता स्वीकार करना यह निर्विरोध निर्णय कर स्थगित कर दिया गया कि मुद्र पूर्व में एक राष्ट्रसंघ आयोजन भेजा जाए, जोकि घटनास्थल पर जाकर इस बात की जाँच करे कि “चीन और जापान के बीच शांति भंग होने की आशंका पैदा करने वाली क्या ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ सकता है”, किन्तु आयोजन पर यह बन्धन रखा गया था कि वह “किसी भी पक्ष के सैनिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप” न करे। इस आयोजन में पाँच बड़े राष्ट्रों (ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इटली) के प्रतिनिधि रहे गये थे तथा उसका अध्यक्ष ब्रिटिश प्रतिनिधि लॉर्ड लिटन (Lord Lytton) को बनाया गया था।

लिटन आयोजन के अपना कार्य आरम्भ करने से पहिल ही, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ घट गईं। चीनियों ने जापानियों के आक्रमण का उत्तर अपने परम्परा-नुकूल अस्त्र—जापानी माल का बहिष्कार—से दिया था। उत्तेजना इतनी फैल चुकी थी कि यदा कदा दुर्घटनाएँ घटित हो जाया करती थीं। जनवरी १९३२ के अन्त में, एक ऐसी ही घटना से, जिसमें कि कुछ जापानी मिश्रणों पर शर्माई में हमला किया गया था, तथा उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, जापान के सैनिक अधिकारियों को चीन को पाठ पढ़ाने का एक बहाना मिल गया। एक बड़ी

सेना शंघाई में उतारी गई और उसने अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती को अपना मंडू बना कर चेपे (Chapei) उपनगर पर हम बरसाए तथा उसे लगभग जला ही डाला। किन्तु शंघाई पर स्थायी रूप से अधिकार करना जापान का वर्तमान कार्यक्रम नहीं था। मार्च के प्रारम्भ में ही, चीन में लिटन-आयोग के आ जाने से जापानियों ने भी इस अशोभनीय-भ्रमहृत्वपूर्ण घटना को रफा दफा करना चाहा। लम्बी बातों-प्रो के बाद, जिनमें ब्रिटिश मंत्री ने मध्यस्थ का काम किया, जापानी सेनाएँ मई में शंघाई से हटा ली गईं। इसी बीच जापान ने मंचूरिया में कठपुतली मंचूकुओ गणतन्त्र (puppet Republic of Manchukuo) स्थापित कर मंचू (Manchu) वंश के मन्तिम वंशज पु-यि (Pu Yi) को उसका राष्ट्रपति (president) बनाकर अपना विजय का सुट्टा बना लिया था। इसी वर्ष के मन्तिम भाग में, जापान ने इस गणतन्त्र को जो कि वास्तव में जापानी सलाहकारों की सहायता से प्रशासित होता था, एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में सरकारी तौर पर मान्यता दे दी।

इधर जेनेवा में भी घटनाचक्र चल रहा था। जनवरी २६ को, जबकि शंघाई में युद्ध चल रहा था आखिर चीनी सरकार ने यह माँग की कि अनुबध्पत्र के दसवें और पन्द्रहवें अनुच्छेद लागू किए जायें। इसके बाद ही उसने यह अनुरोध भी किया कि राष्ट्रसंघ सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाये। मामले की परिषद् से राष्ट्रसंघ-सभा में ले जाने का कारण स्पष्ट था। छोटे राष्ट्रों ने, जिन्हें कि आक्रमण से सबसे अधिक भय रहता था, प्रारम्भ से ही बड़े राष्ट्रों की प्रपेक्षा, जिन पर अनुशास्तियों को लागू करने का दायित्व पड़ना, इस बात की उत्सुकता अधिक ही दिखाई थी कि जापान पर बल प्रयोग (coercion) किया जाये। राष्ट्रसंघ-सभा में, छोटे राष्ट्रों का काफी बहुमत था। सभा का विशेष अधिवेशन मार्च में हुआ और उसमें कई सुन्दर भाषण दिए गए। किन्तु लिटन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक वह अपना निर्णय घोषित नहीं कर सकी थी तथा लिटन आयोग की रिपोर्ट शरद के पहले तैयार न हो सकती थी। ग्रीष्म में, जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में उलझा हुआ था, तथा लुसाने में क्षतिपूर्ति का निबटारा हो रहा था। इस प्रकार सुदूर पूर्व समस्या लगभग भुला दी गई।

सितम्बर के अन्त में लिटन आयोग का प्रतिवेदन जेनेवा पहुँचा और नवंबर में वह परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह प्रतिवेदन एक लंबा और विस्तृत

दस्तावेज या जिसमें न केवल मचूरिया घटना की ही चर्चा की गई थी, अपितु चीन-जापान संबंधों के लगभग हर पहलू पर प्रकाश डाला गया था। जिन विभिन्न बहानों को बताकर जापान मचूरिया पर अपने प्राक्रमण का औचित्य बताना चाहता था, उनको आयोग ने बिना किसी हिचक के अस्वीकार कर दिया था और यह निर्णय दिया कि स्वतंत्र मचूरिया राज्य पूर्ण गल्प (complete fiction) है। इसके विपरीत, उसने इस बात से भी इंकार नहीं किया कि पिछले दिनों जापान के प्रति चीन का रुख गहन और उत्तेजनात्मक रहा है। उसने यह निर्णय दिया कि न तो पूर्वस्थिति की स्थापना से और न ही बोगस मचूरिया राज्य की यथावत् बनाए रखने से समस्या का संतोषजनक समाधान हो सकेगा। इसलिए उसने यह सिफारिश की कि राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में चीन और जापान के बीच वार्ताएं चलें तथा उनके परिणामस्वरूप मचूरिया में स्वायत्तशासी शासन की स्थापना की जाए।

लिटन प्रतिवेदन पर राष्ट्रसंघ की परिषद, सभा और सभा की एक समिति ने, जिस कि अनुबंधपत्र के पंद्रहवें अनुच्छेद के अनुसार एक प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा गया था, क्रमशः विचार किया। समिति ने अपना प्रतिवेदन लगभग विल्कुल ही लिटन प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया। उसमें यह सिफारिश की गई थी कि चीन और जापान राष्ट्रसंघ सभा द्वारा गठित की जान वाली एक समिति के तत्वावधान में जापानी सेनाओं को हटा लेने तथा चीन के सार्वभौमत्व के अन्तर्गत मचूरिया में स्वायत्तशासन की स्थापना के लिए वार्ताएं चलाएं। उसमें यह सुझाया गया था कि राष्ट्रसंघ के सदस्य मचूरिया की वर्तमान सरकार को मांगता न दें किंतु इसके साथ ही उसने यह भी अस्वीकार कर दिया था कि मचूरिया में पूर्वस्थिति कायम की जाये।

जो भी हो, इस प्रतिवेदन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता इस बात में थी कि वह इस कुशलता के साथ लिखा गया था और उसमें किंगो प्रकार का निर्णय देने से बचा गया था ताकि अनुबंधपत्र के सोलहवें अनुच्छेद के अन्तर्गत अनुशास्तिर्वा लगाने की आवश्यकता न पड़े। अनुबंधपत्र, पेरिस सम्मेलन और नौ राष्ट्र-संघ के प्रथम कर्तव्यों का उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। किंतु उसमें इस निष्कर्ष से बचा गया था कि जापान ने इन कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। जापान का यह मन उसमें विधिवत् अस्वीकार किया गया था कि मचूरिया अभियान

केवल पुलिस कार्रवाई थी। किन्तु उसमें लिटन प्रतिवेदन का निम्नलिखित भाग उद्धृत कर उसका समर्थन किया गया था कि “वर्तमान मामला एक देश द्वारा दूसरे देश पर राष्ट्रसंघ के अनुबध्पत्र में निर्धारित समझौते के तरीको को समाप्त करने से पहिले ही युद्ध घोषित कर देने का नहीं है और न ही वह पड़ोसी देश की सशस्त्र सेनाओं द्वारा किसी देश के सीमात का अतिक्रमण किए जाने से सम्बन्धित साधारण मामला है।” इस उद्धरण की महत्ता स्पष्ट थी। यदि जापान ने युद्ध का आश्रय नहीं लिया था, तो उसने अनुबध्पत्र का उत्सघन भी नहीं किया था और सोलहवें अनुच्छेद को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अनुशास्तिमो पर तो वास्तव में कभी विचार ही नहीं किया गया। प्रतिवेदन में केवल उसी दृष्टि की सिफारिश की गई थी जो कि अमरीकी विदेशी-मन्त्री ने पहिले पहल सुझाया था और जिसमें—मच्छुक्रुओं को माग्यता नहीं देना—अमरीकी सरकार सहयोग देने के लिए तैयार थी।

फरवरी २४, १९३३ को, राष्ट्रसंघ सभा ने इस प्रतिवेदन पर अपना मत दिया। उस दिन उपस्थित चवालीस प्रतिनिधिमंडलों में से बयालीस ने उसे स्वीकार कर लिया। स्पाम ने मत नहीं दिया और जापान ने उसके विरोध में अपना मत दिया किन्तु प्रतिवेदन के निर्विरोध स्वीकार किए जाने पर विवाद से सम्बन्धित एक पक्ष के विपरीत मत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही परिणाम की घोषणा की गई, जापानी प्रतिनिधिमंडल सभागृह से एक साथ उठकर चला गया। एक माह बाद, जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की विधिबत् सूचना भी दे दी।

प्रतिवेदन स्वीकार करने के बाद, राष्ट्रसंघ-सभा ने एक समिति “स्थिति का उत्तार-चढ़ाव देखने” और राष्ट्रसंघ के सदस्यों तथा गैर सदस्यों को उनकी कार्रवाई और रक्त में मेल लाने के उद्देश्य से सहायता करने के लिए” नियुक्त की। सोवियत सरकार राष्ट्रसंघ के राजनैतिक अंगों से इस समय भी सहयोग नहीं करना चाहती थी। अमरीकी सरकार ने सहयोग देना सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस समिति के लिए अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। किन्तु, राष्ट्रसंघ के लिए अब वस्तुतः कोई प्रयत्न करना शेष नहीं रह गया था। समिति ने दो स्पष्ट मुद्दों—सुदूर पूर्व को शस्त्रास्त्रों का निर्यात और भ्रमान्यता (non-recognition) निर्यात के व्यावहारिक परिणाम—पर विचार किया।

वहाँ तक पहिले प्रश्न का सम्बन्ध है, कोई परिणाम नहीं निकल सका। ब्रिटिश सरकार ने कुछ प्रबुद्धिमानों पूर्वक ग्रेट ब्रिटेन से चीन और जापान दोनों की ही शस्त्रास्त्र भेजने पर रोक लगा दी। किन्तु जब और किसी ने उसके इस उदाहरण का अनुकरण नहीं किया, तब यह रोक हटा ली गई और इसके बाद दोनों ही पक्षों की शस्त्रास्त्र भेजने की सीमा निश्चित करने का और कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इस प्रकार जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, समिति ने समान्य राज्य के साथ शास्त्र-तार और वाणिज्यिक सबबों तथा ऐसे राज्य में रहने वाले विदेशी कूटनीतिक प्रनिधियों की स्थिति का कुछ जटिलताओं की ही ध्यानवीन की। बाहरी दुनिया से संपर्क की अधिकान व्यावहारिक सुविधाएँ मच्छुम्पों की सुलभ रही। किन्तु उसका अस्तित्व जापान के सिवाय अन्य किसी भी महत्त्वपूर्ण देश ने मान्य नहीं किया।

राष्ट्रसंघ पर परिणाम (Consequences to League)

जापान द्वारा मच्छुरिया-विजय प्रथम विश्व-युद्ध के बाद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सीमाचिह्नों (landmarks) में से एक थी। उससे यह सूचित होता था कि वाणिज्य सन्मेलन द्वारा कुछ समय के लिए टाल दिया गया शक्ति-सम्पर्क (struggle for power) अब पुनः प्रारम्भ होने वाला था। बैसे मारे विश्व के लिए इस घटना ने यह सूचना दी कि युद्ध-समाप्ति के बाद, दुनने नये रूप में जो 'शक्ति-कूटनीति' ("power-politics") किसी प्रकार बन्द होगई थी, उसका पुनः आधय लिया जाने वाला था। शानि समझौते के बाद पहिली बार, काफी बडे पैमाने पर युद्ध किया गया था। (यद्यपि उडे पुलिस कार्रवाई बनाया गया था) और विजेता ने काफी क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिया था (यद्यपि उडे एक स्वतन्त्र राज्य घोषित किया गया था)। राष्ट्रसंघ के लिए, जिनक अनुबधपत्र और प्रादर्शों की प्रवहेलना की गई थी, इस घटना के परिणाम बहुत अधिक हुए थे। इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल था कि राष्ट्रसंघ के सदस्य (विशेषतः बडे राष्ट्र जिन पर अनुबधपत्र का पालन करवाने का मुख्य भार आवश्यक रूप से था) किसी शक्तिशाली और सुमज्जिन राज्य की आक्रमणात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार नहो थे।

इस असमर्थता को छिपाने के लिए कई बहाने उस समय पेश किए गए थे। यह अग्नि-परीक्षा ऐसे समय पर आई थी जब सारा संसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्पूर्ण व नाशकारी कमी आ जाने से कष्ट-ग्रस्त था। दिवाळी तीर पर यह कहा जाता था कि यदि अनुवधपत्र के अनुसार जापान से वित्तीय और आर्थिक सम्बन्ध तोड़ लिए जाएं, तो उसका अर्थ जानबूझकर वर्तमान आर्थिक कष्ट को और भी भयंकर बना लेना होगा। जापान के प्रतिरिक्त ब्रिटेन ही राष्ट्रसंघ का एक ऐसा सदस्य था जिसने पास प्रथम थ्रॉलो का समुद्री बैठा था। यदि जापान आर्थिक अनुशास्तियों के उत्तर में अनुशास्ति लगाने वाले राष्ट्रों के चीन स्थित मचीन प्रदेशों पर आक्रमण कर देता, तो अपने सामान्य शत्रुओं से इतनी दूरी पर ब्रिटिश नौसेना प्रतिरक्षा (defence) शायद ही ठीक तौर से कर पाती। इसलिए यह विचार फैल गया कि यह (जापान सम्बन्धी) मामला एक अपवाद है और उसे पूर्वोदाहरण (precedent) नहीं माना जा सकता। दूरी बहुत अधिक थी। अनुवधपत्र के इक्कीसवें अनुच्छेद के लेखकों और लोकार्थों सचिकर्ताओं ने सुरक्षा के प्रादेशिक स्वरूप (regional character of security) को मान्यता देकर बुद्धिमानी ही की थी। योरोपीय राज्यों से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे दुनिया के उस पार अनुशास्तियाँ लगाएँ। चीन की असाधारण स्थिति, जिस पर राष्ट्रसंघ-सभा के प्रतिवेदन में सावधानीपूर्वक जोर दिया गया था, से भी राष्ट्रसंघ के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने का औचित्य सिद्ध हो जाता था। यद्यपि अनुवधपत्र सुदूर पूर्व में असफल हो चुका था, तदपि उससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता था कि योरोप में वह प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगा मंचूरिया विवाद की अंतिम अवस्थामों में, केवल चीनी प्रतिनिधि—जिसने दुःखपूर्वक यह कहा था कि, चीन से “यह स्वीकार कर लेने की आशा नहीं की जा सकती कि सचियों, अनुवधपत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के मान्य सिद्धान्तों का प्रवर्तन मंचूरिया की सीमा के पास ही समाप्त हो जाता है”^१—को छोड़कर सभी के मन में यह आत्मसतोषकारी भावना भरी हुई थी।

1 “Cannot be expected to admit that the operation of treaties, covenants and the accepted principles of international law stops at the border of Manchuria”

इसके प्रतिरिक्त, मचूरिया घटना ने राष्ट्रसंघ को एक और लाभ—अमेरिका की सद्भावना की प्राप्ति—सहज ही हो गया था। यह अवश्य ही था कि परिषद की कार्यवाहियों में अमरीकी प्रतिनिधि ने बहुत ही बड़े समय तक भाग लिया था। यह भी अनिश्चन ही था कि यदि राष्ट्रसंघ आर्थिक अनुशास्त्रियाँ लगाता, तो अमेरिका उसके साथ सहयोग करता अथवा नहीं। यह स्पष्ट था कि अमरीकी सैनिक सहयोग की आशा किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती थी। किन्तु अमेरिका का राष्ट्रसंघ का सदस्य बन जाना अब भी पहिले की भाँति ही असम्भव था। परन्तु इन सभी मर्यादाओं के होते हुए भी, राष्ट्रसंघ के प्रति अमरीकी लोकमत में एक निश्चन परिवर्तन हुआ। इस प्रश्न (मचूरिया) पर राष्ट्रसंघ के हर निश्चय का अमरीकी सरकार ने प्रकट रूप से स्वागत किया—अब तक अमेरिका की जो नीति रही थी, उसमें यह एक नई बात थी। इस वधा में समवनः और अधिक प्रगति हुई होती किन्तु निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में अमेरिका द्वारा भाग लिए जाने के हतोत्साहकारी प्रभाव ने इसमें रूकावट डाल दी।

मचूरिया विवाद के ही समय, राष्ट्रसंघ की दो और युद्धों—दोनों ही दक्षिण अमेरिका में हुए—की समस्या का सामना करना पड़ा। इस बार भी अमरीकी सरकार ने राष्ट्रसंघ की कार्यवाही का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। इनमें से पहिल युद्ध का सम्बन्ध चाको (Chaco) से था, जो कि दूरस्थ एक निर्जन (uninhabited) प्रदेश था तथा जिसके लिए बोलिविया और पैराग्वे (Paraguay) में वर्षों से संघर्ष चल रहा था। वर्ष १९३२ में नियमिन युद्ध प्रारम्भ हो गया और अगले वर्ष पैराग्वे ने युद्ध की विधिवत् घोषणा कर दी। राष्ट्रसंघ ने इस विवाद का निवटारा पहिल अनुवचपत्र के अनुच्छेद म्यारह के अधीन और बाद में पन्द्रहवें अनुच्छेद के अधीन किया। उसके लगभग सभी सदस्यों और अमेरिका ने दोनों ही युद्धरत (belligerent) राष्ट्रों को युद्ध सामग्री भेजे जाने पर रूकावट लगा दी किन्तु हर प्रयत्न निष्फल गया। युद्ध चलता ही रहा और १९३५ में उसकी समाप्ति पर पैराग्वे की विजय हुई। दूसरा विवाद पेरू (Peru) द्वारा कोलंबिया की छोटी सी लेटिसिया (Leticia) बस्ती और उसके निकटवर्ती क्षेत्र पर कब्जा कर लेने से सम्बन्धित था। कोलंबिया ने पन्द्रहवें अनुच्छेद के अधीन परिषद् से अपील की। इस पर परिषद् ने मार्च १९३३ में पेरू

से कोलंबिया के क्षेत्र से हट जाने का अनुरोध किया। पहिले तो पेरू ने इस अनुरोध की अवहेलना की किन्तु इसी बीच पेरू में ही कुछ ऐसी घातक घटनाएँ घटी कि पेरू का रुख धार्मिक बुद्धिसंगत हो गया। इस वर्ष के अन्त में एक राष्ट्र-संघ आयोग कोलंबिया को उक्त जिला लौटाए जाने का अधीक्षण करने (to superintend) के लिए लेटिशिया गया। किन्तु न तो चाको में राष्ट्रसंघ की सफलता और न ही लेटिशिया में उनकी सफलता से मचूरिया और निःशस्त्रीकरण सम्मेलन जैसी गंभीर समस्याओं के प्रति सत्कार की चिन्ताएँ दूर हो सकी।

६. निःशस्त्रीकरण सम्मेलन

(The Disarmament Conference)

यह केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि यदि निःशस्त्रीकरण सम्मेलन १९२५ और १९३० के बीच में हुआ होता तो उसे अपने कार्य में सफलता मिली होती। किंतु इतना निश्चित है कि फरवरी १९३२ में जब उसका अन्तिम अधिवेशन हुआ—जब आर्थिक संकट चरम-सीमा पर था और जापानियों ने शंघाई पर हमला किया था—तब उसकी सफलता के लगभग सभी आसार मिट चुके थे। मचूरिया-विफलता (fiasco) के बाद ही हुई उसकी असफलता उस संकट-काल की समाप्ति थी जो कि १९३० में प्रारम्भ हुआ था। जो भी हो, सम्मेलन का विघटन देने से पूर्व उन बस वर्षों पर यहाँ सशस्ति दृष्टिपात करना आवश्यक है जो सम्मेलन के अनुकूल वातावरण तैयार होने लगे।

निःशस्त्रीकरण समस्या

(The Disarmament Problem)

मित्र-राष्ट्रो ने वसैलीज-संधि में यह घोषणा की थी कि जर्मनों का लगभग पूर्ण निःशस्त्रीकरण का उद्देश्य “सभी राष्ट्रों के शस्त्रीकरण का व्यापक सीमा (limitation) प्रारम्भ करना संभव बनाना” था। अनुबन्धपत्र के प्राठवें अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रसंघ के सदस्यों ने यह स्वीकार किया था कि “राष्ट्रीय-सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किसी भी राष्ट्र के शस्त्रास्त्रों की निम्नतम सीमा निर्धारित करना वांछित बनाए रखने के लिए आवश्यक है।” इसलिए, एक तरफ तो मित्र-राष्ट्र सरकारों ने जर्मनी को यह वचन (जो निःविधित (legally) नहीं, तो नैतिक दृष्टि से तो बचनकारी या ही) दिया था कि जर्मनी को निःशस्त्रीकरण कर दिए जाने के बाद व्यापक निःशस्त्रीकरण किया जाएगा, और दूसरी ओर उन्होंने शस्त्रास्त्रों की रकमों में “राष्ट्रीय सुरक्षा” (national safety) को सर्व-प्रमुख मान लिया था। इन दोनों सिद्धान्तों में संघर्ष ही निःशस्त्रीकरण समस्या थी।

अनुबन्धपत्र के आठवें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रसंघ-परिषद् का यह कर्तव्य था कि वह "विभिन्न सरकारी द्वारा विचार और कार्रवाई" के लिए शस्त्रास्त्रों में कमी सम्बन्धी योजनाएँ बनाये। नवम्बर १९२० में, परिषद् ने इस कार्य में उसे सहायता पहुँचाने के लिए एक "स्थायी मिश्रित आयोग" ("Temporary Mixed Commission") की स्थापना की जिसमें अ-सेना (civilians) और सेना दोनों ही के प्रतिनिधि थे। किन्तु निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में पहिली सफलता वाशिगटन सम्मेलन में मिली। इस सम्मेलन में, प्रमुख नौसैनिक राष्ट्रों (naval powers) की नौसेना का सीमान्त टनो और अनुपातों की एक सरल सी सांख्यिक योजना (numerical scheme) द्वारा कर दिया गया था। अब यह राष्ट्रसंघ का काम था कि वह उस जमाने की सेना के सबसे महत्वपूर्ण अंग—थल सेना (क्योंकि वायु-सेना अभी अपनी शैशवावस्था में ही थी) पर भी यह सिद्धान्त लागू करे। अस्थायी मिश्रित आयोग के ब्रिटिश प्रतिनिधि ने १९२२ में सेनाओं के सीमान्त के लिए एक सांख्यिक योजना प्रस्तुत की। उसके अनुसार सेनाएँ ३०,००० सैनिकों के कल्पित यूनिटों (imaginary units) में विभाजित की जानी थी और कुछ यूनिट (युद्धपोतों के समान) हर राष्ट्र के लिए निर्धारित किए जाने थे। इस प्रकार फ्रांस को छः यूनिट या १८०,००० सैनिकों की सेना मिलनी थी तो इटली को चार यूनिट, ग्रेट ब्रिटेन को तीन इत्यादि। दुर्भाग्यवश इस सीधी साधी योजना की लगभग हर योरोपीय देश के सैनिक विशेषज्ञ ने आलोचना की। दिखाऊ तौर पर यह तर्क किया गया कि कुछ टनो का युद्धपोत तो थोड़े-बहुत अक्षों में एक प्रामाणिक वस्तु है और बन्दूकों के रूप में उसका अधिकतम पूरक (maximum complement) ज्ञात है किन्तु ३०,००० सैनिकों के यूनिट की शक्ति का कोई माप नहीं हो सकता तथा उसके शस्त्रास्त्रों के अनुपात में उसकी शक्ति लगभग बिल्कुल ही अनिश्चित हो सकती है। इस प्रकार थल-सेना निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी ठोस योजना को निदास्पद तरीके से टाल दिया गया।

किन्तु अनुच्छेद आठ तो ज्यों का त्यों बना हुआ था उसके बारे में कुछ न कुछ कदम उठाना आवश्यक था ही। तो ऐसे अवसर पर "राष्ट्रीय सुरक्षा" की शर्त पर भरोसा करते हुए, फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि निःशस्त्रीकरण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यक शर्त है। फ्रांसीसियों

के इस दृष्टिकोण को ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का भी समर्थन मिला। अगले तीन वर्षों में, प्रारूप पारस्परिक सहायता संधि (Draft Treaty of Mutual Assistance), जेनेवा उपसंधि और लोकार्नों संधियों की धूम रही। इस सम्पूर्ण अवधि में निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में दो बातों को छोड़ और कुछ भी प्रगति नहीं हुई। एक तो, वाशिंगटन सम्झौते के आधार पर छोटे-छोटे राष्ट्रों का नौसैनिक शस्त्रोकरण (armaments) सीमित करने का असफल प्रयास और दूसरे, शस्त्रों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नियन्त्रित करने के लिए एक सम्झौता जिस पर कभी भी अमल नहीं किया गया।

लोकार्नों संधियों पर हस्ताक्षर और राष्ट्रसंघ में जर्मनी के प्रवेश की सम्भावना ने निःशस्त्रीकरण की ग्राही में एक बार पुनः गति ला दी। लोकार्नों सम्मेलन में की गई अन्तिम उपसंधि में, हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने अपने आपको इस बात के लिए वचनबद्ध किया था कि इन सम्झौतों के परिणामस्वरूप, “अनुबन्धपत्र के आठवें अनुच्छेद में उपबन्धित निःशस्त्रीकरण प्रभावपूर्ण तरीके से तथा शीघ्र ही किया जा सकेगा।” इस समय के बाद से जर्मनी द्वारा अन्य राष्ट्रों को भी निःशस्त्र करने की मांग निःशस्त्रीकरण कार्रवाई का एक निर्णायक घटक (determining factor) हो गई। दिसम्बर १९२५ में, परिषद् ने एक निःशस्त्रीकरण सम्मेलन तैयारी आयोग (Preparatory Commission for the Disarmament Conference) की नियुक्ति की जिसकी पहली बैठक मई १९२६ में हुई। जर्मनी, अमेरिका और सोवियत-संघ सभी से इस आयोग के सदस्य बनने का अनुरोध किया गया था। प्रथम दोनो देशों ने तुरन्त ही और सोवियत संघ ने अगले वर्ष यह निमन्त्रणा स्वीकार कर लिया।

फिर भी, कार्य की प्रगति धीमी ही हुई। सन् १९२६ का अधिकांश भाग दो प्राविधिक उप-आयोगों (“technical” sub commissions) के कार्य में ही व्यतीत हो गया जो यह परिभाषित करने का कठिन कार्य कर रहे थे कि किस प्रकार के शस्त्रास्त्र सीमित और कम किए जाएं। जब ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने निःशस्त्रीकरण-सम्झौतों के प्रारूप प्रस्तुत किए, तब वही जाकर मार्च १९२७ में तैयारी आयोग ने वास्तव में अपने विषय को छुड़ा। ये प्रारूप केवल सत्याम सम्झौते (dummy convention) ही थे। उनमें कोई प्रांकडे नहीं दिए गये थे बल्कि एक रूपरेखा यह बताने के लिए दी

गई थी कि क्या और किस प्रकार सीमित किया जाये। किन्तु फिर भी वे अत्यधिक मत विभिन्नताएँ सूचित करते थे जिनमे से अनेक तो मूलभूत थी। सैनिकों के मामले में, फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल केवल सेवारत सैनिकों (man on service) की ही संख्या सीमित करना चाहता था जबकि ब्रिटिश, अमरीकी और जर्मन प्रतिनिधिमंडल प्रशिक्षण प्राप्त सभी व्यक्तियों की संख्या सीमित करने के पक्ष में थे। जहाँ तक सैनिक सामग्री का प्रश्न है, जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल की यह माँग थी कि सभी महत्वपूर्ण शस्त्रास्त्रों की स्पष्ट सांख्यिक सीमा निर्धारित की जाये जैसी कि वॉर्सेलोज की संधि में उसके (जर्मनी) लिए निश्चय की गई थी। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल अप्रत्यक्ष उपाय—प्रायः व्ययक में ही सैनिक सामग्री पर व्यय की सीमा बाँध कर (सीमन का केवल यही प्रकार जर्मनी पर अभी तक लागू नहीं किया गया था)—द्वारा यही कार्य करना चाहता था जबकि ब्रिटिश और अमरीकी प्रतिनिधिमंडलों का यह विचार था कि सैनिक सामग्री का सीमन अव्यवहार्य (impracticable) है। नौसैनिक सामग्री के विषय में फ्रांसीसी और इटालियन प्रतिनिधिमंडल की केवल यही माँग थी कि समुद्री २० का सीमन कुल टन (total tonnage) निश्चित कर लिया जाये। इसके विपरीत, ब्रिटिश और अमरीकी प्रतिनिधिमंडल हर प्रकार के जहाज का अलग अलग सीमन चाहते थे। प्रायः व्ययक के सम्बन्ध में फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल व्यय का सीमन चाहता था जबकि ब्रिटिश और इटालियन प्रतिनिधिमंडल परस्पर सम्मत रूप में व्यय का विस्तृत प्रकाशन आवश्यक समझते थे। अमरीकी और जर्मनी प्रतिनिधिमंडल प्रायः व्यय के सम्बन्ध में किसी प्रकार के ठहराव करना उचित नहीं समझते थे। आयोग ने इन विभिन्न दृष्टिकोणों को लिपिबद्ध किया और आगे किसी समय विचार के लिए वह स्थगित हो गया।

इसी बीच, अमरीकी सरकार ने एक अप्रत्याशित प्रस्ताव रखा। इन विलंबों से घबरी हो, उसने वाशिंगटन नौसेना-संधि (Naval Treaty) के अन्य हस्ताक्षरकर्त्ताओं को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जिसमें कि उन जहाजों के सम्बन्ध में विचार किया जाना था जो कि उक्त संधि में शामिल नहीं किए जा सके थे। फ्रांस ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। यदि मौका आ ही जाता तो वह इस बात के लिए तैयार था कि नौसेना सम्बन्धी जो बातें वह स्वीकार करे, उनके बदले में उसकी कुछ ऐसी बातें स्वीकार की जाएँ

जिन्हें वह अपने हित में अधिक महत्त्वपूर्ण समझता है। यदि वह केवल नौसैनिक निःशस्त्रीकरण पर ही विचार-विमर्श में शामिल होता, तो यह बात स्पष्ट ही उसके हित में नहीं होती। इटली ने भी फ्रांस का अनुकरण किया। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन और जापान ने सम्मेलन में शामिल होना स्वीकार कर लिया। तदनुसार (accordingly), जून १९२७ में जेनेवा में तीन-राष्ट्र सम्मेलन हुआ।

ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीकी और ब्रिटिश दोनों ही सरकारों ने इस कठिनाई का महत्त्व बहुत कम रखा था कि वाशिंगटन में निर्धारित सीमाओं को उन जहाजों पर जो युद्धपोत नहीं हैं (non-capital ships); युद्धपोत-भिन्न जहाज) लागू करना कठिन है। अमरीकी प्रतिनिविमंडल ने यह प्रस्ताव रखा कि ५ : ५ : ३ का वाशिंगटन अनुपात गश्ती जहाजों (cruisers), विध्वंसकों (destroyers) और उनुब्जियों (submarines) पर भी लागू किया जाये और इसी आधार पर उसने अंकड़े प्रस्तुत किये। ब्रिटिश प्रस्ताव इसमें भी अधिक जटिल था। ब्रिटिश सरकार का यह मत था कि उसका विशाल साम्राज्य भर में फैले भद्रों और मोर्चों (communications) के कारण ब्रिटेन को कम से कम सत्तर गश्ती जहाजों की आवश्यकता है। अभी तक ग्रेट ब्रिटेन जितने गश्ती जहाजों का निर्माण कर चुका था या कर रहा था, उनसे यह सख्या काफी अधिक थी। इसलिए उसने यह प्रस्ताव रखा कि गश्ती जहाजों को दो वर्गों में, कुल दस और तीसों की शक्ति के अनुसार, विभाजित किया जाये—बड़े गश्ती जहाजों पर वाशिंगटन अनुपात लागू किया जाये और छोटे गश्ती जहाजों पर सख्या सम्बन्धी कोई बंधन न हो। उसने यह सुझाव भी रखा कि युद्ध-पोतों (capital ships) का आकार घटाया जाये। संक्षेप में, ब्रिटिश सरकार जहाजों के आकार में चहुँमुखी कमी (all-round reduction) करके स्वर्ध में कमी करना चाहती थी किन्तु छोटे गश्ती जहाजों के सम्बन्ध में कोई बन्धन नहीं चाहती थी या उनकी सीमान-सख्या बहुत अधिक निर्धारित कराना चाहती थी। अमरीकी सरकार किसी भी प्रकार के जहाज का आकार घटाने की कोई उपशोषिता नहीं समझती थी। वह इस बात पर विचार करने के लिए तैयार नहीं थी कि वर्तमान गश्ती जहाजों की सख्या से अधिक सख्या निश्चित की जाये तथा उसे यह सदह था कि ब्रिटिश सरकार वाशिंगटन में स्वीकार किए गये समानता के सिद्धान्त से बचना चाहती है। जापानी प्रतिनिधि-मंडल की स्थिति बीच की थी और उसके रुख से यह प्रतीत होता था कि उक्त

दोनों विरोधी जिस बात पर सहमत हो जाएंगे, उसे वह स्वीकार कर लेगा। किन्तु गश्ती अहाज सम्बन्ध मतभेद पर कोई समझौता नहीं हो सका तथा सम्मेलन की समाप्ति पर यह स्वीकार कर लिया गया कि सम्मेलन असफल रहा है। निःशस्त्रीकरण-प्रयास की यह प्रथम प्रकट पराजय थी।

जेनेवा नौसैनिक सम्मेलन की असफलता की काली छाया १९२७ की राष्ट्र-संघ-सभा पर भी पड़ी और उसने वह मार्ग अपनाते हुए, जो कि जेनेवा में निःशस्त्रीकरण के आधार पर चले नहीं दिखने पर अपनाया जाता था, यह सिफारिश की कि सुरक्षा समस्या का और अधिक अध्ययन किया जाये। लिट्विनोव (Litvinov) के नेतृत्व में एक सोवियत प्रतिनिधि-मंडल के प्रथम आगमन से तैयारी आयोग (Preparatory Commission) के शब्द अधिवेशन में जान आ गई। लिट्विनोव ने प्रभावपूर्ण ढंग से यह प्रपीस की कि निःशस्त्रीकरण पूर्ण (total) और सार्वदेशिक (universal) हो। किन्तु इस प्रस्ताव को कोई समर्थन नहीं मिला। तथा वसंत अधिवेशन में जो गतिरोध (deadlock) दूर नहीं किया जा सका था, उसके कारण लिट्विनोव के प्रस्ताव से कम क्रांतिकारी आधार पर भी प्रगति नहीं की जा सकी। ऐसी परिस्थितियों में, आयोग ने राष्ट्रसंघ सभा से सकेत पाकर पचनिर्णय और सुरक्षा समिति (committee on Arbitration and Security) नियुक्त की जिसके कार्य का विवरण पहिले ही दिया जा चुका है। दो वर्षों तक निःशस्त्रीकरण समस्या एक बार फिर पृष्ठभूमि में चली गई।

सन् १९२९ से पहले आकाश साफ होने के आधार दिखाई नहीं दिये। उस वर्ष हर्बर्ट हूवर अमेरिका का राष्ट्रपति बना तथा उसके तीन महीने बाद मेकडॉनल्ड की द्वितीय मजदूरदलीय सरकार ग्रेट ब्रिटेन में सत्तारूढ़ हुई। इन परिवर्तनों ने सम्भवतः ऐसे समझौते को निकट लाने में सहायता की जिसकी दोनों पक्ष बहुत दिनों से आकांक्षा करते थे। शब्द में मेकडॉनल्ड ने अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा के परिणामस्वरूप, यह निश्चय किया गया कि जनवरी १९३० में लंदन में एक और नौसैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जाए। इस बार, फ्रांस और इटली तथा जापान ने भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया किन्तु फ्रांस ने नौसेना, चल सेना तथा वायु-सेना सम्बन्धी शस्त्रास्त्रों के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध (interdependence) की बात इस बार भी दोहराई।

लंदन नौसैनिक सम्मेलन (London Naval Conference) का मार्ग उसके पूर्वगामी (predecessor) सम्मेलन से बहुत भिन्न था। ग्रेट ब्रिटेन ने गश्ती जहाजों की अपनी आवश्यकता सत्तर से पचास कर दी थी। इस सस्या से समझौता हो सकना संभव हो गया। यद्यपि ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही के लिए यह निःशस्त्रीकरण की अपेक्षा पुनर्शस्त्रीकरण (rearmament) का ही कदम था। इस बार फ्रांस ने वही रुख अपनाया जो पहले ब्रिटेन ने दिखाया था। उसके प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि उसके उपनिवेश-प्रदेशों (colonial possessions) के कारण यह आवश्यक है कि फ्रांस गश्ती-जहाजों का एक बड़ा बेड़ा रखे। उन्होंने इस आंग्ल-अमरीकी प्रस्ताव को कि वाशिंगटन अनुपात गैर-युद्धपोती (non-capital ships) जहाजों पर भी लागू किया जाए; तथा इटली का यह दावा कि इस मामले में उसे फ्रांस के बराबर माना जाए ये दोनों ही बातें अस्वीकार कर दी। इन सम्मेलन की इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाधान ने उस पर वाशिंगटन-सन्धियों द्वारा लादी गई असमान-ताओं के प्रति प्रथम बार खुले आम असंतोष व्यक्त किया और सभी प्रकार के जहाजों के मामले में ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका के साथ समानता (parity) का अस्थायी दावा प्रस्तुत किया। अन्त में काफी कठिनाई के बाद, उसे इस बात के लिए राजी कर लिया गया कि वह वाशिंगटन अनुपात (जिसके अनुसार उसे ब्रिटिश या अमरीकी टनों का ६० प्रतिशत मिला था,) को बड़े गश्ती जहाजों के लिए इस शर्त पर स्वीकार करले कि छोटे गश्ती-जहाजों और विध्वंसकों के लिए उसका यह अनुपात ७० प्रतिशत होगा तथा पनडुब्बियों के मामले में उसे समानता प्राप्त रहेगी। अप्रैल में इसी आधार पर एक सीमन संधि (limitation treaty) की गई। फ्रांस की अपेक्षित्या दुराग्रहपूर्ण सिद्ध हुई। इस कारण वह समझौता केवल ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और जापान तक ही सीमित रहा। इसके साथ ही पाँचों राष्ट्र इस बात पर सहमत हो गए कि वाशिंगटन-सन्धि की अवधि में पाँच वर्षों की और वृद्धि कर दी जाए।

इस आशिक सफलता ने राष्ट्रसंघ को इस दिशा में पुनः प्रयत्न करने की प्रेरणा दी। राइनभूमि खाली करा लेने के बाद, जर्मनी अपना सारा ध्यान निःशस्त्रीकरण पर केन्द्रित कर सकता था, अतः इस क्षेत्र में अधिकाधिक प्रगति के लिए जेनेवा में जर्मनों का जोर बाह्य प्रति बाह्य बढ़ता ही गया। यह निश्चय

किया गया था कि तैयारी आयोग का अन्तिम अधिवेशन १९३० के शरद में हो और उसके बाद, चाहे कोई भी विषय निर्णीत होने से क्यो न रह गया हो, बहुत समय से स्थगित चला आ रहा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया जाये। अन्तिम अधिवेशन में भी सीमन-सिद्धान्तो सम्बन्धी मतभेदों को दूर करने की दिशा में प्रगति नहीं की जा सकी जोकि आयोग की पिछली कार्यवाहियों में भी बराबर रोके अटकते चले आ रहे थे। किन्तु एक अस्थायी प्रारूप समझौता (dummy draft convention) (जिसमें इस समय भी अंकड़े नहीं दिए गए थे) बहुमत द्वारा स्वीकार किया गया। जो उस से असहमत थे, उन्होंने अपनी आप-त्तिर्था और शर्तें पाद टिप्पणियों (foot-notes) में दे दी किन्तु इस प्रकार के दस्तावेज का व्यावहारिक मूल्य बहुत कम था। सब पूछा जाए तो सम्मेलन ने उसका उपयोग भी नहीं किया। किन्तु उस से निःशस्त्रीकरण संबंधी वे मूलभूत मतभेद सामने आ गए जिनका सामना सम्मेलन को करना पड़ सकता था। तैयारी आयोग के पाँच वर्षों के श्रम का केवल यही परिणाम सामने आया था। अब मार्ग प्रशस्त हो चुका था। सम्मेलन २ फरवरी १९३२ को आयोजित किया गया।

नि शस्त्रीकरण सम्मेलन (The Disarmament Conference)

सम्मेलन में एकसठ राज्यों, जिनमें से पाच राज्य राष्ट्रसंघ के सदस्य भी नहीं थे, के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे और उसका अध्यक्ष आर्थर हेन्डरसन बनाया गया था। सन् १९३१ में अपनी नियुक्ति के समय, हेन्डरसन ब्रिटिश मज-दूरदलीय सरकार में विदेशी मन्त्री थे। किन्तु अगस्त में इस सरकार ने स्तीफा दे दिया तथा आगामी आम चुनावों में हेन्डरसन संसद (Parliament) का सदस्य नहीं चुने जा सके। इसलिए एक गैर-सरकारी व्यक्ति की हैसियत से ही उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यह एक अप्रत्याशित दुर्योग था। यदि इस सम्मेलन का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का उच्च पदाधिकारी रहा होता, तो वह सम्मेलन को मामलों पर विचार करने और निर्णय लेने में सहायता करने में अधिक समर्थ हो सकता था। सम्मेलन का अन्तिम परिणाम तो संभवतः वही होता जो कि होना था किन्तु फिर भी सम्मेलन को गिराने वाले टाल-मटोल और हिचकचाहट से तो बचा ही जा सकता था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों ही

सरकारों ने जेनेवा में मन्त्रिमण्डलीय प्रतिनिधि—जो सदैव नीति-संचालन करते रहें—नियुक्त न कर स्थिति को और भी खराब बना दिया। जर्मनी की प्रातरिक स्थिति ने और भी बुरा प्रभाव डाला। मई १९३२ में, ब्रुनिंग (Bruning) की कमजोर और समझौते के मार्ग पर चलने वाली सरकार अपदस्थ हो गई और पपेन सायन पापेन (Papen)—जो कि राष्ट्रीय समाजवादियों से मोर्चा लेने की महत्ता के प्रति अत्यन्त सजग था—को चलाक और क्रूर सरकार में लिया। इन छोटी छोटी बाधाओं तथा अर्थ-संकट द्वारा किए गए सर्वनाश एवं जापान द्वारा मधूरिया पर हमले ने सम्मेलन के भाग्य का पेंसला हो कर डाला।

जहाँ तक निःशस्त्रीकरण का प्रश्न है, तैयारी आयोग ने इस दिशा में मार्ग प्रशस्त करने की अपेक्षा मार्ग के गड़बड़ों की सूचना ही अधिक दी थी। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि निःशस्त्रीकरण सम्मेलन ने आयोग से लगभग बिल्कुल ही भिन्न मार्ग अपनाया यद्यपि आयोग के पारश्रम का सम्मान करने के लिए उसने यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप समझौते को यह “आधार” मानकर चलेगा। सम्मेलन के सदस्यों में एक स्मरण-पत्र वितरित कर फ्रांसीसी प्रतिनिधिमण्डल ने इस दिशा में पहिला कदम उठाया। इस स्मरणपत्र के द्वारा उसने यह प्रस्ताव रखा था कि राष्ट्रसंघ की अपनी पुलिस हो। जिन राष्ट्रों के पास युद्धपोत, बड़ी पनडुब्बियाँ या भारी तोपखाना हो उनका यह कर्त्तव्य हो कि आवश्यकता पड़ने पर वे राष्ट्रसंघ पुलिस को उनका उपयोग करने दें। इसके साथ ही बमवर्षक वायुयानों का प्रयोग करने का एकाधिकार राष्ट्रसंघ पुलिस को ही दिया जाना था। अनेकों छोटे-छोटे यारोपीय राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था; किन्तु यह प्रस्ताव ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका—जो अधिराष्ट्रीय सेना (supernational military force) के सुझाव का सदा ही विरोध करते थे—तथा जर्मनी, जो इस प्रस्ताव को निःशस्त्रीकरण के वास्तविक प्रश्न को टालने की एक और कुचेष्टा मानता था, को फूटी आँखों नहीं सुहाया। फ्रांस ने भी राष्ट्रसंघ पुलिस संगठित करने पर और अधिक जोर नहीं दिया। किन्तु सम्मेलन निःशस्त्रीकरण सबघी किसी ठोस कदम पर जब भी विचार करता, तब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता था कि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलन को इस बात का पुनः स्मरण अवश्य कराएगा कि विचारवादी प्रस्ताव पर फ्रांस का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए फ्रांस की सुरक्षा में कुछ न कुछ वृद्धि होना आवश्यक है।

ब्रिटिश विदेशमन्त्री के उद्घाटन भाषण में निहित एक प्रस्ताव का सम्मेलन के काय पर सीधा प्रभाव पड़ा। सर जान साइमन ने यह सुझाव रखा कि सम्मेलन “परिणामात्मक सीमन” (“*qualitative limitation*”) पर विचार करे अर्थात् शस्त्रास्त्रों का सीमन संख्या द्वारा न किया जाये, (इसी प्रकार के सीमन पर तैयारी आयोग ने मुख्य रूप से विचार किया था) बल्कि कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार के शस्त्रास्त्रों को बिलकुल ही समाप्त कर दिया जाये जो प्रतिरक्षात्मक युद्ध (defensive warfare) की अपेक्षा आक्रमणात्मक युद्ध के काम अधिक आ सकते हों। इस सुस्पष्ट प्रस्ताव को बहुत अधिक समर्थन मिला। भारी तोपों, टैंकों, पनडुब्बियों, वमवर्ष के वायुयानों और गैस को अनेक प्रतिनिधिमंडलों ने विशेष रूप से आक्रमणात्मक शस्त्रों की कोटि में रखा। किन्तु जब यह प्रश्न नौसैनिक, धल-सैनिक और वैमानिक विशेषज्ञों के तीन प्रयोगों के सामने रखा गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि आक्रमणात्मक और प्रतिरक्षात्मक शस्त्रों में सब की एक राय हो सकना कठिन है। एक ओर यदि ब्रिटिश और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पनडुब्बियों को आक्रमणात्मक और युद्धपोतों को प्रतिरक्षात्मक मानने दें, तो दूसरी ओर, अन्य प्रतिनिधिमंडल इससे ठीक उलटा सोचते थे। कई प्रतिनिधिमंडल सभी प्रकार के टैंकों को आक्रमणात्मक मानते थे। किन्तु फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल केवल ७० टन से अधिक के टैंक को (जो कि अभी अस्तित्व में भी नहीं आया था) — को आक्रमणात्मक मानता था जबकि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने पच्चीस टन की सीमा सुझाई थी। केवल जर्मन प्रतिनिधिमंडल के पास ही एक सुसंगत कसौटी थी। उसके अनुसार वर्सेलीज की संधि में निषिद्ध सभी शस्त्रास्त्र आक्रमणात्मक कोटि में आते थे और बाकी सब प्रतिरक्षात्मक श्रेणी में। किन्तु इस कसौटी के होते हुए भी, वे एक स्पष्ट असंगत बात कर गये। उनकी यह मान्यता थी कि सभी सैनिक वायुयान आक्रमणात्मक हैं किन्तु असैनिक वायुयानों, जो कि वर्सेलीज की संधि में सम्मिलित किए जाने से छूट गए थे, पर नियन्त्रण के किसी भी सुझाव का वे जोरदार विरोध करते थे। केवल रासायनिक युद्ध आयोग (Commission on Chemical Warfare) ने ही यह निर्विरोध सिफारिश की थी कि युद्ध में हानिकर गैसें (noxious gases) का प्रयोग निषिद्ध कर दिया जाये (इतनी सफलता तो १९२५ में हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को पहिले ही मिल चुकी

थी) किन्तु इस प्रकार की गैसों को बनाने या उन्हें अपने पास रखने पर नियंत्रण के लिए कोई योजना नहीं बनाई जा सकी ।

विभिन्न प्रायोग इन स्वल्प परिणामों (meagre results) की सूचना खून से पहले नहीं दे सके । जुसाने सम्मेलन की ओर ध्यान आकृष्ट हो जाने से इसमें और भी बिलम्ब हो गया । अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा जिसका आधारभूत सिद्धान्त यह था कि वर्तमान सशस्त्र सेना और शास्त्रास्त्रों में एक तिहाई कमी की जाये । ब्रिटिश ने इस प्रस्ताव का नम्रनापूर्ण किन्तु अनमने भाव से स्वागत किया क्योंकि उस यह सदेह था कि यह प्रस्ताव ब्रिटिश ब्रिटेन के गश्ती जहाजों में कमी करने की कटपूरी योजना है । जुलाई के मध्य में, जब विभिन्न प्रतिनिधिमंडल इस प्राशय के एक प्रस्ताव पर कि औद्योगिकता से पहिले कितनी प्रगति की जा चुकी है, विचार करने के लिए एकत्रित हुए, तो उन्हें यह जानकारी बड़ी उलझन हुई कि इस दिशा में ऐसी कोई सफलता ही प्राप्त नहीं हुई थी जिसका उल्लेख किया जा सके । जुलाई २० को सम्मेलन के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया था कि निम्नलिखित बातों पर समझौता हो गया है :— (१) बमबर्षा (air bombardment) निषिद्ध करना, वायुयानों की सङ्ख्या सीमित करना तथा अर्धनिक वायुयानों का विनियमन (regulation), (२) भारी तोपखाना और एक अधिकतम प्रकार—जो कि अभी निश्चित नहीं किया गया था—के टैंकों (tanks) को सीमित करना; और (३) रासायनिक युद्ध निषिद्ध करना । इकतालीस प्रतिनिधिमंडलों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया । आठ (इटली सहित) ने मत ही नहीं दिया और दो (जर्मनी तथा सोवियत संघ) ने उसका विरोध किया । जर्मन प्रतिनिधि ने जो मद्दा ही इस सिद्धान्त पर जोर देता रहा कि अन्य राष्ट्रों को भी वर्सलोज की संधि के अनुसार अपना निःशस्त्रीकरण कर लेना चाहिए या पुनर्शस्त्रीकरण (rearming) का जर्मनी का अधिकार मान लेना चाहिए, यह घोषणा की कि सम्मेलन के भावी कार्य में जर्मनी केवल तब ही भाग लेगा, जबकि “राष्ट्रों के समान अधिकार (का सिद्धान्त) स्पष्ट और निश्चित रूप से मान लिया जायेगा ।”

अवकाशकाल में वार्ताओं का कोई परिणाम नहीं निकला । अक्टूबर में जब सम्मेलन का पुनः अधिवेशन हुआ, तब जर्मनी का स्थान रिक्त हो चुका था ।

दो माह तक, सम्मेलन का काम लगभग बिलकुल ही बन्द पड़ा रहा। इस समय की महत्त्वपूर्ण घटना केवल यही थी कि फ्रांस ने एक नई सुरक्षा योजना प्रस्तुत की और यह प्रस्ताव रखा कि शस्त्रास्त्रों के निर्माण पर सभी देशों में राज्य का एकाधिकार (state-monopoly) रहे। किन्तु इस समय जर्मनी का प्रश्न सबसे महत्त्वपूर्ण था। अखिर ११ दिसम्बर को, एक रास्ता निकाला गया। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने जर्मनी का यह दावा स्वीकार कर लिया कि उसे ऐसे किसी भी समझौते में शामिल होने के समान अधिकार प्राप्त हैं जिसके अनुसार सभी देशों को सुरक्षा प्राप्त हो सके।" इन शर्तों पर जर्मनी ने सम्मेलन में पुनः शामिल होना स्वीकार कर लिया। समानता का सिद्धान्त मान्य किया जा चुका था; यद्यपि "सुरक्षा-समझौता" ("system of security") की आवश्यकता के कारण फ्रांस अब भी बाजी जीत लेना चाहता था। निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का प्रथम वर्ष इस समयित आशा के साथ समाप्त हो गया।

सम्मेलन जनवरी १९३३ के अन्त में पुनः प्रारम्भ हुआ। दिसम्बर समझौते का व्यावहारिक परिणाम केवल यही हुआ था कि फ्रांस की सुरक्षा-माँग और जर्मनी की निःशस्त्रीकरण-माँग की खुले-आम टक्कर हो गई। मार्च के मध्य में, जबकि पूर्ण गतिरोध हो चुका था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेनेवा आया और उसने "मेकडॉनल्ड योजना" प्रस्तुत की। इस योजना से पहली बार सम्मेलन को समझौते का सम्पूर्ण प्रारूप प्राप्त हुआ जिसमें कि योरोप के लगभग हर देश में सीमित किए जाने वाले सैनिकों और सामग्री की सख्या दी गई थी। योजना का हार्दिक स्वागत हुआ। किन्तु निःशस्त्रीकरण-समझौते की आशा अब लगभग विलकुल ही समाप्त हो चुकी थी। अगले चार सप्ताहों में इस योजना पर जो वाद-विवाद हुए, उनसे एक बार पुनः यह स्पष्ट होगया कि मूलभूत मुद्दों पर ही बहुत अधिक मतभेद है। जून में सम्मेलन इस आशा, जो अब परम्परा बन चुकी थी—के साथ स्थगित हो गया कि अवकाश काल में निजी वार्ताओं द्वारा शेष मतभेद दूर हो जाएँगे।

जनवरी के अन्त में, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री (Chancellor) चला आ रहा था और नात्सी शासन ने अपने पैर दृढतापूर्वक जमा लिए थे। इस कारण यह स्वाभाविक ही था कि फ्रांसीसी सरकार ने जर्मनी के दावों को स्वीकार करने में अधिक अनिच्छा प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु यह और भी अधिक

भावश्यक हो गया था कि बिना किसी विलंब के जर्मनी के साथ समझौता कर लिया जाये। दुर्भाग्यवश १९३३ के ग्रीष्मावकाश में जो एक योजना तैयार हो सकी वह फ्रांसीसी ही थी जिसमें कि निःशस्त्रीकरण सम्मेलन को दो कालों में विभाजित करने का मुझाव दिया गया था। चार वर्षों के प्रयत्न या परीक्षा-काल में, शस्त्रास्त्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी (international supervision) की प्रणाली स्थापित की जानी थी तथा राष्ट्रीय सेनाओं का पुनर्गठन प्रारम्भ किया जाना था। सोमन का प्रश्न द्वितीय-काल में ही हल में लिया जाना था। ब्रिटिश और इटालियन सरकारें इस प्रस्ताव से सहमत थीं। अक्टूबर १४ को सर जॉन साइमन ने सम्मेलन के कार्यालय (Bureau) में उसका विधिवत् समर्पण किया। इसके कुछ ही घंटों के भीतर, जर्मनी ने यह घोषणा की कि उसने निःशस्त्रीकरण सम्मेलन तथा राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी है।

जर्मनी के प्रसंग हो जाने से इस कार्य को बड़ा मायासत पहुँचा, क्योंकि जर्मनी ही निःशस्त्रीकरण का अधिकधिक आकर्षण-केन्द्र होता जा रहा था। छ माह तक सम्मेलन कुछ भी प्रगति नहीं कर सका और इस अवधि में जर्मनी सहित प्रमुख राष्ट्र सूदनीनिक पत्र-व्यवहार द्वारा विचारों का आदान प्रदान ही करते रहे। फरवरी १९३४ में ईडन (Eden) पेरिस, बर्लिन और रोम गये। ईडन के बर्लिन वास (stay in Berlin) के समय, हिटलर ने यह प्रस्ताव रखा कि जर्मनी अपनी सेना के लिए ऐसी कोई भी सीमा स्वीकार करने के लिए तैयार है जो फ्रांसीसी, इटालियन और पोलिश सेनाओं के लिए समान रूप से स्वीकार की जाए। उसने यह प्रस्ताव भी रखा कि जर्मनी वायुसेना का ऐसा कोई भी प्रतिनिध निरिधन करने के लिए प्रस्तुत है जो कि उसके पड़ोसी राष्ट्रों की वायु-सेना की समुक्त सख्या का ३० प्रतिशत या फ्रांस की वायु-सेना की संख्या का २० प्रतिशत (जो भी कम हो) हो। फ्रान्सीसी सरकार ने इसका उत्तर “जर्मनी के (प्रस्तावित) पुनःशस्त्रीकरण के वैधकरण (legalisation)” के प्रति विरोध प्रकट कर दिया तथा यह मन प्रकट किया कि कोई भी निःशस्त्रीकरण सम्मेलन करने से पहिले यह प्रश्न निरिधन कर लिया जाए कि यदि सम्मेलन का पालन नहीं किया गया तो शास्त्रियाँ (penalties) लगाई जाएंगी और ऐसी स्थिति के लिए कुछ गारन्टियाँ दी जाएँगी। इस पर ब्रिटिश सरकार ने फ्रान्सीसी सरकार से यह पूछा कि यदि सन्तोषजनक गारन्टियाँ दी जाएँ, तो क्या वह हिटलर का प्रस्ताव स्वीकार

करने के लिए तैयार है। अन्त में, १७ अप्रैल को, फ्रांसीसी सरकार ने यह उत्तर दिया कि अभी हाल ही में जर्मनी का जो सैनिक आय-व्ययक (budget) प्रकाशित हुआ है उससे यह स्पष्ट है जर्मनी पुनर्शस्त्रीकरण करना चाहता है इसलिए फ्रांस जर्मनी के प्रस्तावों पर वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है।

यह उत्तर ही सम्मेलन का वास्तविक अन्त था। यद्यपि वह कुछ महीनों और चलता रहा तथा इस बीच उसकी समितियाँ गौण विषयों, जैसे शस्त्रास्त्रों का निर्माण और व्यापार तथा सैनिक आय-व्ययको का प्रकाशन पर विचार करती रही। किन्तु उसके अधिवेशन अब बीच-बीच में होने लगे तथा उसका सारा अस्तित्व ही प्रवास्तविक और असतत (unreal and fitful) हो गया। सन् १९३४ की समाप्ति के बाद, उसके अधिवेशन होना भी बन्द हो गये यद्यपि वह नियमानुसार न तो समाप्त किया गया और न विश्व आर्थिक सम्मेलन के समान स्थगित ही हुआ। उसके अध्यक्ष की भी १९३५ के शरद में मृत्यु हो गई।

निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का अविराम मृत (lingering death) उस युद्धोत्तर-काल के इतिहास की अन्तिम कहानी था जो कि १९३० में आर्थिक संकट की शुरुआत से प्रारम्भ हुआ था। इस काल के कुछ माह उस नए काल में भी शामिल थे जो कि जर्मनी में हिटलर द्वारा सत्ता ग्रहण कर लेने से प्रारम्भ हुआ था। वास्तव में इन दोनों ही घटनाओं का अत्यन्त निकट संबंध था और दोनों ही एक काल से दूसरे काल में संक्रमण (transition) की सूचक थी। मित्र-राष्ट्रों द्वारा निःशस्त्रीकरण सबधी अपना वचन पूरा नहीं किए जाने के कारण जर्मनी के पुनर्शस्त्रीकरण को उचित ठहराया जा सकता था या कम से कम उसे पुनर्शस्त्रीकरण के एक कारण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। इस पुनर्शस्त्रीकरण का आवश्यक परिणाम अन्य देशों में अधिक भय का फैलना और अधिक शस्त्रीकरण हुआ। जिस कुचक्र (vicious circle) को १९१९ के राजनीतिज्ञों ने तोड़ना चाहा था, वह एक बार फिर पूरे वेग से चलने लगा। जिसे शक्ति कूटनीति (power politics) ने सुदूर पूर्व में १९३१ में पहिली बार अपना रंग दिखाया था, उसी का आन्ध्र १९३३ में सारे विश्व में लिपटा जाने लगा।

चार-राष्ट्र समझौता (Four-Power Pact)

एक ऐसी घटना के बारे में यहाँ एक अनुलेख (postscript) जोड़ा जा

सकता है जिसका यद्यपि नि.शस्त्रीकरण सम्मेलन से प्रासंगिक संबंध ही है, तदपि वह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि वह दोनों कालों की सीमा-रेखा (border-line) पर घटित हुई थी, तथा उससे इटली की उस समय की नीति स्पष्ट हो जाती है जिस समय जर्मनी एक सैनिक राष्ट्र के रूप में पुनः प्रागे आता जा रहा था। मार्च १९३३ में, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री "मेक्डानल्ड योजना" लेकर जेनेवा आये थे, तब वे साइमन को साथ ले मुसोलिनी से नि.शस्त्रीकरण-समस्या पर चर्चा करने के लिए रोम भी गये। मुसोलिनी का नि शस्त्रीकरण में कभी भी विश्वास नहीं रहा था और वह नि.शस्त्रीकरण के प्रतिरिक्त मन्त्र बातों की चर्चा करना ही अधिक पसंद करता था। जैसे ही ये प्रतियोगिता इटली पहुँचे, वैसे ही एक प्रस्तावित चार-राष्ट्र सम्मेलन, जो कि इटली, ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में किया जाना था, का प्राक्षुप उनक सामने रख दिया गया।

पिछले दशक (decade) में इटली की नीति का प्रमुख ध्येय यह था कि फ्रांस, जो दूसरा लैटिनी बड़ा राष्ट्र (Latin Great Power) था, के साथ इटली की समानता का दावा किया जाये। विशेषतः इटली को फ्रांस की उपनिवेशीय श्रेष्ठता (colonial superiority) तथा पोलैंड और लघु मंत्री-संघ के साथ गुटबन्दी के कारण योरोप में फ्रांस की शक्ति से चिढ़ थी। इटली की उपनिवेशीय महत्वाकांक्षाएँ पूरी होने के लिए तो अभी और अधिक उपयुक्त अवसर की आवश्यकता थी। किन्तु इसी बीच मध्य योरोप में फ्रांस के प्रभाव का मुकाबिला करने के लिए उसने लघु-मंत्रीसंघ के विरुद्ध हंगरी, और बालकन देशों में युगोस्लाविया के विरुद्ध बल्गेरिया का पक्ष लिया। इस प्रकार उसके दो ऐसे राज्यों का पक्ष लेने, जिनकी विदेश नीति का एकमात्र लक्ष्य ही यह था कि शांति संधियों में संशोधन कराया जाए, के कारण इटली 'संशोधनवाद' (revisionism) का प्रमुख समर्थक हो गया। इस कारण उसे संशोधनवादी राष्ट्रों में सबसे बड़े राष्ट्र—जर्मनी के साथ काम करने का एक सामान्य आधार मिल गया और १९२६ के बाद से ही इटली तथा जर्मनी के सम्बन्ध उत्तरोत्तर घनिष्ठ होते गए। इसलिए १९३३ के वसंत में इटली का उद्देश्य यह था कि जर्मनी को यथासंभव शीघ्र अन्य बड़े राष्ट्रों की श्रेणी में पुनः ला बैठाया जाए; फ्रांस के पिछलग्गुओं (satellites)—पोलैंड और लघु मंत्रीसंघ—को कमजोर बनाया जाये तथा शांति-संधियों में संशोधन की माँग को बढ़ावा दिया जाये।

ब्रिटिश मन्त्रियों को दिए गए प्रारूप समझौते में ये ध्येय स्पष्ट परिलक्षित थे। इस प्रारूप की शर्तों के अनुसार, चारो राष्ट्रों को यह घोषणा करनी थी कि वे अपनी योरोपीय नीति का मेल इस प्रकार बैठाएंगे कि “भावश्यकता होने पर अन्य राष्ट्र भी” उसे अपना सकें। इस प्रकार स्पष्ट है कि योरोप के अन्य राष्ट्रों का नेतृत्व (hegemony) भी उन्होंने अनधिकारपूर्वक अपने हाथों में ले लिया और फ्रांस के साधियों का स्थान गौण कर दिया गया। दूसरे, इन चारो राष्ट्रों ने यह भी घोषित किया कि शांति संधियों में सन्तुलन पर विचार भी उनकी सामान्य नीति का एक अंग रहेगा। लघु-मंत्रिसभ और पोलैंड के लिए यह दूसरा आघात था। तीसरे, चारो राष्ट्र इस बात पर सहमत हो गए कि यदि निःशस्त्रीकरण सम्मेलन से समस्या का समाधान नहीं निकल सका, तो वे धीरे धीरे पुनर्शस्त्रीकरण करने का जर्मनी का अधिकार स्वीकार कर लेंगे। अन्त, उन्होंने यह वचन दिया कि “योरोप से असंबन्धित (सभी) प्रश्नों (extra-European questions) तथा “उपनिवेशीय क्षेत्र” के सम्बन्ध में वे अपनी नीति समरूप रखेंगे। चूँकि चार में से दो राष्ट्रों की उपनिवेशीय महत्वाकांक्षाएँ थी, इसीलिए इस प्रारूप से यह आभास होता था कि वे उन उपायों का अध्ययन करना चाहते जिनका आश्रय लेने पर उनकी ये महत्वाकांक्षाएँ पूरी हो सकती थी।

उपनिवेश सम्बन्धी धारा को छोड़, इस प्रारूप में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसका ब्रिटिश हित पर सीधा प्रभाव पड़ता हो। किन्तु ब्रिटिश मन्त्रियों ने यह जान लिया कि इस प्रारूप का अधिकांश भाग फ्रांसीसी सरकार को बहुत बुरा प्रतीत होगा जिसे (और जर्मन सरकार को भी) कि यह प्रारूप साथ ही साथ भेजा गया था। इसलिए उसने किसी भी प्रकार का वचन न देने की बुद्धिमानी की। फ्रांस में, वास्तव में उसका काफी विरोध हुआ जो कि लघु-मंत्रिसभ तथा पोलैंड के भी क्रोधपूर्ण विरोध के कारण और भी तीव्र हो गया। जो भी हो, फ्रांसीसी सरकार ने समझौते को बिलकुल ही अस्वीकार कर देने की अपेक्षा उस की हानिकार बातों को दूर करने का प्रयत्न करने का निश्चय किया। दो माह से भी अधिक तक कूटनीतिक चर्चाएँ चलाने के बाद कही उसे अपने इस ध्येय में सफलता मिली। संशोधित समझौते के अनुसार, चारो राष्ट्रों ने यह वचन दिया कि वे “राष्ट्रसभ के ढाँचे के भीतर” सभी राष्ट्रों से सहयोग करेंगे। अनुवचन

के दसवें घोर सोलहवें अनुच्छेद की उन्होंने पुन पुष्टि की (reaffirmed) जिनमें कि वर्तमान व्यवस्था (existing order) को बनाए रखने की व्यवस्था थी। अनुच्छेद उन्नीस की भी उन्होंने पुनः पुष्टि की जिसमें कि सतुलित शब्दों में सशोधन की बात कहो गई थी। यदि निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन कोई ऐसे प्रश्न प्रनिर्णीत छोड़ दे, जिनका सम्बन्ध इन राष्ट्रों से विशेषतया हो, तो ये राष्ट्र जन पर भावस में विचार करेंगे—ऐसी व्यवस्था भी की गई थी। उपनिवेश-प्रश्नों सम्बन्धी युद्ध बिल्कुल ही हटा दिया गया। सशोचित समझोते से किसी को भी आघात नहीं पहुँच सकता था। यह इतना हानिरहित था कि ऐन मौके पर, जर्मनी ने उसे स्वीकार करने से लगभग इन्कार ही कर दिया। किन्तु अन्त में, ७ जून १९३३ को रोम में चारों राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हो ही गये।

लघु मंत्रीसमूह ने समझोते के अन्तिम अंग के हानिरहित होने पर सतोष व्यक्त किया था। किन्तु लघु-मंत्री-समूह क्षेत्रों में यह असुचिकर भावना बनी रही कि इटली ने उनके अत्यन्त महत्वपूर्ण हितों पर कुठाराघात किया है तथा फ्रांस ने उनकी रक्षा में अनुचित ढीलडाल दिखाई है। पोलैंड के आत्मभिमान को बहुत अधिक चक्का लगा। छोटे राष्ट्रों में सबसे बड़े राष्ट्र पोलैंड ने इटली—जो बड़े राष्ट्रों में सबसे छोटा था—का इस सफलता का तीव्र विरोध किया क्योंकि योरोपीय नीति (निर्धारक) नेताओं की सगति से इटली ने उसे बर्चित कर दिया था। उसने अपना क्रोध फ्रांस पर निकास किया जिसने पोलैंड की महत्ता को मुसोलिनी के घमंड के सामने बलि चढ़ा दिया था। चार राष्ट्र समझौता कभी भी अमल में नहीं आया (फ्रांस और जर्मनी दोनों ही उसका अनुसमर्थन नहीं कर सके)। इसलिए फ्रांस और उसके साथियों में फूट के बीज बोकर अब उनके सम्बन्धों में शिथिलता लाकर उसका एक उद्देश्य तो पूरा हो ही गया। ऐसा कर, उसने राष्ट्रों की उस नई श्रुतबन्दी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो कि जर्मन नीति के नये संचालन (new direction) का आवश्यक परिणाम थी।

चतुर्थ भाग

जर्मनी का पुनरुद्भव

(Re-emergence of Germany)

संधियों का अंत

(The End of The Treaties)

(१९३३—१९३६)

१०. नात्सी क्रान्ति (Nazi Revolution)

जनवरी ३०, १९३३ को हिटलर जर्मनी का प्रधानमन्त्री (Chancellor) बना। उसकी सरकार में तीन नात्सी और साठ राष्ट्रवादी (Nationalists) थे। इस समय जर्मन संसद को भी नए घाम चुनाव के लिए विघटित (dissolved) कर दिया गया। पिछली चुनावों में जो घाम चुनाव हुए थे, उनमें नात्सी पार्टी को २१० स्थान मिले थे तथा जर्मन संसद में वह सबसे बड़ी पार्टी (largest single party) बन गई। अब यह संसद में पूर्ण बहुमत (absolute majority) प्राप्त करने की आशा करती थी। फरवरी २७ को, जब चुनाव भी नहीं हो पाए थे, जर्मन संसद (Reichstag) भयन रहस्यपूर्ण परिस्थितियों (mysterious circumstances) में बल गया। इस घटना का बहाना लेकर कथित (alleged) कम्युनिस्टों और उनसे सहानुभूति रखने वालों (sympathisers) की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ (round up) की गईं। यह कार्य कुछ मशहूरों में पुलिस द्वारा किन्तु मुख्य रूप से ब्राउन (brown) वर्दी पहनने वाले सैनिकों द्वारा किया गया था। चुनाव के परिणामस्वरूप नात्सी प्रतिनिधियों की संख्या ६२ और बढ़ गई। इस घटना के बाद से ही वैधानिक और संवैधानिक उपायों (legality and constitutional forms) को ताक में उठाकर रख दिया गया। इस समय यहूदियों, सोशल-डेमोक्रेटों तथा कम्युनिस्टों को तो, वास्तव में गैरकानूनी (outlawed) ही कर दिया गया। उनमें से अनेकों को अपने घरों से निकालकर मजबूत दीवारों वाले शिविरों (concentration camps) में रखा गया था जहाँ बहुत अधिक शारीरिक यातनाएँ दी गईं। कई हत्याएँ भी इस समय हुईं किन्तु हत्याओं को दब दिलाने का प्रयत्न नहीं किया गया। अन्य पार्टियों के जो सदस्य नई तानाशाही (dictatorship) का विरोध करते थे या उसकी आलोचना करते थे, उनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया गया। सन् १९३३ के मध्य तक, नात्सी पार्टी को छोड़ सभी अन्य पार्टियों (non-Nazi

parties) और पार्टि सगठनों को जबर्दस्ती विघटित कर दिया गया। अब जर्मन संसद का केवल यही कार्य रह गया था कि मूले-भटके जब भी उसका अधिवेशन हो, तब वह प्रधानमन्त्री की नीति घोषणाओं (declarations of policy) को सह्य मान ले। अगस्त १९२४ में हिन्देनबर्ग (Hindenburg) की मृत्यु होने पर, हिटलर (Herr Hitler) को बहुत अधिक बहुमत में राष्ट्रपति चुना गया। वह इसके साथ ही साथ प्रधानमन्त्री भी बना रहा।

विदेश नीति के क्षेत्र में, नए शासन की घोषणाएँ शांतिपूर्ण तथा भय दूर करने वाली थी। हिटलर ने जोर देकर यह अस्वीकार किया कि शांति-समझौते को बल प्रयोग कर (by force) सशोधित करने की उसकी कोई इच्छा है। किन्तु यह बात नहीं भुलाई जा सकी थी कि हिटलर द्वारा १९२४ में लिखित अपने आत्म चरित्र 'मैन कम्फ' ("Mein Kampf") Tr.)—जिसकी अब लाखों प्रतियाँ बिकती थी—में फ्रांस को जर्मनी का कट्टर दुश्मन बताया गया था तथा जर्मनी की वर्तमान सीमाओं से बाहर यहाँ-वहाँ रहने वाले सभी जर्मन अल्पसंख्यकों को जर्मनी में शामिल कर लेने का दावा किया गया था एवं पूर्वी योरोप को जर्मन उपनिवेशीकरण (colonisation) के लिए उपयुक्त स्थान माना गया था। इसके प्रतिरिक्त, गुप्त रूप से जर्मनी के पुनर्शास्त्रीकरण का जो कार्य कुछ वर्षों से चल रहा था, वह अब तेजी से चलने लगा किन्तु उसे गुप्त रखने की अब इतनी परवाह नहीं की जाती थी। सवि निषेध (treaty prohibition) का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए, वायु सेना की स्थापना की गई थी। केवल एक ही मामले में हिटलर ने हमेशा ही आत्म-नियंत्रण बरता। जर्मन नीति की जिस मूलभूत गलती के कारण ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी का शत्रु बन गया था, उसे ध्यान में रखते हुए, हिटलर ने ब्रिटेन की मौलिक शक्ति के साथ प्रतिद्वन्द्विता करने के प्रयत्न की किसी भी पुनरावृत्ति (repetition) का दृढ़ विरोध किया।

नात्सी क्रांति का सारे समय संसार में गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव दो प्रकार का था। कुछ देशों में, हिटलरी तानाशाही की क्रूरताओं (cruelties) और ज्यादतियों के प्रति नैतिक क्रोध (moral indignation) की भावना सर्वप्रधान थी। अन्य देशों में, इस बात की इतनी ही गहरी चिन्ता थी कि १९१८ के शांति-समझौते को खुली चुनौती दी गई है। दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया पहिले प्रकार की प्रतिक्रिया से अधिक प्रभावपूर्ण प्रतीत होती थी। ग्रेट

ब्रिटेन और अमेरिका में, जहाँ कि क्रोध—न डर— की ही भावना प्रधान थी, जर्मनी के प्रति नीति में कोई स्पष्ट परिवर्तन (marked change) नहीं हुआ। इटली और सोवियत संघ में, जहाँ की सरकारें स्वयं ही हिंसा द्वारा सत्तास्थ हुई थीं, नैतिक भर्त्सना (moral censure) के लिए गुनाह कम ही थे। हिटलर के सत्तास्थ होने के अन्तर्राष्ट्रीय परिणामों की तीव्र भावना से इन देशों ने एक-एक अपनी नीति बदल दी। अन्य महत्वपूर्ण योरोपीय राष्ट्रों के राजनैतिक दृष्टिकोण में नात्सी क्रांति के कारण जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनका विवेचन इस अध्यास में किया जाएगा।

पोलैंड और सोवियत संघ

(Poland And the Soviet Union)

इन (नात्सी क्रांति द्वारा लाये गए) परिवर्तनों में प्रथम एक भावपूर्ण जनक विरोध शांति (reconciliation) थी। सन् १९१९ के बाद के योरोप में, जर्मनी और पोलैंड में जिनकी कट्टर शत्रुता थी, उनकी योरोप के और किसी भी देश में नहीं थी, दोष जर्मनी से पूर्वी प्रशा (Prussia) को दृष्टक करने वाले समुद्रगामी पोलिश गलियारे के कारण जर्मन लोगो की वसंलीज की सन्धि के विरुद्ध शिकायत करने का, सर्वाधिक नाटकीय अवसर मिल गया था। अपने प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण पोलैंड के जर्मन अल्पसंख्यकों द्वारा राष्ट्रसंघ को जितनी शिकायतें हमेशा ही की जाती थी उतनी अन्य कोई भी अल्पसंख्यक नहीं करते थे। पोलैंड और डानजिग के बीच विवाद जितनी बार परिषद् की कार्यसूची (agenda) में रहते थे, उतना और कोई प्रश्न नहीं रहता था। नात्सी क्रांति के दूसरे ही दिन, इन झगडों में से एक सर्वाधिक गंभीर झगडा हुआ। उस दिन २०० पोलिश सैनिकों को बिना किसी अधिकार के डानजिग बन्दरगाह के एक स्थान पर उतारा गया। किन्तु फिर भी, इस घटना के कुछ ही महीनों के भीतर पुनर्मेल (*rapprochement*) की दिशा में पहला कदम चलाया गया। हिटलर के प्रधानमन्त्रित्व की प्रथम वर्षगांठ से कुछ ही समय पहिले जनवरी १९३४ में एक जर्मन पोलिश समझौते पर हस्ताक्षर हो गए जिसके कारण पोलैंड की विदेश नीति और पूर्वी योरोप के कूटनीतिक नक्शे (diplomatic configuration) में धातुल परिवर्तन होगया। इस समझौते के दो परिणाम हुए, उनमें सर्वाधिक स्पष्ट परिणाम ये :—जर्मन और

पोलिश समाचारपत्रों द्वारा पिछले पंद्रह वर्षों से एक दूसरे पर जो विषवमन किया जा रहा था, उसका बन्द हो जाना तथा पोलैंड के जर्मन भ्रत्यस्त्यको की शिकायतों और डानज़िग संबंधी विवादों का राष्ट्रसंघ की कार्य-सूची पर से हट जाना ।

दोनों ही पक्षों ने जिन बातों से प्रेरित होकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, उनका कुछ स्पष्टीकरण यहाँ देना आवश्यक है । हिटलर ने पश्चिमी योरोप को भ्रमभीत कर अपना शत्रु बना लिया था । और चूँकि उसने कम्युनिस्टों को भी वरपोदित (persecuted) किया था इसलिए रेपेलो संधि (Rapallo) में उसके पूर्वगामी (predecessors) शासकों ने जो मार्ग अपनाया था उसे अपना कर वह सोवियत-संघ से सतुलन की पूर्ति करने (redress the balance) की माशा नहीं कर सकता था । उसे यह भय था कि वह बिल्कुल भ्रकेसा रह जाएगा । इसके अतिरिक्त, वह इस निर्णय— इस निर्णय पर उसकी अपनी अस्तित्वन उत्पत्ति का सभवतः प्रभाव पड़ा होगा— पर पहुँचा था कि जर्मनी को सबसे पहिले दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए । अपने पूर्वी पड़ोसी से मित्रता कर लेना सभी दृष्टियों से उपयुक्त था । पोलैंड के साथ मित्रता उसने यह वचन देकर की कि आगामी दस वर्षों तक वह पोलैंड के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही—चाहे वह प्रचार के रूप में हो या और किसी अन्य प्रकार की—नहीं करेगा ।

पोलैंड ने जिन प्रेरणाओं से यह समझौता किया, वे भी इतनी ही प्रबल (cogent) थी । पन्द्रह वर्षों से वह दो शत्रु-राष्ट्रों के बीच असुविधापूर्वक रहा था । उसका एक साथी, फ्रांस, उससे दूर था । लोकानों-संधि से फ्रांस की यह प्रवृत्ति पहिले ही स्पष्ट हो चुकी थी कि फ्रांस अपनी सुरक्षा की चिन्ता पहिले करेगा और पोलैंड के हितों की बाद में । चार राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर कर अभी हाल ही में उसने पोलैंड की भावनाओं को गहरी चोट पहुँचाई (wounded to the quick) थी । बड़े राष्ट्र के रूप में जर्मनी के पुनरुत्थान के कारण, आपत्ति के समय फ्रांस की सहायता मिल सकना पहिले से भी अधिक अनिश्चित हो गया था । पोलैंड अब अपने दोनों ही बड़े पड़ोसियों से शत्रुता नहीं कर सकता था । उसे दोनों में से किसी एक को मित्र बना लेना आवश्यक था । उसने उसके साथ

ही मित्रता की जिसे उसने अधिक शक्तिशाली और अधिक विश्वसनीय समझा। यह अवश्य ही सत्य था कि जर्मन-पोलिश समझौते से उसे केवल दस ही वर्षों के लिए त्राण मिला था। किन्तु जो स्थिति दस वर्षों तक स्थिर रह सकती हो, वह स्थायी भी बन सकती है। इस दिशा में भी एक प्रयोग कर देखना उपयोगी हो या।

सोवियत सघ में इस समझौते के प्रति जो प्रतिक्रिया हुई उसका और अधिक विस्तृत वर्णन देना अभीष्ट है। सन् १९२७ तक सोवियत सरकार ने अमेरिका को छोड़ सभी मुख्य राष्ट्रों से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए थे। इस वर्ष सोवियत प्रतिनिधि पहिली बार जेनेवा आये थे। सन् २७ में स्टालिन की "एक ही राज्य में समाजवाद" (socialism in a single state) नीति की विजय हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना—जो १ अक्टूबर, १९२८ को अमल में आई—के स्वीकार किए जाने का अर्थ यह था कि औद्योगीकरण (industrialisation) बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया जाएगा और उसके समय क्रांति के शास्त्रीय सिद्धांतों की अपेक्षा राज्य के व्यावहारिक हितों पर पहिले ध्यान दिया जाएगा। सोवियत सघ और ग्रेट ब्रिटेन के बीच १९२६ में पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित होना सामान्य स्थिति (normal conditions) के निर्माण की दिशा में एक और कदम था। सोवियत अधिकारियों को अब केवल अमरीकी सरकार और राष्ट्रसंघ से ही समझौता करना शेष था।

इस दिशा में तीन वर्षों तक कोई प्रगति नहीं की जा सकी। किन्तु १९३२ के शरद में, सोवियत सघ ने इटली और फ्रांस से अनाक्रमण समझौते (non-aggression pacts) किए। अगले वर्ष की प्रथम तिमाही में दो ऐसी घटनाएँ घटित हो गई जिन्होंने सोवियत नीति में बिल्कुल ही नया परिवर्तन ला दिया। हिटलर जर्मनी में सत्तास्थ हुआ और राष्ट्रसंघ-सभा द्वारा भर्त्सना किए जाने पर, जापान ने राष्ट्र-संघ की सदस्यता त्याग दी। इन घटनाओं की मास्को में समुचित (appropriate) प्रतिक्रिया हुई। सन् १९३३ के प्रीप्सकाल में जर्मनी से सामान्य भय (common fear) के कारण सोवियत सघ और फ्रांस में पुनर्मेल तेजी से बढ़ा और संधि-संशोधन के विरुद्ध अनेकों वक्तव्य सोवियत समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए। इसके साथ ही साथ दो ऐसे राष्ट्रों में जिन्हें

जापान से सबसे अधिक भय था,—सोवियत संघ और अमेरिका—घनिष्ठता बढ़ी। नवम्बर १९३३ में लिट्विनोव ने वाशिंगटन की यात्रा की और सोवियत सरकार की ओर से इस घाटय के समुचित आश्वासन दिये कि अमेरिका में प्रचार-कार्य (propaganda) नहीं किया जाएगा और सोवियत संघ में रहने वाले अमरीकियों को घामिक स्वतन्त्रता दी जाएगी। अमरीकी सरकार ने सोवियत सरकार को कूटनीतिक मान्यता भी दे दी। इस प्रकार सोवियत कूटनीतिज्ञों ने दो संभाव्य मित्र (potential allies) प्राप्त कर लिए थे—एक जर्मनी के विरुद्ध; और दूसरा जापान के विरुद्ध।

प्रब सोवियत सरकार की पुरानी आत-चारणा (ancient prejudice)—राष्ट्रसंघ में उसका प्रवेश—और नष्ट होना शेष थी। फ्रांस इस कदम पर जोर देता था। यदि फ्रांस-सोवियत युटबन्दी (Franco-Soviet alliance) की जाती तो उसमें युद्ध-पूर्व कूटनाति (pre-war diplomacy) की अत्यधिक मध्यमता। और यह बात समस्त ब्रिटिश को अच्छी नहीं लगती। जर्मन आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा में सामान्य हित की अभिव्यक्ति (manifestation) राष्ट्रसंघ की सामान्य सदस्यता से ही हो सकती थी। इसलिए जुलाई १९३४ में फ्रांस ने ब्रिटिश और इटली को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ में प्रवेश दिलाने के लिए अन्य देशों का समर्थन प्राप्त करने में उसका साथ दें। सितम्बर में राष्ट्रसंघ की सभा का जो अधिवेशन हुआ, उस में रूस को विधिवत् राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया। इस समय केवल तीन राज्यों—स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और पुर्तगाल—ने ही इसके विरोध में अपना मत दिया। पोलैंड ने सावधानी (precaution) के बतौर दो कदम उठाए। एक तो उसने पृथक् रूप से सोवियत सरकार से यह वचन प्राप्त कर लिया कि पोलैंड में रहने वाले रूसी अल्पसंख्यकों से राष्ट्रसंघ को वह न तो कोई याचनापत्र (petition) भिजवाएगी और न ही किसी ऐसे याचनापत्र का समर्थन करेगी। दूसरे, राष्ट्रसंघ में उसने यह खुले आम घोषित कर दिया कि पोलैंड अब यह नहीं मानता कि पोलिश अल्पसंख्यक प्रश्नों पर विचार करने का राष्ट्रसंघ को कोई अधिकार प्राप्त है। पोलैंड की यह घोषणा, वास्तव में, अल्पसंख्यक संधि (minorities treaty) को समाप्त करने की घोषणा ही थी।

हिटलर से सोवियत सरकार को जो भय था, उसे दूर करने के लिए राष्ट्र-

संघ की सदस्यता से प्राप्त सुरक्षा व्यर्थ थी, इसलिए सोवियत सरकार फ्रांस से सीधा ही समझौता करने के लिए जोर देती रही। फ्रांस इस अनुरोध को मंजूरी नहीं देना चाहता था किन्तु फ्रांस ने पहिले इस बात का पता लगा लिया कि फ्रांस और सोवियत संघ के बीच किए जाने वाले गारन्टी-समझौते में यदि जर्मनी को भी सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाए और लोकार्नो पूर्वोदाहरण (precedent) के अनुसार, यदि यह समझौता पारस्परिक आधार पर (in both directions) लागू किया जाये तो ऐसे समझौते पर ग्रेट ब्रिटेन को कोई आपत्ति नहीं होगी। तदनुसार (accordingly), फ्रांसीसी और सोवियत सरकारों ने एक पूर्वीय समझौते (Eastern pact) का प्रारूप तैयार किया जिस के अनुसार फ्रांस और सोवियत संघ को न केवल जर्मनी के आक्रमण के विरुद्ध एक दूसरे को गारन्टी देनी थी अपितु जर्मनी को भी उनमें से किसी के भी आक्रमण के विरुद्ध गारन्टी उन दोनों को देनी थी। योजना कुछ कृत्रिम (artificial) प्रतीत होती थी क्योंकि ऐसी परिस्थितियों की कल्पना कर सकना कठिन था जिनमें जर्मनी सोवियत संघ के विरुद्ध फ्रांस या फ्रांस के विरुद्ध सोवियत संघ की सहायता लेता। जो भी हो, फरवरी १९३५ में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रारूप का अनुमोदन कर दिया और अन्य प्रस्तावों, जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा, के साथ यह जर्मन सरकार को भेज दिया गया। जर्मनी ने जो आपत्तियाँ उठाई वे प्रस्ताव को मंजूरी दे देने के बराबर (tantamount to refusal) ही थी। फ्रांसीसी और सोवियत सरकारों को इस परिणाम की आशा थी और संभवतः उनकी इच्छा यही थी कि यही परिणाम निकले। इसका लाभ उन्होंने एन फ्रेंस सोवियत समझौते (France-Soviet Pact) पर मई १९३५ में हस्ताक्षर कर उठाया। इस समझौते के अनुसार उन्होंने यह बचन दिया कि यदि किसी यूरोपीय राष्ट्र द्वारा आक्रमण किया गया तो वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। नात्सी क्रांति के परिणामस्वरूप पुनः-पूर्व की फ्रांस सोवियत मैत्री पुनः हो गई।

ऑस्ट्रिया और इटली

(Austria And Italy)

ऑस्ट्रिया को अपनी विदेशी नीति का प्रथम लक्ष्य (object) बनाने

सम्बन्धी हिटलर का निश्चय कई मानों में दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ^१। सन् १९१६ से १९३३ तक की अवधि में यह बात सशयहीन थी कि अधिकांश ऑस्ट्रियन जनता जर्मनी के साथ संध बनाने की इच्छुक थी। किन्तु इस प्रकार के संध-निर्माण का जो निषेध संधियों में किया गया था, उसकी आलोचना संधियों के और किसी भी अनुच्छेद की अपेक्षा अधिक न्यायोचित रूप से की जा सकती थी। परन्तु नात्सी क्रांति के कारण अधिकांश ऑस्ट्रियन लोगो का मत बदल गया था। न तो सोशल-डेमोक्रेट, जो कि ऑस्ट्रियन संसद में सबसे अधिक बहुमत वाली पार्टी के थे, और न ही यहूदी, जो कि काफी अधिक संख्या में थे और विएना में जिनका काफी प्रभाव था, ही यह सोचते थे कि नात्सी जर्मनी में उनके साथियों (comrades) की जो स्थिति हुई है, वैसी ही उनकी भी हालत हो। कैथोलिक धर्माधिकारी (Catholic Church) जिनका ऑस्ट्रियन राजनीति में काफी भाग था, भी जर्मन नात्सियों द्वारा जर्मनी में उनके अनुयायियों पर किए गए अत्याचारों के कारण नात्सियों के विरोधी बन चुके थे। अविश्वास (mistrust) के इन विशेष कारणों के अतिरिक्त, परम्परा से आरामपसन्द ऑस्ट्रियन जर्मनी के नए शासन की पाश्चात्तिक और हमनपूर्ण क्षमता को संदेह की दृष्टि से देखता था। यह संभव हो सकता है कि हिटलर के सत्तास्थ होने के बाद किसी भी समय यदि ऑस्ट्रिया में स्वतंत्र मतदान (free vote) होता तो जर्मनी के साथ संध बनाने के पक्ष में ही बहुमत होता। किन्तु यह बहुमत १९३३ के पहले, संभव बहुमत के समान अत्यधिक और निर्विवाद (overwhelming and incontestable) किसी भी स्थिति में नहीं होता।

जो भी हो, नात्सी क्रांति की ऑस्ट्रिया में प्रथम प्रतिक्रिया अनुकरण (imitation) की हुई। मार्च १९३३ में, ऑस्ट्रिया के प्रधानमन्त्री डोलफुस (Dollfuss) ने संविधान को स्थगित कर (by suspending the constitution) प्रतिनिधि सभा (Chamber) में सोशल-डेमोक्रेटों के विरोध को अमान्य कर दिया (over-ruled)। इस घटना के बाद से, ऑस्ट्रियन सरकार हीमवेर (Heimwehr) नामक गैर सरकारी सैनिक संगठन की सहायता पर ही अधिक भरोसा करने लगी। यह संगठन सोशल-डेमोक्रेटों की सशस्त्र सेना को

१ "Hitler's decision to make Austria the first object of his foreign policy proved in many respects unfortunate."

संतुलित रखने के लिए कुछ ही वर्षों पूर्व अस्तित्व में आया था। इसके बाद जर्मन सरकार मैदान में उतर आई। ऑस्ट्रियन सरकार के निन्दापूर्ण प्रसारण (broadcasts) म्युनिक (Munich) कार्यक्रम के एक नियमित अंग हो गए। ऑस्ट्रियन क्षेत्र पर जर्मन वायुयानों ने नात्सी प्रचार-पत्रों (propaganda leaflets) गिराये। सीमांत पार कर ऑस्ट्रियन नात्सीयों को घात और धन (money) चोरी से भेजे गये। ऑस्ट्रिया की यात्रा करने के इच्छुक जर्मन लोगों पर निरोधात्मक विसा फीस (prohibitive visa fee) लगाई गई। ऑस्ट्रियन सरकार ने इसका उत्तर, जून १९३३ में, ऑस्ट्रियन नात्सी पार्टी का दमन कर, दिया।

यदि बड़े राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करते, तो हीमवेर (Heimwehr) एवं कुछ जन-प्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद भी ऑस्ट्रिया संभवतः जर्मनी के भागे शीघ्र ही घुटने टेक देता। नात्सी दासन की ज्यादातियों के विरुद्ध व्यापक रोष अब अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था किन्तु ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जर्मनी के अभियान (campaign) के कारण वह और भी बढ़ गया। ऑस्ट्रिया की स्वतन्त्रता को बनाए रखने के प्रश्न पर फ्रांसीसी लोकमत की अपेक्षा ब्रिटिश लोकमत बहुत ही कम आग्रहपूर्ण होगया। बर्लिन में कूटनीतिक प्रतिनिधित्व (diplomatic representations) किए गए किन्तु उनका बहुत अधिक परिणाम नहीं निकला। अगस्त में, ऑस्ट्रिया ने एक और अन्तर्राष्ट्रीय झुल्ला लिया जिसकी घेरे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और गारन्टी अन्य अनेक छोटे राष्ट्रों ने दी।

इस घटना के बाद से, इटली ऑस्ट्रिया का प्रमुख संरक्षक बन गया। पिछले कुछ वर्षों तक, वह असंतुष्ट और "सशोधनवादी" राष्ट्र रहा था और हाल ही में उसने लगभग सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर जर्मनी के ही समान रुख अपनाया था। नात्सी क्रांति से प्रेरणा पाकर अब इटली की विदेश नीति भी सोवियत संघ की नीति की भाँति नाटकीय ढंग से बदल गई। इटली अफ्रीका या पूर्वी योरोप सम्बन्धी संधि में सशोधन की माँग कर सकता था। किन्तु यदि जर्मनी को ऑस्ट्रिया को अपने राज्य में मिला लेने दिया गया होता तो वह इटली जैसे राष्ट्र के लिए—जिसने दक्षिणी टायरोल (Tyrol) नामक जर्मनी ऑस्ट्रियन प्रांत अपने राज्य में मिला लिया था—संभवतः एक खतरनाक पड़ोसी होता। सन् १९३३-३४ के शीतकाल में, इटली की सरकार

ने हीमवेर को गुप्त आर्थिक सहायता देना प्रारम्भ किया क्योंकि वह हीमवेर को ऑस्ट्रियन स्वतन्त्रता का मुख्याधार (bulwark) मानती थी। इस सहायता के बदले में, मुसोलिनी ने यह मांग की कि ऑस्ट्रियन सोशल-डेमोक्रैटों का तत्ता उलट दिया जाए जो विएना की नगरपालिका में इस समय भी अधिकार जमाए हुए थे और ऑस्ट्रिया में फासिस्ट लाइन्स (fascist lines) की सरकार कायम की जाये। यह मांग फरवरी १९३४ में पूरी कर दी गई। इसका कोई गम्भीर प्रतिरोध नहीं हुआ। सैकड़ों प्रमुख सोशल-डेमोक्रैटों को जेलों में डाल दिया गया और सभी समाजवादी (socialist) संस्थाओं का दमन किया गया। इसके बाद से ही ऑस्ट्रिया की गृह (domestic) और विदेश नीति इटली द्वारा नियंत्रित होने लगी।

इस सारी कार्रवाई का परिणाम यह हुआ कि ऑस्ट्रिया के प्रति ग्रेट ब्रिटेन की जो सहायता भी तब तक चली आई थी, उससे ऑस्ट्रिया बर्चित हो गया यद्यपि ब्रिटिश सरकार यह घोषित करती रही कि ऑस्ट्रिया की स्वतन्त्रता में उसकी दिलचस्पी है। किन्तु नात्सियों को इससे और भी प्रयत्न करने की प्रेरणा मिली। जुलाई २५, १९३४ को, ऑस्ट्रियन नात्सियों के एक दल ने सचीव चांसरी (federal chancery) पर अधिकार कर लिया और भाग निकलने के समय डोलफुस पर प्राणघाती प्रहार किया (fatally wounded)। जो भी हो, विद्रोहियों (rebels) को सेना या अधिकांश जनसंख्या का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। शाम होते-होते, सरकार के नियन्त्रण में वियना पुनः आगया। अन्यत्र (elsewhere) केवल छुटपुट घटनाएँ (sporadic outbreaks) ही घटीं थी। यह समान्यतः माना जाता था कि जर्मन सहायता के बिना यह विद्रोह संगठित नहीं किया जा सकता था और कई लोग तो हिटलर को डोलफुस की मृत्यु के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी मानते थे। सीमांत पर खींच ही इटालियन कुमुक मेजी गई। इस बारे में भी बहुत अनुमान लगाया था कि विद्रोह (insurrection) सफल हो जाता तो इटालियन कुमुक ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में कूच कर जाती भयवा नहीं।

जुलाई १९३४ की घटनाएँ ऑस्ट्रिया के इतिहास में दूसरा मोड़ सिद्ध हुई हैं। ऑस्ट्रिया सबधी नीति असफल हो जाने से जो बदनामी हुई थी, उसका हिटलर पर गहरा प्रभाव पड़ा और संभवतः उसे यह मय था कि यदि वह अपनी उसी

नीति-पर चलता रहता, तो इटली सेना की सहायता से उनका बदला लेता । जर्मनी ने अपना पंथरा (tactics) बदल दिया । ऑस्ट्रियन नाटियों को हिंसात्मक कार्य (acts of violence) करने के लिए प्रोत्साहित करना अब बन्द कर दिया गया और ऑस्ट्रियन सरकार को नीति की जर्मनी द्वारा निन्दा प्रब करीब-करीब बन्द कर दी गई । हिटलर ने अनेक बार यह भस्वीकार किया कि ऑस्ट्रिया की स्वतन्त्रता को खतरा पंदा करने या उसके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने के उसका कोई विचार है । यह नीति दो वर्षों तक जारी रही । जुलाई १९३६ में, जबकि अबीसीनिया अभियान (Abyssinian Venture) के कारण मध्य योरोप पर इटली का प्रभाव कम हो चुका था, तब ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के साथ एक पुनर्मेलो (pact of reconciliation) किया । इसके थोड़े ही समय बाद, हीमबेर, जिसे अब इटली आर्थिक सहायता नहीं दे सकता था, को विघटित (disbanded) कर दिया गया । इन घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि ऑस्ट्रिया पर जर्मनी तथा इटली का एक प्रकार का मिश्र अधिकार (condominium) होगया । किन्तु चूंकि इसके साथ ही साथ जर्मनी और इटली के संबंधों में सुधार हो चुका था, इसलिये कुछ समय तक यह जानने का अवसर ही नहीं आया कि जर्मनी के साथ किसकी मंत्री अधिक थी ।

फ्रांस, इटली और लघु-मैत्रीसघ

(France, Italy And the Little Entente)

सन् १९३६-३८ के शीतकाल में जर्मनी से इटली के विलगाव (alienation) तथा ऑस्ट्रिया पर इटली का संरक्षण जैसा शासन स्थापित होने के मध्य और दक्षिणी योरोप में महत्वपूर्ण प्रतिघात हुये ।

इसमें से प्रथम प्रतिघात फ्रांस और इटली के संबंधों में तीव्रगति से सुधार होता था । यूगोस्लाविया के दावों के समर्थन के कारण युद्ध के बाद, फ्रांस और इटली में प्रतिद्वन्द्विता बढ गई थी । तब न, वह अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई । अन्तोंका में, फ्रांस १९१५ की लंदन संधि (London Treaty of 1915) के अनुसार इटली के दावों को सन्तुष्ट करने में असफल रहा था, और ट्यूनिस् (Tunis) के फासीसी प्रयोग राज्य (dependency) में इटालियनों की स्थिति के बारे में लगातार संघर्ष चलता रहता था । नौसैनिक मामलों में, फ्रांस द्वारा समानता का दावा कर दिए जाने के कारण, इटली असमानित हो

चुका था योरोप सम्बन्धी अन्य प्रश्नों पर, इटली हमेशा ही मूलपूर्व-
 शत्रु राष्ट्रों को शिकायतों का समर्थन करता था और फ्रांस के साथी—
 यूगोस्लाविया—के प्रति बराबर शत्रुता रखता था। सन् १९३३ तक फ्रांस
 और इटली के संबंध विगड़ते गये। किन्तु भ्रॉस्ट्रिया पर हिटलर की गिद्धदृष्टि
 एक ऐसा खतरा था जिससे ये दोनों ही देश समानरूप से भयभीत
 थे। भ्रॉस्ट्रिया की स्वतन्त्रता में समानहित ने उन्हें सीधे ही निकट ला
 दिया। सितम्बर १९३४ में, यह समावना प्रचारित की जाती थी (possibility
 was canvassed) कि शेष (outstanding) कठिनाइयों का समाधान
 निकालने के लिए फ्रांसीसी विदेशमन्त्री बारथो (Barthou) सरकारी तौर पर
 भेंट (official visit) के लिए रोम जाएगा।

किन्तु समाधान जितना सरल प्रतीत होता था, उतना सरल नहीं था। दोनों
 ही पक्षों के मध्य योरोप में आसामों (clients) थे। चेकोस्लोवाकिया,
 यूगोस्लाविया और रूमानिया फ्रांस के मित्र, राष्ट्र थे। इटली बहुत अधिक समय
 से हंगरी का समर्थन करता चला आ रहा था। मार्च १९३४ में, इटली, भ्रॉस्ट्रिया,
 और हंगरी के बीच रोम में अर्ध-राजनैतिक, अर्ध-आर्थिक (semi-political,
 semi-economic) स्वरूप के अनेक समझौते हुए थे। अतएव जब तक फ्रांस
 या इटली अपने आसामियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता; तब तक
 यह आवश्यक था कि फ्रांस-इटली पुनर्मेल (rapprochement) हो जाने से
 पहिले मध्य योरोप के प्रतिद्वन्द्वी गुटों में पुनः मंत्री स्थापित की जाये। इटली
 हंगरी और भ्रॉस्ट्रिया पर दबाव डाल सकता था। अब देखना यह था कि फ्रांस
 लघु मंत्रीसभ के साथ क्या कदम उठाता।

फ्रांस के चार राष्ट्र समझौते में भाग लेने का लघु-मंत्रीसभ ने विरोध
 किया था—किन्तु पोलैंड की भांति तीव्रतापूर्वक नहीं। इटली के साथ फ्रांस की
 वर्तमान गतिविधि को भी सदेह की दृष्टि से देखा जाता था। किन्तु मंत्रीसभ के
 तीनों ही सदस्यों को यह सदेह समान रूप से नहीं था। सच पूछा जाय तो
 भ्रॉस्ट्रिया को हिटलर की घमकी ने ही इस मंत्री में पहिली गंभीर फूट (serious
 rift) डाल दी थी। यदि भ्रॉस्ट्रिया को जर्मनी अपने राज्य में मिला लेता तो चेको-
 स्लोवाकिया चारों ओर खतरे से घिर जाता। इसीलिए उसने हर ऐसे कदम का
 स्वागत किया जो कि फ्रांस और इटली ने ऐसी स्थिति को रोकने के लिए

उठाया। यदि जर्मनी ग्रीसिट्रिया को अपने में मिला भी ले, तो यूगोस्लाविया को अधिक भय नहीं था। किन्तु यदि इटली ग्रीसिट्रिया का स्वामी बन बैठता, तो यूगोस्लाविया अपने को इटली से घिरा हुआ अनुभव कर सकता था। अतएव फ्रांस और इटली के बीच पुनर्मेली उसे (यूगोस्लाविया को) पसन्द नहीं थी क्योंकि इस पुनर्मेली का उद्देश्य ही ग्रीसिट्रिया पर इटली के प्रभाव को मजबूत बना देना था। रुमानिया इतनी दूर था कि उस पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ सकता था तथा उसे केवल इसी बात का चिन्ता था कि हंगरी के विरुद्ध लघु-मैत्रीसंध का संगठन बना रहे। सन्धि में, लघु-मैत्रीसंध के दोनों ही सदस्य ग्रीसिट्रिया की स्वतन्त्रता बनाए रखने के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति (lip-service) जता सकते थे। किन्तु यदि यह स्वतन्त्रता अवास्तविक हो जाती और ग्रीसिट्रिया अन्य किसी राष्ट्र के निर्देशक प्रभाव (directing influence) में आ जाता तो बेकोस्लोवाकिया यह अधिक पसन्द करता कि वह राष्ट्र इटली हो, यूगोस्लाविया यह चाहता कि वह राष्ट्र जर्मनी हो।

अक्टूबर १९३४ में जबकि यह प्रश्न निश्चित ही था, यूगोस्लाविया का राजा अलेक्जेंडर फ्रांसीसी सरकार के सामने अपना दृष्टिकोण रखने लिए सरकारी तौर पर मॉट के हेतु फ्रांस पहुँचा। मार्सेलीज (Marseilles) में उसकी बायीं से मुलाकात हुई। जहाज से उतरकर, योही वे दोनों एक मोटर में खाना हुए, एक क्रोएट (Croat) आतंकवादी की पिस्तौल ने उनके प्राण ले लिए। यह कुख्यात था ही कि इटली और हंगरी दोनों ही ने असंतुष्ट (disaffected) यूगोस्लावियों को आश्रय और सहायता तक दी थी ताकि इन लोगों का उपयोग किसी दिन विद्रोह उमाड़ने (fomenting rebellion) में किया जा सके। मार्सेलीज अपराध में इटली या हंगरी का सीधा हाथ है यह सिद्ध करना कठिन था। किन्तु यूगोस्लाविया ने राष्ट्रसंघ में विरोध प्रदर्शित करने का निश्चय किया। यदि दोनों ही सबधित बड़े राष्ट्र—फ्रांस और इटली—यह दृढ़ निश्चय नहीं करते कि इस दुःख घटना को उनके बीच प्रारम्भ हुए पुनर्मेल (incipient rapprochement) में बाधा न बनने दिया जाए, तो स्थिति समवतः सकटपूर्ण हो जाती। इस अवसर पर एक गुप्त सौदा (tacit bargain) कर लिया गया। यूगोस्लाविया को इस बात पर राजी कर लिया गया कि वह केवल हंगरी पर ही आरोप लगाए और जेनेवा में अपने विरोध के समय

इटली का कोई उल्लेख (mention) न करे। इसके बदले में इटली हंगरी—इटली की सहायता के बिना जो कि असहाय (helpless) था—को इस बात के लिए राजी कर लेगा कि वह इतनी भर्त्सना (censure) स्वीकार करले जितनी कि यूगोस्लाव रोप को सतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो। जेनेवा में इस योजना के अनुसार कार्रवाई हुई। श्रमपूर्ण चर्चाओं (arduous negotiations) के बाद, परिपक्व निर्विरोध यह घोषित कर सकी कि, “कुछ हंगेरियन अधिकारियों (authorities) ने, मार्सेलोज अपराध की तैयारी से संबंधित कृत्यों (acts) संबंधी कुछ जिम्मेदारियाँ जो चाहे असावधानी के कारण हो, अपने ऊपर ली होनी” और हंगेरियन सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह जिन अधिकारियों का दोष सिद्ध हो जाए, उन्हें दण्ड दे।

फ्रांसीसी भूमि पर शासक अलेक्जेंडर की हत्या के तीन मुख्य परिणाम हुए। उससे इटली के प्रति यूगोस्लाविया का सदेह बढ गया। उससे यूगोस्लाविया और फ्रांस में कुछ अनबन होगई। किन्तु फ्रांस और इटली के बीच पुनर्मैत्री स्थापित होने में उससे धीघ्रता हुई। जनवरी १९३५ के आरम्भिक दिनों में, बाथों का उत्तराधिकारी लावाल (Laval) रोम गया और उसने मुसोलिनी से अनेक समझौते किए जिनके साथ ही लम्बे समय से चला आ रहा फ्रांस और इटली के बीच का बँर समाप्त हो गया। जहाँ तक जर्मनी का संबंध है, दोनों ही राष्ट्रों ने यह समझौता किया कि यदि जर्मनी ने पुनर्शास्त्रीकरण की नीति अपनाई तो वे “उसके (जर्मनी के) प्रति अपनाए जाने वाले अपने रुख में तालमेल (concert upon) रखेंगे।” वैसे ही मध्य योरोप के बारे में उन्होंने ऑस्ट्रिया और उस के सभी पड़ोसियों (स्विट्जरलैंड को छोड़कर) से यह सिफारिश करने का समझौता किया कि वे इस आशय का समझौता करें कि एक दूसरे के मामलों में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा अपने देशों की स्वतन्त्रता को नष्ट करने या “राजनैतिक अथवा सामाजिक व्यवस्था” (“political or social regime”) को उलट देने के प्रयत्नों को किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुँचाएँगे। (सच पूछा जाय तो इस प्रस्तावित समझौते की चर्चा चलाने का कभी कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया, इसी बीच उन्होंने यह वचन दिया कि यदि ऑस्ट्रिया की स्वतन्त्रता को किसी प्रकार का खतरा हुआ, तो वे ऑस्ट्रिया से तथा उसके अन्य इच्छुक (willing) पड़ोसियों से परामर्श करेंगे। जहाँ तक अफ्रीका का प्रश्न है, लंदन संधि के अंत-

गंत अपने दावे को सत्याते हुए फ्रांस ने इटली को मूमध्यरेखा के समीप स्थित फ्रांसीसी अफ्रीका (French Equatorial Africa) की एक पट्टी (strip) जो कि इटली के अफ्रीकनस्थ लीबिया (Libya) प्रांत से लगी हुई थी तथा इरिट्रिया (Eritrea) के समीपस्थ फ्रांसीसी सोमालिलेन्ड का एक त्रिकोणाकार (triangle) क्षेत्र सौंप दिए। ट्युनिस में इटलीवासियों की स्थिति का विनियमन कर दिया गया तथा लावाल ने मुसोलिनी को यह आश्वासन दिया, कि यदि इटली को अफ्रीका में कोई सुविधाएँ प्राप्त हो तो फ्रांस को उनसे कोई सरोकार नहीं होगा। मागे चलकर फ्रांसीसियों की ओर से यह कहा गया कि इस आश्वासन, जिसकी शर्तें गुप्त रखी गई थी, का सम्बन्ध केवल आर्थिक सुविधाओं से था।

हिटलर के सत्तारूढ होने से जो कूटनीतिक उल-पुल (volte-face = complete change of front in argument or opinion-Tr.) हुई उनमें अन्तिम महत्वपूर्ण उल-पुल फ्रांस और इटली में पुनर्मंत्री थी। इस सारे घटनाचक्र के परिणामों को यहाँ अब संक्षेप में दिया जा सकता है। पोलैंड अब फ्रांस से अलग हो गया था (यद्यपि पोलिश-फ्रांसीसी मैत्री को अभी विधिवत् समाप्त घोषित नहीं किया गया था) तथा जर्मनी से उसके निकट सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे। सोवियत संघ ने अपना परंपरागत (traditional) सशोधनवादी दृष्टि (revisionist attitude) त्याग दिया था तथा बर्सेलीन संधि का समर्थन करने की फ्रांसीसी नीति को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। इटली भी जर्मन-विरोधी मोर्चे (anti-German front) में सम्मिलित हो चुका था। वह मध्य योरोप में अपनी चीकियों (outposts) के रूप में ग्रांस्ट्रिया और हंगरी का उपयोग करता रहा। जहाँ तक सधु मैत्रीसंधि का सम्बन्ध है चेकोस्लोवाकिया फ्रांस और इटली जैसी स्थिति में था तथा वह ग्रांस्ट्रिया के निकट आ चुका था (किन्तु हंगरी के निकट नहीं, जिसके कि सशोधनवादी दावे (claims) अभी नहीं त्यागे गए थे)। इसके विपरीत यूगोस्लाविया इटली से उलटा मार्ग अपना रहा था, वह फ्रांस से अलग हो गया था, तथा जर्मनी के निकट सम्पर्क में तेजी से आता जा रहा था। मई १९३५ में, चेकोस्लोवाकिया और सोवियत संघ में एक समझौता—जिसकी शर्तें एक पख (fortnight) पूर्व हुए फ्रांस-सोवियत समझौते के ही समान थी—हो जाने से राष्ट्रो का यह

पुनर्विभाजन समाप्त हो गया। इस समझौते ने लघु मंत्रीसभ में बढ़ती जा रही फूट को सामने ला दिया, क्योंकि रूमानिया ने इसी प्रकार का समझौता करने का अनुरोध ध्वनीकार कर दिया तथा यूगोस्लाविया उन कतिपय योरोपीय राज्यों में से था जो कि अब भी सोवियत सरकार को मान्यता नहीं देना चाहते थे।

बालकन मैत्रीसभ

(The Balkan Entente)

सन् १९२४ में बालकन देशों में नए सभ बने किन्तु यहाँ उनका कारण नात्सी क्रांति नहीं थी। युद्ध के बाद हंगरी से सामान्य भय (common fear) के कारण जिस प्रकार बेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रूमानिया परस्पर निकट आ गए थे, उसी प्रकार बल्गेरिया के प्रति सामान्य शत्रुता (common hostility) के कारण यूगोस्लाविया, रूमानिया और ग्रीस सयुक्त हो गए थे। सन् १९१३ के बालकन युद्ध के बाद बल्गेरिया के विभाजन का चौथा लाभप्राही (beneficiary) राष्ट्र, टर्की, स्वयं भी १९१९ में पराजित राष्ट्रों की श्रेणी में आ चुका था। कई वर्षों तक वह अपने पुराने बालकन साधियों से घलग रहा और केवल सोवियत सभ से ही निकट सम्बन्ध बढ़ाता रहा। किन्तु १९३० में उसने ग्रीस से जो उसका कट्टर शत्रु था, अपनी शत्रुता समाप्त कर दी। सन् १९३२ में, वह राष्ट्रसभ का सदस्य बन गया। टर्की, यूगोस्लाविया, रूमानिया और ग्रीस ने १९३४ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने एक दूसरे के बालकन सीमान्तों की परस्पर गारन्टी दी। बल्गेरिया ने इस समझौते में शामिल होने से इन्कार कर दिया क्योंकि उसमें ऐसे सीमान्तों की पुष्टि की गई थी जिनका वह हमेशा ही विरोध करता रहा था। भ्रमरानिया को जिसके मामलों में इटली प्रमुख भाग लेता रहा था, को इस समझौते में शामिल होने का निमन्त्रणा ही नहीं दिया गया।

किन्तु इस समझौते द्वारा स्थापित “बालकन मैत्रीसभ” बहुत कमजोर ढाँचा साबित हुआ। यूगोस्लाविया के लिए इस समझौते का प्रमुख लक्ष्य बालकन मामलों में इटली के हस्तक्षेप के विरुद्ध अपनी सुरक्षा प्राप्त करना था। इसके विपरीत, ग्रीस ने इटालियन नौसेना से सघर्ष करने की हिम्मत नहीं होने के कारण समझौते के अनुसमर्थन के साथ ही साथ यह घोषणा भी की कि इस समझौते का स्वीकार करने में वह किसी भी गैर बालकन राष्ट्र से युद्ध करने

का अपना कोई कर्तव्य नहीं मानता है। इस घोषणा के परिणामस्वरूप यूनान और यूगोस्लाविया में अनबन हो गई। इसी बीच, यूगोस्लाविया और बल्गेरिया के सम्बन्धों में सुधार होना प्रारम्भ हुआ। यूगोस्लाविया से सहानुभूति रखने वाली एक बल्गेरियन (प्रभाव) सरकार ने अपने आपको इटालियन प्रभाव (influence) से मुक्त कर लिया जो सोफिया में अभी तक स्थायी रूप से चला आ रहा था; और युद्ध के बाद पहिली बार, उसने (बल्गेरिया) उन मेसिडोनियन आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जो यूगोस्लाविया सीमान्त में छाए हुए थे। इसके बाद, बालकन देशों में स्थिति अस्थिर और अनिश्चित (fluid and undefined) बनी रही। बालकन मंत्रीसभ कायम रहा। किन्तु यूगोस्लाविया मंत्रीसभ के सदस्य यूनान की अपेक्षा बल्गेरिया के अधिक विकट प्रा गया जो कि मंत्रीसभ का सदस्य भी नहीं था। मार्च १९३१ में यूनान में हुए एक ठूहयुद्ध और उसके बाद राजतन्त्र की पुनर्स्थापना से सामान्य शांति (general tranquility) भंग नहीं हुई।

जून १९३६ में मांट्रेन्स (Montrenx) में एक सम्मेलन हुआ। टर्की के अनुरोध पर, इस सम्मेलन में तुर्काने संधि पर प्रमुख हस्ताक्षरकर्त्ताओं (principle signatories) ने यह समझौता किया कि जलडमरूमध्य (the Straits) के असेमीकरण सम्बन्धी तुर्काने संधि के अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जाए। परिवर्तनों के अनुसार, टर्की को जलडमरूमध्य में जलिवन्दी करने की स्वतन्त्रता मिल गई और शांति तथा युद्ध काल में जलडमरूमध्य में से युद्धपोतों के आवागमन (passage of warships) सम्बन्धी विनियम (regulations) निर्धारित किए गये।

११. संधियों का परित्याग (Repudiation of Treaties)

पिछले अध्याय में वर्णित कहानी से स्पष्ट है कि सारे ससार ने यह कितनी जल्दी अनुभव कर लिया कि नात्सी आति का अर्थ जर्मनी का पन्द्रह वर्षों तक पृष्ठभूमि में रहने के पश्चात् बड़े राष्ट्रों की 'पक्ति' में पुनः आ जाना था। मार्च १९३५ से प्रारम्भ होने वाली पन्द्रह महीनों की अल्प किन्तु नाटकीय अवधि में युद्धोत्तर इतिहास में अज्ञात पैमाने पर, अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का खुले आम उल्लंघन किया गया। शांति संधियों के जिन उपबन्धों को अभी तक अमान्य किया गया था वे या तो आपसी समझौते द्वारा या मौन स्वीकृति से, अथवा अप्रकट उल्लंघन (silent evasion) द्वारा अमान्य किए गये थे। जर्मनी की स्थिति अब इतनी सुदृढ़ थी कि वह संधियों को विधिवत् अस्वीकार करने (formal repudiation) का मार्ग अपना सकता था। उसने वर्सैलीज की आरोपित शांति (dictated peace) और स्वेच्छा से की गई शोकार्नों संधि को भी अस्वीकार किया। इसी बीच योरोप के एक और बड़े राष्ट्र ने बिना किसी बहाने (with an absence of excuse)—इस राष्ट्र की यह कार्रवाई १९३१ में जापान की सैनिक कार्रवाई से इस माने में ही भिन्न थी—राष्ट्र सभ के एक दूसरे सदस्य पर आक्रमण किया और उसके क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया, इस प्रकार शांति समझौते तथा उसके अगभूत अनुबंधपत्र पर दोनों ही क्षेत्रों से एक साथ घातक प्रहार किए गये। इन पन्द्रह महीनों में यह स्पष्ट हो गया कि सन् १९१९ के राजनीतिक पराजित राष्ट्र पर सम्बन्धित समय तक दांडिक निर्बंधन (penal restriction) लगाने और स्थिति को बनाए रखने (status quo) के लिए सामान्य कार्रवाई (common action) के आधार पर नई विश्व-व्यवस्था स्थापित करने के प्रति आवश्यकता से बहुत अधिक आशावान रहे थे।

जर्मनी द्वारा परित्याग (The German Repudiation)

वर्सैलीज संधि पर प्रहार करने से पहिले, हिटलर को एक महत्वपूर्ण प्रश्न

के समाधान की प्रतीक्षा करनी पड़ी। वसैलीज की संधि के अमल में आने के पन्द्रह वर्षों बाद, सार (Saar) के भाग्य का निर्णय जनमत द्वारा किया जाना था। पन्द्रह वर्षों की यह अवधि जनवरी, १९३५ में समाप्त हो गई। जनमत धारोति (duly) लिया गया। उसके समय व्यवस्था बनाए रखने और स्वतन्त्र मतदान की गारन्टी के लिए ब्रिटिश सेनापतित्व में एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना सम्बन्धित क्षेत्र में रखी गई थी। सार निवासियों को वापस जर्मनी में शामिल होने, या फ्रांस में मिलने, या राष्ट्रसंघ प्रशासन में ही रहने के प्रश्न पर अपना मन देना था। इस समय जो ५०० ००० मत पड़े उनमें ६० प्रतिशत जर्मनी के पक्ष में थे और ६ प्रतिशत में भी कम राष्ट्रसंघ प्रशासन में ही रहने के पक्ष में थे। पहिला मार्च को यह क्षेत्र जर्मनी को वापस लौटा दिया गया। अब जर्मनी की, जैसा कि हिटलर घनेक बार घोषित कर चुका था, पश्चिम में और अधिक क्षेत्रिक महत्वाकांक्षाएँ (territorial ambitions) नहीं थी। वसैलीज की संधि से भी जर्मनी को अब और कोई आशा नहीं थी।

फरवरी ३ प्रारम्भ में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी मन्त्री लन्दन में एकत्रित हुये और उन्होंने जर्मन सरकार तथा अन्य सम्बन्धित सरकारों की जानकारी (information) के लिए एक नीति-वक्तव्य (statement of policy) प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह आशा प्रकट की कि जर्मन सरकार प्रस्तावित पूर्वी और मध्य योरोपीय समझौते (Eastern and Central European Pacts—में सहयोग देगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह सुझाव भी रखा था कि लोकार्नो संधि के अतिरिक्त एक वायुसेना समझौता (Air Pact) भी किया जाये जिसके अन्तर्गत लोकार्नो राष्ट्र यह वचन दें कि उनमें से किसी पर भी यदि हवाई हमला किया गया तो वे अपनी वायुसेना द्वारा उसकी सहायता करेंगे। इस सुझाव की प्रमुख विशेषता यह थी कि ग्रेट ब्रिटेन न कबल एक गारन्टोदाता (guarantor) के रूप में सामने आता—जैसा कि वह लोकार्नो संधि में इस रूप में सामने आया था—परंतु जर्मनी के हवाई हमले के विरुद्ध फ्रांस और बेल्जियम की गारन्टी मिल जाती तथा फ्रांस और बेल्जियम व विरुद्ध जर्मनी को।

जर्मन सरकार ने वायुसेना समझौते का स्वागत किया और अपने को वचन-बद्ध न करते हुए (non committally) यह आश्वासन दिया कि वह अन्य

प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा यह सुझाव रखा कि सारी बातों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ सम्मेलन का आयोजन किया जाये। फ्रांसीसी सरकार को कुछ आश्चर्यान्वित करते हुए, ब्रिटिश सरकार ने यह सुझाव मान लिया तथा विदेश मन्त्री साइमन (Simon) और राष्ट्रसंघ-मामलों के मन्त्री (Minister for League of Nations Affairs) ईडन ने बर्लिन आने का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया किन्तु भेंट होने से पहिले ही बहुत सी घटनाएँ घट गईं। संसद (Parliament) के सामने अपने पुनर्शास्त्रीकरण कार्यक्रम के स्पष्टीकरण के लिए ब्रिटिश सरकार को एक स्मरणपत्र प्रकाशित करना पड़ा। इस स्मरणपत्र (memorandum) में अन्य किसी भी कारण की चर्चा नहीं करते हुए, इस बात पर जोर दिया गया था कि जर्मनी के शास्त्रीकरण से खतरा पैदा हो गया है। इस आक्षेप के प्रति जर्मनी में बहुत अधिक रोष प्रकट किया गया। कुछ अवस्थ होने का बहाना बनाकर हिटलर ने ब्रिटिश मंत्रियों की भेंट की तारीख रद्द कर दी। इसी समय फ्रांस की प्रतिनिधि सभा में भी फ्रांस की सेना में वृद्धि करने का प्रश्न पर विचार किया जा रहा था। हिटलर ने नाटकीय प्रति-प्रहार (dramatic counter-stroke) करने का निश्चय किया। मार्च १६, १९३५ को उसने यह घोषणा की कि जर्मनी अब वर्सेलीज संधि की सैनिक धाराओं से अपने को बद्ध नहीं मानता तथा भविष्य में जर्मनी की शान्तिकालीन सैन्य सख्या छत्तीस डिवीजन या ५५०,००० सैनिक रहेगी एवं इतने सैनिकों की पूर्ति अनिवार्य भर्ती (conscription) द्वारा की जाएगी।

इस घोषणा से फ्रांस में काफी व्याकुलता फैल गई। ग्रेट ब्रिटेन में, लोकमत बहुत पहिले से ही इस बात पर जोर देता रहा था कि जर्मनी के पुनर्शास्त्रीकरण को निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता का अवश्यभाव (inevitable) परिणाम बताना संपूर्ण सत्य नहीं है। हिटलर ने अब साइमन और ईडन को फिर निमन्त्रण दिया। हिटलर के उक्त निश्चय से फ्रांसीसी, इटालियन और सोवियत क्षेत्रों में जो चिन्ता उत्पन्न हो गई थी, वह इसलिए कुछ कुछ कम हो सकी थी कि ईडन वारसा (Warsaw), मास्को और प्रैग (Prague) की भी यात्रा करने वाले थे। मार्च १५ को बर्लिन-भेंट यथा समय हुई। किन्तु उसके व्यावहारिक परिणाम बहुत ही कम हुए। हिटलर ने वायुसेना सम्झौते के स्वागत की

बात पुनः दोहराई और पूर्वी एव, कुछ कम मात्रा में मध्य योरोप समझौते के प्रति अपनी अनिच्छा प्रकट की। उसने अपने शांतिपूर्ण इरादों (pacific intention) की पुनः पुष्टि की। जर्मन सेना की संख्या अपरिवर्तनीय रूप से (irrevocably) निश्चित कर दी गई। किन्तु उसने यह सुझाव रखा कि यल-सेना के मामले में जर्मनी अन्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया गया कोई भी सामग्री-सीमन (limitation of material) स्वीकार कर लेगा। वायुसेना के मामले में, उसने फ्रांस के साथ बराबरी का दावा किया, यद्यपि सोवियत वायु-सेना में दीर्घ वृद्धि की देखते हुए, जर्मनी को अपने इस दावे पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हो सकना सम्भव था। नौसेना के बारे में, जर्मनी को यह स्वीकार था कि ब्रिटिश नौसेना के ३५ प्रतिशत के बराबर सभी प्रकार के जहाज उसे रखने दिए जाएँ।

इसी बीच, जर्मनी की कार्रवाई पर विचार करने के लिए, फ्रांस ने अप्रैल में राष्ट्रसंघ परिषद् का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की थी। इस अधिवेशन की तैयारी के रूप में, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इटालियन राजनीतिज्ञ स्ट्रेसा (Stresa) में एकत्रित हुए। स्ट्रेसा सम्मेलन ने प्रस्तावित पूर्वी और मध्य योरोप समझौतों सबधी अपने अनुमोदन की पुनः पुष्टि की। उसने इस बात पर भी अनिर्णायक चर्चा (inconclusive discussion) की कि छोटे-छोटे भूतपूर्व शत्रु-राष्ट्रों (lesser ex-enemy states) को पुनर्गठनीकरण की विधिवत् अनुमति (permission) दी जाए अथवा नहीं। इटली (मोंस्ट्रिया और हंगरी द्वारा उकसाए जाने के कारण) इस कदम के पक्ष में था जबकि फ्रांस (लघु मैनोसच देशों की प्रेरणा पाकर) उसके विरोध में था। किन्तु इस सम्मेलन का प्रमुख कार्य राष्ट्रसंघ परिषद् में प्रस्तुत किए जाने वाले एक ऐसे प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करना था जिसमें वर्सेलीज संधि के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों को अस्वीकार करने के कारण जर्मनी की निन्दा की गई थी। तीनों राष्ट्रों ने यह प्रस्ताव परिषद् में यथाविधि रखा और वह निर्विरोध स्वीकृत भी हो गया। मतदान के समय अनुपस्थित रहकर केवल डेन्मार्क ने यह अभिव्यक्त किया कि जर्मनी के आरोपकों (accusers) के साथ जो कुछ हुआ है, उसका दोष जर्मनी के सिर पर भी है। प्रस्ताव केवल धोस (empty gesture) ही था क्योंकि उसके बाद न तो कोई कार्रवाई की गई और न कोई कार्रवाई किए जाने का इरादा ही था। किन्तु

उससे जर्मनी में बहुत रोप फैला। विशेषकर जर्मनी को इस बात पर आश्चर्य था कि जिस ग्रेट ब्रिटेन ने अपने विदेशमन्त्री को बर्लिन भेजकर जर्मनी को कार्रवाई को क्षमा कर दिया प्रतीत होता था वही अब जेनेवा में बिना शर्त भरसना प्रस्ताव (unqualified vote of censure) रखने में अग्रग्रा बना हुआ था।

किंतु अभी तो और भी आश्चर्यजनक बात होनी शेष थी। राष्ट्रसंघ परिषद्-मुद्रिकल से ही विसर्जित हुई होगी कि बर्लिन को यह सूचना भेजी गई कि ब्रिटिश सरकार हिटलर का यह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार है कि सभी प्रकार के जहाजों के रूप में जर्मनी की नौसैनिक शक्ति ब्रिटेन की शक्ति का ३५ प्रतिशत रहे और इस आधार पर किए जाने वाले किसी भी समझौते का ब्रिटिश सरकार स्वागत करेगी। जर्मन प्रतिनिधि यथासमय लंदन आए और जून में एक आंग्ल-जर्मन नौ-सैनिक समझौते (Anglo-German naval agreement) पर हस्ताक्षर हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने वर्सेल्लोज संधि के नि.गस्त्री करण सबंधी उपबन्धों को अमान्य करने के कारण, जर्मनी की कड़े शब्दों में निन्दा करने के बाद, अब स्पष्ट रूप से यह मान लिया जर्मनी को संधि द्वारा लगाए गए नौसैनिक निर्बंधनों (naval restrictions) को अवहेलना (ब्रिटिश शक्ति के ३५ प्रतिशत तक) करने और कुछ ऐसे प्रकार के जहाजों को रखने जिनमें पनडुब्बियाँ—जिनका संधि में बिल्कुल निषेध कर दिया गया था—भी शामिल थी, का अधिकार है। यह समझौता ब्रिटिश सामान्य बुद्धि (common sense) की एक खूबी प्रणीत होती थी। क्योंकि जहाँ एक ओर फ्रांस ने किसी भी प्रकार का समझौता करने से इन्कार कर जर्मनी को थल-सेना का असिमित पुनर्शास्त्रीकरण (unlimited rearmament on land) करने के लिए उत्साहित किया था, वही दूसरी ओर ग्रेट ब्रिटेन ने समझौता करने की तत्परता दिखाकर, जर्मन नौसैनिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण सीमन करा लिया था। किन्तु पहिले जो कुछ हो चुका था, उससे यह समझौता इतना असंगत (inconsistent) मालूम पड़ता था कि फ्रांस, इटली और सोवियत संघ में उससे इतनी हैरानी (bewilderment) हुई जितनी ब्रिटेन द्वारा जेनेवा प्रस्ताव का अग्रग्रा बनने के समय भी जर्मनी में नहीं हुई थी।

सन् १९३५ के प्रथम छः महीनों में जर्मनी के प्रति ब्रिटिश नीति इतनी हलचल (vacillating) रही थी कि उसकी आलोचना होना अनिवार्य था। इसका कारण यह प्रतीत होना है कि दो विरोधी नीतियाँ (conflicting

policies) पर एक साथ चला जा रहा था। नात्सी क्रांति के बाद प्रथम दो वर्षों में, कुल मिलाकर (on the whole) नात्सी अतिथियों (excesses) का ब्रिटिश लोकमत पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि जर्मनी की शिकायतों और महत्वाकांक्षाओं के प्रति उसकी सहानुभूति नहीं रह गई थी। ब्रिटिश सरकार, यद्यपि किसी प्रकार के वचन (commitments) देने के लिए तैयार नहीं थी, तदपि उसने फ्रांसीसी, इटालियन और सोवियत सरकारों को पूर्वस्थिति—विशेषकर मध्य योरोप में जहाँ कि उसे सबसे अधिक सीधा खतरा प्रतीत होना था—बनाए रखने के लिए प्रतिरक्षात्मक गुटबद्धियाँ (defensive alliances) करने के उनका प्रयत्न को प्रोत्साहित किया था। किन्तु जनवरी १९३५ तक, जबकि फ्रांस और इटली में पुनर्मेलो (reconciliation) से ये गुटबद्धियाँ लगभग पूरी हो चुकी थी, तब नात्सी शासन के निरुद्ध रोप ग्रेट ब्रिटेन में कम होने लगा। अधिकांश लोकमत इसी दृष्टिकोण का समर्थक हो गया था कि इटली और सोवियत संघ के साथ फ्रांस के समझौते का केवल यही परिणाम हुआ था कि जर्मनी अकेला (isolated) पड़ गया था और चारों तरफ से घिर गया था (encircled) तथा वसैलीज संधि में समाविष्ट असमानताएँ यथावत् बनी हुई थी—संक्षेप में, वे ही परिस्थितियाँ भविष्य में भी बनी रहे जो कि नात्सी क्रांति के लिए अधिकांशतः जिम्मेदार थी। जिन लोगों का यह मत था, वे इस बात से तो इन्कार नहीं करते थे कि जर्मनी किसी दिन शांति के लिए खतरा हो सकता है किन्तु उनका यह विश्वास था कि फ्रांसीसी, इटालियन और सोवियत नीति उस खतरे को केवल बढ़ा ही रही हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार का प्रथम लक्ष्य जर्मनी के चारों तरफ ढाले गए घेरे (ring) को तोड़ना, जर्मनी की शिकायतों पर मित्रतापूर्ण चर्चा करना तथा उसे पुनः राष्ट्रसंघ में ले आना होना चाहिये। साइमन की बर्लिन यात्रा इस विचारधारा के लोगों के मत को स्वीकार कर लेना ही था। किन्तु दूसरा मत, अर्थात् जर्मन खतरे का सामना करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपनाया जाने वाला सही भाग उन राष्ट्रों को हर सम्भव सहायता देना है जिन्हें जर्मनी से खतरा प्रतीत होता है, अब भी अनेक क्षेत्रों में दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित किया जाता था। स्ट्रेसो और जेनेवा में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडलों के रक्त में इस मत की ही प्रधानता रही। उसके बाद माँग जर्मनी नौसैनिक समझौता होने पर जर्मनी से समझौता कर लेने की नीति पुनः शीर्षपरि (uppermost) हो गई। इस कारण ब्रिटेन की नीति में जो अनिश्चितता पाई

उसने फ्रांस और उसके साथियों को ब्रिटिश इरादों के प्रति बहुत अधिक सदेहशील (suspicious) बना दिया तथा जर्मनी को ब्रिटिश नीति पुनः बदल जाने की आशा करने के लिए प्रोत्साहित किया किन्तु इस नीति में यह उलट फेर हुआ ही नहीं ।

इटली द्वारा परित्याग

(The Italian Repudiation)

सन्धन संधि के अन्तर्गत इटली के दावों का जो अन्तिम समाधान निकाला गया था, उससे इटली की औपनिवेशिक मत्स्वाकाक्षाएँ अब भी पूरी नहीं हुई थी । ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस से अब और अधिक आशा नहीं की जा सकती थी । किन्तु मुसोलिनी कुछ समय से इस समाधान पर विचार कर रहा था कि इटली स्वयं ही अपनी सहायता कर सकता है अथवा नहीं । उसने फ्रांस की ईर्ष्या और विरोध पर ही अभी तक हमेशा भरोसा किया था । यह सत्य जान पड़ता है कि जर्मनी को प्रोत्साहित करने और उसकी सहायता करने की इतालियन नीति का प्राथमिक कारण इटली की यह इच्छा रही हो कि फ्रांस यूरोप में ही इतनी चिन्ताओं में पड़ा रहे कि वह अन्य स्थानों में इटली की योजनाओं में बाधक न हो सके । किन्तु घटनाओं ने दूसरा ही रूप धारण कर लिया । सन् १९३५ के प्रारम्भ में, फ्रांस को यूरोप में इटली की मित्रता की इतनी आवश्यकता थी कि वह अफ्रीका में इटली को कोई भी सुविधा देने के लिए तैयार था । मुसोलिनी ने शीघ्र ही अवसर का लाभ उठाया और रोम में के समय उसने अबीसीनिया में अग्रगामी इतालियन नीति (forward Italian policy) (जिसका विस्तार सम्भवतः इस समय ठीक-ठीक निश्चित नहीं किया गया था) के प्रति लावल की मौन सम्मति (acquiescence) प्राप्त कर ली ।

अबीसीनिया का चुनाव कई कारणों से किया गया था । लिबेरिया (Liberia) को छोड़, अबीसीनिया ही अफ्रीका में स्वतन्त्र देशों राज्य (native state) के रूप में बचा था । वह सोमालिलैंड और इरिट्रिया (Eritrea) नामक वर्तमान इतालियन उपनिवेशों के बीच में स्थित था । उसके बारे में यह विख्यात था कि उसके अन्तर्प्रदेश में, जिसका विकास अभी तक नहीं किया गया था, खनिज सम्पत्ति (mineral wealth) विद्यमान है । इसके अतिरिक्त वहाँ एक ऐसी घटना इटली के आक्रमण से पूर्व घट गई, जो इटली की

योजनापूर्ण उत्तेजना के कारण सम्भवतः घटी हो या इटली का उससे कोई सम्बन्ध न भी रहा हो—जिसके कारण इटली को अबीसीनिया में कार्रवाई करने का एक बहाना मिल गया। दिसम्बर १९३४ में, वालवाल (Walwal) ग्राम के निकट अबीसीनियन सैनिक टुकड़ी और इतालियन सोमालिलैंड के एक सैन्य-दल में घुटमेड हो गई। इस मामूली मिश्रित (skirmish) में कुछ इटलीवासियों की मृत्यु हो गई। इस पर इटली की सरकार ने अबीसीनिया से समा-याचना (apology) और क्षतिपूर्ति के रूप में भारी रकम की मांग की। अबीसीनिया ने राष्ट्रसंघ से अपील की और यह अनुरोध किया कि अनुबन्धपत्र के ग्यारहवें अनुच्छेद के अधीन यह मामला परिषद् की कार्यसूची में शामिल किया जाये।

अनुबन्धपत्र और पेरिस समझौते (Pact of Paris) के अतिरिक्त दो ऐसी सन्धियाँ थी जिनके कारण इटली युद्धसम कार्रवाई (warlike action) नहीं कर सकता था। सन् १९०६ में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने एक समझौता किया था जिसके अनुसार उन्होंने यह घोषित किया था कि “अबीसीनिया की अखंडता को अखंड (intact) बनाए रखने” (“maintain intact the integrity of Abyssinia”) में उनका सामान्य हित है। इटली ने भी १९२८ में अबीसीनिया से एक सन्धि की थी जिसके अनुसार दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे को यह वचन दिया कि ये “सदा शांति और मित्रता” (“constant peace and perpetual friendship”) बनाए रखेंगे तथा अपने सभी विवादों को “समझौते और पञ्चनिर्णय द्वारा” (“procedure of conciliation and arbitration”) सुलझाएँगे। सन् १९१३ में जब अबीसीनिया को राष्ट्रसंघ का एक सदस्य बनाया गया था, तब इटली अबीसीनिया को प्रवेश दिलाने वाले प्रमुख समर्थकों में से एक था। अतएव, जब जनवरी १९३५ में परिषद् के सामने अबीसीनिया की अपील आई, तब इटली के प्रतिनिधि ने अनुबन्धपत्र के ग्यारहवें अनुच्छेद के अधीन वालवाल घटना पर विचार किए जाने को अनावश्यक बताया क्योंकि उनकी राय में, “इस घटना से दोनों देशों के शांतिपूर्ण-सम्बन्धों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की आशा नहीं थी”। इसके साथ ही उसने इस बात की भी इच्छा प्रकट की कि १९२८ की संधि के अधीन वह समझौते और पञ्चनिर्णय द्वारा इस समस्या का

समाधान निकालने के लिए तैयार है। परिषद् ने इस आश्वासन पर आगे किसी समय विचार के लिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया।

अगले तीन माह तक, इटालियन सरकार ने पंचो (arbitrators) की नियुक्ति में विलंब किया। इसी अवधि में इरिट्रिया और इटालियन सोमालिलैंड स्थित इटालियन सैनिक टुकड़ियों के लिए इटली से सैनिक और युद्ध-सामग्री की जो कुमुक भेजी गई, उससे यह प्रतीत होता था कि गम्भीर सैनिक कार्रवाई की जाने वाली है। तीन सप्ताह बाद स्ट्रेसो में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इटालियन मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ। किन्तु अफ्रीका की स्थिति गम्भीर होती हुए भी, किसी भी प्रतिनिधि ने उसको और सकेत तक नहीं किया। सम्मेलन द्वारा जो "अन्तिम घोषणा" की गई थी उसमें कहा गया था कि "यूरोप की शान्ति को खतरा उपस्थित करने वाले सन्धियों के किसी भी एक पक्षीय अस्वीकरण (unilateral repudiation) का यह सम्मेलन विरोध करता है। जहाँ तक मुसोलिनी का सम्बन्ध है, प्रथम दो शब्दों का जोड़ा जाना मुश्किल से अप्रसंगिक (accidental) था। यूरोप के ही मामलों में उलझे होने के कारण ब्रिटिश प्रतिनिधि अरुचिकर (unwelcome) अबीसीनियन समस्या का उल्लेख कर निश्चय ही असामंजसपूर्ण दान नहीं करना चाहते थे। किन्तु इटली द्वारा खुले आम युद्ध की तैयारियों पर उनके मौन का मुसोलिनी ने यह अर्थ लगाया कि फ्रांस की भाँति ग्रेट ब्रिटेन भी उसकी अफ्रीकी कार्रवाई के प्रति उदारतापूर्ण (benevolent) या कम से कम उदासीनतापूर्ण (indifferent) रुख अपना कर सतोष कर लेना चाहता है।

स्ट्रेसो सम्मेलन के बाद हुए राष्ट्रसंघ परिषद् के अधिवेशन में भी अबीसीनिया की अपील पर इसलिए विचार नहीं किया जा सका कि इटली सरकार ने यह आश्वासन फिर दिया कि बालबाल घटना के सबंध में पचनिर्यय कराने के लिए वह तैयार है। इस बार सबभूच ही पंचो की नियुक्ति की गई। अन्ततः, सितंबर ३ को, पंच एकमत निष्कर्ष (unanimous conclusion) पर पहुँचे। उनका निष्कर्ष यह था कि बालबाल घटना के लिए किसी भी सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सच पूछा जाए तो यह घटना गभीर महत्त्व (intrinsic importance) की नहीं थी। भारी सख्या में इटालियन सेना इकट्ठी करने का बहाना प्रस्तुत कर उसने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया था और अब उसे एक ओर रखा जा सकता था।

इसी बीच, वास्तविक समस्या अर्थात् अबीसीनिया को इटली से सैनिक खतरा (military threat) पर विचार करने लिए प्रयत्न किए गये थे। जून १९३५ में, ईडन रोम गए और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि ग्रेट ब्रिटेन अबीसीनिया को ब्रिटिश सोमालिलैण्ड में स्थित जीला बन्दरगाह (port of Zeila) दे और उसके बदल में अबीसीनिया ओगडेन (Ogaden) का अपना दक्षिणी प्रांत इटली को दे। मुसोलिनी ने इस प्रस्ताव को दो कारणों से अस्वीकार कर दिया। एक तो यह कि इटली को सौंपा जाने वाला क्षेत्र एक दम अपर्याप्त है और दूसरे अबीसीनिया को समुद्र तक पहुँच का मार्ग मिल जाने से अबीसीनिया की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। अगस्त में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के प्रतिनिधि १६०६ के समझौते से संबंधित पक्षों की हैसियत से पेरिस में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन का परिणाम फ्रांस-ब्रिटेन का यह प्रस्ताव था कि अबीसीनिया के “भौतिक विकास और प्रशासनिक पुनर्संगठन (administrative reorganisation) में सहायता का अनुरोध राष्ट्रसंघ से करने के लिए अबीसीनिया से कहा जाए तथा इस प्रकार की सहायता पहुँचाते समय, राष्ट्रसंघ “इटली के विशेष हितों” का “विशेष रूप” से ध्यान रखे। इस प्रस्ताव को भी इटालियन सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए जब ४ सितम्बर को—बालवाल पक्ष द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किए जाने के दूसरे दिन—प्राक्सिर् जब राष्ट्रसंघ परिषद् न १६ मार्च की अबीसीनिया की अपील पर विचार करना प्रारम्भ किया, तब मामला इतना बड़ चुका था कि जेनेवा में होने वाली किसी भी कार्रवाई का इस समस्या पर प्रभाव नहीं पड़ सकता था। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री सर सेम्युअल होर (Sir Samuel Hoare) ने राष्ट्रसंघ-सभा में यह प्रस्तावित एवं जोरदार घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार अनुबध्पत्र के अधीन अपने कर्तव्यों को कार्यान्वित करने (to carry out) का विचार रखती है। परिषद् की एक समिति ने अबीसीनिया की “सहायता-योजना” (“scheme of assistance”) तथा इटली और अबीसीनिया के बीच “क्षेत्रिक पुन. समायोजन (territorial readjustments) सम्बन्धी योजनाएं तैयार की जिन्हें परिषद् ने बाद में स्वीकार भी कर लिया। किन्तु अक्टूबर २ को इटली का अबीसीनिया पर आक्रमण प्रारम्भ होगया।

राष्ट्रसंघ-सभा में ब्रिटिश विदेशमन्त्री ने जो भाषण दिया था, और जेनेवा में छोटे-छोटे राज्यों तथा ग्रेट ब्रिटेन के लोकमत ने उसका जो उत्साहपूर्ण

स्वागत (enthusiastic reception) किया, उससे यह स्पष्ट हो चुका था कि मुसोलिनी का यह भाषा करना गलत था कि राष्ट्रसंघ प्रक्रियाशील (quiescent) रहेगा। अबीसीनिया के मामले में युद्ध (hostilities) प्रारम्भ होते ही भीमतापूर्वक परिषद् द्वारा की गई कार्रवाई व उससे पहिले वास्तविक समस्या को टालने के उसके प्रयत्नों और मंचरिया के मामले में जापान के विरुद्ध विपरीत निर्णय (adverse verdict) देने की परिषद् की अनिच्छा (reluctance) में कितना अन्तर था। अक्टूबर ७ को, परिषद् की एक समिति ने एक प्रतिवेदन तैयार किया, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि इटली ने 'अनुबंधपत्र के बारहवें अनुच्छेद के अधीन अपने अनुबंधनों (covenants) की अवहेलना करते हुए युद्ध का आश्रय लिया है।' दूसरे दिन परिषद् के सदस्यों ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया, केवल इटली ने ही उसका विरोध किया। दो दिनों के बाद, राष्ट्रसंघ सभा ने अनुच्छेद सोलह के अधीन सदस्यों की अपने कर्तव्यों का पुनः स्मरण कराते हुए, उनसे यह सिफारिश की कि उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में साम्प्रक्त लाने के लिए वे एक समिति गठित करें। अक्टूबर १६ तक साम्प्रक्त समिति (co-ordinating committee) ने राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों से यह अनुरोध किया कि वे (१) अपने-अपने देशों से सभी प्रकार के ऋण या साख (loans or credits) इटली को देना बन्द कर दें, (२) हर प्रकार की युद्ध सामग्री और युद्ध प्रयोजनों (war purposes) के लिए विशेष रूप से आवश्यक कुछ वस्तुओं के इटली को निर्यात किए जाने पर रोक (embargo) लगा दें, तथा (३) इटली से आयातों (imports) पर भी रोक लगावें। ऑस्ट्रिया, हंगरी और भलबानिया को छोड़ राष्ट्रसंघ के सभी योरोपीय सदस्यों तथा कुछ भ्रमहत्वपूर्ण अपवादों (insignificant exceptions) को छोड़, राष्ट्रसंघ के गैर योरोपीय सदस्यों ने इन कदमों का अनुमोदन किया था। फ्रांस बड़ी विचित्र स्थिति में था कि उसे अपने ऐसे नए साथी के विरुद्ध अनुशास्त्रियाँ लगानी पड़ी थी जिसे उसने एक वर्ष से भी कम समय पहिले अपना मित्र बनाया था। किन्तु उसने इतने अधिक समय तक राष्ट्रसंघ के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की थी और सोलहवें अनुच्छेद को वास्तविक बनाने की इतनी इच्छा व्यक्त की थी कि वह अब इन कदमों का विरोध नहीं कर सकता था।

नवम्बर १८, १९३५ को, राष्ट्रसंघ के इतिहास में पहिले बार अनुशास्त्रियाँ—

यद्यपि उनका स्वरूप केवल आर्थिक था और वे भी पूर्णरूपेण नहीं लगाई गई थी—लागू हो गई ।

जैसी कि आशा की गई थी, उसके विपरीत युद्ध के प्रथम तीन मास इटली के लिए इतने अशुभ नहीं रहे । इटली की सेनाएँ अबीसीनिया में दूर तक प्रवेश कर गईं और ब्रम्बरपक वायुयानों की सहायता से, हर स्थान पर अबीसीनिया का मुकाबला करती रही । किन्तु मुख्य अबीसीनियन सेना का कुछ भी नहीं बिगड़ा । सैनिक विशेषज्ञों को इसमें संदेह ही था कि इरिट्रिया और इटालियन सोमालिलैंड को घेर से आगे बढ़ने वाली दोनों ही इटालियन सैनिक टुकड़ियाँ अबीसीनिया को एक मात्र रेलवे [एडिस अबाबा (Addis Ababa) से समुद्र तट (coast) तक की रेलवे लाइन] तक पून में वर्षाकृत प्रारम्भ होने से पहले पहुँच कर मिल सकेंगी ।

दिसम्बर में फ्रांस को यह आश्वासन हो गई कि यदि इटली अबीसीनिया में असफल हुआ तो मध्य योरोप की स्थिति पर उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है । ब्रिटिश सरकार को सम्भवतः यही मय था । वह तो यहाँ तक डरती थी कि निराशा की स्थिति में, कहीं मुसोलिनी ग्रेट ब्रिटेन पर आक्रमण न कर बैठे, क्योंकि अनुशास्त्रियों लगवाने में ग्रेट ब्रिटेन का ही प्रमुख हाथ था । होर लावल से मिलने के लिए पेरिस गये । इटली और अबीसीनिया की सरकारों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने शांति की शर्तें तैयार की । उनका प्रमुख उद्देश्य यह था कि शांति की शर्तें इतनी आकर्षक हो कि मुसोलिनी युद्ध बन्द करने के लिए तैयार हो जाए । यह प्रस्तावित (proposed) किया गया था कि इटालियन सेनाओं ने अभी तक जितने अबीसीनियन क्षेत्र पर आक्रमण किया था, उससे भी काफी अधिक क्षेत्र इटली को दिया जाये । इसपर अबीसीनिया को यह प्रलोभन दिया गया कि उसे ब्रिटिश सोमालिलैंड में समुद्रतक गलियारा दिया जाएगा । ये प्रस्ताव जब प्रकाश में आए तब ग्रेट ब्रिटेन में बहुत रोष फैल गया । लोकमत का यह विश्वास था कि इस योजना का उद्देश्य सकटपूर्ण स्थिति से ससम्मान छुटकारा पा जाने में इटली की सहायता करना है । और ग्रेट ब्रिटेन का लोकमत यह अनुभव करता था कि राष्ट्रसंघ के सदस्य के नेता ग्रेट ब्रिटेन का यह कर्तव्य नहीं है कि वह एक आक्रमणकर्त्ता राष्ट्र को अपने आक्रमण का लाभ उठाने में सहायता पहुँचाये । और वे त्यागपत्र दे दिया ; और उसके स्थान में ईदन मन्त्री

हुये। इस घटना के बाद होर-सावाल योजना की धीर कोई चर्चा सुनाई नहीं पड़ी।

मार्च १९३६ से पहिले तक अबीसीनिया में इटली का धीर भी तीव्र गति से आगे बढ़ना स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं हुआ था। अप्रैल की समाप्ति में पहिले इरिट्रियन सेना रेलवे और राजधानी के बिल्कुल समीप आ गई। आन्तरिक व्यवस्था (internal order) भंग हो गई और पहिली मई को अबीसीनिया के सम्राट (Emperor) देश छोड़कर भाग गये। उनके पलायन (flight) से संगठित मुकाबिले (organised resistance) का अंत हो गया। कुछ ही दिनों के बाद एडिस अबाबा पर इटालियन सेनाओं ने अधिकार कर लिया। मई की नवी तारीख को इटली के नायक को सम्राट घोषित कर दिया गया और सारे अबीसीनिया को इटली में सरकारी तौर पर (officially) मिला लिया गया।

इटली की विजय राष्ट्रसंघ के लिए गंभीर आघात तथा ग्रेट ब्रिटेन के लिए बड़ी उत्कण्ठ का विषय थी। अनुशास्तियों के कारण यद्यपि इटली का व्यापार ठप्प हो चुका था और उनका कुप्रभाव उसकी स्वर्ण संचिति (gold reserve) पर पड़ा था, तदपि उसे इतनी क्षति नहीं पहुँची थी कि इटली की सैनिक कार्रवाई में किसी प्रकार की रुकावट आये। अब यह स्पष्ट था कि इटली युद्ध के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से अपने शिकार को नहीं छोड़ेगा। फ्रांस के समान ग्रेट ब्रिटेन भी अपने इस निश्चय पर दृढ़ था कि इटली से युद्ध मोल नहीं दिया जाये। जुलाई में राष्ट्रसंघ सभा का जो विशेष अधिवेशन हुआ, उसमें ब्रिटिश सरकार ने यह प्रस्ताव रखा कि अनुशास्तियाँ हटा ली जाएँ। सम्राट की व्यक्तिगत अपील के बावजूद भी, यह प्रस्ताव निर्विरोध स्वीकृत हो गया। सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर राष्ट्रसंघ के सदस्यों से यह अनुरोध किया कि सभा के अगले अधिवेशन में वे इस बात पर अपने विचार प्रस्तुत करें कि “अनु-बध्न के सिद्धान्तों को लागू करने (application of the principles) के तरीके में सुधार” के लिए सर्वोत्तम उपाय कौन से हो सकते हैं।

लोकान्तों का अंत (The End of Locorno)

इटली के प्रति अन्य बड़े राष्ट्रों के दबबू रखा (pusillanimous attitude) का आंशिक कारण यह था कि अबीसीनिया युद्ध की अंतिम अवस्थाओं के समय ही जर्मनी ने एक और अस्वीकरण कर दिया। मई १९३५ में

किए गए फ्रांस-सोवियत समझौते को जर्मनी प्रारम्भ से ही केवल उसके विरुद्ध की गई सैनिक शुटबंदी, तथा इस कारण लोकानों सन्धि से असंगत (incompatible) मानता था—फ्रांसीसी और ब्रिटिश सरकारों का यह मत नहीं था। जर्मनी ने इसका और भी जोरों से विरोध किया। सन् १९३६ के प्रारम्भ में, जब यह समझौता अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया गया, तब हिटलर ने पुनः साहसपूर्ण प्रति प्रहार (counter-stroke) करने का निश्चय किया।

वर्सेलीज की सन्धि के अनुसार जर्मनी राइनभूमि में न तो सशस्त्र सेना रख सकता था और न ही किलेबंदी कर सकता था। लोकानों सन्धि के समय, हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने “सामूहिक रूप से और पृथक् रूप से” (“collectively and severally”) इस बात की गारंटी दी थी कि इन उपबन्धों का पालन किया जाएगा। मार्च १९३६ में, हिटलर ने दायरित (dictated) वर्सेलीज सन्धि को अस्वीकार किया था, किन्तु स्वेच्छापूर्वक की गई लोकानों सन्धि के प्रति पुनः अपनी निष्ठा घोषित की थी। ७ मई १९३६ को, जर्मन सरकार ने ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियम सरकारों को सूचित किया कि चूंकि फ्रांस ने फ्रांस-सोवियत समझौते के अन्तर्गत ऐसे कर्त्तव्य स्वीकार कर लिए हैं, जोकि लोकानों सन्धि के अन्तर्गत फ्रांस द्वारा स्वीकार किए गए कर्त्तव्यों से असंगत हैं, इसलिए वह सन्धि “आंतरिक अर्थ” (“inner meaning”) से रहित हो चुकी है। इस कारण जर्मनी इस सन्धि से अपने आपको अब बाध्य नहीं मानता और उसी दिन जर्मन सेनाएं राइनभूमि पर पुनः अधिकार कर रही हैं। जिस ज्ञापन (memorandum) में यह सूचना दी गई थी, उसमें अनेक प्रस्ताव भी थे। जर्मनी ने यह प्रस्तावित किया कि वह सीमान्त के दोनो ओर समान दूरी तक एक नया असेनीकृत क्षेत्र स्थापित करने, (चूंकि यह सर्वविदित था कि फ्रांस और बेल्जियम अपने क्षेत्र के किसी भी भाग को असेनीकृत करने के लिए तैयार नहीं हैं, जर्मनी का यह प्रस्ताव प्रस्ताव न होकर, विवाद का विषय (debating point) ही था, लोकानों सन्धि के ढंग का एक ऐसा नया समझौता करने, जिसमें राइनभूमि सम्बन्धी धाराएं न हों; अपने पूर्व के पड़ोसी देशों (और जैसा कि हिटलर ने बाद में घोषित किया, प्रॉस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया से भी) से अनाक्रमण समझौते करने, तथा राष्ट्रसंघ में पुनः शामिल होने के लिए राजी है।

फ्रांस में यद्यपि आशका व्यक्त की गई, तदपि अनुशास्त्रियाँ लगाने या बदला लेने (sanctions or reprisals) के लिए कोई गंभीर प्रस्ताव नहीं रखे गए। स्वेच्छापूर्वक की गई एक सन्धि को इस प्रकार अस्वीकार कर देने से ब्रिटिश लोकमत (public opinion) को बड़ा दुःख हुआ किन्तु, कुल मिलाकर वह हिटलर के पिछले कृत्यों (past actions) की भर्त्सना करने की अपेक्षा भविष्य में हिटलर द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावों पर विचार करना ही अधिक पसंद करता था। ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियम सरकारों में मार्च में वार्ताएँ चली। राष्ट्रसंघ परिषद् ने, जिसका अधिवेशन लंदन में विशेष रूप से बुलाया गया था, यह निर्णय दिया कि जर्मनी ने “असेनीकृत क्षेत्रों में सेना को प्रविष्ट कराकर तथा वहाँ उन्हें स्थायी रूप से रखकर” वर्सलोज संधि का उल्लंघन किया है। फ्रांस और बेल्जियम का मय दूर करने के लिए, ब्रिटिश सरकार इस बात पर राजी हो गई कि यदि फ्रांस और बेल्जियम पर जर्मनी ने आक्रमण किया, तो क्या कदम उठाए जाएँ। इस विषय की चर्चा सेनापति सहायकगण (General Staffs) चलाये। जर्मनी और फ्रांस ने “शांति योजनाएँ” (“peace plans”) बनाई। किन्तु ये दोनों ही दस्तावेज इतने अस्पष्ट और विस्तृत (comprehensive) थे कि उनका व्यावहारिक महत्त्व बहुत ही कम था। फ्रांसीसी सरकार से परामर्श करने के बाद, मई के प्रारम्भ में, ब्रिटिश सरकार ने एक प्रश्नावली (questionnaire) जर्मनी के पास इस आशा से भेजी कि जर्मनी के प्रस्तावों का और भी स्पष्टीकरण प्राप्त हो सके। हिटलर ने इस प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया। समस्त प्रश्नावली की भाषा ने उसे अप्रसन्न कर दिया हो। पूरे ग्रीष्म भर, राजनैतिक जगत अभीसीनिया पतन में उलझा रहा और लोकान्तर्गत वार्ताओं की ओर उसका ध्यान नहीं गया। सितंबर में, जब इन वार्ताओं को पुनः प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया गया, तब कठिनाइयाँ अजेय (insuperable) प्रतीत हुई। जर्मनी इस बात के लिए तो तैयार था कि पश्चिम के लिए नया गारन्टी समझौता किया जाये। किन्तु वह सोवियत संघ से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता था। बिना किसी प्रकार के पूर्वोपसमझौते के पश्चिमी समझौता फ्रांस को अस्वीकार्य (unacceptable) था।

इसी बीच एक नई परेधानी पैदा होगई। अधिकांश अन्य छोटे छोटे राष्ट्रों की भाँति, सामूहिक सुरक्षा (collective security) की असफलता और

जर्मनी की शक्ति में बुद्धि का बेल्जियम पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे यह अनुभव हुआ कि फ्रांस-बेल्जियम गुटबन्दी और लोकानों संधि के अन्तर्गत उसने जो बचन (commitments) दिए हैं, वे संरक्षण (safeguard) के बजाय खतरे ही अधिक सिद्ध हो सकते हैं, विशेषकर उस स्थिति में जबकि फ्रांस-सोवियत समझौते के परिणामस्वरूप फ्रांस जर्मनी के साथ किसी लड़ाई में उलझ जाएगा। अक्टूबर १४, १९३६ को उसको और से एक घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया था कि भविष्य में बेल्जियम केवल बेल्जियन नीति पर ही चलेगा और किसी गुटबन्दी में शामिल नहीं होगा तथा अपने पड़ोसियों के विवादों के संबंध में, स्विटजरलैंड और हालैंड की भाँति, पूर्ण तटस्थता (complete neutrality) पूर्ण रूप से अपनाएगा। इस प्रकार अपने पुराने रूप में लोकानों के नवकरण (renewal) की अब सम्भावना नहीं रह गई थी। बेल्जियम गारंटियाँ प्राप्त करने के लिए तो तैयार था, किन्तु अब स्वयं किसी प्रकार की गारंटियाँ नहीं देना चाहता था। नवम्बर में, डेन ने यह स्पष्ट घोषणा की कि “यदि बेल्जियम पर अकारण आक्रमण किया गया तो वह हमारी सहायता पर भरोसा कर सकता है।” और कुछ दिन पश्चात् इसी प्रकार का विश्वास उसने फ्रांस को भी दिलाया। फ्रांसीसी विदेशमन्त्री ने इसका उत्तर प्रतिनिधि सभा में यह घोषणा कर दिया कि, ऐसी ही परिस्थितियों में, फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन या बेल्जियम को सहायता करेगा। इन घोषणाओं को उस पश्चिमी समझौते के अभाव की पूरक माना जा सकता है जो अब अस्तित्व में नहीं आ सकता था।

१२. गैर-यूरोपीय संसार (The Non-European World)

सन् १९३६ के अन्त तक यह स्पष्ट हो चुका था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो व्यापक समझौता सादा गया था, उसका अब कोई स्वीकृत आधार (accepted basis) नहीं रह गया था। अब हमें यह विचार करना है कि संधियों का परित्याग किए जाने के बाद किस प्रकार की आश्चर्यकारक कार्रवाई द्वारा उस व्यवस्था को उलट देने के प्रयत्न किए गए जो संधियों द्वारा स्थापित करने की कोशिश की गई थी। किन्तु चूंकि अपने विषय की लगभग हर अन्य पुस्तक की भांति यह पुस्तक भी असमान अनुपात में यूरोपीय मामलों का ही विवेचन करती प्रतीत होती है, इसलिए समवतः इस अध्याय से इस कमी की पूर्ति होने में सहायता मिले। इस अध्याय के बाद हम अपने मुख्य विषय पर पुनः विचार करेंगे। क्योंकि अन्य किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व यूरोप के ही हाथों में, भले या बुरे के लिए, रहा है। यहाँ जिन कुछ देशों का विवेचन किया जायगा, उनका इन पृष्ठों में अभी तक उल्लेख मात्र ही किया गया है। जिन अन्य देशों का विस्तृत विवेचन पहले ही किया जा चुका है उनके सम्बन्ध में केवल इतना ही आवश्यक होगा कि उनकी कहानी को भी अप्रामाणिक (up-to-date) बना लिया जाये।

मध्य पूर्व (The Middle East)

पूर्वीय भूमध्यसागर (Eastern Mediterranean) से लेकर भारत के उत्तर पश्चिम सीमा तक देशों का जो जाल फैल हुआ है तथा जिन्हें सुविधा की दृष्टि से “मध्य पूर्व” कहा जाता है, वे सन् १९१९ के बाद, अविरोध उथल-पुथल (constant effervescence) तथा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के केन्द्र बन गये। इन देशों में से टर्की ने जानबूझकर इस्लाम धर्म और परम्परा का त्याग कर दिया तथा मुस्लिम जगत से अपना संबंध तोड़कर मध्य पूर्वी और एशियाई राष्ट्र (Asiatic Power) होने की अपेक्षा निचट पूर्वी और यूरोपीय

राष्ट्र होने की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करली। ईरान जिसके पास पूर्वी गोलार्ध (hemisphere) में सबसे अधिक तैल खदानें थी, अपने प्रभावशाली (masterful) शाह रिजा खाँ (Riza Khan)—जिसने १९२५ में तख्त पर जबदस्ती अधिकार कर लिया था—के शासन में समृद्धिशाली हो रहा था। प्राकृतिक संपदा से शून्य (devoid of natural wealth) तथा मोबियत



मध्य पूर्व

मध्य एशिया और ब्रिटिश भारत के बीच स्थित अफगानिस्तान कुछ अनिश्चित स्वतन्त्रता (precarious independence) का उपभोग करता चला आ रहा था, किन्तु १९३४ में उसे राष्ट्रसंघ में प्रवेश मिल जाने से उसकी स्वतन्त्रता, निम्नो, अकार, सुख होगई।

मध्य पूर्व के अन्य देश तुर्की साम्राज्य के वे मृतपूर्व अरब प्रान्त थे जिनके भाग्य का विवेचन पहिले ही किया जा चुका है। इन सभी देशों में, अरब राष्ट्रवाद (nationalism) ही, दोनों विश्व युद्धों के बीच के वर्षों की, प्रमुख समस्या थी।¹ प्रमुख अरब क्षेत्रों का ब्रिटिश और फ्रांसीसी संरक्षित-राज्यों में विभाजन हो जाने से उन अरब नेताओं को बड़ी निराशा हुई जो कि एक संयुक्त अरब राजतन्त्र (United Arab Kingdom) स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे। इस निराशा को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ प्रयत्न किया। हज्जाज (Hedjaz) के शासक हुसैन का एक लड़का ईराक का शासक होगया और दूसरा ट्रांसजोर्डानिया (Transjordan) का अमीर (Emir)। किंतु समस्या इसलिए जटिल हो कि विभिन्न अरब लोगों में परम्परा तथा विकास (tradition and development) का बहुत बड़ा अन्तर था। उनमें सम्य शहरवासियों में लेकर प्रादिमजातीय खानाबदोश (primitive nomads) भी पाए जाते थे। इसलिए अरब राजनैतिक एकता (political unity) इस समय भी एक स्वप्न ही थी। किंतु अरब राष्ट्रवाद, जिसे युद्धकाल में मित्रराष्ट्रों ने टर्कों को पराजित करने की दृष्टि से जानबूझकर बढ़ावा दिया था, के कारण युद्ध के बाद अनेक अवसरों पर अरब लोगों का सघर्ष संरक्षक राष्ट्रों और अरब जनता के बीच रहने वाले गैर अरब अल्पसंख्यकों (non-Arab minorities) से हो जाया करता था।²

ब्रिटेन के संरक्षण (mandated territory) के प्रथम राज्य—ईराक—की स्थिति प्रारम्भ से ही विषम (anomalous) थी। उस पर संरक्षण अधिकार विधिवत् कभी भी प्रदान नहीं किया गया था। किन्तु उसके स्थान में ग्रेट ब्रिटेन और ईराक में एक सन्धि हुई थी—राष्ट्रसंघ ने इसका अनुमोदन किया था—जिसके अनुसार ग्रेट ब्रिटेन ने ईराक को यह बचन दिया था कि वह उसे

1, "In all these countries Arab nationalism was the principle problem of the years between the wars"

2 "But Arab nationalism, deliberately fostered by the Allies during the war for the discomfiture of the Turk, on many occasions after the war brought the Arab peoples into conflict both with the Mandatory Powers and with non-Arab minorities living in their midst"

“आवश्यक सलाह और सहायता... उसके (ईराक के) राष्ट्रीय संप्रभुता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ही (without prejudice to national sovereignty)” देगा। ग्रेट ब्रिटेन के लिए ईराक की महत्ता कुछ भू-शो में उसके समृद्ध तेल कुण्डों (rich oil wells) और किसी सीमा तक योरोप तथा भारत के बीच सीधे वायु पथ (air route) पर ईराक की अनुकूल स्थिति (favourable position) के कारण थी। जो भी हो, अधिकांश ब्रिटिश लोकमन, इस बात के विरुद्ध था कि एशिया के एक लगभग भू-वेष्टित (land-locked) क्षेत्र पर अनिश्चित काल तक ब्रिटेन का शासन जारी रहे। ईराक को उस समय की प्रतीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जबकि वह, अनुबंध-पत्र (Covenant) के शब्दों में, “अपने पैरों पर स्वयं खड़ा (able to stand alone)” हो सकेगा। यह घड़ी १९३२ में आई। उस समय संरक्षण-शासन समाप्त कर दिया गया, ईराक ने ग्रेट ब्रिटेन से पञ्चवीस वर्षों के लिए मैत्री संधि (treaty of alliance) कर ली तथा वह राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया। उसकी स्वतन्त्रता से जो समस्याएँ उठ खड़ी हुईं, उनमें सबसे कठिन समस्या उसके गैर-अरब अल्पसंख्यकों की थी जिनमें कुर्द और असीरियन (Kurds and Assyrians) सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। दुर्भाग्य से, ईराक में राष्ट्रसंघ में प्रविष्ट होने के एक वर्ष के भीतर ही, असीरियनों में उत्पन्न (disturbances) हुए जिनके परिणामस्वरूप ईराकी सैनिक टुकड़ियों ने पाँच सौ असीरियनों को मौत के घाट उतार दिया। स्वतन्त्र राष्ट्रों के परिवार में शामिल हुए इस नए सदस्य—ईराक ही राष्ट्रसंघ का प्रथम अरब सदस्य था—की सतत स्थिरता (continued stability) अनुभवही ब्रिटिश सलाहकारों, जो कि प्रशासन कार्यों में ईराकी सरकार की सहायता करते रहे, को पूर्ववत् ईराकी सरकार की सेवा में रखे रहने पर काफी हद तक निर्भर करती प्रतीत होती थी।

एशिया में ब्रिटेन का दूसरा सखारख-क्षेत्र भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से, जोर्डन नदी (River Jordan) द्वारा विभाजित था। पैलेस्टाइन (Palestine) इस नदी के पश्चिम में था तो ट्रांसजोर्डानिया (Transjordan) इसके पूर्व में। ट्रांसजोर्डानिया शुद्ध अरब राज्य था। उसका अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास केवल इतना ही था कि अपने पड़ोसियों के साथ कभी-कभी उसके सीमांत

विवाद हो जाया करते थे। इसके विपरीत, पेलेस्टाइन की समस्या अन्य किसी भी सरक्षित राज्य की समस्या से अधिक गम्भीर थी।

पेलेस्टाइन में सरक्षण-राज्य करने की शर्तों (जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा १९१७ में यहूदियों को दिए गए एक वचन की पूर्ति (fulfilment) थी, के अनुसार सरक्षक राष्ट्र का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया था कि वह, "उस देश को ऐसी राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति में रखे कि यहूदियों ॥ लिए मातृभूमि (national home) स्थापित करना संभव हो सके तथा इसके साथ ही साथ पेलेस्टाइन के सभी निवासियों के नागरिक (civil) और धार्मिक अधिकार (rights) सुरक्षित रहे।"^१ यदि युद्धकाल में मित्रराष्ट्र सरकारों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए धरबो की महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया होता, तो भी इस कर्तव्य को पूरा करना कठिन हो सकता था। किन्तु यहूदियों को दिए गए वचन और धरबो को दिए गए अस्पष्ट आश्वासन (vague undertaking) (जिसमें गलती से या उचित रूप से ही पेलेस्टाइन को भी शामिल मान लिया गया था) में परस्पर विरोध (contradiction) ने भविष्य के लिए गम्भीर आपत्ति खड़ी कर दी। सन् १९१६ में पेलेस्टाइन की आबादी लगभग बिलकुल धरब थी तथा उसकी जनसंख्या ७००,००० से कुछ ही कम अनुमानित की गई थी। सरक्षण-शासन की स्थापना से पेलेस्टाइन विश्व के यहूदियों का राष्ट्रीय गतिविधि-केन्द्र बन गया तथा यहूदी आप्रवासन (immigration) के लिये उसके द्वार खुल गये। यहूदियों का आगमन (influx), जो प्रथम वर्षों में तुलनात्मक दृष्टि से कम था, योरोप में आर्थिक संकट के प्रारम्भ होने के समय तेजीसे बढ़ गया किन्तु नात्सी क्रांति के बाद जब जर्मनी से यहूदियों की भगदड़ (exodus) शुरू हुई, तब तो उसमें और भी वृद्धि हो गई। सन् १९३४ के अन्त तक, पेलेस्टाइन में यहूदियों की संख्या ३००,००० तक पहुँच गई थी और यदि अधिकारों (authorities) आप्रवासन को कठोरतापूर्वक सीमित नहीं करते, तो यह संख्या और भी अधिक

1. "place the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the jewish national home while at the same time safeguarding the civil and religious rights of all the inhabitants of Palestine."

बढ़ जाती। यहूदी आप्रवासी (immigrants) एक पिछड़ी हुई पूर्वोप (Oriental) भूमि में पारचात्य सभ्यता अपने साथ लाये। जमीरी नौवू (citrus-fruit) की खेती आधुनिक रीति से सगठित एक उभ्रतिशील (flourishing) बड़ा उद्योग होगया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि पेलैस्टाइन मध्य पूर्व का बाणिज्य केन्द्र बन जाएगा। यहूदी नगर तेल-अबीब (Tel-Aviv) का निर्माण और हैफा (Haifa) बन्दरगाह का विकास आधुनिक सत्तार के आश्चर्य बन गये। आर्थिक संकट की पूरी अवधि में पेलैस्टाइन ही केवल एक ऐसा देश था, जिसका घरेलू और विदेशी व्यापार दिन-दूना रात-चौपुना बढ़ा।

समृद्धि की इस लहर में गैर यहूदी जनता ने भी लाभ उठाया। सन् १९१६ और १९३४ के बीच उसकी सख्या बढ़कर ६००,००० होगई। इस कारण यहूदियों और गैर-यहूदियों का अनुपात इस समय भी एक और तीन का था। किन्तु प्रबल किसान, जो कि अशिक्षित, अमिनव्ययी और पूँजीहीन (improvident and devoid of capital) था, यहूदी की बराबरी नहीं कर सकता था। इस कारण अपने ही देश में वह गयकर हीनता (galling inferiority) की स्थिति में आ गया। सन् १९२१, १९२९ और १९३६ में छोटी-छोटी घटनाओं के अतिरिक्त शातिनाशक गंभीर उपद्रव भी हुए जिनमें सैकड़ों व्यक्तियों के प्राण गये। इस घटनाओं के समय हर बार प्रबल लोग यहूदियों पर पहिले आक्रमण करते थे और उसके बाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए रखी गई ब्रिटिश पुलिस तथा सेना पर। इन उपद्रवों के बारे में सर्वाधिक गंभीर तथ्य यह होता था कि उनकी जड़ में, यहूदी आप्रवासन के कारण प्रबल हितों पर आ पड़ी प्रासंगिक कठिनाइयाँ (incidental hardships) नहीं होती थी बल्कि पेलैस्टाइन की यहूदियों की मातृभूमि बनाने के सिद्धान्त का ही विरोध उनके मूल में छुपा करता था।

सन् १९३६ के अन्त में एक शाही प्रयोग (Royal Commission) की नियुक्ति अरबों द्वारा उपद्रव प्रारम्भ किए जाने के कारणों का पता लगाने और सिफारिशें करने के लिए की गई। जुलाई १९३७ में इस आयोग का जो प्रति-वेदन प्रकाशित हुआ, उसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि पेलैस्टाइन का त्रिपक्षीय विभाजन (tripartite division) किया जाये। प्रस्ताव के अनुसार

धार्मिक स्थान (holy places) स्थायी रूप से ब्रिटेन के अधिकार में रहने थे, गेलिली (Galilee) तथा समुद्रतटीय मैदानों (coastal plains) को मिलाकर यहूदी संप्रभुतासम्पन्न राज्य (sovereign state) का निर्माण किया जाना था, तथा शेष भाग अरब राज्य ट्रांसजोर्डानिया में मिला दिया जाना था। (Mandates Commission)—इस योजना को सभी ने मान्यता दी तथा राष्ट्रसंघ के संरक्षण-राज्य आयोग—जिसे यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था—ने भी इसे नापसंद किया। इसी बीच उपद्रव होते रहे। न केवल यहूदियों और ब्रिटिश लोगों की ही अपितु उन अरबों की भी हत्याएं की गईं, जिन्हें समझौते के पक्ष में समझा गया। इस योजना की व्यावहारिकता (practicability) पर विचार करने के लिए एक और आयोग की नियुक्ति की गई। किन्तु १९३८ के दौरान में इस आयोग ने विभाजन का इतना निश्चित विरोध किया था कि इस योजना को ही स्थाप देना पड़ा और लन्दन में एक सम्मेलन बुलाया गया। प्रतिनिधि यहूदियों और अरबों को ब्रिटिश सरकार के सामने अपना मामला पुष्कल रूप से रखने के लिए आमंत्रित किया गया। ब्रिटिश सरकार के सामने अपना मामला रखने के बाद, यदि संभव दिखाई देता, तो एक संयुक्त सभा (joint assembly) में समाधान निकालने का प्रयत्न किया जाना था। किन्तु कोई समझौता नहीं हो सका और ब्रिटिश सरकार ने अपना ही हल लागू करने का निश्चय किया। इस हल से, जिसमें कि यह व्यवस्था की गई थी कि पाँच वर्षों तक केवल १०,००० तक यहूदी आग्रासी प्रतिवर्ष पेलेस्टाइन आ सकते हैं, समझौते की नींव पड़ी। इस बीच, और भी अधिक कठोर सैनिक नियंत्रण के कारण पुनः व्यवस्था स्थापित करने में सफलता मिल चुकी थी। और कुछ हद तक सामान्य मुस्लिम जगत् सबुष्ट हो चुका था। उनके लिए पेलेस्टाइन अरब पित्रभूमि (father land) का एक आवश्यक भाग था। किन्तु फिर भी, पश्चिमी जगत् के कई लोग और विशेषकर प्रोटेस्टेंट धर्मानुयायी अंग्रेजी भाषी राष्ट्रों (Protestant English-speaking nations) के कुछ लोग, जो प्राचीन और अर्वाचीन बाइबिल के इतिहास से तो परिचित थे, किन्तु पॉन्टियस पाइलेट (Pontius Pilate) के बाद के एशिया माइनर के घटनाचक्र के बारे में कम जानकारी रखते थे, का भी इतना ही विश्वास था कि पेलेस्टाइन पर वास्तव में यहूदियों का ही अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यहूदी जाति को जिस भयकरता से अधिकाधिक सताया जा रहा था,

उसै देखते हुए उसके लिए कोई आश्रय स्थान (place of refuge) होना एक अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता थी ।

फ्रांस के संरक्षण-शासन का क्षेत्र संरक्षण के समय से ही दो भागों में विभाजित था । ये दो भाग सीरिया (Syria) और लेबनान (Lebanon) थे । लेबनान में, जो कि सीरिया और पेलेस्टाइन की सीमा पर एक समुद्रतटीय प्रदेश है, अरब ईसाई (Arab Christians) लोग बहुसंख्यक थे । इस क्षेत्र में एक प्रकार की गणतन्त्रीय सरकार थी जो कि समय-समय पर संरक्षक राष्ट्र के हस्तक्षेप की सहायता से अपना कार्य करती रही । लेबनानी ईसाई (Lebanese Christians) जो अपने धर्म के कारण अरब राष्ट्रीय आंदोलन में अलग पड़ गए थे, छोटी-मोटी शिकायतों के होते हुए भी फ्रांसीसी संरक्षण ॥ प्राप्त संरक्षण से संतुष्ट प्रतीत होते थे ।

इसके विपरीत, सीरिया में अरब राष्ट्रीयतावाद उतना ही प्रबल था जितना ईराक और पेलेस्टाइन में । ईराक में ब्रिटिश ने अल्पसंख्यकों की क्षति बढ़ाते हुए एकीकृत राज्य (unified state) की स्थापना की थी । सीरिया में, फ्रांस ने इससे उलटी नीति अपनाई और सीरिया से उन तीन क्षेत्रों को वृथक् कर दिया जिनमें मुख्यतः गैर-अरब बसते थे । उनमें से दो क्षेत्रों—समुद्र-तटीय लतकिया (Latakia) और दक्षिण का जेबेल ड्रूज़ क्षेत्र (Jebel Druse territory) को फ्रांसीसियों के सीधे ही प्रशासन में रखा गया था । तीसरा क्षेत्र—उत्तर में अलेक्जेंड्रेट्टा (Alexandretta) का तुर्की जिला—सीरियन सरकार के नाममात्र क प्रभुत्व (suzerainty) के अधीन एक स्वायत्तशासी प्रांत हो गया । अपनी सामान्य भूमध्यसागरीय नीति के अंग के रूप में जून १९३६ में, फ्रांस ने एक समझौता किया, जिसके अनुसार इस जिले का अधिकांश भाग—अलेक्जेंड्रेट्टा का सैंडजाक (Sandjak)—तुर्की का इस शर्त पर सौंप दिया गया कि तुर्की लोग सीरिया पर अपने अन्य सभी दावों का परित्याग (abandon) कर देंगे तथा उस देश में प्रचार नहीं करेंगे । विच्छेदन (dismemberment) की इस नीति के प्रति सीरियन अरबों ने गंभीर रोष प्रकट किया । समय-समय पर गंभीर विद्रोह भी होते रहे जिनमें प्रमुख १९२५ का विद्रोह था, जबकि फ्रांसीसी सैनिक दमस्कस (Damascus) पर हमला वर्षों को । सन् १९३३ के बाद से तो सीरियन संविधान को बिल्कुल ही

स्थगित (suspended) कर दिया गया था। सन् १९३६ में सीरियन नेताओं और फ्रांसीसी सरकार में नए सिरे से वार्ताएँ चली जिनके परिणामस्वरूप नवंबर में आंग्ल-ईराकी संधि (Anglo-Iraqi Treaty) के ढग की एक संधि हुई। इस संधि के अनुसमर्थन (ratification) के बाद, फ्रांस के समर्थनपूर्वक सीरिया द्वारा राष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिए आवेदन किया जाना था। किन्तु अनुसमर्थन में इतना विलम्ब होगया कि १९३६ के प्रारम्भ में इसका राष्ट्रीय उत्थापन हुए और उच्च आयुक्त (High Commissioner) ने सीरियन संसद को विघटित कर दिया तथा कार्यकारिणी शक्ति (executive power) पाँच सचालकों की एक परिषद् (Council of Directors) के हाथों में सौंप दी—सैनिक प्रतिरक्षा (military defence) का नियंत्रण फ्रांस से ही किया जाना था।

अरेबिया में, इस अवधि की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना इब्न सऊद (Ibn Saud) का उदय (rise) थी, जो कि पहिले नेज्द का सुल्तान (Sultan of Nejd) था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इब्न सऊद ने तुर्की के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की सहायता की थी और मित्र राष्ट्र उसे आर्थिक सहायता (subsidy) देते थे। शांति सम्झौते में उसे मान्यता नहीं दी गई थी। किन्तु खानाबदोश आबादी (nomadic populations) तथा अस्पष्ट सीमान्तो (undefined frontiers) के इस प्रदेश में उसने अपने राज्य का विस्तार धीरे धीरे अतिक्रमण (encroachment) कर तथा कठोर शासन द्वारा किया। सन् १९२६ में हदजाज (Hedjaz) के शाह हुसैन को पराजित कर और उसे निकाल बाहर कर, उसने उसके क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिला लिया तथा अपने आपको हदजाज एव नेज्द का शाह घोषित कर दिया। आगे चलकर सारे देश का नाम बदल कर साउदी अरेबिया (Saudi Arabia) रख दिया गया। स्पष्ट ही है कि इब्न सऊद ने अपने को एक शक्तिशाली स्वतन्त्र अरब शासक माने जाने का दावा सुस्थिर कर लिया था। साउदी अरेबिया ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिए आवेदन नहीं किया किन्तु १९३६ में ईराक ट्रांसजोर्डानिया और मिस्र से संधियाँ कर अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली। अरब ऐक्य (solidarity) के इन प्रदर्शनों का आशिक कारण अरबीसीनिया में इटली की सफलता के बाद इटली की महत्वाकांक्षाओं से भय था। इसी परिस्थिति के कारण ग्रेट ब्रिटेन और अरब राज्यों के संबंध और भी मित्रतापूर्ण होगये।

मिस्र की गणना यद्यपि "मध्य पूर्व" में नहीं की जाती है, तदपि अरबी-भाषी (Arab-speaking) देशों के इस सलिप्त विवेचन में उसका भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। स्वेज नहर के निर्माण से ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिक भ्रष्टो (British Imperial communications) की दृष्टि से मिस्र का एक महत्त्वपूर्ण स्थान होगया। युद्ध से पहिले तीस वर्षों तक मिस्र-मध्यपि नाम के लिए वह टर्कों के प्रभुत्व में था—ब्रिटेन के अधिकार में था। दिसम्बर १९१४ में जब टर्कों युद्ध में सम्मिलित हुया, तब तुर्की सम्प्रभुता समाप्त कर दिया और ब्रिटिश रक्षित राज्य (protectorate) की घोषणा कर दी गई। युद्ध के बाद राष्ट्रीय भावमोलन की प्रचड़ता के कारण रक्षित राज्य कायम रहना कठिन होगया। मिस्र के राष्ट्रीय नेताओं से समझौता करने की निष्पक्ष चेष्टा के बाद, १९२२ में ग्रेट ब्रिटेन ने एक घोषणा जारी कर मिस्र की स्वतन्त्रता को मान्यता दी। किन्तु देश की प्रतिरक्षा विदेशियों और मध्यसह्यको का सरक्षण अपने हाथों में रखा तथा सूडान पर ग्रेट ब्रिटेन एवं मिस्र का संयुक्त सार्वभौमत्व (joint sovereignty) स्थापित कर दिया गया। इस घोषणा के बाद, उसने विदेशी राष्ट्रों को पत्रों द्वारा यह सूचित किया कि मिस्र के मामलों में यदि किसी भी विदेशी राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया तो ग्रेट ब्रिटेन उसे अपनी ही सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा।

इस घोषणा से जो विषम (anomalous) स्थिति उत्पन्न हुई, वह दोनों ही पक्षों के लिए उत्तमपूर्ण (full of embarrasment) थी। अनेक बार यह प्रयत्न किया गया कि एक सन्धि कर इस स्थिति को विनियमित कर लिया जाये। किन्तु ये प्रयत्न १९३६ से पहिले तब तक सफल नहीं हो सके जब तक अयोसीनिया में इटली की सफलता ने ग्रेट ब्रिटेन और मिस्र दोनों ही में अपने आपसी सम्बन्धों को सुधारने की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं कर दी। अगस्त १९३६ में हस्ताक्षरित सन्धि के अधीन ग्रेट ब्रिटेन ने यह वचन दिया कि कुछ शर्तों पर वह मिस्र के अन्तर्प्रदेश (interior) से अपनी सैनिक दुकडियाँ हटा लेगा और उन्हें केवल नहर क्षेत्र (Canal Zone) में ही सीमित रखेगा। विमोक्ष (Capitulation) अर्थात् प्रमुख विदेशी राष्ट्रों के निवासियों द्वारा मिस्र में उपभोग किये जाने वाले क्षेत्रीय अधिकारों (extra-territorial rights) का अन्त करने में मिस्र की सहायता करेगा; राष्ट्रसंघ की सदस्यता

के लिये मिस्र के दावे का समर्थन करेगा; तथा सूडान के प्रशासन में मिस्री (Egyptian) अधिकारियों को भी शामिल करेगा।

ये वचन उस समय पूरे हो गये, जबकि ८ मई १९३७ को माट्रेक्स (Montreux) में हुए एक सम्मेलन में मिस्र में हित रखने वाले राष्ट्रों ने विमोक (Capitulation) के अधीन अपने अधिकार त्याग दिए तथा २६ मई को एक सार्वभौम राज्य (sovereign state) की हैसियत से मिस्र को राष्ट्र-संघ का सदस्य बना लिया गया। सन् १९३८ में ग्रेट ब्रिटेन के साथ उन ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों की स्थिति के बारे में एक समझौता किया गया जो पिछले समझौते के अधीन स्वेज नहर की रक्षा के लिए रखी गई थी। मिस्र अपनी स्वतन्त्र स्थिति की रक्षा करते हुए भी ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहा।

सुदूर पूर्व (The Far East)

मार्च १९३३ में जापान के राष्ट्रसंघ से हट जाने के कारण सुदूर पूर्व में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि तनाव (tension) बढ़ता ही गया। जापान ने अपनी मंचूरिया-विजय को शीघ्र ही सूरद बना दिया पूर्वी एशिया के प्रमुख राष्ट्र (dominant power) की अपनी स्थिति बना ली। जापानी विदेश विभाग (Japanese Foreign Office) ने अप्रैल १९३४ में समाचार पत्रों को एक वक्तव्य प्रकाशित करने को दिया, उसमें जापान की प्रथम महत्वपूर्ण नीति-घोषणा (declaration of policy) का समावेश था। इस वक्तव्य में, "पूर्वी एशिया में (जापान की) विशेष जिम्मेदारियों" ("special responsibilities in East Asia") का उल्लेख करने के बाद यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था कि "चीन के अतिरिक्त ऐसा कोई भी देश नहीं है जो पूर्वी एशिया में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी का जापान के साथ दावा कर सके।" तथा विदेशी राष्ट्रों द्वारा चीन की सहायता पहुँचाने सम्बन्धी पृथक् अथवा संयुक्त (singly or jointly) कार्रवाई पर भी जापान को "भारति" है। इन भारतियों का सम्बन्ध "प्राविधि अथवा वित्तीय (technical or financial) सहायता (जैसी कि राष्ट्रसंघ ने चीन को हाल ही में देना स्वीकार किया था) के नाम पर" की जाने वाली कार्रवाई तथा युद्ध-सामग्री भेजने या अनुदेशकों या सलाहकारों (instructors or advisers) की सेवाएं उधार

देने के रूप में दी जाने वाली सैनिक सहायता से भी था। इस धोखा को धो "जापान के मुनरो सिद्धांत" ("Monroe Doctrine") के नाम से विख्यात हुई, अनेक परवर्ती अवसरों (subsequent occasions) पर दोहराया गया। सन् १९३५ के शीघ्र में शेष चीन ॥ उसके अनेक उत्तरी प्रान्तों को घुस कर देने के लिए किया गया। एक प्रयत्न चीनियों के सत्याग्रह के सामने विफल हो गया। किन्तु मंचूरिया के समीप के चीनी क्षेत्र में, जापानी सैनिक अधिकारियों को पूर्वी होई स्वायत्तशासी सरकार (East Hopei Autonomous Government) नामक एक कठपुतली सरकार (puppet administration) की स्थापना में सफलता मिल गई। इसके प्रतिरिक्त आगे चलकर उन्होंने चीनी कुँगी अधिकारियों के कार्य में जानबूझकर हस्तक्षेप किया तथा इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में से चोरी से माल लाने-लेजाने वालों को काफी प्रोत्साहित किया। अनुचित लाभ को जापानी व्यापारियों को जेबों में पहुँचाने और चीनी सरकार के मालों साधनों तथा प्रतिष्ठों को बर्बाद पहुँचाने के लिए यह एक बड़ी चतुराईपूर्ण धाल थी। सन् १९३६ में चीन के अनेक भागों में की गई जापानियों की छुटपुट हत्याएँ (sporadic murders) इस बात का प्रमाण थी कि जापानियों के प्रति कटु भावनाएँ उत्पन्न हो चुकी थी।

स्वयं चीन में, जापान के मज ने चीनियों की एकता के सूत्र में बाँधने का काम किया, यद्यपि उसके परिणाम आधा के विपरीत बहुत धीमे हुए तथा वे आंशिक (partial) थे। बारोडींग के चले जाने के काफी समय बाद भी मध्य चीन (Central China) में अनेक स्थानीय सौविधपूर्ण नान्किंग सरकार की पत्तली का बर्ब बनी रही तथा विस्तृत क्षेत्र (extensive areas) तथाकथित चीनी सौविध सरकार के नियन्त्रण में ही रहे। सन् १९३३ के बाद, इनमें से अनेक क्षेत्रों को नान्किंग सरकार ने पुनः अपने क्षेत्र में मिला लिया। उत्तर-पश्चिम चीन में सुसंगठित कम्युनिस्ट सेनाएँ अब भी विद्यमान थीं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रिक कम्युनिस्ट (Communist International) सङ्गठन की महासभा (congress) के १९३५ के अधिवेशन में निर्धारित की गई नीति के अनुसार, इन सेनाओं का लक्ष्य अब नान्किंग सरकार को उलटना नहीं था, बल्कि उत्तर चीन में जापान से मुकाबिले को सुदृढ़ बनाना तथा उसकी सहायता

करना था। दक्षिण चीन में, १९३६ के ग्रीष्म में नानकिंग सरकार के विरुद्ध एक सैनिक विद्रोह (military rebellion) हुआ किन्तु उसे कोई सहायता नहीं मिली। उसके परिणामस्वरूप केन्टन की अर्ध स्वतन्त्र (semi-independent) सरकार का दमन किया गया। हाल ही के इन वर्षों में नानकिंग और केन्टन के बीच सहयोग और किसी भी समय की अपेक्षा अधिक निकट जाना पड़ा। इस प्रकार १९३६ के अन्त में, नानकिंग स्थित चीनी सरकार—जिसे सेनापति च्यांग काई-शेक का योग्य नेतृत्व प्राप्त था—का मध्य और दक्षिण चीन में धीरे-धीरे अधिकार बढ़ होता गया तथा उत्तर चीन में जापान के विरुद्ध वह अपने प्रभाव को सुदृढ़ बनाए रही। दिसम्बर में उत्तर-पश्चिम सीमात पर अल्प-कालीन (short-lived) विद्रोह हुआ। विद्रोही सेना ने स्वयं च्यांग काई शेक को ही अनेक दिनों तक बंदी बनाए रखा। जो भी हो, च्यांग को बंदी बनाने वालों द्वारा समर्पण से च्यांग की स्थिति सुदृढ़ होगई और चीन एकता के रास्ते की ओर प्रगति होता दिखाई दिया। यह एकता जापान के आक्रमण के विरुद्ध हुई थी।

किन्तु जुलाई १९३७ में पेकिंग से कुछ निकट चीन और जापानी सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़ हो जाने के कारण और भी अधिक घटनाएँ घटित हो गईं तथा युद्ध की घोषणा किए बिना ही, युद्ध आरम्भ हो गया। पेकिंग खाली कर दिया गया (evacuated) और चीनी जो अब भी मुकाबिला कर रहे थे, धीरे-धीरे येलो नदी (Yellow River) तक खदेड़ दिए गए जबकि नौसेना और वायु सेना सघाई पर आक्रमण करती रही। इस वर्ष के अन्त तक जापानियों ने न केवल इस नगर पर अपितु राजधानी नानकिंग पर भी अधिकार कर लिया था। हवाई बमबाजी के कारण बचाव के साधनों से हीन जन-समुदाय का बंध ही अधिक हुआ और उसके साथ ही साथ, चाहे संयोग से हो या गलत उत्साह के कारण हो (by accident or mistaken zeal), चीन में ब्रिटिश राजदूत घायल हो गया तथा अपर यांगट्सी (Upper Yangtse) में एक अमरीकी और एक ब्रिटिश जहाज को क्षति पहुँची। किन्तु योरोप में कुछ ऐसा घटनाचक्र चल रहा था कि ग्रेट ब्रिटेन को कूटनीतिक विरोध तक ही अपना रोष सीमित रखना पड़ा। इस प्रकार अमेरिका ने जापान से क्षमा-याचना (apology) प्राप्त करके ही संतोष मान लिया। इसी बीच, राष्ट्रसंघ ने, जिसके

सामने तथ्य (facts) चीनी प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए थे, जापान की कार्रवाई को सन्धि-कृत व्यो का अन्याय्य भंग (unjustifiable breach) बताकर उसकी विधिवत् निन्दा की तथा अपने सदस्यों से इस बात पर विचार करने के लिए अनुरोध किया कि वे आक्रमण के शिकार (victim of aggression) राष्ट्र को किसी सीमा तक सहायता कर सकते हैं।

सामग्री और अनुशासन (equipment and discipline) में श्रेष्ठ होने ने कारण यद्यपि जापानी सेनाएं हर स्थान पर घाते बढ़ने में सफल हो सकी, तदपि चीनी उनका मुकाबिला बराबर करते रहे। सबसे पहिले हकाऊ—जो प्रत्यायी राजधानी बन चुका था तथा उसके अनुयायी नगर (satellite cities) जुलाई १९३८ में विजित कर लिए गए। प्रक्टूर में केन्टन पर भी प्रप्रत्याशित सरलतापूर्वक अधिकार कर लिया गया। धीरे-धीरे जापान ने सभी बदरगाहों पर अधिकार कर लिया और चीनी सेनाओं को उस रसद (supplies) पर निर्भर बना दिया, जो उन्हें भूमि के रास्ते सोवियत संघ से, या रेलमार्ग द्वारा फासीसी हिन्द-चीन (Indo-china) से या नवनिर्मित मोटर सड़क से बर्मा ■ ब्रिटिश साधनों द्वारा प्राप्त हो सकती थी। सन् १९३९ के अन्त तक, हिन्द-चीन रेलमार्ग को काट दिया गया। मोटर सड़क पर बहुत अधिक भार पड़ने लगा तथा सोवियत सहायता पर और अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता था। किन्तु चीन मुकाबिला करता ही रहा।

जहाँ तक सोवियत संघ का प्रश्न है, जापान द्वारा मन्चूओ (Manchu-kuo) विजय के कारण रूस में गंभीर आशंका (serious apprehension) फैल गई थी और सोवियत संघ ने इस कारण कई प्रति-उपाय (counter measures) किये थे। ये अनेक प्रकार के थे। सबसे पहिले तो, सोवियत सरकार ने अमरीकी सरकार द्वारा कूटनीतिक मान्यता प्राप्त करने की चेष्टा की और उसमें उसे सफलता भी मिल गई। दूसरे, उसने जापान को (या नाम के लिए, मन्चूओ को) मचूरिया से होकर जाने वाली चीनी पूर्वी रेलवे में रूसी हित (Russian interest) बेचकर संघर्ष (friction) के अवसरों में कमी करने का प्रयत्न किया। तीसरे, मध्य एशिया में उसने सोवियत प्रभाव बढ़ाया। चीन के बिल्कुल पश्चिम में स्थित सिंकिआंग (Sinkiang) प्रान्त या चीनी तुर्किस्तान (Chinese Turkistan), जिसमें अनेक मूल जातियों

की मिश्रित आबादी बसती है, बहुत समय से नानकिंग सरकार से लगभग स्वतन्त्र चला आ रहा था तथा वहाँ पर प्रतिद्वन्द्वी अधिकारियों (rival authorities) में समय-समय पर गृह युद्ध होते रहते थे। सन् १९३३ में सोवियत सेना और वायुयानों ने ऐसे ही एक स्थानीय संघर्ष (local struggle) में हस्तक्षेप किया तथा नानकिंग सरकार द्वारा मान्य स्थानीय चीनी राज्यपाल (Governor) को पुनः व्यवस्था तथा अपना शासन स्थापित करने में सहायता की। कुछ समय तक सिक्किम में, राजनैतिक तथा आर्थिक सोवियत प्रभाव सर्वोपरि (paramount) हो गया। मार्च १९३६ में बहिर् मंगोलिया (Outer Mongolia) — यद्यपि वह नाममात्र के लिए चीन के सार्वभौमत्व में था—जोकि वास्तव में १९२१ से एक सोवियत गणराज्य (Soviet Republic) रहा था, ने सोवियत संघ से एक मैत्री-संधि की, जिसके अनुसार हर पक्ष ने यह वचन दिया कि विदेशी आक्रमण के समय वह एक-दूसरे की सहायता करेगा। लगभग इसी समय स्टालिन ने एक भमरीकी पत्रकार को सूत्र रूप में यह जानकारी दी की यदि बहिर् मंगोलिया में, जापान ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया, तो उसका संघ सोवियत संघ से युद्ध लगाया जाएगा। इस प्रकार जापान द्वारा मंचूरिया में कायम की गई चौकियों (outposts) की ही तरह सोवियत संघ ने भी सिक्किम और बहिर् मंगोलिया में चौकियाँ कायम कर रखी थी, किन्तु उनके स्थानीय प्रशासनों में सोवियत नियन्त्रण इतना प्रत्यक्ष (direct) नहीं था, जितना कि मंचूकुओ में जापान का।

अमेरिका और विश्व राजनीति

(America And World Politics)

सन् १९३०-३३ के आर्थिक संकट के जितने विनाशकारी (disastrous) परिणाम अन्य देशों में हुए थे उतने अमेरिका में नहीं हुए थे। किंतु राज्य के कर्तव्य (functions of the state) सम्बन्धी वर्तमान धारण (conception) में और कहीं भी इतना प्रत्यक्ष एवं प्रतिकारी (direct and radical) परिवर्तन नहीं हुआ जितना कि अमेरिका में। संकट से पहले, अमेरिका ने लैसी फेरी (*laissez faire*) तथा निर्बन्धनहीन निजी व्यापार (unrestricted individual enterprise) के सिद्धान्तों का लगभग पूरी तरह—आयात निर्यात कर-संरक्षण (tariff protection) ही केवल

एक अपवाद था—यालन किया था। उद्योग और वाणिज्य में राज्य के हस्तक्षेप को अब भी अधिकांशतः अवांछनीय, अमरीकी परम्परा के विरुद्ध (undesirable un-American), और यहाँ तक कि अनैतिक (immoral) माना जाता था। संकट ने इस दृष्टिकोण को भ्रांति (fallacy) को उसके सच्चे स्वरूप में ला दिया। जब उद्योग और अर्थव्यवस्था का सारा ढाँचा ढहड़हाने लगा तथा अमरीकी जनसंख्या का दसवाँ हिस्सा बेकार (unemployed) हो गया, तब पूँजी और श्रम (capital and labour) दोनों ही मुक्ति के लिए राज्य का मुँह ताकने लगे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट का प्रशासन-कास नए मापदंड पर अमरीकी आर्थिक जीवन के पुनर्निर्माण के लिए किए गए लम्बे प्रयत्नों की एक कहानी है। स्थिति में जब पुनः सुधार होने लगा, तब प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ (forces of reaction) ने उस समय “नए कार्यक्रम” (“New Deal”) के नाम से विख्यात अमरीकी नीति के विरुद्ध सिर उठाने का प्रयत्न किया। अमरीकी संविधान द्वारा अमरीकी कांग्रेस को “विदेशों से तथा विभिन्न राज्यों के बीच वाणिज्य का विनियमन करने” (to regulate Commerce with foreign Nations and among the several States)” की शक्ति दी गई है। कुछ खींचतान करके ही इस व्यवस्था का यह अर्थ लगाया गया कि मूल्य नियन्त्रण (price-control) तथा श्रम स्थिति निर्धारण (fixing of labour conditions) जैसे विषय भी इसी व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं। उद्योग और कृषि को नियन्त्रित करने तथा श्रमिकों की सुरक्षा (protection of labour) प्रदान करने सम्बन्धी सरकार के और अधिक प्राधिकारी कबलों को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अवैधानिक ठहरा दिया तथा इस कारण उन्हें वापस लेना पड़ा। नवम्बर १९३६ में जिस अल्पधिक बहुमत से राष्ट्रपति रूजवेल्ट का निर्वाचन हुआ, उससे स्पष्ट था कि राज्य द्वारा विनियमन (state regulation) के नए सिद्धान्त को अमरीकी जनता ने किस प्रकार सहर्ष स्वीकार कर लिया है।

सन् १९३३ के बाद के वर्षों में, इस शांतिपूर्ण गृह-क्रान्ति (peaceful domestic revolution) में ही अमरीकी सरकार की शक्ति लगी रही तथा विदेशी मामलों का इस समय गौण स्थान (second place) हो गया। जापान की मचूरिया कार्रवाई का प्रथम प्रभाव अमेरिका को राष्ट्र-संघ के साथ सह-

योग करने के लिए प्रेरित करना हुआ था। सन् १९३२ के ग्रीष्मकाल में, रिपब्लिकन (Republican) और डेमोक्रेटिक (Democratic) दोनों ही पार्टियों ने यह घोषणा की कि यदि पेरिस समझौते (Pact of Paris) का भंग (breach) किया जाए अथवा उसके भंग किए जाने की आशंका हो तो वे इस क्षण में हैं कि अमरीकी सरकार और अन्य सरकारें परस्पर परामर्श करें। मई १९३३ में, निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में अमरीकी प्रतिनिधि यह ने घोषित किया कि यदि कोई निःशस्त्रीकरण समझौता किया गया, तो अमरीकी सरकार इस बात के लिए सहमत हो जाएगी कि, भविष्य में संकट के समय (in future emergencies) यह अन्य सरकारों से परामर्श करेगी तथा वे जो कार्रवाई करना चाहेंगी, उसमें अमरीकी सरकार बाधा नहीं डालेगी। किन्तु जब सम्मेलन असफल हो गया और जब योरोप तथा प्रशांत सागर में स्थिति अधिक दुर्भाग्यपूर्ण तथा अधिक भयपूर्ण (darker and more menacing) हो गई, तब अमरीकी लोकमत तेजी से वृथक्करण (isolation) की नीति पर चलने का पक्षपाती होने लगा। दिसम्बर १९३५ में, लंदन में एक नौसैनिक सम्मेलन यह विचार करने के लिए हुआ कि वर्ष के अन्त में लंदन नौसैनिक संधि समाप्त हो जाने पर क्या स्थिति होगी। सन् १९३४ के अन्त में जापान ने १९२१ में की गई वाशिंगटन पाँच-राष्ट्र संधि को समाप्त करने के लिए आवश्यक दो वर्ष की सूचना दे दी थी। जापान को हमेशा के लिए वाशिंगटन अनुपात या ऐसा अन्य कोई अनुपात स्वीकार करने लेने के लिए राजी कर लेना असम्भव प्रतीत हुआ था जो उसकी समुद्री बेड़े का सीमाना ब्रिटिश और अमरीकी बेड़े से कम सीमा पर निश्चित करना। लंदन सम्मेलन का परिणाम ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में केवल यही समझौता हुआ कि इन देशों ने जो अज्ञात निर्मित किए हो या प्राप्त (acquired) किए हों, उनके बारे में वे एक और अग्रिम सूचना दें तथा विभिन्न प्रकार के युद्ध-पोतों का अधिकतम टन परिणाम (maximum tonnage) निश्चित किया जाए। और सभी बातों में, १९३६ के अन्त में सभी पक्षों को पुनः स्वतन्त्रता मिल गई।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, सन् १९३५ के प्रारम्भ से ही अमरीकी सरकार का प्रमुख उद्देश्य युद्ध में घसीटे जाने की संभावना से भी बचना रहा था।^१

१. 'Since the beginning of 1935 the principal aim of the

उस वर्ष, अपने बचनों को कम करने की नीति (policy of reducing its commitments) का अनुसरण करते हुए उसने फिलिपाइन (Philippines)—जो पश्चिमी प्रशान्तसागर में एकमात्र अमरीकी सैनिक प्रह्ला था—से हट जाने (to withdraw) तथा इन द्वीपों को दस वर्षों की परीक्षावधि (probationary period) के बाद, पूर्ण स्वतन्त्रता दान का निश्चय किया। सन् १९३५ के ग्रीष्मकाल में स्वीकृत तटस्थता अधिनियम (Neutrality Act) भी इस निश्चय के समान ही महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम के अनुसार युद्ध भड़क उठने की स्थिति में, अमरीकी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वह युद्धरत दोनों ही पक्षा को युद्ध सामग्री तथा आवश्यक उत्पादन (key products) निर्यात किए जाने पर रोक लगाये। अमरीकी राष्ट्रपति ने इस अधिकार का उपयोग इटली-अबीसीनिया युद्ध में किया भी था। फरवरी १९३६ में इस अधिनियम में किए गये संशोधन के अनुसार ^२ रोक भावी युद्धों में, न केवल ऐच्छिक (optional) अपितु बाध्यकर (obligatory) होगई। संशोधन में युद्धरत पक्षों को श्रृंखला दिए जाने पर भी रोक लगादी गई। किन्तु महत्व की बात यह थी कि इस अधिनियम से अमरीकी गणतन्त्रों (republics) को मुक्त रखा गया था।

योरोप तथा सुदूर पूर्व के बखेडों से अपने आपको घुबक् रहने के समुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) क इस प्रयत्न के साथ ही साथ अन्य अमरीकी देशों (American countries) के अधिकाधिक निकट घाने को समुक्त राज्य अमेरिका को इच्छा भी इतनी हा प्रबल थी। मध्य और दक्षिणी अमेरिका के देशों में अमेरिका के प्रति परम्परागत अविश्वास कई बरों से चल रहा था। मुनरो मिद्धान का यह व्यापक अर्थ लगाया गया था कि व्यवस्था बनाए रखने और विदेशी जान-माल की रक्षा करने के लिए, आवश्यकता पडने पर मध्य और दक्षिणी अमेरिका के मामलों में हस्तक्षेप करना समुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार एवं कर्त्तव्य है।^१ इस प्रकार १९०३ में

American Government in international affairs had been to avoid any possibility of becoming involved in war ”

३. “The Monroe Doctrine was widely interpreted as implying that the United States had the right and duty to intervene in Central and South America, where necessary in order to maintain order and protect foreign lives and property.”

क्यूबा (Cuba) और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की गई संधि द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को स्पष्ट हो यह अधिकार दिया गया था कि वह इन प्रयोजनों के लिए हस्तक्षेप करे। अमरीकी जहाज निकारागुआ (Nicaragua) में घड़े समय को छोड़कर १९१२ से ही तथा हैटी (Haiti) में १९१५ से ही रहे थे, तथा अन्य देशों में कुछ कम स्थायी हस्तक्षेप (less permanent interventions) किया गया था। समय-समय पर होने वाली प्रसिद्ध अमरीकी महासभाओं (Pan-American Congresses)—जिनमें से प्रथम १८८१ में हुई थी—के कारण वह दुर्भावना (ill will) दूर नहीं हो सकी थी जो कि “महा दण्ड” (Big Stick) और “डॉलर साम्राज्यवाद (Dollar Imperialism)” के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी ऐसा खुले आम कहा जाता था।

सन् १९३० के लगभग, किसी सीमा तक आर्थिक संकट के कारण, अमरीकी लोकमत मध्य और दक्षिणी अमेरिका में हस्तक्षेप की नीति से विमुक्त होने लगा। सन् १९३३ के प्रारम्भ में, निकारागुआ से अमरीकी जहाज हटा लिए गए और इसी वर्ष के माघ में जब राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने उद्घाटन भाषण में यह कहा कि, “यह राष्ट्र अच्छे पड़ोसी (Good Neighbour) की नीति पर चलेगा।” तब इन वादों का यह अर्थ लगाया गया कि अमेरिका का अभी तक जो रुक रहा है वह निश्चित रूप से बदल चुका है। इसी वर्ष में, अर्जेन्टाइना गणतन्त्र ने एक नया समझौता किया, जिसके अनुसार उसने आक्रमणात्मक युद्ध का त्याग किया तथा शक्ति के प्रयोग से उत्पन्न स्थितियों को अमान्य करने की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका स्वागत किया और कई अमरीकी तथा कुछ योरोपीय राज्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए। सन् १९३३ के अन्त में मोन्टेविडो (Montevideo) में हुई सातवीं प्रसिद्ध-अमरीकी महासभा (The Seventh Pan American Congress) में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री ने समझौतापूर्ण घोषणा की। अगले वर्ष संयुक्त राज्य के जहाज हैटी से अन्तिम रूप से हट गए और १९०३ में क्यूबा से की गई संधि भी रद्द कर दी गई। दिसम्बर १९३६ में, अपने पुनर्निर्वाचन (re-election) के तुरन्त बाद ही, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्यूनो एयर्स (Buenos Aires) में हुई आठवीं प्रसिद्ध-अमरीकी महासभा में स्वयं उपस्थित होकर

लेटिन अमेरिका को अनुग्रहीत किया। इस महासभा में एक सन्धि स्वीकार की गई, जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी भी अमरीकी गणतन्त्र की शांति को कोई सतरा उत्पन्न हुआ, तो हस्ताक्षरकर्ता (signatories) "शांतिपूर्ण सहयोग के कदम उठाने पर परस्पर परामर्श करेंगे"। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में हुए उन दो युद्धों के बानबूद भी, जिन्होंने कि दक्षिण अमेरिका को विकृत (disfigured) कर दिया, अमरीकी महाद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुष्टि इतने निजतापूर्ण कभी नहीं रहे थे जितने कि वे इस समय हो गये थे।

इसी बीच, अमरीकी गणतन्त्रों का अधिकाधिक मेल कराने और उन्हें अन्य राष्ट्रों प्र युद्धों में फँसने से बचाने की दोहरी प्रवृत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जारी रही, जहाँ कि तटस्थता (neutrality) बनाए रखने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए विधान (legislation) में और अधिक प्रगति की जा चुकी थी। सन् १९३५ के अधिनियम के उपलब्ध (provisions) और उसके बाद के संशोधन केवल दो वर्षों के लिए ही स्वीकार किए गए थे। इसलिए १९३७ में एक नया तटस्थता अधिनियम स्वीकृत हुआ। उसने शस्त्रा-शस्त्रों के निर्यात और जहाजों पर पुनः रोक लगा दी। उसके अनुसार वाणिज्य-पोतों (merchant men) पर सत्ताशस्त्र रखने तथा अमरीकी नागरिकों को किसी भी युद्धरत राष्ट्र के जहाज में यात्रा करने की मनाही भी कर दी गई—नागरिकों को नुकसान पहुँचने से संयुक्त अमेरिका को सम्भवतः युद्ध में शामिल होना पड़ सकता था। अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रपति को इस बारे में स्वविवेक (discretion) के अनुसार यह निर्णय करने का अधिकार मिल गया कि युद्धरत राज्यों को अमरीकी जहाजों में माल निर्यात करने का निषेध किया जाए भयवा नहीं। किन्तु "दाम चुकाओ और ले जाओ (cash and carry)" सिद्धान्त के आधार पर अन्य देशों के राष्ट्रवासी सामग्री का मूल्य चुकाकर यह निर्यात कर सकें तो उन्हें छूट थी। राष्ट्रपति को "संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थिति भूमि"—दूसरे शब्दों में, कनाडा को—माल का परिवहन (transport of goods) करने की अनुमति देने का अधिकार भी दे दिया गया, क्योंकि मार्ग में (en route) रुकने से संघर्ष का कोई कारण उपस्थित नहीं हो सकता था।

जो भी हो, यूरोप में राजनैतिक बायदों से बचने के सकल्प (determi-

nation) का आशय पूर्ण पृथक्करण (complete isolation) नहीं था अन्य महाद्वीपों के समान योरोप से आर्थिक सहयोग (economic collaboration) की नीति पर चलने के लिए अमरीकी लोकमत लगभग निर्विरोध रूप से पक्ष में था। सन् १९३४ में प्रथम बार स्वीकृत तथा १९३७ में तीन और वर्षों के लिए नवकृत (renewed) पारस्परिक व्यापार समझौता अधिनियम (Reciprocal Trade Agreement Act) का नाम मंत्री कॉर्डेल हल (Secretary Cordell Hull) ने सर्वाधिक-अनुपहीत राष्ट्र (most-favoured nation) आधार पर—जिसमें पारस्परिक आधार पर आयात-निर्यात कर में कमी तथा व्यापार पर लगाए गए अन्य बांधनों को सीमित करना शामिल था—बाइस राष्ट्रों, जिनसे अमेरिका का अधिकांश विदेश-व्यापार होता था, से व्यापारिक समझौते कर उठाया। उसका यह विश्वास था कि राज-नीतिक सकट उत्पन्न करने में अधिक राष्ट्रवाद (economic nationalism) एक बड़ा कारण रहा है और यदि व्याप्य आयात-निर्यात-कर संरक्षण (tariff protection) के साथ सुसंगत यथासम्भव निर्वधि (freest possible) आधार पर बहुपक्षीय व्यापार (multilateral trade) पुनः प्रारम्भ किया जाए, तो वह केवल राजनीतिक और शैक्षिक पुनर्व्यवस्थापन (rearrangements) की अपेक्षा तानाशाही, आक्रमण और युद्धों की पुनरावृत्ति (recurrence) रोकने में अधिक सक्षम हो सकेगा।

इसके प्रतिरक्ति सुदूर पूर्व में अमेरिका ने अल्पीकृत वचनों (reduced commitments) सम्बन्धी १९३४-३७ की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के आधार प्रकट किये।^१ अमरीकी राष्ट्रपति ने जानबूझ कर यह स्वीकार करने से बचने का प्रयत्न किया कि चीन में जापान की कार्रवाई "युद्धस्थिति" (state of war) है, क्योंकि यदि वह इस कार्रवाई को युद्धस्थिति स्वीकार कर लेता, तो तटस्थता अधिनियम (Neutrality Act) के उपबन्ध लागू हो जाते और चीन को अमरीकी सहायता बन्द कर देनी पड़ती। सघर्षरत चीनियों के प्रति स्पष्ट रूप से अधिमान (preference) दर्शाया गया तथा आयात-निर्यात बैंक

1. "In the Far East, moreover, the United States showed signs of a reaction against the 1934-37 policy of reduced commitments"

(Import-Export Bank) के जरिये उन्हें ऋण दिए गये। अमरीकी सरकार ने चीन में अपने किन्हीं भी परम्परागत अधिकारों को छोड़ने से दृढ़तापूर्वक इंकार कर दिया तथा चीनी सवि-बन्दरगाहों तथा समुद्र (treaty ports and waters) में अपनी नौसेना एवं यलसेना को पूर्णतः बनाए रखा। जुलाई १९३६ में उसने जापान अमेरिका वाणिज्यिक संधि को रद्द किए जाने (denunciation) की सूचना प्रकाशित की। यह संधि अंत में जनवरी १९४० में समाप्त कर दी गई। अमेरिका और जापान के बीच वाणिज्यिक सम्बन्ध दैनंदिन आधार (day-to-day basis) पर चलते रहे तथा जापान ने इस कारण अमरीकी अधिकारों का और अधिक प्रतिक्रमण (encroachment) नहीं किया कि अमरीकी कार्योस तथा अमेरिका के प्रभावशाली दलों द्वारा जापानी धायानों पर रोक या विभेदात्मक चुगौ (discriminatory duties) लगाने की जो जोरदार मांग की जा रही है, वह कही पूरी न कर दी जाये। सन् १९४६ में जो पूर्ण स्वतंत्रता विधित (legally) दी जाने वाली थी, उसके विरुद्ध भी फिलिपाइन द्वीपों तथा अमेरिका में घादोलन जोर पकड़ रहा था। जिस अवधि तक फिलिपाइन-व्यापार (Philippine trade) को अधिमानात्मक सुविधाएं (preferential advantages) दी जानी थी, उसमें बुद्धि कर दी गई तथा राजनैतिक एवं सैनिक शासन की समाप्ति सम्बन्धी अधिनियम (Act) में संशोधन करने की चर्चा प्रारंभ की जाती थी।

ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल

(The British Commonwealth of Nations)

ग्रेट ब्रिटेन और स्वशासी अधिराज्यो (self governing dominions) के आपसी सम्बन्ध वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध नहीं कहे जा सकते और वे इस पुस्तक के बाहर के विषय हैं। किन्तु चूंकि अधिराज्य राष्ट्रसंघ के सदस्य (जैसा कि भारत भी है) हैं तथा उनकी अपना विदेश नीति है, इसलिए उनकी स्थिति का यहाँ कुछ उल्लेख किया जा सकता है।

सन् १९१६ में वर्सेलोज की संधि पर जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, और भारत ने स्वयं अपनी पृथक हैसियत से हस्ताक्षर किये, तब वे प्रथम बार अन्तर्राष्ट्रीय समाज के सदस्यों के रूप में सामने आये। संधि पर अल्फाबेटिकली की अक्षरानुसार (alphabetical) सूची में उनका नाम

नहीं था बल्कि उन्हें “ब्रिटिश साम्राज्य” शीर्षक (rubric) के अन्तर्गत ही रखा गया था। यह तथ्य इस बात को स्पष्ट करता था कि उन्हें स्वतन्त्र संप्रभुतासम्पन्न (sovereign) राज्य नहीं माना गया था। अनुबन्धपत्र का पहिला अनुच्छेद जिसके अनुसार “कोई भी पूर्णतः स्वशासी राज्य, अधिराज्य या उपनिवेश” राष्ट्रसंघ का सदस्य हो सकता था, स्पष्ट ही उनकी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए रखा गया था। सन् १९२३ में जब आयरिश स्वतन्त्र राज्य (Irish Free State) ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता के लिए आवेदन किया, तब उसके आवेदन-पत्र को राष्ट्रसंघ समान ने जिस आधार पर स्वीकार किया वह यह था “जो अधिराज्य पहिले से ही राष्ट्रसंघ के सदस्य हैं, उनकी ही भांति आयरिश स्वतन्त्र राज्य भी उन्हीं शर्तों पर ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक अधिराज्य है।” अधिराज्यों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए १९२६ से पहिले और कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इस वर्ष साम्राज्यिक सम्मेलन (Imperial Conference) ने ग्रेट ब्रिटेन तथा स्वशासी अधिराज्यों की परिभाषा इस प्रकार की कि वे “ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्तशासी समुदाय हैं (autonomous communities), उनकी स्थिति बराबरी की है ... यद्यपि वे ब्रिटिश सम्राट् (Crown), के प्रति सामान्य निष्ठा के कारण संयुक्त हैं और स्वेच्छा से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं।” (“Autonomous Communities within the British Empire equal in status ... though united by a Common allegiance to the Crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations”)। स्टेट्यूट ऑफ़ वेस्टमिनिस्टर (Statute of Westminster), जिसमें इस स्थिति को वैधिक तथा सार्वधानिक आधार (legal and constitutional basis) दिया गया था, ब्रिटिश संसद (Parliament) द्वारा स्वीकार किया गया तथा अधिराज्यों ने भी उसे स्वीकार कर लिया।

इस परिभाषा से जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न हुई वह सदिग्धता (ambiguities) से मुक्त नहीं थी। ब्रिटिश सरकार [सन् १९२६ के बाद जिसका सरकारी नाम “ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संयुक्त राज्य की सम्राट की सरकार” (“His Majesty’s Government in the

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) होगया था] हमेशा इस बात पर जोर देती थी कि न तो अनुबन्धन ही और न ही ऐसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता जो कि राष्ट्रसंघ के सदस्यों द्वारा आपस में किया जाए, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्यों के आपसी सम्बन्धों पर लागू होते हैं। जो भी हो, आयरिश राजनीतिज्ञ इस मत की सदा ही आलोचना करते थे। अन्य अधिराज्य सैद्धांतिक प्रश्न पर अपना निर्णय देने से अधिकारनःबचते थे। सन् १९२६ में राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों ने जब स्थायी न्यायालय के विधान की ऐच्छिक धारा (optional clause of the Statute) पर हस्ताक्षर किए, तब यह मतभेद बिलकुल सामने आ गया। ग्रेट ब्रिटेन, जिसका अनुकरण आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी किया, ने हस्ताक्षर के समय यह शर्त रखी कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्यों के आपसी विवाद न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कनाडा और दक्षिण अफ्रीका ने भी यही शर्त रखी किन्तु उसके साथ ही इस आशय का वक्तव्य भी दिया कि वे यह मत मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इस प्रकार के विवाद स्वतः से ही (*ipso facto*) न्यायालय के अधिकार के बाहर हैं। आयरिश प्रतिनिधि ने इन विवादों सम्बन्धी कोई शर्त नहीं रखी। इसी समस्या का एक और पहलू [जो कि सौभाग्य से शास्त्र विषयक (academic) हो रहा] यह था कि यदि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का कोई सदस्य अनुबन्धन का उल्लंघन करते हुए युद्ध का आश्रय ले, तो क्या राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्य सोलहवें अनुच्छेद के प्रचीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

इन सैद्धांतिक कठिनाइयों के साथ ही साथ, मूलभूत प्रश्नों (fundamental issues) पर कुछ महत्वपूर्ण दृष्टि विभिन्नताएं (divergencies of opinion) भी थी। वास्तव में, उन विदेशियों के भय उचित नहीं थे जो यह सोचते थे कि राष्ट्रसंघ के संविधान (constitution) के कारण ब्रिटिश सरकार को छः मत प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि विषय-विस्तार पर (point of detail)—केवल इन्हीं पर जेनेवा में बहुमत से निर्णय किया जाता था—ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य कदाचित ही एक पक्ष में पाये जाते थे। वित्तीय और धार्मिक मामलों में, अधिराज्य और भारत ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध रहकर भी अपने राष्ट्रीय हितों का पक्ष लेते थे। राजनैतिक क्षेत्र में, भारत स्वतन्त्र कार्रवाई नहीं कर सकता था। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्यों के बीच

मतभेद विषय की अपेक्षा महत्व सम्बन्धी मतभेद (differences of emphasis rather than of substance) सिद्ध होने थे। कनाडा जो स्वयं सुरक्षित था तथा अपने पड़ोसी संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित था, यह दृष्टि इच्छा व्यक्त करता था कि राष्ट्रसंघ के अन्य सदस्यों की प्रविरक्षा (defence) करने सम्बन्धी उत्तरे कर्तव्य कम से कम रहें। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इतने दूर प्रतीत होने थे कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनका लगातार रुचि दिखाना कठिन था। लेकिन समय-समय पर उन्हें जापान का नय लगा रहता था, और जब कभी भी पक्षेय आप्रवासियों (coloured immigrants) को अपने देश में नहीं आने देने सम्बन्धी उनकी नीति की आलोचना की जाती थी, वे हमेशा ही उसे नापसन्द करते थे। दक्षिण अफ्रीका संभवतः सुरक्षा-समस्याओं में अधिक रुचि दिखाना था। वह उन इन्-गिने देशों में से था, जिसने जुलाई १९१६ में दृष्टी के बिन्दु अनुशास्त्रियाँ वापस लेने के प्रति अनुमोदन (disapproval) प्रकट किया था। आयरिश (Irish) लोग अपनी किसी अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर चलने की अपेक्षा स्वतन्त्रता का सिद्धान्त स्थिर करने के प्रति ही अधिक चिन्तित प्रतीत होने थे। तीन अधिराज्यों—आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका—का युद्ध क्षेत्रों पर संरक्षण-राज्य था, जिनके विषय में वे राष्ट्रसंघ की प्रतिवर्ष प्रतिवेदन देने थे। सन् १९२७ के बाद से, परिषद् (Council) में एक अस्थायी स्थान (non permanent seat) हमेशा ही किसी न किसी अधिराज्य को प्राप्त रहा।

सन् १९१६ में युद्ध आरम्भ होने पर यह अन्तिम रूप से स्पष्ट होगया कि अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेन का नेतृत्व स्वतः ही स्वीकार करने के लिए अपने भावकी बाध्य नहीं मानते थे तथा उनमें से प्रत्येक ही अपने अधिकारपूर्वक तथा अपनी प्रतिष्ठा एवं हित का विचार करते हुए कार्य करता था।

१३. पुनः युद्ध की लपटों में (Relapse Into War)

यह हम पहले ही देख चुके हैं कि १९१६ के समझौते से असन्तुष्ट राष्ट्रों ने १९३६ के अन्त तक इस समझौते के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों से मुक्त होने का अपना अधिकार जता दिया था। अब वे अपनी हानि-पूर्ति (satisfaction) का दावा कर रहे थे जिसका अर्थ यह हानि पूरी नहीं होने पर केवल युद्ध ही हो सकता था। इस सतरे के कारण, ब्रिटिश सरकार ने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निःशस्त्रीकरण करने का अपना प्रयत्न पूर्णतः छोड़ दिया। मार्च १९३७ में नेविल चेम्बरलेन (Neville Chamberlain) ने वित्तमन्त्री (Chancellor of Exchequer) की हैसियत से यह घोषणा की कि प्रतिरक्षा-व्यय की पूर्ति अब केवल कर लगाकर ही नहीं की जाएगी। चेम्बरलेन ने यह प्रस्ताव रखा था कि इस प्रयोजन के लिए चालीस करोड़ पाँच का ऋण लिया जाएगा तथा पाँच वर्षों की अवधि में प्रतिरक्षा पर डेढ़ अरब पाँच व्यय किए जाएंगे। प्रधान मन्त्री बाल्डविन (Baldwin) ने इन प्रस्तावों का समर्थन यह कह कर किया था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य आक्रमण को रोकना है तथा कुछ वर्षों तक सीमित व्यय करने के बाद, जीवन स्तर या समाजोपयोगी सेवाओं (social services) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही ब्रिटेन प्रतिरक्षा पर यह व्यय कर सकता है। बाल्डविन और विदेश मन्त्री ईडन दोनों ही ने यह स्वीकार करने से इन्कार किया कि ग्रेट ब्रिटेन ने राष्ट्रसंघ छोड़ दिया है। बाल्डविन ने यह आश्वासन प्रकट की कि राष्ट्रसंघ की शार्वार्ड के साथ ही साथ “प्रादेशिक समझौते” (“regional pacts”) भी किए जाएंगे जिनमें कुछ क्षेत्रों के लिए कुछ राष्ट्रों से भारन्टी दी जाएगी। किन्तु ईडन को यह स्वीकार करना पड़ा कि इस दिशा में बहुत कम प्रगति हो सकी है। और उन्होंने ब्रिटिश शस्त्रीकरण का समर्थन यह कह कर किया कि यह आवश्यकता ही शांति की सर्वोत्तम गारन्टी है।

उस समय युद्ध का खतरा अनिश्चित था; जर्मनी की पूरी शक्ति फ्रांसीसी

मेगीनाट लाइन (French Maginot Line) के विरुद्ध प्रतिरक्षा-निर्माण करने में लगी हुई थी। इस "सिगफ्रीड लाइन (Siegfried Line)" ने पूर्ण हो जाने पर, जर्मनी संयुक्त ताकत (united force) से पश्चिमी सीमा को अपने अधिकार में रख सकता था और पूर्व को और अपने प्रयत्न केन्द्रित कर सकता था। किन्तु सारा योरोप, विशेषकर फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, युद्ध की इस नई अभिनयशाला (theatre of war) में कब क्या घटित हो जाए, यह अनिश्चित ही मानते थे।

स्पेनिश गृह-युद्ध (Spanish Civil War)

सन् १९३६ के उत्तरार्ध (latter half) की सबसे महत्वपूर्ण घटना एक ऐसे देश में घटी जिसका अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अनेक वर्षों से अमहत्वपूर्ण भाग रहा था। स्पेन में १९२३ में जो तानाशाही स्थापित हुई थी वह १९३० में उलट दी गई। अगले वर्ष वहाँ के शासक अलफोन्सो तेरहवें (Alfonso XIII) ने राजगद्दी त्याग दी तथा स्पेन में प्रजातांत्रिक गणतन्त्र (democratic republic) की स्थापना की गई। सन् १९३१ से १९३६ तक इस प्रजातन्त्र में दक्षिणपथी राजवादियों (royalists) और अन्य प्रतिक्रियावादियों (reactionaries) तथा वामपथी अराजकतावादियों एवं कम्युनिस्टों में कुछ अनिश्चित संतुलन (precarious balance) बना रहा। राज्य की अर्थव्यवस्था अण्व्यवस्थापूर्ण (chaotic) हो गई तथा सार्वजनिक व्यवस्था (public order) को प्रायः खतरा उत्पन्न हो जाता था। जुलाई १९३६ में, स्पेनिश मोरक्को (Morocco) स्थित सेना के सेनापति फ्रांको (General Franco) ने सैनिक विद्रोह की घोषणा कर दी और मुख्यतः मूरिश (Moorish) सेना की सहायता से स्पेन में कूच कर दिया। अधिक विरोध के बिना ही, उसने स्पेन के बिल्कुल दक्षिणी भाग (extreme south) पर अधिकार कर लिया तथा सारे पश्चिमी स्पेन पर धीरे-धीरे विजय पा ली। नवम्बर के मध्य तक, विद्रोही मेड्रिड के उपनगरी (suburbs of Madrid) तक पहुँच गये; स्पेनिश सरकार हट कर वेलेन्सिया (Valencia) चली गई तथा राजधानी का पतन निकट प्रतीत होते लगा। इस समय के बाद से, सरकारी सेना का मुकाबिला कड़ा होने लगा। वर्ष के अन्त तक, तीन समय हल—वामपथियों की

विजय, दक्षिण पश्चिम की विजय या उनके गतिरोध (stalemate)—लगभग समान रूप से समव प्रतीत होने लगे ।

वैसे अन्य परिस्थितियों में, स्पेनिश गृह युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय घटना नहीं हुआ होता । जिन कारणों से वह अन्तर्राष्ट्रीय घटना हो सका, वे दो प्रकार के थे । एक तो, इटली—प्रबोसीनिया में हाल ही में उसकी विजय ने भूमध्यसागर के सामरिक महत्व (strategic importance) को सामने ला दिया था—ने पश्चिमी भूमध्यसागर में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के अवसर का स्वागत किया । दूसरे, प्रथम विश्व-युद्ध के बाद से, यह विचार जोर पकड़ रहा था कि किसी देश विशेष का आन्तरिक संगठन जिस राजनैतिक सिद्धान्त पर आधारित हो, अन्य देशों में उस सिद्धान्त की विजय के लिए उस देश को प्रोत्साहन तथा सहायता देना चाहिये । सन् १९२७ से पहिले सोवियत संघ ने यह नीति अपनाई थी और आगे चलकर अन्य देशों ने भी उसका अनुकरण किया था । जर्मनी ने १९३३-३४ में ऑस्ट्रियन, नारिसियों को आर्थिक और वस्त्रास्त्रों की सहायता दी थी । जर्मनी से भी अधिक सफलतापूर्वक इटली ने इस बात पर जोर दिया कि ऑस्ट्रिया में फासिस्ट शासन की स्थापना की जाये । १९३६ में इटली और जर्मनी ने स्पेनिश गृह-युद्ध को फासिज्म और कम्युनिज्म के बीच सचप माणा—यद्यपि उनके कारण उचित प्रतीत नहीं होते थे—तथा विद्रोहियों की सहायता करना ठीक समझा । इस प्रकार के संगमग सभी मामलों में, हस्तक्षेपकर्ता देश (intervening country) के राष्ट्रीय हितों और किसी राजनैतिक सिद्धान्त के कल्पित हितों (supposed interests) में भेद कर पाना कठिन प्रतीत होता है ।

इसमें सदेह की शु जाइश कम हो है कि इटली, किसी न किसी रूप में, सेना-पति फाको द्वारा किए गए विद्रोह का गुप्त सहकारी (privy) था, क्योंकि फ्रैंको की सेना को मोरक्को से लाने के लिए इटालियन वायुयानों की सहायता प्रारम्भ से ही प्राप्त हुई थी^१ । कुछ ही सप्ताहों में, स्पेनिश गृह-युद्ध के कारण सारे

1. "There can be little doubt that Italy, at any rate, was privy to General Franco's rebellion; for the help of Italian aeroplanes was forthcoming at the very outset to transport his troops from Morocco"

यूरोप के ही दो सेमो (camps) में बँट जाने की आशा का होने लगी। इटली, जर्मनी, और पुर्तगाल खुले आम विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति जताते थे जबकि सोवियत संघ स्पेन सरकार के साथ सहानुभूति रखता था। किसी भी कीमत पर (at all costs) तटस्थ बने रहने के लिए उत्सुक ब्रिटिश सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन से स्पेन को युद्ध-सामग्री भेजे जाने पर १५ अगस्त को रोक लगा दी। फ्रांस ने भी ब्रिटेन का अनुसरण किया। तत्पश्चात् इन दोनों देशों ने यूरोप के सभी देशों से इस आशय का एक समझौता करने का अनुरोध किया कि वे किसी भी पक्ष को युद्ध सामग्री नहीं भेजेंगे तथा इस समझौते पर किस प्रकार अमल किया जा रहा है इसकी देखरेख करने के लिए लंदन में एक अहस्तक्षेप-समिति (non-intervention committee) गठित की जाएगी। मुख्यतः पुर्तगाल की आनाकानी (reluctance) के कारण, कुछ विसत्र के पश्चात्, यह समझौता हो गया। इस समझौते के कारण कुछ सप्ताहों तक स्पेन को शास्त्रास्त्र का भेजा जाना रुक गया था—ऐसा प्रतीत होता है। किन्तु उसके कुछ समय बाद ही, स्पेनिश और सोवियत सरकारें समझौते का उत्सर्जन करने के लिए, इटली, जर्मनी तथा पुर्तगाल की निंदा करने लग गईं। इन आरोपों का उत्तर सोवियत सरकार पर आरोप—जो जीघ्र ही उठने ही लगे थे—लगाकर दिया गया। अक्टूबर के बाद से, इटली और जर्मनी, न्यूनाधिक प्रकट रूप से विद्रोहियों को शास्त्रास्त्र भेज रहे थे, तथा सोवियत सरकार स्पेन की सरकार को। नवम्बर में, जब मेड्रिड का घेराव निकट दिखाई देता था, इटली और जर्मनी ने सेनापति फ्रैंको द्वारा स्थापित सरकार को सरकारी तौर पर मान्यता दे दी। काफी सख्या में इटली और जर्मन सैनिक विद्रोहियों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे। इसी प्रकार स्पेनिश सरकार की ओर से इसी सैनिक टुकड़ियाँ तथा फासिस्ट-विरोधी इटलीवासी और भास्की-विरोधी जर्मन लोग लड़ रहे थे। स्पेनिश गृह-युद्ध यद्यपि स्पेन की भूमि पर हुआ था तदपि उसने यूरोपीय गृह-युद्ध के कई लक्षण धारण कर लिए थे।^१

राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्वात्मक गुटबन्दी

(Rival Grouping of the Powers)

सन् १९३६ के अन्तिम महानो की दूसरी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना जर्मनी

१. "The Spanish Civil War assumed many of the aspects of European civil war fought on Spanish territory."

और जापान के बीच एक समझौता था। राजनैतिक दृष्टि से, यह समझौता फ्रांस-सोवियत समझौता का ही परिणाम और प्रतिरूप (consequence and counterpart) था। इसमें आश्चर्य की बात केवल इतनी ही है कि यह समझौता और भी जल्दी नहीं हो सका था। किन्तु उस समय की विशेषता के अनुसार, यह मंत्री समझौता (pact of alliance) न होकर कम्युनिज्म को रोकने के लिए परस्पर सहायता सम्बन्धी समझौता था।

इस प्रकार १९३६ की समाप्ति तक ससार का काफी भाग दो गुटों में बँट चुका था। एक का नेतृत्व जर्मनी, इटली और जापान करते थे तो दूसरे का फ्रांस तथा सोवियत संघ। पहिले गुट को कभी-कभी फासिस्ट राष्ट्र कहा जाता था किन्तु इसमें सदेह ही है कि यह शब्द जापान के लिए भी प्रयुक्त करना उचित था। दूसरे गुटों को इतनी सरलता से कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। सोवियत संघ ने १९३६ में जो सविधान स्वीकार किया था, उसमें यद्यपि प्रजातन्त्र के कुछ बाह्य रूपों (external forms) को स्थान दिया गया था, तदपि पारचाय प्रजातन्त्र उसके लिए उतनी ही पराई चीज थी जितनी कम्युनिज्म फ्रांस के लिए। उस समय प्रचलित यह सिद्धांत कि किसी भी देश का वर्गीकरण उस राजनैतिक सिद्धांत के अनुसार किया जाए जिसे वह मानता है, भ्रामक (misleading) हो गया। ये प्रतिद्वन्द्वात्मक गुटबंदियाँ होने का प्रमुख कारण किसी सामान्य राजनैतिक सिद्धांत में विश्वास नहीं था। प्रथम गुट, कई कारणों से, १९१९ में किए गए विश्व के क्षेत्रिक समझौते से असन्तुष्ट था जबकि दूसरा गुट उसे बनाए रखना चाहता था। मूलभूत मतभेद मुख्यतः उन लोगों में था जो कि विश्व व्यापार के तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय वितरण (international distribution) से सन्तुष्ट और असन्तुष्ट थे।^१

इस समय ब्रिटिश सरकार ने किसी भी गुट में शामिल होने से इकार कर दिया तथा सतर्कतापूर्ण तटस्थता का रस (attitude of cautious neutrality) तब तक अपनाए रखा, जब तक कि अन्य राष्ट्रों की अशांतिकारक कार्रवाई के कारण उसे यह रस त्याग देने के लिए विवश नहीं हो जाना पड़ा। यह अफ-

१ "The fundamental division was between those who were in the main satisfied with the existing international distribution of the world's goods and those who were not."

बाह्र उड़ जाने कारण कि स्पेनिश मोरक्को में जर्मन सेनाएं जमा हो गई हैं, १९३७ के प्रारम्भ में चिन्ता का कारण उपस्थित हो गया। भय इस बात का था कि सेनापति फ्रैंको इस क्षेत्र को किसी की सहायता के बदले में उसे दे सकता है। फ्रांसीसी सरकार ने १९२२ के समझौते—जिनके अनुसार रिफ युद्ध (Riff war) में फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने के बाद, स्पेन ने यह वचन दिया था कि वह सामरिक (strategic) महत्त्व के इस क्षेत्र का स्वत्वान्तरण (alienation) नहीं करेगा—का सार्वजनिक रूप से स्मरण कराया। जो भी हो, जर्मनी ने ऐसी किसी महत्वाकांक्षा से इन्कार किया। सेनापति फ्रैंको ने भी यह घोषणा की कि स्पेनिश क्षेत्र को मसह बनाए रखने के लिए वह कृतसंकल्प (determined) है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे-जैसे जर्मनी ने इटली को मुख्य भूमिका करने के लिये छोड़ दिया। जर्मनी की सहायता मुख्यतः सामग्री और टेक्निसियन (technicians) तक ही सीमित थी जबकि इटली की सेनाएं पृथक् और स्पष्ट सेना के रूप में लड़ती थी तथा उनकी सफलताओं का रोम में विजय के रूप में स्वागत किया जाता था। जहाँ तक स्पेनिश सरकार का प्रश्न है उसकी अन्तर्राष्ट्रीय ब्रिगेड (International Brigade) को स्पष्ट ही किसी देश विशेष का कहा जा सकता था, किन्तु सामग्री—जिसका अधिकांश भाग संभवतः रूस से आता था—अधिकांशतः फ्रांस से होकर आती थी।

जून १९३६ में, ल्यॉन ब्लूम (Leon Blum) के नेतृत्व में लोक मोर्चा (Front Populaire)—क्रांतिकारियों (Radicals), समाजवादियों और कम्युनिस्टों की पुनर्वन्दी—की सरकार बन जाने से फ्रांस में गम्भीर राजनीतिक संकट उपस्थित हो जाने के कारण, योरोप की सामान्य स्थिति पर और भी गहरा प्रभाव पड़ा था। इस सरकार ने श्रमिकों और मालिकों के संबंधों में परिवर्तन सम्बन्धी विधियाँ (laws) इतनी तेजी से बनाई कि धनिक वर्गों (wealthier classes) ने उन्हें क्रांतिकारी माना। सम्पन्न और सुशिक्षित यहूदी, ब्लूम को इन क्षेत्रों में मास्को का दूता (agent) माना जाता था। स्पेन में विजय उस पक्ष की हुई जिसका तयान्वित फासिस्ट राष्ट्रो ने पक्ष लिया था। इसका मुख्य कारण यह था कि जर्मनी और इटली ने—स्पेन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो यह देखने के लिए वचनबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य होते हुए भी—स्पेनिश सरकार का पासा पलट देने के लिए आवश्यक

सीमा तक सामग्री और कुमुक (reinforcements) द्वारा उसकी सहायता की थी। किन्तु ब्लूम—स्पेनिश प्रश्न पर उसकी भावनाएँ कुछ भी रही हो—अन्य सभी फ्रांसीसियों की भाँति यह सोचता था कि फ्रांस का मुख्य हित ग्रेट ब्रिटेन के साथ कदम मिलाने में है। इधर ब्रिटिश सरकार ने यदि अहस्तक्षेप (non-intervention) की वास्तविकता बनाए रखने का नहीं, तो कम से कम हस्तक्षेप को व्यापक योरोपीय युद्ध का रूप धारण करने से बचाने का, तो हर प्रयत्न किया हो। तनाव १९३६ के वसंत तक जारी रहा जबकि कैटे-लोनिया (Catalonia) में गरातन्न सरकार की स्थिति कमजोर हो चुकी थी, मैड्रिड पर अन्ततः (finally) सेनापति फ्रैंको की सेना ने अधिकार कर लिया। उसके बाद फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ही की सरकारों ने फ्रैंको सरकार को विधिवत् मान्यता दे दी।

किन्तु इससे विश्व-स्थिति कम संकटपूर्ण नहीं हुई। जिस समय स्पेनिश युद्ध पूरे वेग से चल रहा था, उस समय जापान ने चीन में अपनी कार्रवाई प्रारम्भ की। अन्य सब बातों के होते हुए भी यह कार्रवाई आक्रामकतात्मक चढ़ाई (aggressive invasion) ही थी क्योंकि युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी। नवम्बर १९३७ में, इटली कॉमिन्टर्न विरोधी समझौते (Anti-Comintern pact) में शामिल हो गया जो कि जर्मनी और जापान के बीच किया गया था। इसके अनुपरिणाम स्वरूप (as a sequel) इटली ने राष्ट्र-सभ से हट जाने की घोषणा ११ दिसम्बर की। म्युनिक में जब स्वयं मुसोलिनी ने हिटलर से समारोहपूर्ण सरकारी भेंट (ceremonial official visit) की थी, तब जर्मनी के साथ इटली के सुदृढ़ सम्बन्धों की पुष्टि हो चुकी थी। उसके प्रत्युत्तर में, १९३८ में, रोम में हिटलर का बड़े समारोहपूर्वक स्वागत किया गया। ऐसी कोई भी बात नहीं छूटी जो कि बर्लिन-रोम पुरी (Berlin-Rome axis)—कम से कम सिद्धांत रूप में जिससे जापान भी संबद्ध था—की शक्ति की पुष्टि करने के लिए आवश्यक हो। यह सम्भव प्रतीत होने लगा कि असन्तुष्ट राष्ट्रों की हानि-पूर्ति के लिए बिलकुल निकट भविष्य में ही कार्रवाई की जायगी। चेकोस्लोवाकिया के जर्मन तत्व अपने असन्तोष की घोषणा पहिले ही कर चुके थे तथा जर्मनी में शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त कर चुके थे। सूडेटन जर्मनों का नेता हेनलीन (Henlein) एक योरोपीय व्यक्तित्व का व्यक्ति हो गया तथा प्रचार कार्य के लिए ब्रिटेन भागा।

इसी बीच रूस में एक महत्त्वपूर्ण शुद्धि (purge) चल रही थी। सोवियत सरकार ने १९३६ में कई ऐसे राजनीतिज्ञों पर मुकदमे चलाए जो लेनिन के समय के आतिकारी दलों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रह चुके थे। अब, १९३७ में कुछ सुविख्यात सेनापतियों को भी इसी प्रकार निकास दिया गया था। यह अनुमान किया जाने लगा कि फ्रांस सोवियत युटबन्दों का सैनिक महत्त्व (military value) इससे बहुत कम हो गया है। इस विषय में भी सदेह बढ़ रहा था कि ऑस्ट्रिया की स्वतन्त्रता में इटली का वही हित अब भी बना रहेगा जो कि जैनर-सोमा पर अपनी सैनिक दुबकियाँ जमाकर उसने १९३४ में दिखाया था।

कुल मिलाकर, १९३७ का वर्ष अप्रकट घटनाओं (undisclosed events) की तैयारी का वर्ष ही था।^१ भूमध्यसागर (Mediterranean) में युद्ध का खतरा सबसे अधिक प्रतीत होता था जहाँ इटली वर्तमान शक्ति-विभाजन (division of power) से बहुत अधिक असंतोष प्रकट किया करता था। उसका यह दावा था कि अबीसीनिया में उसे जो नई प्राप्ति हुई है उसके कारण उसे स्वेज नहर (Suez Canal)—जो कि अबीसीनिया तक जाती है—के नियन्त्रण में स्थान मिलना चाहिए तथा ट्यूनिस् (Tunis) की जनसंख्या में इटालियन लोगों की प्रमुखता से यह स्पष्ट है कि यह उपनिवेश, वास्तव में, इटली के अधिकार में ही होना चाहिए। इटली द्वारा ग्रेट ब्रिटेन—जिसके विस्तृत पुनर्शास्त्रीकरण को जर्मनी और इटली दोनों ही के प्रति ठोस प्रतिरोध (positive resistance) की नई नीति का सूचक माना जाता था—के विरुद्ध प्रचंड प्रचार किया गया। ब्रिटिश विदेशमन्त्री ईडन ने जेनेवा में १६ जनवरी १९३८ को हुई राष्ट्र-संघ परिषद् की बैठक में, ब्रिटेन की सैनिक तैयारियों को अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि करने के सहयोग सम्बन्धी उन सिद्धान्तों की सहायक बताया जिन पर राष्ट्रसंघ आधारित था। किन्तु ब्रिटिश संसद (Parliament) में हुई बहस से ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में मतभेद की सूचना मिलती थी और २० फरवरी को यह घोषित कर दिया गया कि ईडन का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। जर्मन और इटालियन प्रचार साधन (organs of publicity) प्रायः ही ईडन को अपने वैध दावों (legitimate claims)

^१ 1. "But, on the whole, 1937 was only a year of preparation for undisclosed events."

की पूर्ति में बाधक प्रचारित करते रहे थे। ब्रिटिश लोकसभा में अपने त्यागपत्र पर प्रकाश डालते हुए ईडन ने यह स्पष्ट किया कि वे इटली से किसी भी प्रकार की वार्ता चलाने के तब तक विरोध में थे, जब तक कि इटली शत्रुतापूर्ण प्रचार (hostile propaganda) बन्द करने और स्पेन से अपनी सेनाएं हटा लेने सम्बन्धी अपने वचन पूरे नहीं कर देता। प्रधानमन्त्री के रूप में बाल्डविन के उत्तराधिकारी नेविल चेम्बरलेन (Neville Chamberlain) ने ईडन के उत्तराधिकारी लॉर्ड हेलिफेक्स (Lord Halifax) के सहयोगपूर्वक इटली से वार्ता चलाने के अपने विचार को घोषणा की। बाइसवी फरवरी को चेम्बरलेन ने यह मत प्रकट किया कि छोटे छोटे देशों में इस विश्वास को बढ़ावा देना गलत होगा कि राष्ट्रसंघ आक्रमण से उनकी रक्षा करेगा। लगभग दो वर्षों पूर्व ही, चूंकि बाल्डविन ने राष्ट्रसंघ को ब्रिटिश नीति का अतिम धाक्य (sheet-anchor) घोषित किया था, अनएव अब यह स्पष्ट था कि इस समय मोर्चा (front) बदन दिया गया था। चेम्बरलेन ने यह स्वीकार किया कि पहिले उन्हें विश्वास था कि इस प्रकार की सहायता समब हो सकेगी किन्तु अब उन्होंने अपनी राय बदल दी है। यदि यह आश्वासन दिया जाता कि स्पेन में विदेशी सेनाएं हटा लेने सम्बन्धी ब्रिटिश योजनाएं स्वीकार कर ली जाएंगी, तो ग्रेट ब्रिटेन यह वचन दे सकता था कि वह इटली की अवीसीनिया-विजय को मान्यता देने के लिए राष्ट्रसंघ से अनुरोध करेगा।

जर्मनी द्वारा आक्रमण का प्रारम्भ (Germany Begins Aggression)

इसी बीच, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नया खतरा उपस्थित होगया। स्ट्रेसा (Stresa) में १९३५ में हस्ताक्षरित (signed) एक समझौते के अधीन ब्रिटेन ने फ्रांस और इटली के साथ ही ऑस्ट्रिया की स्वतन्त्रता और अखंडता (independence and integrity) में अपना हित घोषित किया था। अन्य राज्यों पर नास्तो जर्मनी ने जो आक्रमण किए उनमें से प्रथम आक्रमण के कारण इस स्वतन्त्रता को इस समय गम्भीर खतरा था उपस्थित हुआ था।

सन् १९३८ के प्रारम्भ में, हिटलर ने जर्मनी की सभी सशस्त्र सेनाओं को सर्वोच्च कमान (supreme command) अपने हाथों में ले ली थी। इस प्रकार जो अधिकारी उनके सामान्य कार्यक्रम (general line of action)

का विरोध करते थे, उन पर वह अपनी इच्छा लाद सकता था। रिबेन्ट्रॉप (Ribbentrop) जो अभी तक ग्रैंट ब्रिटेन में राजदूत था नायरथ (Neuroth) के स्थान पर विदेशमन्त्री बना। इसके बाद से, आक्रामक कार्रवाई प्रारम्भ हुई। ऑस्ट्रियन नात्सियो द्वारा आयोजित अशांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बाद, ऑस्ट्रिया के प्रधानमन्त्री शुचनिग (Schuschnigg) को हिटलर ने बर्चट्स-गाडेन (Berchtesgaden) में बैठ के लिए बुलाया। शुचनिग ने एक प्रकार का अल्टीमेटम स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार उसे अपनी सरकार में नात्सी प्रतिनिधियों को लेना पड़ा। जो भी हो, इतने में ही उसकी खर नही रही। बारहुनी मार्च को जर्मन सेनाएँ विना में प्रविष्ट होगई और उन्होंने विना पर अधिकार कर लिया। इस सेना को एक टुकड़ी तुरन्त ही ब्रेनर दर्रे (Brenner Pass) पर पहुँची और इटालियन चौकियों के सैनिकों तथा उसने परस्पर अभि-वादन किया। सन् १९३४ से ही इटली के रुख में भारी परिवर्तन हो चुका था। ऑस्ट्रिया में इस आक्रमण का कोई विरोध नहीं हुआ। सम्भवतः अधिकांश आबादी यह चाहती थी कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल कर लिया जाये। किन्तु यह स्पष्ट था कि इसके बाद आक्रमण एक अन्य देश में हो सकता था जहाँ उसका तीव्र विरोध हो। चेकोस्लोवाकिया पर इसका यह परिणाम हुआ कि अब उसे अतिविस्तृत (greatly extended) सीमा पर जर्मनी की शक्ति का सामना करना था। कार्पेथियन (Carpathians) स्थित जर्मनी के सामने का इस क्षेत्र का कुछ भाग किलेबंदी पूर्ण (fortified) था तथा ऑस्ट्रिया के सामने का शेष भाग खुला हुआ था। उसकी कुल जनसंख्या डेढ़ करोड़ से कम थी। उसमें से लगभग पैंतीस लाख सूडेन जर्मन थे जो कि सीमा पर सुगठित समूहों (compact groups) के रूप में बसे हुए थे। डेन्यूब की ओर दक्षिण में करीब-करीब दस लाख मैग्यार लोग (Magyars) थे जो हंगरी से पुनः संयुक्त हो जाने की माँग करते थे। पूर्व में पोलैंड टेस्चेन (Teschén) नामक महत्वपूर्ण खनिज-जिले (mining district) का दावा करता था जो मित्र-राष्ट्रों द्वारा लादे गए एक समझौते के अनुसार १९२० में चेक लोगों को मिला था।

तो, इन परिस्थितियों में, चेक सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक गतिविधि करने (to hold manoeuvres) की जर्मनी ने तैयारियाँ की। चेक सरकार

ने अपनी कुछ रक्षित सेना (reserves) बुला ली और इसी बीच सूडेटनो से कोई समझौता कर लेने के लिए चिन्तापूर्ण प्रयत्न किये। किन्तु चेक सरकार न केवल प्रान्तरिक व्यवस्था बनाए रखने में समर्थ हो सकी अपितु जबरदस्ती आक्रमण का मुकाबिला करने के लिए भी तैयार थी। फ्रांस और सोवियत संघ भी इस बात के लिए वचनबद्ध थे कि यदि उस पर आक्रमण हो, तो वे उसकी सहायता करें। इस सम्बन्ध में कुछ करने का ब्रिटेन का कोई सीधा उत्तरदायित्व नहीं था। किन्तु २४ मार्च को चेम्बरलेन ब्रिटिश लोकसभा में कह चुके थे कि यदि इस कारण से ब्रिटेन का मित्र फ्रांस युद्ध में घसीटा गया, तो औपचारिक घोषणाओं (formal pronouncements) की अपेक्षा तथ्यों का विवशतापूर्ण सत्य (inexorable pressure of facts) संभवतः अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। इस घोषणा का यह अर्थ लगाया गया था कि ब्रिटेन ने यह वचन दिया है कि यदि फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया का साथ दिया, तो ब्रिटेन भी उसका साथ देगा।

इन सब बातों के होते हुए भी, योरोपीय युद्ध का भय स्पेन में चल रहे युद्ध से ही मुख्यतः सम्बन्धित था। क्योंकि वहाँ गणतन्त्रीय सरकार (Republican Government) के अधिकार का बन्दरगाहों में जो ब्रिटिश जहाज माल पहुँचाते थे, उन पर विद्रोहियों के वायुयानों—जिनमें कि जर्मन या इटालियन चालक होते थे, ऐसा कहा जाता था—द्वारा प्रायः बमबर्षा की जाती थी। किन्तु दोनों ही पक्षों से विदेशी सेना हटा लेने की एक ब्रिटिश योजना पर धर्चा भी चल रही थी। मध्य योरोप में घिर रहे विपत्ति के बादलों को कम करने के लिए, लॉर्ड रन्सिमन (Lord Runciman) को समझौता कराने (conciliator) तथा सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए भेजा (चेक सरकार ने इसके लिए औपचारिक रूप से ही अनुरोध किया था) भेजा गया। किन्तु जर्मन सरकार से परामर्श कर प्रस्तुत किए गए सूडेटनो दावे अधिकधिक माँगपूर्ण (insistent) होते गये। यद्यपि उन्हें और अधिक रियायतें (concessions) देने का प्रस्ताव किया गया था, तदपि १२ सितम्बर को हिटलर (Herr Hitler) ने न्यूरेम्बर्ग (Nuremberg) में एक विशाल जनसमूह (great gathering) के सामने सूडेटनो की यह सलाह दी कि वे जर्मनी में

पुनः शामिल होने की अपनी मांग पर दृढ़ रहे तथा उन्हें जर्मन सेना की सहायता प्राप्त रहने का वचन भी हिटलर ने दिया। चूंकि फ्रांस और सोवियत संघ चेक लोगो की सहायता करने का वचन दे चुके थे, इसलिए इससे युद्ध की आशंका उत्पन्न हो गई। ब्रिटेन की ओर से चेम्बरलेन ने इस समय प्रयत्न करना प्रारम्भ किया। सितम्बर १४ को उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि वे शांतिपूर्ण समाधान के लिए स्वयं जर्मनी जाना चाहते हैं। पन्द्रहवीं तारीख को वे वायुयान द्वारा म्युनिक गए और बेसटिसगाडेन में हिटलर से उनकी भेंट कराई गई। वहाँ से वे दूसरे ही दिन वायुयान से लंदन लौट आये। सितम्बर १८ को फ्रांस के प्रधानमंत्री देलादियर (Daladier) और विदेशमंत्री बॉनेत (Bonnet) भी उनके साथ हो लिये। इसी समय राष्ट्रसंघ-सभा अधिवेशन चल रहा था; लिटविनोव ने चेक सरकार और फ्रांस को दिया गया वचन—यदि फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया की ओर से हस्तक्षेप किया तो चेक लोगों की सहायता करने के लिए सोवियत सरकार अपने सभी साधनों का उपयोग करेगी—सार्वजनिक रूप से दोहराया। किन्तु सैनिक सहयोग के विषय में कोई परामर्श नहीं किया गया। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रूस में स्टालिन द्वारा प्रारम्भ किया गया शुद्धि कार्य (purge) जारी था तथा इस कारण सोवियत सैन्य मशीन (military machine) की कार्य-कुशलता के बारे में संदेह व्यापक रूप से फैला हुआ था।

चेम्बरलेन और देलादियर ने मिलकर एक योजना बनाई जिसे वे सम्यक्त रूप से चेकोस्लोवाक सरकार के सामने रखना चाहते थे। उसके अनुसार सूडेटन जर्मन आबादी वाला काफ़ी क्षेत्र जर्मनी को सौंप दिया जाना था। योजना के इस अंग को चेम्बरलेन ने जातिकारी किन्तु आवश्यक शल्यक्रिया (surgical operation) बताया। चेकोस्लोवाक सरकार ने धोखेबाजी की कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन से बहुत अधिक दबाव के कारण, उसे इस योजना के प्रति अपनी मोन सम्मति (acquiescence) देनी पड़ रही है। राइन स्थित गोडैसबर्ग (Godesberg) में हिटलर से दूसरी भेंट के लिए चेम्बरलेन पुनः वापस जर्मनी गये। इस अवसर पर नात्सी नेता (Führer) ने इतनी आश्चर्यजनक मांगें रखी कि चेम्बरलेन ने उनका एक ज्ञापन (memorandum) प्रेष भेज देने के प्रतिरिक्त और कुछ करने में इन्कार कर दिया। यह निश्चय किया

गया कि यदि हिटलर ने चेक क्षेत्र में तत्काल ही कूच कर जाने की अपनी धमकी को धसती रूप दिया, तो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन हिटलर का मुकाबला करने में चेक लोगों की सहायता करेंगे। ब्रिटिश नौसेना को तैयार कर लिया गया और हवाई हमले (air raid) के विरुद्ध लन्दन में जल्दी-जल्दी कदम भी उठाए गये। किन्तु चेम्बरलेन ने—उनका इस समय भी यह मत था कि जो रियायतें पहिले दी जा चुकी हैं उनको देखते हुए ऐसे कोई मतभेद शेष नहीं बचे हैं जिनके कारण युद्ध संभव हो सके—पुनः एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए मुसोलिनी से प्रार्थना की और इस प्रार्थना में चेम्बरलेन की सफलता भी मिली। उन्नीसवीं सितम्बर को हिटलर, मुसोलिनी, चेम्बरलेन और देलादियर के एक सम्मेलन ने वे शर्तें^१ तय करदीं जो कि चेक लोगो पर लादी जानी थी। इन चर्चाओं के समय चेक लोगों या सोवियत संघ का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। इन शर्तों को मान लेने के कारण झुठ जनता का सामना कर पाने में असमर्थ पाकर चेकोस्लोवाक सरकार ने त्याग-पत्र दे दिया। चेक सेना (Czech Legion) के एक विख्यात नेता सेनापति सिरोवी (Syrový) ने शासन का कार्यभार संभाला। कुछ दिनों के बाद बेंनेस (Benes) ने, जो कि मसारीक (Masaryk) की मृत्यु के बाद से ही, राष्ट्र-पति के पद पर था, भी त्यागपत्र दे दिया और देश त्याग कर दिया। कुछ समय तक तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि चेम्बरलेन की विजय हुई है। वापस लौटने पर, उनका बहुत उत्साह से स्वागत किया गया था, और उन्होंने हिटलर तथा स्वयं उनके द्वारा हस्ताक्षरित वह दस्तावेज अभिमानपूर्वक बताया था जिसमें यह घोषणा की गई थी कि दोनों ही राजनीतिज्ञों के देश मतभेद के सभी संभव कारणों को मिटा देने के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं तथा योरोप की शांति में योगदान करना चाहते हैं। देलादियर ने यद्यपि इस प्रकार के किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तदपि फ्रांस में उसका भी इसी प्रकार उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया।

आगे चलकर यह प्रकट किया गया कि हिटलर ने चेम्बरलेन को यह आश्वासन भी दिया था कि सूडेटन क्षेत्र की प्राप्ति योरोप में उसकी क्षेत्रिक

महत्वाकांक्षाओं में से अन्तिम महत्वाकांक्षा है (last of his territorial ambitions in Europe) और जर्मन लोगों के प्रतिरिक्त अन्य जातियों (races) के लोगों को जर्मनी में शामिल करने की उसकी इच्छा नहीं है। स्वयं हिटलर ने स्पोर्ट पैलास्ट (Sport Palast) बर्लिन में २६ सितम्बर, १९३८ को बोलते हुए कहा, “मैंने श्री चेम्बरलेन को आश्वासन दिया है और मैं अब भी इस बात पर जोर देता हूँ कि जब यह समस्या हल हो जाएगी तब यूरोप में जर्मनी की और कोई क्षेत्रिक समस्या नहीं रह जाएगी। मुझे चेक राज्य में और कोई रुचि नहीं रह जाएगी तथा मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ। हम और अधिक चेक (Czech) नहीं चाहते।”

चेकोस्लोवाक राज्य में बहुत अधिक संकुचन (drastic reduction) हो चुका था। पूर्व में, पोलैंड ने सशस्त्र कार्रवाई (armed action) की धमकी देकर देशीय क्षेत्र और उसकी महत्वपूर्ण कोयला-खदानों की माँग की थी जो पूरी कर दी गई। दक्षिण में, हंगरी ने बहुत अधिक क्षेत्र के लिए दावा किया जिसमें कि दस लाख के लगभग मैग्यार (Magyars) लोग रहते थे। यह माँग भी विवशतापूर्वक पूरी कर दी गई। चेकोस्लोवाक राज्य का सदा ही प्रशासक और असंतुष्ट अंग स्लोवाकिया स्वायत्त शासन की माँग करता था। तुलनात्मक दृष्टि से, वह एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था और प्रशासन कार्य मुख्यतः चेक अधिकारियों के ही हाथों में था। परिणामस्वरूप ईर्ष्या बढ़ी जिसे जर्मन दलालों ने अग्रपूर्वक प्रोत्साहित किया। स्लोवाकिया चेक प्रदेशों—जो अब अत्यधिक अस्तव्यस्त हो चुके थे—से उत्तरोत्तर (increasingly) पृथक् होता गया। म्युनिक में लायी गई शर्तों के अनुसार, एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग—जिसमें जर्मनी के साथ ही साय फ्रिटैन, फ्रांस, इटली और चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि होने थे—द्वारा चेक क्षेत्र से सूडेटन जिलों को पृथक् करने वाली रेखा निश्चित की जानी थी। किन्तु वास्तव में हुआ यह कि जर्मन सेना आगे बढ़ती गई और उसने जिस पर मन

“I have assured Mr. Chamberlain and I emphasise it now, that when this problem is solved Germany has no more territorial problems in Europe. I shall not be interested in the Czech State any more, and I can guarantee it. We don't want any Czech any more.”

भाया, उसी पर अधिकार कर लिया जिसमें अनेक ऐसे शहरो पर अधिकार करना भी शामिल था जिनकी भावादी मुख्यतः चेक थी। चेक राज्य के लिए प्रशासन की एक काम चलाऊ इकाई (workable unit of administration) बनाने के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसी बीच, पोलैंड और हंगरी ने अपने दावों की पूर्ति सैनिक अधिकार (military occupation) द्वारा करने का प्रयत्न किया जिसका चेकोस्लोवाक सेना ने मुकाबिला किया। विशेषतः सम्बे और सकडे चेकोस्लोवाक क्षेत्र के एकदम पूर्वी भाग में स्थित रुथेनिया (Ruthenia) के पिछड़े प्रांत के विषय में विवाद था। हंगरी उसे हर्षित चाहता था कि उसके मिल जाने से उसे पोलैंड के साथ सामान्य सीमान्त मिल जाता। किंतु जर्मनी की यह इच्छा थी कि रुमानिया की सीमा तक फैला हुआ यह क्षेत्र नाममात्र के लिए स्लोवाकिया के अधीन रहे जो कि उत्तरोत्तर जर्मनी के नियन्त्रण में आता जा रहा था। इस प्रकार ब्युनिक में बड़े राष्ट्रों ने जो समझौता सादा था उसने वास्तव में बुद्धारम्भ (outbreak of war) को टाल दिया था किन्तु इस बात के अनि-रिक्त कि तीस लाख जर्मन और स्कोडा (Skoda) स्थित विद्यास शस्त्रास्त्र फैक्टरी का नियन्त्रण स्थायी रूप से जर्मनी के हाथों में रहे और किता बात का निबटारा नहीं किया गया था।^१ ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने यह अनुमति कर कि उनकी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक पराजय हुई, अपने पुनर्जातीयकरण के कार्य को तेजी से हाथ में ले लिया। जबकि एक के बाद एक चेक सरकार के प्रमुख के रूप में उत्तराधिकारी होने वाले किंकर्तव्यविमूढ (embarrassed) राजनीतिज्ञ सभी

- 1 "Thus the settlement imposed by the Great Powers at Munich had indeed avoided the outbreak of war, but settled nothing, except that three million Germans, and the control of the great arms factory at Skoda, should be permanently attached to the Reich. Great Britain and France, recognising that a major diplomatic defeat had been inflicted on them, took energetically in hand the task of their own rearmament; while the embarrassed statesman who succeeded one another as heads of the Czech Government expressed on all occasions their desire to conform to German Policy."

भवसरो पर यह व्यक्त करने लगे कि वे जर्मन नीति के साथ कदम मिलना चाहते हैं।

किंतु समर्पण (submission) ही पर्याप्त नहीं था। हिटलर ने लगभग दार्द लाख उन जर्मनों की सुरक्षा के बारे में चिंता प्रकट की जो कि अभी भी चेक शासन में रह रहे थे। मार्च १५, १९३९ को उसने राज्य के राष्ट्रपति बीनेस के उत्तराधिकारी हेचा (Hacha) को बुलाकर प्रचंड सैनिक कार्रवाई (violent military action) की धमकी दे, हेचा को इस बात के लिए राजी कर लिया कि बोहेमिया और मोरेविया के पुराने प्रांत जर्मनी के संरक्षण में भाजाएँगे तथा उन पर जर्मन सेना द्वारा अधिकार कर लिया जायगा। किंतु सच्चाई यह है कि जर्मन सेनाएं उस समय के पहले से ही सीमांत पार कर रही थी और कुछ चेक नगरों पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया था। स्लोवाकिया को नाम मात्र के लिए स्वतन्त्र रहने दिया गया। किंतु पैंसठ लाख चेक जनता को एक बार फिर जर्मन शासन—जो उस शासन से बहुत भिन्न था जिसका अनुभव चेक जनता ऑस्ट्रियन साम्राज्य के अंग के रूप में कर चुकी थी—वे अन्तर्गत ले आया गया।

युद्ध का आरम्भ (Outbreak of War)

विजेता के रूप में प्रेग में प्रविष्ट होने के तुरन्त बाद ही हिटलर ने लिथुआनिया (Lithuania) की सरकार को एक अलटीमेटम देकर यह माँग की कि मेमल (Memel) और उसके आसपास का जिला उसे सौंप दिया जाये। इक्कीसवीं मार्च को उस पर अधिकार कर लिया गया और इस बाल्टिक बंदरगाह का पुनः सैनिकरण (re-militarisation) तुरन्त ही प्रारम्भ हो गया। लगभग इसी समय रिबेन्ट्रॉप ने पोलैंड के राजदूत को वे अन्तिम शर्तें बताईं जो जर्मनी पोलिश सरकार पर लादना चाहता था। ये शर्तें थी—डानजिग—जो विस्तुला (Vistula) का प्रवेश द्वार है—जर्मनी को पुनः लौटा दिया जाये तथा जर्मनी को वह क्षेत्र दिया जाये जो पूर्वी प्रशा से शेष जर्मनी को संयुक्त करता है। इस पर पोलैंड का उत्तर यह था कि वह इन आरोपित शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है।

चूँकि यह स्पष्ट था कि हिटलर द्वारा चेम्बरलेन को स्वयं दिया गया आश्वासन महत्वहीन था, और पोलैंड के प्रति भी वे ही चार्ज प्रारम्भ हो गई थी

जो कि चेकोस्लोवाकिया के प्रति चली गई थी इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भ्रम यह धोखा करने का निष्पत्तिक कदम उठाया कि, “यदि ऐसी कोई कार्यवाई की गई जिससे पोलैंड की स्वतन्त्रता को स्पष्ट ही खतरा हुआ और यदि पोलिश सरकार अपनी राष्ट्रीय सेनाओं से उसका मुकाबला करना आवश्यक समझे” तो ग्रेट ब्रिटेन अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता पोलैंड को देगा। फ्रांस पहिले से ही पोलैंड का मित्र था; किन्तु चेम्बरलेन को यह कहने का अधिकार दिया गया था कि वे फ्रांस की ओर से भी यह बात कह सकते हैं।

कुछ ही दिनों के बाद, इटली ने तैजो से हमसा कर अलबानिया बन्दरगाहों पर अधिकार कर लिया तथा उसका स्वामी बन बैठा। अलबानिया की स्वतन्त्रता की रक्षा करने का भार, विधि की विडम्बना से, विशेष रूप से इटली को ही सौंपा गया था। इस प्रकार आक्रमण एक नए क्षेप में प्रारम्भ हो गया। ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी नीति को यहाँ तक मोड़ा कि फ्रांस के साथ मिलकर उसने ग्रीस और रूमानिया को उस प्रकार की सहायता की गारन्टी दी जैसी पोलैंड को दी गई थी। पोलैंड ने भी अपनी महत्ता का अनुभव कर यह गारन्टी पारस्परिक आधार पर दी थी और आक्रमण की स्थिति में फ्रांस तथा ग्रेट ब्रिटेन की सहायता करने का वचन दिया था। यूगोस्लाविया, जिससे सम्भवतः ग्रीस से कम खतरा नहीं था, ने भी यह धोखा की कि उसे सहायता की आवश्यकता नहीं है। जर्मनी और इटली दोनों ही के साथ उसके व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ रहे थे और चेकोस्लोवाकिया का उदाहरण ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार की गारन्टी को बहुत अधिक सरक्षण मानना सहज नहीं था। जो भी हो ग्रीस तथा उसके बन्दरगाहों में, ब्रिटेन की सहायता से पहुँचा जा सकता था। रूमानिया के पास रूस के बेसारेबिया (Bessarabia) क्षेत्र और बल्गेरिया के दोब्रुजा (Dobrudja) क्षेत्र तथा ट्रान्सिलवानिया का हगेरियन क्षेत्र था, इस कारण वह सहायता का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार कर सकता था। इसके अतिरिक्ति, इस समय ब्रिटिश सरकार को टर्की से एक सधि कर सकने में सफलता मिल गई जिसके अनुसार संपिक्तीको में से प्रत्येक ने यह वचन दिया कि यदि भूमध्यसागर क्षेत्र में उनके हितों को किसी प्रकार का खतरा उपस्थित हुआ, तो वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसी प्रकार का एक समझौता टर्की और फ्रांस के बीच उस समय किया गया था जब अलेक्जेंड्रेट्टा के सेन्डजाक (Sandjak of Alexandretta) क्षेत्र से सम्बन्धित टर्की के दावे पूरी तरह संतुष्ट किए जा चुके थे।

ग्रेट ब्रिटेन में इन तैयारियों में और भी गति उस समय आई जबकि २० अप्रैल को एक विधेयक (Bill) प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार रण-सेवा योग्य आयु (military age) के सभी आदमियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया जाना था। उसके स्वीकार हो जाने पर, उन्नीस और बीस वर्ष के आदमियों को तुरन्त ही सेना में भरती होने के लिए आमन्त्रित किया गया। योगोपरीय ढंग (Continental model) पर आतंकाल में इस अनिवार्य-भर्ती सेना (conscript army) के संगठन को ग्रेट ब्रिटेन के इस निश्चय का, कि और अधिक आक्रमण को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया जाए, सबसे सबल प्रमाण माना गया था। जर्मन सरकार ने ब्रिटेन की इन सारी कार्रवाइयों को इस बात का प्रमाण माना कि, “ब्रिटिश लोग ब्रिटेन द्वारा युद्ध आरम्भ करने को अब असंभव नहीं मानते बल्कि इसके विपरीत उसे ब्रिटिश नीति की प्रमुख समस्या (capital problem) मानते हैं।” (“that the British no longer regard war by Britain as an impossibility, but on the contrary as a capital problem of British policy”)। अप्रैल की सत्ताइसवी तारीख को उसने १९३५ के आंग्ल-जर्मन नौसैनिक समझौते (Anglo-German naval agreement of 1935) को मानने से भी इन्कार कर दिया जिसके अनुसार जर्मनी ने अपनी नौसेना ब्रिटेन की नौसेना के पैंतीस प्रतिशत तक ही सीमित रखना स्वीकार कर लिया था। हिटलर ने यह शिकायत की कि ग्रेट ब्रिटेन उस समझौते की अवहेलना कर रहा है जिस पर कि स्वयं उसने और चेम्बरलेन ने म्युनिक सम्मेलन के बाद हस्ताक्षर किए थे तथा जो “दोनों ही देशों की जनता की इस इच्छा का प्रतीक (symbol) था कि वे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे।” तथा ब्रिटेन अब जर्मनी को घेरने की नीति पर पुनः चलने लगा है।

वास्तव में इस नीति का जोरो से अनुसरण किया जा रहा था किन्तु इसके लिए पर्याप्त कारण था क्योंकि यह तो स्पष्ट था ही कि यदि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही उसे किसी भी प्रकार की सीधी सहायता नहीं दे सकेंगे। उनके द्वारा दी गई गारन्टी का समबत-रोधक मूल्य (deterrent value) ही हो सकता था। यह बात भी इतनी ही स्पष्ट थी कि यदि तोखिल सच दो पड़ोसी प्रजातन्त्रों के साथ सहयोग करता, तो

विशाल लायुसेना द्वारा एक विशाल सेना आक्रमणकर्ता (aggressor) के अग्रगण्य समीप ही जमा की जा सकती थी। फ्रांस अब भी सोवियत संघ का मित्र था, तथा मार्च के बाद से, संयुक्त कार्रवाई सबको वार्नार्ण मास्को में चल रही थी, और यह विश्वास के साथ कहा जाता था कि उनका परिणाम अनुकूल (favourable) निकलेगा, विशेषकर उस स्थिति में जब यह घोषणा की गई थी कि वार्ताओं में भाग लेने के लिए फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के सैनिक प्रतिनिधि भेजे गए हैं। किन्तु वार्ताओं में आकुलताकारी विलंब (perplexing delay) हुआ तथा यह ज्ञात हो सका कि सोवियत संघ तब तक कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि वास्तिक राज्यों, लिथुआनिया, लेटविया (Latvia), इस्टोनिया और फ़िनलैंड सभी सोवियत गारण्टी भी उसमें शामिल न हो। जो भी हो, इन देशों ने यह घोषणा की कि उन्हें ऐसी किसी गारण्टी की आवश्यकता नहीं है जो उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी करती हो। उन्होंने जर्मनी के साथ अनाक्रमण समझौते (non-aggression pacts) करने का प्रस्ताव रखा और किया भी ऐसा ही। पोलैंड ने भी अपने क्षेत्र में किन्हीं भी परिस्थितियों में, सोवियत सेना को प्रविष्ट होने देने से इन्कार कर दिया। इतना सब कुछ होते हुए भी, बूँक हिटलर की नीति का प्रभुल उद्देश्य, सोवियत संघ जिसका भी पक्ष ले, उसका प्रचंड विरोध करना था, मतएव यह धाशा करना स्वाभाविक ही था कि सोवियत संघ ऐसी किसी भी कार्रवाई में सहायता पहुँचाएगा जो कि एकसंघात्मक जर्मन गणतंत्र (Third Reich)* की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए की जाये। इसी समय एकाएक यह बात हुआ कि जर्मनी और रूस के बीच एक अनाक्रमण समझौता करने के लिए रिबेन्ट्रॉप मास्को आ पहुँचा है। इस प्रकार के समझौते पर २३ अगस्त को हस्ताक्षर होगे। इस समझौते का केवल यही फल नहीं हुआ कि पूर्व में जर्मनी का जो कुछ भी विरोध होता वह पोलैंड को अपने ही साधनों के भरोसे करना

*First Reich—Germany as an Empire.

Second Reich—Federal republic

Third Reich—Unitary republic—Tr.

पड़ता अपितु इसका परिणाम यह भी हुआ कि उसे रसद (supply) का एक ऐसा साधन मिल गया जिससे किसी भी समुद्रीय नाकेबंदी (maritime blockade) का खतरा बहुत कम हो गया।

इस घोषणा के बाद, ग्रेट ब्रिटेन पोलैंड को दिए गए अपने वचन वापस ले लेगा—यह भाषा इतनी प्रबल प्रतीत होती थी कि चेम्बरलेन ने जर्मन प्रधानमंत्री को सचेत करते हुए स्वयं लिखा कि “यदि परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो ब्रिटिश सरकार बिना किसी विलम्ब के अपनी पूरी ताकत का उपयोग करेगी।”¹ चेम्बरलेन ने यह यह भी लिखा कि उनके मतानुसार (in his judgment) जर्मनी और पोलैंड के बीच ऐसा कोई प्रश्न ही विवादास्पद (at issue) नहीं है जो ताकत का प्रयोग किए बिना हल नहीं किया जा सकता हो तथा नहीं किया जाना चाहिये (“could not and should not be resolved without the use of force”)।

जर्मनी और पोलैंड के बीच तत्कालीन विवाद डानजिग और तथाकथित—गलियारे (corridor) से संबंधित था जो बर्सेलीज की संधि द्वारा जर्मनी से पृथक् कर दिए गये थे। क्षेत्र जर्मनी से पूर्वी प्रशा के विभाजन का भी हमेशा विरोध किया जाता था। इससे विपरीत स्वयं हिटलर ने भी प्रायः यह स्वीकार किया था कि पोलैंड को समुद्री मार्ग की आवश्यकता है। किन्तु पोलैंड ने मछली व्यवसाय प्रधान ग्राम गिडनिया (fishing village of Gdynia) में, अपने ही क्षेत्र में, एक नए बंदरगाह का निर्माण कर विस्तुला (Vistula) में व्यापार के लिए एकमात्र बंदरगाह के रूप में डानजिग के एकाधिकार को ही न केवल समाप्त कर दिया था अपितु उसकी महत्ता में भी वास्तव में कमी कर दी थी। व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता और राजनैतिक आदर्शवाद इस प्रश्न के साथ जुड़ गये। किन्तु जर्मनी में डानजिग को शामिल करने की इच्छा उस पर अधिकार करने वाले राष्ट्र की यह महत्वाकांक्षा सूचित करती थी कि वह राष्ट्र वहाँ पर सैन्य शक्ति का ऐसा केन्द्र स्थापित करना चाहता था कि वह पोलैंड का समुद्र से संबंध तोड़ सके। गलियारे के भारपार एक क्षेत्रातीत कटिबंध (extra-

1. “If the case should arise, the British Government would employ without delay all the forces at their command”.

territorial belt) के लिए किए गए एक और दावे को पोलैंड ने मस्वीकरा कर दिया क्योंकि इसे उसने जर्मनी द्वारा पोलैंड का और अधिक क्षेत्र जर्मनी में मिलाये जाने संबंधी प्रथम कदम समझा। इन कारणों से पोल लोगोंने आत्म-समर्पण करने से इन्कार कर दिया। अब जर्मनी द्वारा तीन पुषक् मोर्चों पर पोलिश क्षेत्र पर एक साथ आक्रमण किया जाना था। यह आक्रमण पहिली सितम्बर को हुआ। तीन सितम्बर को ग्रेट ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी और, उसके कुछ ही घंटों बाद, फ्रांस ने भी एण्मेरी फ्लैंक दी।

परिशिष्ट
(Appendices)

१. मुनरो सिद्धांत (Monroe Doctrine)

[अमरीकी राष्ट्रपति मुनरो द्वारा २ दिसम्बर १८२३ को
की गई घोषणा से उद्धरण]

.....यह प्रयत्न इस सिद्धांत—जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार और हित (rights and interests) सम्बन्धित (involved) हैं—को घोषणा करने के लिए उपयुक्त है कि अमरीकी महाद्वीप, जिसने अपनी स्थिति मुक्त एवं स्वतंत्र (free and independent) बनाली है तथा उसे इस प्रकार बनाए रखा है, को कोई भी योरोपीय राष्ट्र भविष्य में उपनिवेशीकरण के उपयुक्त न समझे ।

.....जब हमारे अधिकारों पर आघात किया जाता है या जब उन्हें गंभीर खतरा उपस्थित हो जाता है केवल तब ही हम क्षति के प्रति रोष प्रकट करते हैं या अपनी प्रतिरक्षा के लिए तैयारी करते हैं । इस मोक्षार्थ में जो भी गति-विधियाँ की जाएँ, उनसे हमारा आवश्यक रूप से निकटतर संबंध है । इसके जो कारण हैं वे सभी विज्ञ (enlightened) और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों (observers) को स्पष्ट होने चाहिए । मित्र राष्ट्रों (allied powers)* की राजनैतिक शासन-प्रणाली इस बारे में अमेरिका की शासन-प्रणाली से आवश्यक रूप से भिन्न है । यह अन्तर उनकी संबंधित सरकारों में विभिन्नता के कारण है । अपनी इस प्रणाली की प्रतिरक्षा के लिए, जो जन धन (blood and treasure) की इतनी क्षति उठाकर प्राप्त की गई है तथा जो कि उसके अपने विज्ञतम (most enlightened) नागरिकों की बुद्धिमत्ता से परिपक्व (matured) हुई और जिसके अवीन हमने अपूर्व सुख (unexampled felicity) का उपभोग किया है, यह सारा राष्ट्र कृत-संकल्प है । अतः अमेरिका और उक्त राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण तथा स्पष्ट भाषण (candour) की भावना से प्रेरित होकर हम यह जता देना चाहते हैं कि यदि उन्होंने अपनी प्रणाली को

*अर्थात् ब्रिटेन, फ्रांस, प्रशा और रूस ।

इस गोलाघं में भी फैलाने का कोई प्रयत्न किया, तो उनके इस प्रयत्न को हमारी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा समझा जाएगा। किसी भी योरोपीय राष्ट्र के वर्तमान उपनिवेशों अथवा अधीन क्षेत्रों में हमने न तो हस्तक्षेप किया ही है और न करेंगे ही। किन्तु जिन सरकारों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है, उसे बनाए रखा है, तथा उनकी उस स्वतंत्रता को हमने बहुत सोच विचार और न्याय्य सिद्धान्तों पर मान्यता दे दी है, उन पर अत्याचारपूर्ण शासन करने या अन्य किसी प्रकार से उनके भाग्य को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यदि किसी योरोपीय राष्ट्र द्वारा हस्तक्षेप किया गया, तो हम उसे संयुक्त-राज्य अमेरिका के प्रति अमित्रतापूर्ण रुख के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं समझ सकेंगे।

२. विलसन के चौदह सूत्र (Fourteen Points)

[जनवरी ८, १९१८ को अमरीकी कांग्रेस (Congress) में राष्ट्र-पति विलसन द्वारा दिए गए अभिभाषण (Address) से उद्धरण]

(१) प्रकट रूप से किए गए शांति के इन प्रकट अनुबन्धनों (covenants) के बाद, किसी भी प्रकार के गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय समझौते नहीं किए जाएंगे और कूटनीतिक गतिविधि सदैव ही स्पष्ट रूप से तथा लोगों को अन्धकार में रखे बिना ही (in the public view) की जाएगी ।

(२) जब तक कि अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धनों को लागू करने के लिए सामुद्रिक आवागमन अन्तर्राष्ट्रीय कारेंवाई द्वारा आशिक रूप में या पूरी तरह से बन्द नहीं कर दिया जाए, तब तक शांति और युद्ध काल दोनों ही में समान रूप से क्षेत्रिक सागर (territorial waters) से बाहर भी सामुद्रिक आवागमन (navigation) की पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी ।

(३) शांति स्वीकार करने और उसे बनाए रखने के लिए संगठित होने वाले राष्ट्रों के लिए, ध्यासंभव, सभी आर्थिक रुकावटें दूर की जाएंगी तथा राष्ट्रों में परस्पर व्यापार के लिए समान अवसर प्राप्त कराने की परिस्थितियाँ निर्मित की जाएंगी ।

(४) इस बात की पर्याप्त गारन्टियाँ ली और दी जाएंगी कि गृह-सुरक्षा (domestic safety) से संगति रखते हुए, राष्ट्रों के शास्त्रात्मक कम से कम कर दिए जाएँ ।

(५) सभी औपनिवेशिक राज्यों का निर्वाध, उदार और पूर्ण निष्पक्ष समायोजन कर लिया जाएगा जिसका आधार इस सिद्धान्त का कठोर पालन होगा कि सार्वभौमत्व के ऐसे सभी प्रश्नों का निराकरण करते समय सम्बन्धित जनता के हितों का भी उतना ही ध्यान रखा जाएगा जितना उस सरकार के न्याय्य (equitable) दावों का जिसका कि हक (title) निश्चित किया जाना है ।

(६) समस्त रूसो क्षेत्र से सेनाएं हटा ली जाएं और रूस से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का इस प्रकार समाधान निकाला जाए कि रूस को अपने राजनैतिक विकास और अपनी राष्ट्रीय नीति के स्वतन्त्र निर्धारण के लिए बाधाराहित तथा अडचनहीन (unhampered and unembarrassed) अवसर प्राप्त कराने तथा उसे यह आश्वासन दिलाने—आश्वासन ही क्या, वह जैसी सहायता स्वयं चाहे या उसे जैसी सहायता की आवश्यकता हो वैसी सहायता उपलब्ध कराने—कि उसकी अपनी संस्थाओं के होते हुए भी (under institutions of her own choosing) स्वतन्त्र राष्ट्रो के समाज में उसका हार्दिक स्वागत (sincere welcome) होगा, मे विश्व के अन्य राष्ट्रों का सर्वाधिक और उन्मुक्त (free and best) सहयोग प्राप्त हो सके। आगामी महीनों में रूस के साथ अन्य देशों द्वारा जो व्यवहार किया जाएगा, वह उनकी सद्भावना (goodwill), उनके अपने हितों की तुलना में उसकी आवश्यकताओं के प्रति समझदारी तथा उनकी बुद्धिमत्ता और स्वार्थहीन सहानुभूति की अग्नि परीक्षा (acid test) होगा।

(७) सारी दुनिया इस बात पर सहमत होगी कि बेल्जियम से सेनाएं हटा ली जानी चाहिए तथा उसे पुनः अपना पूर्व अस्तित्व प्राप्त हो जाना चाहिए किन्तु उसके उस सार्वभौमत्व में कमी करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए जिसका उपभोग वह अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ ही साथ कर रहा है। इस कार्य के प्रतिरिक्त और कोई भी कार्य राष्ट्रों में उन विधियों (laws) के प्रति बिस्मय पैदा नहीं कर सकेगा जो स्वयं उन्होंने एक दूसरे के सम्बन्धों के नियमन (government) के लिए निश्चित किए हैं। इस उपचारक कार्य (healing act) के बिना अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सारा ढाँचा और बँधता सदैव ही अधूरे रहेंगे।

(८) सारा फ्रांसीसी क्षेत्र स्वतन्त्र कर दिया जाए और आक्रमित भाग उसे पुनः लौटा दिए जाएं तथा आल्सेक लॉरेन (Alsace Lorraine) के सबष में प्रशा ने १८७१ में फ्रांस को जो क्षति पहुँचाई है तथा जिसने लगभग पचास वर्षों तक विश्व शांति को अनिश्चित बना रखा है, उसकी पूर्ति की जाए ताकि सभी के हित में शांति को एक बार सफ्टरहित (secure) बनाया जा सके।

(९) इटली के सीमान्तों का समायोजन (adjustment) राष्ट्रीयता (nationality) के स्पष्ट मान्य आधार पर पुनः किया जाए।

(१०) प्रॉस्ट्रिया-हंगरी की जनता को राष्ट्रों में जिसका स्थान हम सुरक्षित और निश्चित देखना चाहते हैं, स्वायत्तशासिक विकास का सर्वाधिक निर्वाध (freest) अवसर दिया जाना चाहिए ।

(११) रूमानिया, सर्बिया (Serbia) और मॉन्टेनेग्रो (Montenegro) खाली कर दिए जाएं, अधिकृत क्षेत्र वापस तोटा दिए जाएं; सर्बिया को निर्वाध तथा सुरक्षित समुद्री मार्ग दिया जाए; तथा विभिन्न बालकन राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध निष्ठा और राष्ट्रीयता (allegiance and nationality) के इतिहास सिद्ध (historically established) आधार पर मित्रतापूर्ण सलाह (friendly counsel) द्वारा निश्चित किए जाएं एवं विभिन्न बालकन राज्यों की राजनैतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता और क्षेत्रिक प्रसङ्गता (territorial integrity) की अन्तर्राष्ट्रीय गारंटियों सम्बन्धी समझौते किए जाएं ।

(१२) वर्तमान अॉटोमान साम्राज्य (Ottoman Empire) के तुर्की भागों को सुरक्षित सार्वभौमत्व (secure sovereignty) का आश्वासन दिया जाए किन्तु इस समय जो अन्य राष्ट्र-जातियाँ (nationalities) तुर्की शासन में रह रही हैं उन्हें बिल्कुल सुरक्षानुष्ठान जीवन तथा स्वायत्तशासिक विकास के हस्तक्षेप हीन अवसर (unmolested opportunity) का आश्वासन दिया जाए तथा डारडेनेल्लोज (Dardanelles) को अन्तर्राष्ट्रीय गारंटियों के अनुसार सभी राष्ट्रों के व्यापार और जहाजों के लिए निर्वाध मार्ग के रूप में स्थायी रूप से खोल दिया जाए ।

(१३) एक स्वतंत्र पोलिश राज्य की स्थापना की जाए जिसमें वे क्षेत्र शामिल किए जाएं जिनमें निर्विवाद रूप से पोल आवासी हो । इस राज्य को सुरक्षित और निर्वाध समुद्री मार्ग दिया जाए तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा उसकी आर्थिक और राजनैतिक स्वतन्त्रता तथा क्षेत्रिक प्रसङ्गता की गारंटी दी जाए ।

(१४) छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के राष्ट्रों की राजनैतिक स्वतन्त्रता और क्षेत्रिक प्रसङ्गता की पारस्परिक गारंटियाँ समान रूप में प्राप्त हो सकें, इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए कुछ विशिष्ट अनुबंधों (specific covenants) के अनुसार राष्ट्रों के एक विशाल संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए ।

३- राष्ट्रसंघ (League of Nations) के अनुबंधपत्र से उद्धरण (extracts)

[इसमें वे सभी धाराएँ शामिल हैं जिनका संदर्भ
इस पुस्तक में दिया गया है]

अनुच्छेद १

“... और यदि समा का दो-तिहाई बहुमत उसे सदस्य बनाना स्वीकार करे, तो ऐसा कोई भी पूर्णतः स्वशासी (fully self-governing) राज्य, अधिदेश या उपनिवेश जिसका उल्लेख परिशिष्ट (Annex) में न किया गया हो, राष्ट्रसंघ का सदस्य बन सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसे अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करने की अपनी सच्ची इच्छा की प्रभावकारी गारंटियाँ देनी पड़ेंगी तथा उसकी भुसेना, नौसेना और वायुसेना तथा शस्त्रास्त्र सबकी जो विनियम (regulations) राष्ट्रसंघ द्वारा निश्चित किए जाएँगे, उन्हें वह स्वीकार करेगा।

अनुच्छेद ४

“..... यदि राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य परिषद् का सदस्य न हो और यदि उसके हितों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले विषयों पर परिषद् की किसी बैठक में विचार किया जाना हो तो उसे परिषद् की उस बैठक में सदस्य की हस्तियत से शामिल होने के लिए, एक प्रतिनिधि भेजने के लिए आमन्त्रित किया जायेगा।

अनुच्छेद ५

जब तक कि इस अनुबंधपत्र में अथवा वर्तमान संधि की शर्तों के द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबोधित (otherwise expressly provided) न किया गया हो, समा या परिषद् की किसी भी बैठक में निर्णय के लिए बैठक में उपस्थित राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों की सहमति (agreement) आवश्यक होगी।

समा या परिषद् की बैठकों की प्रक्रिया (procedure) संबंधी सभी मामलों, जिनमें विशेष मामलों की जाँच के लिए समितियों की नियुक्ति भी शामिल

होगी, का विनियमन सभा या परिषद् द्वारा किया जाएगा तथा उनसे संबंधित निर्णय बैठक में उपस्थित राष्ट्रसंघ के सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जा सकेगा।

अनुच्छेद ८

राष्ट्रसंघ के सदस्यों की यह मान्यता है कि शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से संगति रखने हुए, राष्ट्रीय शस्त्रास्त्रों का कम से कम किया जाना तथा सामूहिक कार्रवाई (common action) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन किया जाना आवश्यक है।

अनुच्छेद १०

राष्ट्रसंघ के सदस्य संघ के सभी सदस्यों की सैनिक अखंडता (territorial integrity) तथा वर्तमान राजनैतिक स्वतन्त्रता का स्वयं सम्मान करने तथा बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का वचन देते हैं। ऐसे किसी आक्रमण के समय या ऐसे किसी आक्रमण की धमकी या खतरे के समय, परिषद् यह परामर्श देती कि किन उपायों द्वारा यह कर्तव्य पूरा किया जा सकता है।

अनुच्छेद ११

कोई भी युद्ध अथवा युद्ध की धमकी, चाहे उसका प्रभाव राष्ट्रसंघ के किसी भी सदस्य पर तत्काल ही पड़ता हो अथवा न पड़ता हो, इसके द्वारा (hereby) सारे राष्ट्रसंघ से सम्बन्धित घोषित किए जाते हैं तथा राष्ट्रसंघ ऐसी कोई भी कार्रवाई कर सकेगा जो कि राष्ट्रों की शांति बनाए रखने के लिए उचित और प्रभावपूर्ण समझी जाए। यदि ऐसा कोई संकट-काल (emergency) उपस्थित होगा, तो राष्ट्रसंघ के किसी भी सदस्य के अनुरोध पर महासचिव (Secretary-General) तुरन्त ही परिषद् की बैठक बुलाएगा।

राष्ट्रसंघ के हर सदस्य का यह भी मित्रतापूर्ण अधिकार (friendly right) घोषित किया जाता है कि वह सभा या परिषद् के ध्यान में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव डालने वाली ऐसी कोई भी परिस्थिति ला सकेगा जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति भंग होने या राष्ट्रों के बीच सद्भावना—जिस पर कि शांति निर्भर करती है—विगड़ने की आशंका हो।

अनुच्छेद १२

राष्ट्रसंघ के सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि यदि उनके बीच कोई

ऐसा विवाद उठ खड़ा हो जिसका परिणाम विग्रह (rupture) हो सकता हो तो वे उस मामले के सम्बन्ध में पचनिर्णय कराएँगे या न्यायालय में उसका निबटारा कराएँगे या जाँच (inquiry) के लिए परिषद् के पास भेजेंगे और वे इस बात पर भी सहमत हैं कि वे तब तक युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे, जब तक कि पक्षों के फैसले या न्यायालय के निर्णय या परिषद् के प्रतिवेदन की तीन माह न बीत गए हों।

अनुच्छेद १४

स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के लिए परिषद् योजनाएं बनाकर राष्ट्रसंघ के सदस्यों के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगी। यह न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के ऐसे किसी भी विवाद को सुन सकेगा और उस पर निर्णय दे सकेगा जो कि विवाद से संबंधित पक्ष उसके सामने प्रस्तुत करें। यदि परिषद् या सभा कोई प्रश्न या विवाद उसके पास भेजे, तो न्यायालय अपनी परामर्शपूर्ण राय (advisory opinion) भी दे सकेगा।

अनुच्छेद १५

यदि राष्ट्रसंघ के सदस्यों के बीच ऐसा कोई विवाद उठ खड़ा हो, जिसका परिणाम संभवतः विग्रह हो सकता हो और यदि उसे अनुच्छेद १३ के अनुसार पचनिर्णय या न्यायालय द्वारा निबटारे के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो राष्ट्रसंघ के सदस्य यह समझौता करते हैं कि वे उस मामले को परिषद् के सामने प्रस्तुत करेंगे। विवाद से संबंधित कोई भी पक्ष महासचिव को विवाद विद्यमान होने की सूचना देकर इस प्रकार के मामले को प्रस्तुत कर सकता है। महासचिव उस विवाद की पूरी जाँच और उस पर विचार के लिए सभी प्रावश्यक प्रबन्ध करेगा।

परिषद् विवाद का निबटारा कराने का प्रयत्न करेगी और यदि इस प्रकार के प्रयत्नों में उसे सफलता मिली, तो एक वक्तव्य प्रकाशित किया जाएगा जिसमें विवाद सम्बन्धी वे तथ्य और स्पष्टीकरण तथा समझौते की वे शर्तें दी जाएँगी जिन्हें प्रकाशित करना परिषद् उचित समझे।

यदि विवाद का इस प्रकार निबटारा न हो सके, तो परिषद् या तो निर्विरोध मत से या बहुमत द्वारा एक प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करेगी जिसमें विवाद सम्बन्धी तथ्यों और उन सिफारिशों का उल्लेख किया जाएगा जो कि सम्बन्धित

विवाद के सबंध में न्याय्य और उचित (just and proper) समझ कर की जाए.....

यदि विवाद से सम्बन्धित एक या अधिक पक्षों के प्रतिनिधियों के प्रतिरिक्त परिषद् के अन्य सदस्य, किसी प्रतिवेदन पर एकमत हो जाएँ (unanimously agree to), तो राष्ट्रसंघ के सदस्य यह समझना करते हैं कि वे विवाद से सम्बन्धित उस पक्ष के विरुद्ध युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे जो कि प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का पालन करे।

यदि परिषद् ऐसा प्रतिवेदन तैयार करने में असफल रहे जिस पर विवाद से सम्बन्धित एक या अधिक पक्ष के प्रतिनिधियों को छोड़कर उसके सदस्य एकमत हो सकें, तो राष्ट्रसंघ के सदस्यों का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे अधिकार और न्याय (right and justice) बनाए रखने के लिए, जो कार्रवाई करना वे आवश्यक समझें, उसे वे करें।

यदि विवाद से सम्बन्धित किसी पक्ष द्वारा यह दावा किया जाए तथा यदि परिषद् यह पाए कि विवाद ऐसे मामले से सम्बन्धित है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि (law) के अनुसार उस पक्ष के एक दम घरेलू अधिकार (domestic jurisdiction) में है, तो परिषद् इस आशय का प्रतिवेदन देगी तथा उसके निष्कारों के बारे में कोई सिफारिश नहीं करेगी।

इस अनुच्छेद के अधीन किसी भी स्थिति में परिषद् विवाद को सभा में भेज सकती है। यदि विवाद से सम्बन्धित कोई भी पक्ष अनुरोध करे, तो विवाद इस प्रकार सभा में भेजा जाएगा किन्तु शर्त यह है कि ऐसा अनुरोध परिषद् के समस्त विवाद प्रस्तुत किए जाने के चौदह दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद १६

यदि राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य अनुच्छेद १२, १३, या १५ के अधीन अपने अनुवन्धनों (covenants) की अवहेलना कर युद्ध का आश्रय ले, तो वह स्वतः ही (*ipso facto*) राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों के विरुद्ध युद्ध करने वाला समझा जाएगा। राष्ट्रसंघ के सदस्य इसके द्वारा यह वचन देते हैं कि वे तुरन्त ही उससे सभी प्रकार के वाणिज्यिक अथवा आर्थिक सम्बन्ध तोड़ लेंगे, अनुवन्धपत्र की अवहेलना करने वाले राज्य के राष्ट्रवासियों और अपने राष्ट्रवासियों के बीच सभी प्रकार का व्यवहार निषिद्ध कर देंगे, तथा अनुवन्धपत्र की अवहेलना करने वाले

राज्य के राष्ट्रवासियों तथा अन्य किसी भी राज्य के राष्ट्रवासियों के बीच समो प्रकार के आर्थिक, वाणिज्यिक और व्यक्तिगत (personal) व्यवहार को, रोकेंगे चाहे वह राज्य राष्ट्रसंघ का सदस्य हो अथवा न हो ।

ऐसी स्थिति में परिपद का यह कर्तव्य होगा कि वह संबंधित विभिन्न सरकारों को यह सिफारिश करे कि राष्ट्रसंघ के अनुबन्धनों (Covenants of the League) की रक्षा के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सशस्त्र सेना के लिए राष्ट्रसंघ के सदस्य कितनी संख्या में समर्थ बलसेना, नौसेना या वायुसेना पुरस्कृत रूप से हों ।

अनुच्छेद १७

यदि राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य और ऐसे किसी या किन्हीं राज्य या राज्यों के बीच विवाद हो, जो कि राष्ट्रसंघ का/कि सदस्य न हो/हों, तो ऐसे राज्य अथवा राज्यों से संबंधित विवाद के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रसंघ की सदस्यता के कर्तव्यों को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करने का अनुरोध किया जा सकता है, जैसी कि परिपद श्याम समझे . "

अनुच्छेद १६

समय समय पर सभा राष्ट्रसंघ के सदस्यों को विश्व शान्ति को जिन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के जारी रहने से खतरा हो सकता है उन पर विचार करने तथा ऐसी संधियों पर पुनर्विचार करने की सलाह दे सकती है जो कि इस समय अप्रवर्तनीय (inapplicable) हो गई हो ।

अनुच्छेद २१

इस अनुच्छेद की किसी भी बात का किन्हीं ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों—जैसे पंच निर्णय-संधियों (treaties of arbitration) तथा मनरो सिद्धान्त ॥ समान प्रादेशिक समझौतों (regional understandings) की बंधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि शांत बनाए रखने के लिए किए गए हो ।

अनुच्छेद २२

उन उपनिवेशों और क्षेत्रों पर, जो कि पिछले युद्ध के परिणामस्वरूप उन राज्यों के सार्वभौमत्व में नहीं रह गए थे, जिनका पहिले उन पर शासन था तथा जिनमें ऐसे लोग बसते हैं, जो कि आधुनिक विश्व की कठिन परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े होने योग्य नहीं हैं, यह सिद्धान्त लागू किया जाए कि ऐसे

लोगों का कल्याण और विकास (well-being and development) सभी देशों का पवित्र कर्तव्य (sacred trust of civilisation) है तथा इस कर्तव्य के निश्चित रूप से पालन के लिए व्यवस्था इसी अनुबंधपत्र में कर दी जाए।

इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ऐसे लोगों का संरक्षण उन समुचित राष्ट्रों को सौंपा जाए जो अपने साधनों, अपने अनुभव या अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, इस जिम्मेदारी को सब से अच्छी तरह निभा सकते हों तथा जो यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए प्रस्तुत हों तथा इस संरक्षण अधिकार का उपयोग वे राष्ट्रसंघ की ओर से संरक्षक-राज्य के रूप में करें।

सम्बन्धित जनता के विकास की अवस्था, उनके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक हालत और इसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण संरक्षित राज्यों का स्वरूप विभिन्न होगा।

पहिले तुर्की साम्राज्य में शामिल कुछ समुदाय (certain communities) विकास की ऐसी अवस्था तक पहुँच गए हैं कि उनके अस्तित्व अस्थायी रूप से स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में माना जा सकता है किन्तु कोई एक संरक्षक-राज्य उन्हें तब तक प्रशासकीय सलाह (administrative advice) और सहायता देता रहेगा, जब तक कि वे अपने पैरों पर स्वयं खड़े न हो जाएँ। संरक्षक-राज्य का चुनाव करते समय इन समुदायों की इच्छाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्य लोग—विशेषकर मध्य अफ्रीका में—ऐसी अवस्था में हैं कि संरक्षक-राज्य की जिम्मेदारी उनके क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन करना होना चाहिए कि उन लोगों को विश्वास और धर्म (conscience and religion) की स्वतन्त्रता—जिस पर केवल सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता (public order and morals) बनाए रखने का ही बंधन हो (subject only to)—की गारंटी प्राप्त हो सके तथा दुष्कर्मों (abuses) जैसे दास व्यापार, शस्त्रास्त्र व्यापार तथा शराब के व्यापार का निषेध किया जा सके एवं किले-बंदी अथवा पलसेनिक या नोसेनिक अड्डे बनाना और पुलिस प्रयोजनों तथा क्षेत्रों

को रक्षा के अतिरिक्त अन्य किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए, देशी (native) लोगों को सैनिक प्रशिक्षण देना रोका जा सके एवं राष्ट्रसंघ के अन्य सदस्यों को व्यापार और वाणिज्य के लिए समान अवसर भी प्राप्त हो सकें ।

ऐसे भी क्षेत्र हैं—जैसे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और कुछ दक्षिण प्रशांत द्वीप—जो जनसंख्या के छिंतरे होने के या छोटे होने या सम्पत्ता के केन्द्रों से दूर पड़ जाने अथवा सुरक्षक-राज्य के क्षेत्र से भौगोलिक निकटता तथा अन्य परिस्थितियों के कारण, सुरक्षक-राज्य के क्षेत्र के ही अविभाज्य भागों के रूप में सुरक्षक राज्य की विधियों के अनुसार ही भली-भाँति शासित किए जा सकते हैं किन्तु देशी लोगों के हित की दृष्टि से उपलिखित सावधानियाँ (safeguards) बरती जानी चाहिए ।

हर सुरक्षित-राज्य के संबंध में, सुरक्षक-राज्य, उसे सौंपे गए क्षेत्र के संबंध में, परिषद् को एक वार्षिक प्रतिवेदन भेजेगा ।

सुरक्षक राज्य का किस सीमा तक प्राधिकार होगा, वह नियंत्रण का प्रशासन करेगा, इसका निश्चय राष्ट्रसंघ के सदस्यों ने पहिले से ही नहीं कर दिया हो, तो परिषद् हर मामले में यह सीमा स्पष्ट रूप से निश्चित करेगी ।

सुरक्षक-राज्यों के वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने और उनकी जाँच करने तथा सुरक्षक कर्तव्यों का पालन करने सबन्धी सभी मामलों पर परिषद् को परामर्श देने के लिए एक स्थायी आयोग की नियुक्ति की जाएगी ।

महत्त्वपूर्ण घटनाओं की कालक्रमानुसार तालिका

१९१८		
जनवरी	२	राष्ट्रपति विलसन के चौदह सूत्र
नवंबर	११	जर्मनी से विरामसन्धि
१९१९		
जून	२८	जर्मनी से वसेलीज की संधि ✓
सितंबर	१०	ग्रॉस्ट्रिया से सेंट जर्मेन की संधि ✓
नवंबर	१७	बलगेरिया से न्यूइसो की संधि ✓
१९२०		
जनवरी	१०	वसेलीज-संधि के अनुमोदन का विनिमय
		राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया
जून	४	हंगरी से ट्रिआन की संधि ✓
१९२१		
मार्च	१६	ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत रूस में व्यापारिक समझौता
मार्च	१८	पोलैंड और सोवियत रूस में रिगा की संधि
दिसंबर	१३	चार-राष्ट्र प्रशांत संधि पर वाशिंगटन में हस्ताक्षर
१९२२		
फरवरी	६	नौसैनिक संधि और चीन से सम्बन्धित नौ-राष्ट्र संधि
		पर वाशिंगटन में हस्ताक्षर
फरवरी	२८	ग्रेट ब्रिटेन द्वारा मिस्र की स्वतन्त्रता को मान्यता
अप्रैल	१६	जर्मनी और सोवियत रूस में रेपेलो की संधि
१९२३		
जनवरी	११	फ्रांसीसी और बेल्जियम सेनाओं द्वारा रूर पर अधिकार
जुलाई	२४	टर्की से जुमाने की संधि
१९२४		
फरवरी	१	ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सोवियत सरकार को मान्यता
अगस्त	३०	डेविस समझौते पर सन्धन में हस्ताक्षर

अक्टूबर २	राष्ट्रसंघ सभा द्वारा जेनेवा-उपसंधि स्वीकार
१९२५	
मार्च १०	ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जेनेवा उपसंधि स्वीकार
दिसम्बर १	लोकान्तर्गत संधियों पर लंदन में हस्ताक्षर
१९२६	
सितम्बर १०	राष्ट्रसंघ में जर्मनी का प्रवेश
१९२७	
जनवरी १	हकाऊ में चीनी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना
विसम्बर १८	रूसी कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रॉट्स्की का निष्कासन
१९२८	
अगस्त २७	पेरिस सम्मेलन (ब्रायएड वेल्थिंग सम्मेलन) पर हस्ताक्षर
१९२९	
अगस्त ३१	हेग सम्मेलन द्वारा रंग योजना का अनुमोदन
१९३०	
अप्रैल २२	नौसैनिक संधि पर लंदन में हस्ताक्षर
जून ३०	मिश्र-राष्ट्र सेनाओं द्वारा राइनभूमि खाली की गई
१९३१	
मार्च २१	जर्मनी और ऑस्ट्रिया में युगी संघ सम्मेलन
जून २०	राष्ट्रपति हूवर द्वारा भुगतान विलंब काल का प्रस्ताव
सितम्बर १९	जापान द्वारा मंचूरिया में सैनिक कार्रवाई का प्रारम्भ
सितम्बर २१	ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वयं-मान का परिचय
१९३२	
फरवरी २	निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का प्रारम्भ
जुलाई ६	लुसाने में क्षतिपूर्ति सम्मेलन पर हस्ताक्षर
अगस्त २०	ग्रेट ब्रिटेन और अधिराज्यों में व्यापारिक सम्मेलन पर
	ओटावा में हस्ताक्षर
अक्टूबर ३	ईराक से ब्रिटिश संरक्षण शासन की समाप्ति
१९३३	
जनवरी ३०	हर हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना

फरवरी २४	मंचूरिया संबंधी राष्ट्रसंघ-सभा का प्रस्ताव जापानी प्रतिनिधिमंडल द्वारा सदस्यता-त्याग
जून १२	विश्व अर्थ-सम्मेलन का प्रारम्भ
अक्टूबर १४	जर्मनी द्वारा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन तथा राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्यागने की घोषणा

१९३४

जनवरी २६	जर्मन पोलिश समझौते पर हस्ताक्षर
सितम्बर १८	सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया
अक्टूबर ६	मार्सेलोज में यूगोस्लाविया के छासक प्रलेक्जेंडर की हत्या

१९३५

जनवरी ७	सिनाई मुमोलिनो और मोसिये लावाल द्वारा रोम में फ्राम इटली समझौता पर हस्ताक्षर
मार्च १६	जर्मनी द्वारा वसॅलोज-संधि के सैनिक उपबन्धों का परित्याग
मई २	फ्रांसीसी-सोवियत समझौते पर हस्ताक्षर
अक्टूबर २	इटली का सेनाओं द्वारा अबीसीनिया में प्रवेश
नवंबर १८	इटली के विरुद्ध आर्थिक अनुशास्तियाँ लगाई गईं

१९३६

मार्च ७	जर्मनी असेनीकुन दोन पर पुनः अधिकार
मई ६	इटली द्वारा अबीसीनिया को अपने राज्य में मिलाया गया
जुलाई ४	इटली के विरुद्ध अनुशास्तियाँ हटा ली गईं
जुलाई १८	स्पेनिश गृहयुद्ध का प्रारम्भ

१९३७

जुलाई ८	जापान द्वारा चीन में अधोषित युद्ध का प्रारम्भ
---------	---

१९३८

मार्च १२	जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया को अपने राज्य में मिलाया गया
सितम्बर २६	चेकोस्लोवाकिया सम्बन्धी म्युनिक समझौता

१९३६

मार्च	१५	बोहेमिया और मोरेविया पर जर्मनी द्वारा अधिकार
अप्रैल	१	स्पेनिश गृहयुद्ध का अंत
अप्रैल	७	अलबानिया पर इटली द्वारा अधिकार
मई	२६	ग्रेट ब्रिटेन में अनिवार्य भरती स्वीकार
अगस्त	२३	जर्मन-सोवियत सम्झौते पर हस्ताक्षर
सितम्बर	१	पोलैंड पर जर्मनी द्वारा चढ़ाई
सितम्बर	३	ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा

.

शब्दावली

अंग्रेजी हिन्दी पर्याय

Abortive treaty	निष्फल संधि
Abrogate	रद्द होजाना
Absolute majority	पूर्ण बहुमत
Abuses	दुष्काय
Academic	विद्यालयीय
Acquiescence	मौन सम्मति
Accuser	आरोपक
Act	१. अधिनियम २. कृत्य
Administration of Justice	न्याय प्रशासन
Adverse vote	विपरीत मत
Advisory opinion	परामर्शपूर्ण राय
Afloat	कजबुक्क
Agenda	कार्यतुली
Agent	१. अभिकर्ता २. दलाल
Aggression, unprovoked	अकारण आक्रमण
Aggressive action	आक्रमणात्मक कारवाई
Aggressive invasion	आक्रमणात्मक चढाई
Aggressor	आक्रमणकर्ता
Agreement	१. करार, समझौता २. सहमति
Air Pact	वायुसेना समझौता
Air route	वायुपथ

Alcohol	मद्यसार
Alien race	विजातीय लोग
Alienation	१. परकीकरण २. स्वत्वान्तरण
Alleged	कथित
Alliance	१. युट्यदी २. मैत्री
Allied and Associated Power	मित्र और साथी राष्ट्र
Allied Commission	मित्र-राष्ट्रीय आयोग
Allied Commissioner	मित्र-राष्ट्रीय आयुक्त
Allied war debts	मित्र-राष्ट्रों के युद्धकालीन कर्ज
Alphabetical	वर्णानुसार
Altercation	झटपट
Ambassador's Conference	राजदूत सम्मेलन
American Immigration Act	अमरीकी आप्रवासन अधिनियम
<i>Amour-Propre</i>	आत्माभिमान
Anglo-Saxon	आंग्ल-सेक्सन
Annex (v.)	मिला लेना
Annual Conference	वार्षिक सम्मेलन
Annuity	वार्षिकी
Anomalous	विषम
Applicable	प्रभावशील
Application	१. आवेदनपत्र २. लागू होना
Arbitration	पंचनिर्णय
Arbitration treaty	पंचनिर्णय संधि
Arbitrator	पंच

Armament	१. शस्त्रास्त्र
Armed action	२. शस्त्रीकरण
Armistice	सशस्त्र कार्रवाई
Assessment	विराम सधि
Asset	निर्धारण
Autocracy	भास्ति
Autonomous	निरंकुशता
Autonomy	स्वायत्तशासो
Auxiliary Craft	स्वायत्ता
Axis	सहायक यान
Balance	धुरी
Balance of trade	संतुलन
Bank of International Settlement	व्यापार संतुलन
Basin	अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बैंक
Battleship	नदी क्षेत्र
Belligerent	युद्धपोत
Belt	युद्धरत
Beneficiary	कटिबंध
<i>Bete noir</i>	हितग्राही
Big Stick	भ्रांत का काटा
Bill	महा दण्ड
	१. विधेयक
	२. बिल
Bilateral	द्विपक्षी
Binding	बधनकारी
Black Shame	अश्वेत सज्जा
Blood and treasure	जन धन
Boom period	तेजी

Bond	१ बंधपत्र
Bond holder	२ ऋणपत्र
Brigade	ऋणपत्रधारी
Brigandage	ब्रिगेड
Budget	बूट-खसोट
Bulwark	आयव्ययक
Bureau	मुख्याधार
Business Concern	कार्यालय
Cabinet	व्यापारिक प्रतिष्ठान
Cabinet crisis	मन्त्रिमण्डल
Camp	मन्त्रिमण्डलीय संकट
Campaign	खेमा
<i>Candour</i>	अभियान
Capital ship	स्पष्ट भाषण
Capitulation	मुद्र पोत
Catholic Church	विमोक्त
Ceded territories	कैथोलिक धर्माधिकारी
Censure	समाप्त क्षेत्र
Censure, vote of	मर्खना
Chamber of Deputies	मर्खना प्रस्ताव
Champion	प्रतिनिधि सभा
Chancellor	पक्षधर
Chancellor of the Exchequer	प्रधानमन्त्री
Charge	वित्त मन्त्री
Civil	ऋणभार
	१ अर्थनिक
	२ नागरिक
Civil political leader	अर्थनिक राजनैतिक नेता

Civil servant	असैनिक कर्मचारी
Civil war	गृह-युद्ध
Classic	शास्त्रीय
Clerk	लिपिक
Cogent	प्रबल
Cognate race	सजातीय जाति
Colonial superiority	उपनिवेशीय श्रेष्ठता
Colonisation	उपनिवेशीकरण
Coloured	अश्वेत
Commission	आयोग
Commission on chemical warfare	रासायनिक युद्ध आयोग
Commissioner	आयुक्त
Committee	समिति
Committee on Arbitration and Security	पचनिर्णय और सुरक्षा समिति
Common action	सामूहिक कार्रवाई
Common fear	सामान्य भय
Commonwealth of Nations	राष्ट्र-मण्डल
Communications (Pl.)	अड्डे और मोर्चे
Communist International	अन्तर्राष्ट्रिक कम्युनिस्ट संस्था
Community	समुदाय
Community of states	राज्य समाज
Compact group	सुगठित समूह
Compensation	क्षतिपूर्ति
Competitive power	प्रतिद्विधा शक्ति
Concentration camp	नजरबन्दो शिविर

Concession	१ रियायत २ सुविधा क्षेत्र
Conciliation	समझौता
Conditional	संशर्त
Condominium	मिश्र अधिकार
Congress	महासभा
Connivance	उपेक्षा
Conscription	अनिवार्य भर्ती
Conservative	अनुदार
Constitutional	सार्वधानिक
Contemporary history	सामयिक इतिहास
Continued	सतत
Contractual obligation	करारिक उत्तरदायित्व
Convention	समझौता
Corridor	गलियारा
Council	परिषद्
Council, supreme	सर्वोच्च परिषद्
Counter-boycott	प्रत्युत्तर बहिष्कार
Counter offensive	प्रत्युत्तर आक्रमण
Counter measures	प्रति उपाय
Counter part	प्रतिरूप
Counter-proposal	प्रत्युत्तर प्रस्ताव
Counter stroke	प्रति-प्रहार
Coup	राज्यदूरण
Court of International Justice	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय
Covenant	१ अनुबन्धपत्र २. अनुबन्धन
Credit	साध

Creditor	लेनदार
Crisis	संकट
Crown	सम्राट
Cruiser	गस्ती जहाज
Customs area	चुङ्गी क्षेत्र
Customs barrier	चुङ्गी नाका
Day-to-day	दैनिक
Deadlock	गतिरोध
Debate	पत्तन
Debit and credit	नामे और जमा
Debt	कर्ज
Debtor country	कर्जदार देश
Decade	दशक
Decree	आज्ञापित
Defection	कल व्यभिमुखता
Defence	प्रतिरक्षा
Defendant	प्रतिवादी
Defensive	प्रतिरक्षात्मक
Defensive alliances	प्रतिरक्षात्मक गुटबन्धियाँ
Defensive warfare	प्रतिरक्षात्मक युद्ध
Definitive	धन्तिम
Degraded	अवनत
Deliberations	विचार विमर्श
Delinquency	पयभ्रष्टता
Deliveries in kind	वस्तु-मुगतान
Demand	माँग
Demilitarisation	अस्त्रनीकरण
Democratic Party (U. S. A.)	डेमोक्रेटिक पार्टी

Democratic republic	प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र
Denunciation	रद्द किया जाना
Dependency	अधीन राज्य
Destitution	अकिंचनता
Destroyer	विध्वंसक
Detachment	सैनिक टुकड़ी
Deterrent	रोधक
Deterrent value	रोधक मूल्य
Devoid of Capital	पूँजीहीन
Dialect	बोली
Dictated peace	भारोपित शांति
Dictatorship	तानाशाही
Diplomacy	कूटनीति
Diplomatic configuration	कूटनीतिक नक्शा
Diplomatic relations	दौत्य संबंध
Diplomatic representative	कूटनीतिक प्रतिनिधि
Directing influence	निर्देशक प्रभाव
Director	संचालक
Director, Council of	संचालक परिषद्
Disaffected	१. अनिष्ठावान २. असंतुष्ट
Disagreement	असहमति
Disarmament	निःशस्त्रीकरण
Disband	विघटित करना
Discretion	स्वविवेक
Discriminatory	विभेदात्मक
Dismemberment	विसृजन
Dispersed	विसर्जित
Dispossessed	हृतधन

Disturbing forces	विक्षोभकारी शक्तियाँ
Document	दस्तावेज, आलेख
Dollar Imperialism	डॉलर साम्राज्यवाद
Domestic revolution	गृह क्रांति
Domestic safety	गृह सुरक्षा
Dominion	अधिराज्य
Downward race	क्षिप्र ह्रास
Draft	प्राकल्प
Due	देय
Dummy convention	सत्याम समझौता
Earmarked	विशेषांकित
Eastern Pact	पूर्वीय समझौता
Easy going	आत्म सतुष्ट
Economic breakdown	अर्थ व्यवस्था भंग
Economic nationalism	आर्थिक राष्ट्रीयतावाद
Economic outlet	आर्थिक बहिर्मुख
Economic union	आर्थिक संघ निर्माण
Embargo	रोक
Empty gesture	शून्य
Encroachment	अतिक्रमण
Enlarged	वर्धित
<i>En route</i>	मार्ग में
Entomology	मानव वक्ष-विज्ञान
Equitable	न्याय्य
European Union	यूरोपीय संघ
Eventually	अतत.
Ex-allies	भूतपूर्व मित्रो
Exchequer	राजकोष
Executive power	कार्यपालन शक्ति
Exonerating	दोषमुक्त कर

Expedient	इष्टकर
Exporter	निर्यातकर्ता
Export subsidy	निर्यात सहायता
Extract	उद्धरण
Extra-territorial	(राज्य) क्षेत्रातीत
Extra-territorial Jurisdiction	क्षेत्रातीत अधिकार
Factor	घटक
Fallacy	भ्रांति
Fascist	फासिस्ट
Fatherland	पितृभूमि
Federal	संघीय
Feud	भाषणी झगड़े
Fiasco	विफलता
Fitful	सतत
Flagging	ह्रासमान
Flagrant	निदास्पद
Fleet	बेड़ा
Flight	पलायन
Foot-Note	पाद टिप्पणी
Forces of reaction	प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ
Formal	औपचारिक
Formally	१. विधिवत् २. नियमानुसार
Fortunes of war	युद्धश्री
Forward policy	अग्रगामी नीति
Four-Power-Pact	चार-राष्ट्र समझौता
Fourteen Points	चौदह सूत्र
Franco-Soviet Alliance	फ्रांस-सोवियत गुटबंदी
Free city	स्वतन्त्र नगर

Free trade	अबाधित व्यापार
Freest possible	अधिकतम निर्बाध
Frontier post	सीमात चौकी
<i>Front Populaire</i>	लोक मोर्चा
Fuhrer	नात्सी नेता
Fundamental	मूलभूत
Fundamental issue	मूलभूत प्रश्न
Garrison	नगर रक्षक सेना
General Act for the Pacific Settlement of International Disputes	अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सामान्य अधिनियम
General Staffs	सेनपति सहायकगण
Gold bloc	स्वर्ण-गुट
Gold parity	स्वर्ण-तुल्यता
Gold reserve	स्वर्ण-कोष
Governor	राज्यपाल (बैंक) अध्यक्ष
Governing body	प्रबन्धकारिणी
Governing Commission	शासी प्रायोग
Great Power	बड़ा राष्ट्र
Great Wall	महान् भित्ति
Head quarter	मुख्यालय
High Commissioner	उच्च आयोग
His Majesty's Govern- ment in the United Kingdom and Northern Ireland	ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संयुक्त राज्य की सम्राट् की सरकार

Holly Alliance	ईसाई देश गुटबंदी
Hostile Land	शत्रुभूमि
House of Commons	लोकसभा (ब्रिटिश)
Humanitarian	मानवतावादी
Idealism	आदर्शवाद
Immigrant	आप्रवासी
Immigration	आप्रवासन
Imminent	आसन्न
Imperial	साम्राज्यिक
Improvident	अमितव्ययी
Incipient	प्रारंभ हुए
Inflation	मुद्रास्फीति
Insoluble	असमाधेय
Instructor	अनुदेशक
Instrument	लेख
Integrity	अखंडता, अखंड
<i>Inter alia</i>	और बातों के साथ ही साथ
Inter allied debts	मित्र राष्ट्रों के आपसी कर्ज
Inter Allied High Com- mission	अन्तर्मित्र-राष्ट्रीय उच्च आयोग
Inter-Governmental	अन्तर्सरकारी
Inter-war history	अन्तर्युद्ध इतिहास
Inter-dependence	अन्योन्याश्रय सम्बन्ध
Interest	हित
Interior	अन्तर्प्रदेश
Interpretation	निर्बचन
Intervening country	हस्तक्षेपकर्ता देश
Invested	विनियोजित
<i>Investing public</i>	विनियोजक जनता

Investor	विनियोजक
<i>Ipsa facto</i>	स्वरूप से ही
Irredentism	पुनर्प्राप्तिवाद
Irrevocably	अपरिवर्तनीय रूप से
Joint Sovereignty	संयुक्त संप्रभुता
Jurisdiction	क्षेत्राधिकार
Key product	‘प्राधार उत्पादन
Kingdom	राजतंत्र
<i>Laissez faire</i>	अबाधता
Landlocked	भूवेष्टित
Latin Great power	लेटिनी बड़ा राष्ट्र
League of Nations	राष्ट्रसंघ
Leased territory	पट्टाभिमित क्षेत्र
Left Wing	वामपंथी दल
Leftist	वामपंथी
Legal conundrum	कानूनी पेंच
Legalisation	बंधकरण
Legality	बंधता
Legally	विधितः
Legation	उपद्रतावास
Legion	सेना
Legislation	विधान
Legitimate	बंध
Lesser States	छोटे-छोटे राज्य
Lesser Power	अल्प महत्वपूर्ण राष्ट्र
Limitation	सीमन
Limitation treaty	सीमन-संधि

Limited Naval Conference	सीमित नौसैनिक सम्मेलन
Linguistic	भाषिक
Little Entente	लघुमन्त्री-संध
Majority	१. बहुमत २. बहुसंख्यक
Mandatory Power	संरक्षणवर्ती राष्ट्र
Mandatory system of Government	संरक्षणवर्ती शासन-प्रणाली
Matter of procedure	नियमिक मामला
Measure of value	मूल्यमान
Mediator	मध्यस्थ
Mein Kampf } My struggle }	मेरा संघर्ष
Memorandum	ज्ञापन ; स्मरण-पत्र
Men on services	सेवारत सैनिक
Merchant man	वाणिज्यपोत
Metallurgical industry	धातु उद्योग
Military age	रण सेवा योग्य आयु
Military autocracy	सैनिक निरंकुशता
Military Convention	सैनिक समझौता
Military machine	सैनिक संगठन
Military Occupation	सैनिक अधिकार
Military threat	सैनिक खतरा
Military value	सैनिक महत्त्व
Milliard	शरब
Mining district	खनिज जिला
Minister for League of Nations Affairs	राष्ट्रसंघ मामलों में मंत्री

Minority treaty	अल्पसंख्यक संधि
Missionary zeal	प्रचारकोचित उत्साह
Monarchy	राजतन्त्र
Moratorium	चुकान बिलव काल
Mortgage	बंधक
Most favoured nation	सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र
Multilateral	बहुपक्षीय
Multiplicity	विविधता
Municipality	नगरपालिका
National	१. राष्ट्रीय २. राष्ट्रवासी
National Assembly	राष्ट्रीय-सभा
National consciousness	राष्ट्रीय चेतना
National home	मातृभूमि
National Socialism	राष्ट्रीय समाजवाद
Nationalism	राष्ट्रवाद
Nationalist party	राष्ट्रवाद पार्टी
Nationalities	राष्ट्र-जातियाँ
Native	देशी
Native State	देशी राज्य
Natural inferiority	प्राकृतिक हीनता
Naval	१. नौसैनिक २. समुद्री
Naval base	समुद्री शट्टा
Naval disarmament	नौसैनिक नि-शस्त्रीकरण
Naval Power	नौसैनिक राष्ट्र
Naval Supremacy	सामुद्रिक प्रभुत्व
Naval treaty	नौसैनिक-संधि
Navigation	सामुद्रिक यावागमन

Nazi Revolution	नात्सी क्रांति
Near East	निकटपूर्व
Negative policy	नकारात्मक नीति
Negligence	प्रमाद
Negotiation	चर्चा
Neutral	तटस्थ
Neutrality Act	तटस्थता अधिनियम
New Deal	नया कार्यक्रम
Nomad	स्नानाबदोश
Nomadic population	स्नानाबदोश आबादी
Non aggression pact	अनाक्रमण समझौता
Non capital ship	युद्धपोत भिन्न जहाज
Non committally	वचनबद्ध न करते हुए
Non European World	गैर योरोपीय संसार
Non existent	अविद्यमान
Non intervention	अहस्तक्षेप
Non legal	अवैध
Non Nazi	नात्सी भिन्न
Non-recognition	अमान्यता
Non territorial	क्षेत्रतर
Noxious gases	हानिकर गैस
Numerical scheme	सांख्यिक योजना
Obligation	१. बाध्यता
	२. दायित्व
Obligatory	बाध्यकर
Observer	पयवेसक
Occupied area	अधिकृत क्षेत्र
Odium	दुरामृत
Offensive	आक्रमणात्मक कार्रवाई

Official	१. अधिकारी
On account	२. (name) अधिकृत
Optional Clause	आंशिक जुगतान
Ordinance	ऐच्छिक धारा
Organ of publicity	अध्यादेश
Organic fusion	प्रचार साधन
Organisation	आवयविक एकीकरण
Organised resistance	संगठन
Oriental	संगठित मुकाबला
Original decline	पौराण्य
Outer	मूल ह्रास
Outlawed	बहिर
Outlawry of war	विधिवहिष्कृत
Outlying	मुद्र का विधि बहिष्कार
Outpost	दूरस्थ
Outstanding	बीकी
Overgrown	दाय, वकाया
Over-riding factor	अतिवर्द्धित
Overtuled	अधिभूत कारण
Pacific Islands	अमान्य कर दिया
Pacifist	प्रशांत द्वीप
Pacifist doctrine of non resistance	शांतिवादी
Pact of alliance	शांतिवादी सत्याग्रह सिद्धान्त
Pact of reconciliation	संश्लेष-समझौता
Pairs of states	गुटबन्दी समझौता
Pan American	पुनर्संश्लेष समझौता
	दो दो राज्य
	अखिल अमरीकी

Panel	क्रमसूची
Paper money	पत्र धुद्रा
Paradoxical	परस्पर विरोधी
Parallel	समातर
Paramount	सर्वोपरि
Parliament	संसद
Parliamentary Democracy	संसदीय प्रजातन्त्र
Parliamentary system	संसदीय शासन-व्यवस्था
Passive resistance	निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह)
Patrol	गश्तीदल
Peace by force	शक्ति द्वारा शांति स्थापित करना '
Peace Conference	शांति-सम्मेलन
Peacemaker	शांति-स्थापक
Peace Settlement	शांति-समझौता
Peak figure	शिरो सख्या
Penal	दांडिक
Penalty	१. दंड २. शास्ति
Pending	विचाराधीन
Pensioner	निवृत्ति वेतनभोगी
Period of crisis	संकट काल
Period of enforcement	प्रवर्तन-काल
Period of optimism	आशावाद काल
Period of pacification	शांतिकरण-काल
Perplexing	आकुलताकारी
Persecute	सपीडित करना
Petition	याननापत्र, प्रार्थनापत्र
Physical guarantee	भौगोलिक गारन्टी
Place of refuge	आश्रय स्थान

Plebiscite	जनमत
Point of detail	विषय-विस्तार
Point of law	विधि प्रश्न
Pointedly	सूत्र रूप में
Police operations	पुलिस कार्रवाई
Political immaturity	राजनैतिक अपरिपक्वता
Political or social regime	राजनैतिक या सामाजिक-व्यवस्था
Polygot	बहुभाषाभाषी
Positive resistance	ठोस प्रतिरोध
Possessions	अधीन प्रदेश
Postscript	उत्तरलेख
Potential	समाध्य
Potentially	समाध्यत
Power	१. शक्ति २. राष्ट्र
Power, Great	बड़ा राष्ट्र
Precarious balance	खतरनाक सतुलन
Precedent	पूर्वोदाहरण
Predecessor	पुरोगामी
Preference	अधिमान
Preferential	अधिमानात्मक
Preparatory Commission for Disarmament Confer- ence	नि शस्त्रीकरण सम्मेलन-तैयारी प्रायोग
Pre war	युद्ध पूर्व
Price control	मूल्य नियन्त्रण
Primitive	प्रादिम जातीय
Private enterprise	निजी उद्योग
Privy	गुप्त सहकारी

Probationary period	परीक्षावधि
Productive guarantee	उत्पादक गारन्टी
Professional	व्यावसायिक
Prohibition	निषेध, मनाहो
Prohibitive visa fee	निषेधात्मक विसा फीस
Pro Germany	जर्मन पक्षी
Proletariat	सर्वहारा
Prosecutor	अभियोक्ता
Protection of labour	श्रमिकों की सुरक्षा
Protectorate	रक्षित राज्य
Protestant	प्रोटेस्टेंट धर्मानुयायी
Protocol	१. पूर्वपत्र २. उपसधि
Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes	अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपसधि
Provision	१. उपबंध (अधिनियम) २. व्यवस्था (अधिनियम)
Provocative	उत्तेजनात्मक
Public debt	लोक ऋण
Public opinion	लोकमत
Puppet Government	कठपुतली सरकार
Purchasing power	क्रय शक्ति
Purge	शुद्धि
Pusillaminous attitude	दब्लू रुख
Questionnaire	प्रश्नावली
Quiescent	अक्रियाशील
Quota	परिमाण निर्धारण

Race	मूलजाति
Racial	मूलजातिक
Radical	क्रातिवादी
Radical ministry	उग्र मन्त्रिमंडल
Rapid	त्वरित
Ratification	अनुसमयन
Reactionary	प्रतिक्रियावादी
Rearmament	पुनर्शस्त्रीकरण
Rearmament on land	यत्सेना का पुनर्शस्त्रीकरण
Rearrangement	पुनर्व्यवस्थापन
Receipt	१. प्राप्ति २. आय
Reciprocal Trade Agreement Act	पारस्परिक व्यापारिक समझौता अधिनियम
Reconciliation	पुनर्मेली
Recurrence	पुनरावृत्ति
Redeemable	विमोच्य
Reduced	अल्पीकृत
Re election	पुनर्निर्वाचन
Re emergence	पुनरुद्भव
Regent	राजप्रशासक
Regional	प्रादेशिक
Regional understanding	प्रादेशिक समझौता
(to) Register	पञ्जीयित करना
Regulation	विनियमन
Reichsbank	(जर्मनी की) राज्य बैंक
Reichstag	(जर्मनी की) लोकसभा
Reinforcement	कुमुक
Relief	राहत

Relief bond	राहत अक्षपत्र
Reluctance	आनाकानी; अनिच्छा
Renewed	नवकृत
Reorganisation	पुनर्सं गठन
Reparation	क्षतिपूर्ति
Reparation Commission	क्षतिपूर्ति आयोग
Reparation Powers	क्षतिपूर्तिप्रहीता राष्ट्र
Repercussion	प्रतिप्रभाव
Repetition	पुनरावृत्ति
Report	प्रतिवेदन
Representation	अभ्यावेदन
Reprisal	प्रतिशोध
Republic	गणतन्त्र
Republican party	रिपब्लिकन पार्टी
Repudiation	१. परिस्थान २. अस्वीकार
Requirements	अपेक्षाएँ
Research work	खोज कार्य
Reserve	१. रक्षित सेना २. संचित (Currency)
Restored	पुनर्स्थापित *
Restriction	निर्बन्धन
Return of power politics	शक्ति-कूटनीति का पुनः प्रारम्भ
Revenue receipt	राजस्व प्राप्ति
Revisionism	१. पुनर्व्याख्यानवाद २. संशोधनवाद
Revival	पुनरुत्कर्ष
Revolution	क्रांति
Revolutionary	क्रांतिकारी

Rift	फूट
Right wing	दक्षिणपंथी दल
Ring	धेरा
Rival	प्रतिद्वन्दी
Rival grouping	प्रतिद्वन्द्वात्मक झुट्यदी
Round up	घरपकड़
Routine activity	नैत्यक गतिविधि
Royal Commission	शाही मायोग
Royalist	राजावादी
Rubric	शीर्षक
Ruling	सत्तास्थ
Rupture	विग्रह
Sacred trust of civil zation	सम्य देशों का पवित्र कर्तव्य
Sanction	अनुशास्ति
Satellite	पिछलग्गू
Satellite cities	अनुयायी नगर
Schedule of payment	भुगतान कार्यक्रम
Second place	गौण स्थान
Secretariat	सचिवालय
Secretary General	महा सचिव
Secretary of state	मन्त्री
Security	१. प्रतिभूति २. सुरक्षा
Security, demand for	सुरक्षा माँग
Self determination of peoples	जनता द्वारा आत्म निर्णय
Self governing	स्वशासी

Semi barbarian	आधे जगली
Semi independent	आध स्वतंत्र
Senior	वरिष्ठ
Separatist	पाषक्यवादी
Sequel	अनुपरिणाम
Settlements	बस्तियाँ
Sheet anchor	अंतिम आश्रय
Short term borrowing	अल्पकालीन ऋण
Signatory	हस्ताक्षर-कर्ता
Signed	हस्ताक्षरित
Silent evasion	अप्रकट उल्लंघन
Sinfulness of war	युद्ध पाप
Skirmish	सामूली भिडन्त
Slavery convention	दासता सम्झौता
Slump	मंदी
Social services	समाजोपयोगी सेवाएँ
Socialist	समाजवादी
Solvency	हैसियत
Sovereignty	संप्रभुता
Soviet	सोवियत
Speculator	सट्टे बाज
Spiritual autobiography	उच्चावशपूर्ण आत्मचरित
Sporadic outbreaks	छुटपुट घटनाएँ
Stabilisation	स्थिरीकरण
Standard Maximum	प्रामाणिक अधिकतम
State bank	राज्य बंक
State machine	प्रशासन तंत्र
State monopoly	राज्य का एकाधिकार
State of war	युद्धस्थिति

State regulation	राज्य द्वारा विनियमन
Statement of policy	नीति वक्तव्य
Statesmanship	राजनीतिकुशलता
Status	स्थिति
<i>Status Quo</i>	पूर्व स्थिति
Statute	विधान
Statute of Westminster	वेस्टमिनिस्टर विधान
stipulate	ठहराव करना
Storm centre	विशेष केन्द्र
Straits	जलडमरूमध्य
Strategic importance	सामरिक महत्त्व
Struggle for power	शक्ति सघर्ष
Subjects	प्रजा
Sub marine	पनडुब्बी
Submission	समर्पण
Subsequent	परवर्ती
Subsidy	आर्थिक सहायता
Suburb	उपनगर
(to) Superintend	अधीक्षण करना
Supernational	अधिराष्ट्रीय
Supernational military force	अधिराष्ट्रीय सेना
Supplementary	पूरक
Supreme Command	सर्वोच्च कमान
Supreme Court	सर्वोच्च न्यायालय
Surgical operation	शल्य क्रिया
Surtax	अधिकर
(to) Suspend	विलंबित करना
Suzerainty	प्रभुत्व

Tacit	मौन
Tactics	पैतरा
Tangled question	पेचीदा प्रश्न
Tantamount to	के बराबर
Tariff	आयात-निर्यात-कर
Tariff protection	आयात निर्यात कर-संरक्षण
Tariff truce	अस्थायी आयात निर्यात-कर समझौता
Technical	प्राविधिक
Technical sub-commission	प्राविधिक उप आयोग
Temporary Mixed Comm- ission	अस्थायी मिश्र आयोग
Territorial waters	क्षेत्रिक सागर
Term	१. अवधि २. निबन्धन
Time honoured	समयाहत
Title	हक
Tonnage	टन परिणाम
Trade Mission	व्यापारिक शिष्टमंडल
Tranquility	शांति
Transaction	लेन देन
Transfer	१. स्थानांतरण २. हस्तांतरण
Transition	संक्रमण
Transport	परिवहन
Treasury view	राजकोष दृष्टिकोण
Treaty of Arbitration	पंचनिष्ठ संधि
Treaty of Mutual Assis- tance	परस्पर सहायता संधि
Treaty of peace	शांति संधि

Treaty prohibition	सधि निषेध
Treaty-veto	सधि निषघ
Tribunal	न्यायाधिकरण
Trio	त्रिगुट
Tripartite	त्रिपक्षीय
Trustee	न्यासी
Unacceptable	अस्वीकार्य
Un-American	अमरीकी परम्परा के विरुद्ध
Unanimity rule	निर्विरोध नियम
Unanimous	निर्विरोध
Unanimously agree	एकमत होजाना
Undefined	अनिश्चित
Unequal treaty	असमान सधि
Undertaking	आश्वासन
Undesirable	अवाछनीय
Undisclosed	अप्रकट
Unexpected	अप्रत्याशित
Unified	एकीकृत
Uninhabited	निर्जन
Union of Soviet Socialist Republics	सोवियत समाजवादी गणतन्त्र सघ
Unit	१. इकाई २. (N1) यूनिट
United	सयुक्त
United States of America	सयुक्त राज्य अमरिका
United States of Europe	यूरोपीय सयुक्त राज्य
Universal	सार्वदेशिक
Unjustifiable	अन्याय्य

Unless otherwise expressly provided	जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबधित न किया गया हो
Unlimited	असीमित
Unofficial	असरकारी
Unofficial name	असरकारी नाम
Unremunerative	अलाभदायी
Unrestricted	१. निर्बन्धनहीन २. अबाधित
Untenable position	असमर्थनीय स्थिति
Unwelcome	अशुचिकर
Upper	उपरि
Uppermost	सर्वोपरि
Up to-date	अद्यावधिक
Usage	प्रथा
Vacillating	दुलमुल
Valid	वैध
Vengeance	प्रतिशोध
Vicious circle	कुचक्र
Victim of aggression	आक्रमण का शिकार
Violation	अतिक्रमण
Volte face	उधल पुधल
Vulnerable	जैय
War Criminal	युद्ध अपराधी
War debt	युद्ध कर्ज
War guilt	युद्ध अपराध
War indemnity	युद्ध-क्षतिपूर्ति
Warlike	युद्धसम
Wartime gain	युद्धकालीन प्राप्ति

Ways and means	प्रयोज्य
Wealthy class	धनिक वर्ग
Well being	कल्याण
White Russia	श्वेत रूस
Without prejudice to	विपरीत प्रभाव डाले बिना हो
World Economic Conference	विश्व अर्थ सम्मेलन
World order	विश्व व्यवस्था
Wounded to the quick	गहरी चोट पहुँचाई
Zenith	चरम शिखर
Zone	क्षेत्र

